राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] **चौदहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का नवां दिवस** **[संख्या : 7**

शनिवार,

19 जुलाई, 2014

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। नमस्कार।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): चरण स्पर्श।

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री रमेश, सदस्य की ओर से वन विभाग के अन्तर्गत बनास परियोजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में विभिन्न मदों से कराये गये कच्चे एवं पक्के निर्माण कार्यों में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(2) श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य की ओर से चने का समर्थन मूल्य तय कर क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से चने खरीदने के आदेश देने के बाद भी किसानों से खरीद नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर उन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य, श्री रमेश एवं श्री गोविन्द सिंह डोटासरा को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से बरसात नहीं होने के कारण नर्मदा नहर परियोजना का पानी सांचौर एवं बाड़मेर को उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से राज्य में चरागाह, सिवाय चक, स्कूलों के खेल मैदान व वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने के सम्बन्ध में।

(3) श्री मानसिंह, सदस्य की ओर से जिला सवाई माधोपुर के मद्दुकला एवं गंगापुर सिटी के बीच स्वीकृत रेलवे अण्डरपास का निर्माण कार्य शुरू करवाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री कैलाश भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर के कतिपय स्थानों पर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री अनीता, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नगर के गांवों की पेयजल समस्या का निवारण करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से जिला अलवर में परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कतिपय मार्गों पर बसें संचालित करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री रामचन्द्र, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भवानी मण्डी की राजस्थान टैक्सटाइल मिल्स द्वारा किये जा रहे अव्यवहारिक कार्यों के खिलाफ कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री विट्ठल शंकर अवस्थी, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा जिले के कपड़ा उद्योग एवं टैक्सराइज यार्न (पालिस्टर फिलामेन्ट) के वैट टैक्स में विसंगति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) डा. जसवन्त सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में लगे उद्योगों में स्थानीय नवयुवकों को रोजगार देने के सम्बन्ध में।

(10) श्री नानालाल अहारी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के ऋषभदेव रैफरल हास्पिटल में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(11) श्री प्रतापलाल भील, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की पेयजल समस्या का समाधान करने हेतु प्रस्तावित योजनाओं की क्रियान्विति करने के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती सोना देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर के चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची।

(1) श्री भंवरसिंह, बीकानेर जिले में बिजली से सम्बन्धित समस्याओं के सम्बन्ध में।

(2) श्री अमराराम, हरिके बैराज से राजस्थान को मिलने वाले प्रदूषित पानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती अमृता मेघवाल, जालौर में कृषि महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री गोतम कुमार, बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र के जासन्ता बांध में अधिशेष पानी का पेयजल के उपयोग में लेने के सम्बन्ध में।

श्री रमेश।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बनास परियोजना में पक्के एवं कच्चे कार्यों में हुई अनियमितताएं

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, वनों का विकास हो और वनों में घना जंगल हो, पानी का ठहराव हो और जो हमारी बनास परियोजना है, वह हमारे करौली, सवाई माधोपुर और टोंक जिले तीनों इसके अन्दर आते हैं इस विभाग के अन्तर्गत, तो इन विभाग के माध्यम से, बनास परियोजना विभाग के माध्यम से जो आज तक, तीन वर्ष की बात कर रहा हूं, बरसों से काम चल रहा है। न किसी सरकार पर आरोप है, मैं बताना चाहता हूं कि विभाग में एक ऐसा सब-डिवीजन है, वन विभाग में कि एक मलाइदार, जिसमें जनता को पता है, न नेता को पता है और अधिकारी मजे से इस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। भारत सरकार के सहयोग से और राजस्थान सरकार

(श्री रमेश)

के सहयोग से, अभी मेरे पास ज्यादा डैटा नहीं हैं, दो साल का जो बजट दिया है 1201.15 लाख और 1100 लाख, तो 23 करोड़ के लम्पसम जो बजट मिला है और इसमें जो काम करवाने हैं एनिकट का निर्माण है, टैंक का निर्माण है, नोंच का निर्माण है और क्लोजर है, कच्चे पक्के निर्माण हैं, बीजारोपण है, फिल्टर है, फार्म पाउण्ड है। इसमें जो कार्य कराये जाते हैं, इनके लिये पैसा दिया जाता है, लेकिन होता क्या है कि इससे पूर्व अकाल राहत के माध्यम से या नरेगा के माध्यम से जो पहले के कार्य हुए हैं, उन्हीं का रिनोवेशन या छोटी-मोटी कहीं प्लास्टर कर देना, जैसे पक्के कार्य हैं, उनमें प्लास्टर कर दिया। एनिकट की कम गहराई की और फिल्टर है तो उसमें भी पुराना फिल्टर है, उसको उलटफेर कर दिया। इसी तरह फार्म पाउण्ड है पुराना खुदा है, उसका रिनोवेशन कर दिया। तो नरेगा के माध्यम से और अकाल राहत के माध्यम से जो काम हुए हैं, उन कामों का इस एम बी में इन्द्राज कर दिया जाता है और माननीय अध्यक्ष महोदय, इस परियोजना में टैण्डर की जो व्यवस्था है, वह डायरेक्ट काम दे दिया जाता है, कोई अनुभव की बाध्यता नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है। वन विभाग में 50 रुपये का पंजीयन कराओ और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और जो जानकार होता है विभागीय फोरेस्टर रेंजर का, वह काम ले लेता है और एक लाख से लेकर करोड़ों रुपये का काम करता है और इसमें भ्रष्टाचार की बात मैं आपको बताता हूं, जो अनियमितताएं हैं, इसमें जो कमीशन है, मैं भी देखकर दंग रह गया। एक काम के बारे में मैंने जानकारी ली तो ठेकेदार से कहा मैंने यह काम आपने गलत किया है। उसने बताया कि मैं काम कहां से करूंगा। इसमें 50 प्रतिशत कमीशन है। जो सिस्टम में अनियमितताएं हैं 50 प्रतिशत। जब 50 प्रतिशत कमीशन होगा तो कांट्रैक्टर भी 10 प्रतिशत लेगा, तो फिर काम कितने पैसों का करायेगा। 10 से 25 प्रतिशत पैसा ही इसमें लग पाता है। बाकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि बनास परियोजना में जो भी काम हुए हैं इन तीन सालों में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में, सपोटरा में, अमरबाड़, नरौली, निभरा, रावतपुरा, अडाडूंगर, कैलादेवी और श्यामपुर रोड, चंदेलीपुरा, बहादुरपुर, दौलतपुरा, कल्याणपुरा, मातोरियाकी, चोणक्य कला, चोणक्या खुर्द, हरिकी आदि में बनास परियोजना के माध्यम से काम हुए। इनमें भारी अनियमितता हुई है और हम यहां लड़ते हैं कि आपके कार्यकाल में यह हुआ, आपके कार्यकाल में वह हुआ। मुद्दा इस बात का है कि सदन में न

(श्री रमेश)

तो जनता को पता होता है, न नेताओं को पता होता है, क्योंकि जो फोरेस्ट में काम होते हैं, जनता का कोई लेना-देना नहीं है। हमारे नेता हैं वह यहां राजनीति में हैं, अपने डाटा बताने में रहते हैं, अपनी राजनीति करते रहते हैं और एक वन विभाग ही ऐसा है, जो मलाइदार है, जो 50 प्रतिशत तक कमीशन, और जिसका मैं विवरण भी बता दूं। 7 प्रतिशत के लगभग गार्ड लेता है, 12 प्रतिशत के लगभग रेंजर लेता है, ए.सी.एफ.सी.एफ. 14 प्रतिशत, मतलब गार्ड से लेकर सी.सी.एफ. तक, यह 50 प्रतिशत कमीशन जाता है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना पैसे का एक साइफन हो रहा है। इसको रोका जाये और इसमें एक जांच कमेटी बिठाई जाये तो माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से मैं इसमें जवाब चाहता हूं कि आप क्या कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। (व्यवधान) आप रेस्पांड कर रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जी हां। अध्यक्ष महोदय, सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य ने वन विभाग द्वारा भू-संरक्षण के जो काम विशेष तौर पर बनास और लूणी नदी के कैचमेंट क्षेत्र में हुए, उनमें भ्रष्टाचार की बात उठाई है। अध्यक्ष महोदय, पूरा राजस्थान जानता है कि पिछले तीन वर्षों में, विशेष तौर पर आपने उल्लेख किया है 2009-10, 2010-11 और 2012-13, यह काल खण्ड कुछ ऐसा था कि इन विभागों के अन्दर कमीशनखोरी कुछ बढ़ गयी थी और आपने खुद ने 50 प्रतिशत कमीशन की बात कही है।

श्री अध्यक्ष: आपने कहा, उसी पर आ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): और आपने यह भी कहा बिना निविदाएं आमंत्रित किये काम हो गये, आपने यह भी कहा है कि 50 रुपये की रसीद काट कर यह काम होते गये। अकाल राहत कार्य के अन्दर जिन कामों को कर लिया उनका दोहरा भुगतान हो गया। 23 करोड़ के कामों का जिक्र आपने किया। कुछ गांव आपने लिख कर दिये हैं, कुछ गांव आपने गिनाये हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा क्योंकि यह सरकार कहने को पारदर्शी नहीं है, यह सरकार वास्तव में पारदर्शी है और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने में इस सरकार ने जो पूरे देश

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में काम आगे बढ़ाया है, आपने देखा होगा एण्टी करप्शन को, जिस तरह के सोफ्ट इक्विपमेंट देकर इन सबके ऊपर शिकंजा कसने की मंशा हमारी मुख्य मंत्रीजी ने रखी है।

तो इनकी पूरी जांच करवायेंगे, माननीय सदस्य, आपके पास और तथ्य हो तो आप लिख कर दे दें। इसकी जांच करवा कर, इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही करायेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

क्रय-विक्रय सहकारी समितियों द्वारा किसानों से चने की खरीद नहीं किया जाना

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान मानसून नहीं आने से परेशान है और जो किसान का चना है, जो समर्थन मूल्य सरकार ने 3100 रुपये तय कर रखा है उसके ऊपर पूरे प्रदेश में जो क्रय-विक्रय सहकारी समितियां खरीद रही हैं वो केवल व्यापारी का चना खरीद रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल व्यापारी को लाभ देने के लिए किसान का चना नहीं खरीदा जा रहा है। हमारे सीकर की हालत यह है कि जब किसान के चने बिकने की बात आयी तो सरकार ने 28 जून को रोक लगा दी कि अब क्रय-विक्रय सहकारी समितियां नहीं खरीदेंगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, अकेली सीकर मण्डी में क्रय-विक्रय के माध्यम से 61 हजार बोरी खरीदी गयीं केवल मात्र उसमें अधिकतर व्यापारियों की हैं जो किसान से गिरदावरी ले लेते हैं और उसके बाद में करते हैं। दांतारामगढ़ में 23 हजार बोरी, यों करके 91 हजार बोरी सीकर क्रय-विक्रय सहकारी समिति और दांतारामगढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति ने खरीदी और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि जो पैसा है वो नहीं दिया जा रहा है। 15 करोड़ से अधिक का पैसा है, डेढ़ महीने से किसान परेशान है, 15 मई के बाद में कोई पेमेंट किसान को नहीं दिया जा रहा है। आज किसान का एक तो चना आपने लिया नहीं, व्यापारियों का लिया, किसान का जितना लिया उसमें से भी 15 करोड़ रुपये आपने डेढ़-डेढ़, दो-दो महीने से रोक रखे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मई के बाद में जून चला गया, जुलाई चली गयी, आज एक किसान चना इसलिए बेचता है,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

अपना अनाज इसलिए बेचता है कि उसको घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है, उसकी बच्ची की शादी करनी होती है, उसको काम करना होता है लेकिन आज दो रुपये सैकड़ों किसान ब्याज का भर रहा है और किसान को उसका मूल्य नहीं मिल रहा है।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वापस सरकार किसानों के चने की खरीद करे, समर्थन मूल्य दे और जिस दिन किसान अनाज लेकर के आता है और उसको तोला जाता है उसके बाद में उसी दिन किसान को पैसा मिलना चाहिए या एक-दो दिन में पैसा मिलना चाहिए अगर दो महीने, तीन महीने तक किसान का पैसा नहीं मिला तो निश्चित रूप से किसान सड़कों पर आ जायेगा, धरने के लिए खड़ा हो जायेगा और अगर ला एण्ड आर्डर की स्थिति बिगड़ गयी तो यह सरकार वैसे भी फेल है, कोई ला एण्ड आर्डर की स्थिति सम्भल नहीं रही है और अगर किसान फिर सड़कों पर आ गया, अगर उसका पैसा नहीं मिला ... (व्यवधान)

किसान की बात कर रहे हैं, किसान को पैसा नहीं दिलाना चाहते हो क्या आप? (व्यवधान) ब्याज बढ़ाया आपकी सरकार ने, आप भी कहने लग गये बहुत अच्छा बजट है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन को सम्बोधित कीजिए आप। नहीं, उधर नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब किसान को समर्थन मूल्य, जब ले लिया किसान का, किसान का चना खरीद लिया उसके बाद में उसको पैसा मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिये, रिपीट मत कीजिए। (व्यवधान) रिपीट मत कीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): तो, अध्यक्ष महोदय, बात तो किसान की ही नहीं करूं, अपराध की भी नहीं करूं, किसान का पैसा भी नहीं दे रही है सरकार, उसका भी नहीं करूं?

श्री अध्यक्ष: आप इधर बात करो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरा केवल मात्र यही निवेदन है कि किसान को मई के बाद में जो उसका चना खरीदा गया, क्रय-विक्रय सहकारी समितियां, सरकार

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

उनका पैसा नहीं दे रही है। सीकर जिले में भयंकर हालात हैं। वहां के लोग, किसान आन्दोलन पर उतारू हैं। रोजाना मण्डी में आते हैं, रोजाना सुबह से शाम वो परेशान होकर के वापस चले जाते हैं। दो महीने से उनका पैसा नहीं मिल रहा है और जो व्यापारियों के साथ में घालमेल कर के क्रय-विक्रय सहकारी समितियों ने चना खरीदा है, किसान का जो चना घर में पड़ा है उसको वापस खरीदने के लिए सरकार को निर्देशित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सरकार पुन: चना खरीदे और किसान का जो बकाया पैसा है उसको जल्दी से जल्दी सरकार दिलाये।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। यह बात आप कह चुके ... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बैठ जाऊंगा लेकिन किसान के लिए यह सदन है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, लेकिन का सवाल नहीं है। आप जो बातें पहले कह चुके हो उन्हीं को रिपीट कर रहे हो। आप अपना चिट देख लो, बार-बार रिपीट करने से क्या होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 80 परसेंट संख्या गांवों में रहती है और केवल किसान अनाज और पशुधन के सहारे जीता है, आज बरसात आ नहीं रही है, उसको पैसे की जरूरत है और वो पैसा सरकार लिये बैठी है। दो-दो महीने का पैसा किसान का बकाया है, माननीय अध्यक्ष महोदय। इसके लिए कोई व्यवस्था तो करें, माननीय मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष: यह कह चुके हैं आप। (व्यवधान) अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह किसान परिवार से आते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: तीन-तीन बार एक बात आप क्यों कह रहे हैं?

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर श्री सुखराम विश्नोई।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: वो चाहे तो दे देते हैं, नहीं चाहते नहीं देते ...(व्यवधान) आप बैठिये।

अगर वो रेस्पोण्ड करना चाहेंगे तो करेंगे। (व्यवधान) बार-बार खड़े मत होइये, यह क्या मतलब है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, वो नहीं देना चाहते हैं तो मैं नहीं दिला सकता। दे रहे हैं आप?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है वो सरकार के ध्यान में आ गया है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो पूरा पेमेंट किया जाता है वो नैफेड के द्वारा भारत सरकार के द्वारा होता है।

अभी माननीय सदस्य ने कहा कि एक-दो दिनों में पेमेंट होना चाहिए, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि पिछली सरकार में आपने एक-दो दिनों में पेमेंट कराया है क्या किसानों को? कोई भी ऐसा है ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): आप मेरी बात सुनें।

माननीय अध्यक्षजी, इसके लिए भारत सरकार को लिख दिया गया है और तुरन्त, पेमेंट आते ही प्राथमिकता के आधार पर किसानों को पेमेंट किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई। प्रतिपक्ष के नेता।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय मंत्रीजी, यह बहुत गम्भीर समस्या है। तीन महीने से पेमेंट बाकी नहीं पड़ा, पेमेंट पड़ा है दिसम्बर से। दिसम्बर के अन्दर मूंगफली खरीदी थी ...(व्यवधान) मूंगफली और चना। चने की खरीद तो अभी मार्च में चालू हुई है और मूंगफली की खरीद हो गयी थी दिसम्बर में और दिसम्बर का पैसा आज किसान को मिला नहीं और किसान कर्ज लेकर अपना खेत जोतता है और फिर फसल निकाल कर बाजार में बेच कर वो कर्ज चुकाता है।

तो यह जो समस्या है इसको आप गम्भीरता से लो। हम यह नहीं कहते कि आपकी गवर्नमेंट ने क्या करा और हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा हम

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

तो यह कह रहे हैं कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, उनका पैसा दिसम्बर से बाकी पड़ा है और इनको तुरन्त प्रभाव से पैसा दिलाया जाए।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। श्री सुखरामजी विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना जो दिया है...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): यही पढ़ रहा हूं, साहब।

श्री अध्यक्ष: हां, यही पढ़ो आप।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): पढ़ कर बोल रहा हूं। आखें तेज हैं, साहब, दिख रहा है।

श्री अध्यक्ष: मुझे लगा, आप भाषण दे रहे हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय 295 में यह भाषण अगर चालू हो जायेंगे तो फिर सभी बोलेंगे। यह पढ़ें न अपना यह। वह तो अक्षरश: पढ़ता है, एक-एक लाइन पढ़नी पड़ती है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह आपने जो लिख कर दिया है वो मेरे पास है। इसको पढ़िये आप। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मैं यही पढ़ रहा हूं, साहब।

श्री अध्यक्ष: हां, पढ़िये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री अध्यक्ष: इसमें नहीं है यह, मैं भी लेकर बैठा हूं। इसमें आप शुरू से पढ़ो, देखिये आप, भाषण के रूप में नहीं पढ़ने के रूप में।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): पढ़ा है, साहब, यही तो पढ़ रहा हूं मैं। (व्यवधान) यह पढ़ रहा हूं न तो।

एक माननीय सदस्य: लाइन टू लाइन पढ़ो।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बरसात के अभाव में नर्मदा का पानी सांचौर व बाड़मेर को उपलब्ध कराया जाना

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि आधा जुलाई का महीना चला गया है और अभी तक पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जालौर व बाड़मेर जिले में बरसात नहीं हुई है। जालौर जिले की सांचौर तहसील व बाड़मेर जिले की गुढ़ामालानी व चौहटन तहसील में नर्मदा नहर चलती है। लेकिन नहर में पानी नहीं होने की वजह से किसान खेतों में खरीफ की फसल नहीं बो पा रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि हमें खरीफ की फसल में पानी देने का प्रावधान नहीं है। ऐसे में किसान खरीफ की खेती नहीं कर पा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के सामने अकाल मंडरा रहा है। चारा नहीं होने से पशुओं को पालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आज चारा दस रुपये किलो मिल रहा है। एक किसान को अपने पशु पालन के लिए रोज 4 सौ रुपये का चारा चाहिए तथा जिन किसानों के पास में 4-5 पशु हों वो अपना परिवार पालें या पशुओं को पालें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इसी में से पढ़ना है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): पढ़ रहा हूं ना मैं। उसी को तो पढ़ रहा था।

श्री अध्यक्ष: पढ़िये, पढ़िये, आप चालू रखिये। आप चालू रखिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: शांत रहें।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): किसान दुविधा में पड़ा है। नर्मदा नहर का पानी बेवजह से नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है। सरकार कल्याणकारी, पारदर्शी होने का व सरकार अपने द्वार जैसे कई कार्यक्रम चला रही है जबकि हम पानी की मांग कर रहे हैं। पूरा स्टाफ नर्मदा सांचौर में लगा हुआ है। सरकार को कोई अतिरिक्त संसाधन जुटाने की जरूरत नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे में मैं मांग कर रहा हूं कि नर्मदा नहर में 1 हजार क्यूसेक पानी चलाया जाये जिससे नर्मदा नेचुरल फ्लो की नहर व

(श्री सुखराम विश्नोई)

सांचौर लिफ्ट, पनौरिया लिफ्ट, भदराई लिफ्ट में प्राप्त पानी किसानों को मिल सकेगा व सरकार को भी अकाल में इन गांवों में आपदा प्रबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी व किसान अपने घर बैठा बाजरी पिलाकर पशुओं व परिवार को पाल सकेगा।

अत: आज ही राज्य सरकार नर्मदा मुख्य कार्यालय सांचौर में कार्यरत मुख्य अभियंता को पत्र भेजकर पानी नहर में छोड़ने के निर्देश दे।

श्री अध्यक्ष: श्री हीरालाल नागर।

राज्य में चरागाह, सिवायचक, विद्यालय मैदान व वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमणों की रोकथाम

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि आज पूरे प्रदेश में समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी जमीन चाहे वह चरागाह हो, सिवाय चक हो, वन भूमि हो या बच्चों के खेल के मैदान हो इन पर अतिक्रमण करके कब्जा करने की होड़ मची हुई है। इन जमीनों पर पंचायतों ने चरागाह विकास या नरेगा में वृक्षारोपण करके विकास किया है या वन क्षेत्रों में वृक्ष लगाये हों, उन वृक्षों को काटकर, नष्ट करके उस जमीन पर भू-माफिया, प्रभावशाली बाहुबलियों द्वारा कब्जा करके समस्त जमीन को हथियाया जा रहा है और सम्पूर्ण प्रशासन चाहे ग्राम पंचायत हो, पटवारी हो, पंचायत समिति हो, तहसीलदार हो, एसडीओ हो से लेकर कलक्टर तक मूकदर्शक होकर इस कुकृत्य को होता देख रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य की बात तो तब होती है जब जन-प्रतिनिधियों के पास यह शिकायतें आती हैं तो शिकायतों से अवगत कराने के बावजूद उन पर प्रभावी कार्यवाही नहीं करके चरागाह भूमि को रेवेन्यू विभाग ग्राम पंचायतों के अधिकार में बताकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं और पंचायतें प्रभावी कार्यवाही करने में नाकाम रहती हैं। सरपंच वोट की राजनीति के कारण इन अतिक्रमणों को हटाने से बचना चाहते हैं। जबकि हालात भीषण हैं। गांवों में खेतों तक जाने के रास्ते नहीं हैं। आये दिन रास्तों को लेकर लड़ाई-झगड़े होना आम बात है और इन शिकायतों को लेकर गांवों में हत्याएं तक हो जाती हैं व कानून-व्यवस्था बिगड़ती है।

उक्त गम्भीर लोक महत्व के विषय को लेकर हमें सदन में इस पर गैर जमानती धाराओं को कठोर कानून बनाना चाहिए तथा सम्बन्धित पटवारी,

(श्री हीरालाल नागर)
ग्राम सेवक, वनपाल इत्यादि विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि वह इन अतिक्रमणों की रिपोर्ट तुरन्त करें और उनकी रिपोर्ट पर सम्बन्धित अधिकारी तुरन्त कार्यवाही कर अतिक्रमणों से भूमि मुक्त करावें तथा जिस पटवारी, ग्राम सेवक, वन कर्मी के क्षेत्र में अतिक्रमण हुआ है उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही का प्रावधान करने हेतु हमें नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता है।

इस हेतु एक अभियान चलाकर हमें अतिकर्मियों द्वारा कब्जा हुई भूमि की सूची तैयार कराकर उन्हें मुक्त कराने के बाद व मुक्त भूमि पर दुबारा कब्जा न करने पर अगर कार्यवाही नहीं होती है तो सम्बन्धित उक्त समय जो कर्मचारी, अधिकारी वहां पदस्थापित रहा हो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये। दोषी पाये जाने पर उसे नौकरी से हटाने का कानूनी प्रावधान करने की आवश्यकता है तभी हम पशु धन, गौ माता व वन्य जीवों को बचा सकते हैं और पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। अन्यथा आने वाले समय में स्थिति और भी भयावह होने की आशंका है।

मेरा इस पर यह सुझाव भी है कि गांवों में सरकारी सिवाय चक, चरागाह भूमि का लैंड बैंक बनाकर सीमाबंदी करवाकर उन्हें चिह्नित कराया जाये, ऐसी भूमि को नरेगा के तहत खाई खुदवाकर मेड़बंदी कराकर सुरक्षित किया जाये और हर वर्ष सम्बन्धित कर्मचारी को यह शपथ-पत्र देना अनिवार्य हो कि उसके क्षेत्र में किसी तरह का अतिक्रमण नहीं है और यदि है तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है। इस प्रकार हम प्रदेश को अतिक्रमण की समस्या से निजात दिला सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री मानसिंह।

महुकला (सवाई माधोपुर) व गंगापुर सिटी के मध्य स्वीकृत रेलवे अण्डरपास का शीघ्र निर्माण

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि महुकला एवं गंगापुर सिटी के बीच स्वीकृत रेलवे अंडर ब्रिज का कार्य शुरू कराने से गंगापुर सिटी व सपोटरा क्षेत्र के 40 गांवों की जनता का आवागमन रहेगा एवं आये दिन घटित होने वाली माननीय दुर्घटनाओं से इंसानी जानों को बचाया जा सकेगा। इसकी विभागीय स्वीकृति F 1(3) (63) (86)/RUIFDCO/RUB Bayana-Nangler Sheesa/2012-13/1295 dated 18/08/2013

(श्री मान सिंह)

द्वारा construction of ROB in Gangapur city NOLC 6.50 cr. महोदय, यह अंडरपास लालफीताशाही का शिकार हो रहा है। सही मायने में रेलवे व RUIF-DCO के मध्य आपसी तारतम्य के अभाव के कारण यह देरी हो रही है, जिसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है।

इस संदर्भ में जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर द्वारा उप शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को प्रेषित पत्र क्रमांक प.17(14) एलसी/न्याय/2010/1792 दिनांक 3.07.2014 एवं वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (उत्तर) पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा द्वारा जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर को प्रेषित पत्र 12.12.2013 एवं 23.01.2014 से यह प्रतीत होता है कि एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाली जा रही है। साथ ही अनभिज्ञता भी जाहिर की जा रही है। महोदय, आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि वस्तुस्थिति क्या है? क्या यह स्वीकृति भी है या नहीं है और यदि स्वीकृति है तो देरी के लिए कौन जिम्मेदार है?

कृपया त्वरित कार्यवाही कर अंडरपास का निर्माण कार्य शुरू करवाया जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश भंसाली।

(अनुपस्थित)

श्री अनीता।

श्रीमती अनीता (नगर): ठीक है साहब, क्या दिक्कत है? यहां कोई श्रीमान, श्रीमती थोड़े ही है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपके यहां श्री राधे, श्री राधे कहते हैं ना इसलिए अध्यक्ष महोदय को ध्यान रह गया। वृंदावन में श्री राधे ही कहते हैं, ब्रज में।

श्री अध्यक्ष: जो सूची में अंकित है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 'श्री' शब्द बना ही केवल महिलाओं के लिए ही है।

श्री अध्यक्ष: अच्छा ही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां। 'श्री' शब्द महिलाओं के लिए ही है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप बताओ तो सही ...(व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): हाउस जानना चाहता है ...(व्यवधान)

श्री सुशील कटारा (चौरासी): सदन में 2-3 अनिता हैं इसलिए पीछे विधान सभा का नाम भी ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अब यह सदन की सम्पति हो गयी है, अब आप बतायें 'श्री' कैसे है ... (व्यवधान)

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में 2-3 अनिता हैं इसलिए कनफ्यूजन हो जाता है कभी-कभी ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय व्यवस्था का प्रश्न है। यह हमारा ज्ञान वर्द्धन करें तिवाड़ीजी। तिवाड़ीजी कह रहे हैं कि 'श्री' शब्द, श्री महिलाओं के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आप यह उद्‌बोधन में कहते हैं कि नाम पुकारते हैं श्री फलानां, श्री फलानां, तो इस पर अगर सदन का ज्ञान वर्द्धन तिवाड़ी जैसा विद्वान कर सकते तो बड़ी महती कृपा होगी आपकी।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें मालूम ही नहीं था कि हमारा जेंडर क्या है? आज पहली बार ज्ञान बढ़ा कि 'श्री' शब्द, इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, या तो इसका शुद्धिकरण कराओ या इसको आप ठीक कराओ। हम सारे महिला वर्ग में आ गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 'श्रीस्यते' 'श्री' लक्ष्मी का ही नाम है। 'श्रीस्यते, लक्ष्मीस्यते पत्न्या वहो रात्रे'।

श्री अध्यक्ष: कभी-कभी ज्ञान वृद्धि होनी चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तो 'श्री' शब्द और 'श्री यंत्र' जो कहते हैं तो वह लक्ष्मीजी का यंत्र है। तो मूल रूप से 'श्री' शब्द लक्ष्मी के लिए और 'श्री' शब्द महिलाओं के लिए ही है। अब हम यहां पर पुरुष महिलाओं से उत्पन्न हुए हैं, उनके कारण से हमारा सारा संचालन होता है और वह हमारी मां है लक्ष्मी, इसलिए 'श्री' शब्द का उपयोग पुरुषों के लिए हो जाता है। हम सब 'श्री' की ही देन हैं इसलिए 'श्री' शब्द स्त्रियों के लिए ही है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। अनीताजी। (व्यवधान)

नगर के गांवों की पेयजल समस्या का निवारण

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में नगर एवं तहसील डीग के क्रमश: 164 एवं 68 गांव हैं मगर वहां पीने के पानी की समस्या ने भयंकर रूप धारण कर रखा है। नगर में 33 क्षेत्रीय योजनाएं स्वीकृत हुई थीं मगर 2 या 3 को छोड़कर सब फेल हो गईं। वहां जनता प्यासी है, पाइप्ड योजना से नगर, सीकर व सुन्दरावली को जोड़ा है। नगर कस्बे व सीकरी में जरूरत के हिसाब का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। सुन्दरावली में एक भी कनेक्शन नहीं है। पम्प एवं टैंक से 9 गांव जुडे हुए हैं पर इस योजना ने भी दम तोड़ दिया, केवल पोखर के सहारे हैण्डपम्प ही केवल पीने के पानी का स्रोत है मगर खारे पानी की वजह से हर 6 माह या साल भर में हैण्डपम्प खराब हो जाते हैं। नगर विधान सभा क्षेत्र में 18 सिंगल फेस स्वीकृत हुए पर आज तक विद्युत कनेक्शन न होने की वजह से पीने का पानी मुहैया नहीं हो पाया और पुरानी जितनी सिंगल फेस थी उन पर बिजली का बिल बकाया चलने की वजह से कनेक्शन काट दिए जाने से जनता पीने के पानी से महरूम हो गई है।

अत: मेरा आपसे निवेदन है कि नगर विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव की क्षेत्रीय पाइप एण्ड टैंक योजना स्वीकृत की जाये जिससे वहां पीने का पानी मिल सके। क्षेत्र के 63 गांवों में आर ओ स्वीकृत हुए, उनमें से कुछ चल रहे हैं एवं कुछ अपूर्ण हैं। ठेकेदार द्वारा पानी डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था ठीक प्रकार से न करने की वजह से भी परेशानी उत्पन्न हो रही है। इसमें भी बदलाव की आवश्यकता है।

विधान सभा क्षेत्र नगर में समस्याग्रस्त गांवों की कई पेयजल योजनाओं के प्रस्ताव राष्ट्रीय पेयजल मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रस्तावित हैं मगर कोई स्वीकृति नहीं मिली। अब इन सब पीने की पानी की समस्याओं का निराकरण किया जाये ताकि जनता को शुद्ध पीने का पानी मिल सके।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानदेव आहूजा।

अलवर में कतिपय मार्गों पर बसों का संचालन

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूं कि अलवर जिले का अधिकांश क्षेत्र केन्द्र एवं राज्य की विशेष परियोजनाओं, विशिष्ट क्षेत्रों यथा मेवात, औद्योगिक कारीडोर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इत्यादि में सम्मिलित होने, राष्ट्रीय एवं राज्य की राजधानी के मध्य होने के बावजूद भी परिवहन एवं बस सुविधाओं से प्राथमिक स्तर पर वंचित है। अलवर जिले में खस्ता हाल परिवहन सेवा संचालित है।

मैं सदन का ध्यान इस बिन्दु पर लाना चाहूंगा कि अलवर शहर का बस अड्डा राज्य के सबसे बड़े बस अड्डों में से एक है। बस अड्डे हेतु उपलब्ध भूमि शहर के मध्य एवं मौके की भूमि है। अलवर जिले में इस बस अड्डे से तीन प्रमुख आगारों की बसों का संचालन किया जा रहा है। अलवर शहर के इस बस अड्डे पर सड़क ही नहीं है। बड़े-बड़े गड्ढे एवं जलाशय बने हुए हैं और गन्दगी का आलम पूरे बस अड्डे पर देखा जा सकता है। पूर्व में मेरे द्वारा अनेक बार इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को आग्रह किया गया है किन्तु वर्तमान तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों, ग्राम पंचायतों, यहां तक कि पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालयों पर ही बसों का संचालन भली-भांति नहीं किया जा रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के निवासियों द्वारा अनेक बार निम्नलिखित मार्गों पर बसों का संचालन तुरन्त प्रभाव से प्रारम्भ किये जाने हेतु आग्रह किया है:-

1. अलवर से रामगढ़-ललावण्डी-मिलकपुर-बरवाड़ा-मालपुर बस सेवा
2. अलवर से चारोटी-इस्तमुरार-खुटेटा-बढेर-मोजपुर-लक्ष्मणगढ़ बस सेवा
3. अलवर से बड़ौदामेव-गण्डूरा-लक्ष्मणगढ़ बस सेवा
4. अलवर से बड़ौदामेव-गोविन्दगढ़-सेदमपुर बस सेवा
5. अलवर से बड़ौदामेव-गोविन्दगढ़-दौगड़ी बस सेवा
6. अलवर से बड़ौदामेव-गोविन्दगढ़-सेमलाखुर्द
7. अलवर से बगड़तिराया-रामगढ़-रसगण बस सेवा
8. अलवर से बगड़तिराया-रामगढ़-नौगांवा-हाजीपुर-खोहर बस सेवा
9. अलवर से चिकानी-बहादुरपुर-दोहली-रामगढ़-अलवर बस सेवा
10. अलवर से बगड़तिराया-रामगढ़-छज्जूबास-खिलौरा-बान्धोली-गढीधनेता होकर नीकच व नाखनौल तक बस सेवा

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

11. रामगढ़ से ललावण्डी-बिलासपुर-सैथली-चावण्ड बस सेवा

अतः मैं सदन से आग्रह करता हूं कि उपरोक्तानुसार अलवर जिले में बेहतर परिवहन सेवा, बेहतर बस अड्डा एवं बेहतर बस सुविधाएं प्रदान करवाये जाने का श्रम करावें।

श्री अध्यक्ष: श्री रामचन्द्र।

भवानी मण्डी की राजस्थान टैक्सटाइल मिल्स के अव्यवहारिक कार्यों के सम्बन्ध में कार्यवाही

श्री रामचन्द्र (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डग के भवानी मण्डी शहर में राजस्थान टैक्सटाइल मिल्स, औद्योगिक इकाई स्थित है जिसमें कुछ विशेष प्रकार की खामियां एवं कमियां हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूं।

1. विधान सभा चुनाव एवं लोक सभा चुनाव वाले दिन मजदूरों को बंधुआ बनाकर, प्रलोभन देकर वोट डालने के संवैधानिक अधिकार से वंचित रखा क्योंकि विधान सभा चुनाव मैंने स्वयं ने लड़ा था, इसलिए कुछ विशेष नहीं कर पाये परन्तु लोक सभा चुनाव में यही गड़बड़ी पुनः दोहराई गई तब हमारे लोक सभा सदस्य श्रीमान् दुष्यंत सिंहजी से फोन पर वार्ता हुई क्योंकि वो स्वयं ही उम्मीदवार थे। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी से कार्यवाही के लिए कहा तो वहां कम से कम 3000 से अधिक मजदूर चुनाव वाले दिन कार्य करते पाये गये जिन्हें 3.30 या चार बजे के आसपास वहां से आजाद करवाया। यह तो आम नागरिक के संवैधानिक अधिकार का हनन है जिस पर चुनाव आयोग ने नोटिस देकर इतिश्री कर ली। वहां पर कार्यरत मजदूरों के बारे में वहां का मैनेजमेंट यह कहकर बचता हुआ नजर आया कि वे तो एमपी क्षेत्र के हैं। इस औद्योगिक इकाई की स्थापना में लिखा है कि हम स्थानीय लोगों को मजदूरी पर रखेंगे लेकिन वहां स्थानीय मजदूरों को प्राथमिकता न देकर बाहरी मजदूरों को प्राथमिकता दी जाती है, इससे हमारे क्षेत्र के लोगों की उपेक्षा होती है और स्थानीय लोग रोजगार के लिए मारे-मारे फिरते हैं, ऐसे स्थानीय लोगों को मजदूरी पर रखने की जिम्मेदारी हर इकाई की बनती है।

(श्री रामचन्द्र)

2. चूंकि इस इकाई में यार्न का उत्पादन होता है, यहां अनेकानेक प्रकार के घातक कैमिकल प्रयोग में लिये जाते हैं, जिनके अपशिष्ट को जिस नाले के द्वारा बहाया जाता है वह उस शहर की एक बड़ी पेयजल योजना में जाकर शामिल होता है इससे पानी के जीव जन्तु मर रहे हैं तथा झुण्ड के झुण्ड मछलियों को मरा हुआ पाया गया है। आने वाले समय में इस पानी से पेयजल की आपूर्ति होनी है जिससे शहर के लोगों को घातक बीमारियां होने की आशंका है।
3. इसी औद्योगिक इकाई में बिजली बनाने का जो संयंत्र है वह कोयला पर आधारित है। चूंकि यह इकाई शहर के मध्य है तथा इसकी दोनों कालोनियां इसी इकाई में स्थित हैं। पूरे शहर पर इसकी राख हवा में फैलती है और शहर का गला घोंटने का कार्य हो रहा है। इससे निकलने वाले घातक अपशिष्ट एवं राख से शहर में अनेकानेक घातक बीमारियों की दस्तक शुरू हो गई है। लिहाजा पर्यावरण विभाग ने किन नियमों का पालन करते हुए इसको इजाजत दी गई यह पता नहीं है लेकिन आधुनिक तकनीक से इसकी रोकथाम के उपाय करने के लिए इस इकाई को पाबन्द किया जाना चाहिए।
4. क्या यह सही है कि यह औद्योगिक इकाई धर्मादा निकालती है? निकालती है तो 1960 से लेकर अब तक कितना धर्मादा इकट्ठा हुआ, विवरण सहित सदन को बताएं कि शहर के विकास में इसका क्या योगदान रहा। अगर इनकी अनुपालना नहीं की गई तो इस मद में इनके खिलाफ एक निश्चित कार्यवाही की सरकार चेष्टा रखती है?
5. इस इकाई के पास इनकी एक कालोनी है जो नाले पर बसी हुई है। इनके द्वारा अतिक्रमण कर कालोनी से गुजर रहे नाले पर एक रोक सी लगा दी गई है जिससे भीम नगर बस्ती में आने का रास्ता बंद हो गया है और इससे इनकी कालोनी को भी हमेशा के लिए खतरा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार प्राकृतिक नदी नालों पर अतिक्रमण करने की इजाजत नहीं है। ऐसे में इस खामी के लिए इनके खिलाफ कार्यवाही जो की जाये, वह सदन में रखी जाये। मेरा अनुनय विनय है कि इस संस्था पर संवैधानिक कार्यवाही कर इसके द्वारा अनैतिक एवं अव्यवहारिक कार्य के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर शहरवासियों को स्वछंद एवं स्वच्छ वातावरण दिलाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

भीलवाड़ा में कपड़ा उद्योग व पालिस्टर फिलामेंट के वैट टैक्स में विसंगति

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत सूचना प्रस्तुत कर निवेदन है कि भीलवाड़ा जिले के कपड़ा उद्योग एवं टैक्सराइज यार्न (पोलिस्टर फिलामेंट) के वैट टैक्स में उत्पन्न विसंगति की ओर सदन का ध्यान विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाना चाहता हूं:-

1. टैक्सटाइल मिनिस्ट्री के अनुसार वर्ष 2010-11 में टैक्सराइज यार्न के 1549.80 मिलियन केजी. उत्पादन में राजस्थान का प्रतिशत बहुत कम है।
2. राजस्थान में वर्ष 2013-14 में 1.44 लाख मैट्रिक टन टैक्सराइज यार्न की खपत हुई है, जो कि ज्यादातर राजस्थान से बाहर दमन एवं दीव से आया है, जिसमें राजस्थान सरकार को कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता है क्योंकि उक्त यार्न राज्य के बाहर से जीरो प्रतिशत सीएसटी पर आता है और राजस्थान से 0.75 प्रतिशत सीएसटी पर राजस्थान से बाहर जाता है जबकि राजस्थान के वस्त्र निर्माताओं को राजस्थान से टैक्सराइजिंग यार्न खरीदने पर 5 प्रतिशत वैट देना पड़ता है।
3. अत: वैट को पोलिस्टर फिलामेंट (टैक्सराइज यार्न) पर 5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत का राज्य सरकार से प्रस्ताव करता हूं ताकि राजस्थान में उत्पादित यार्न राजस्थान में ही खप सके तथा टैक्सराइज इण्डस्ट्रीज बढ़कर निवेश, उत्पादन एवं रोजगार में इजाफा हो सके। यह उद्योग प्रदूषणमुक्त है।
4. राजस्थान वस्त्र उद्योग में 1728 करोड़ का सालाना टैक्सराइज यार्न की खपत है, जिसमें 5 प्रतिशत वैट होने के कारण राजस्थान का राजस्व नहीं के बराबर है।
5. पोलिस्टर फिलामेंट (टैक्सराइज यार्न) पर वैट 5 प्रतिशत से 1 प्रतिशत करने पर नये उद्योग तो विकसित होंगे ही और साथ ही कम से कम 20 करोड़ रुपये सालाना राजस्व में वृद्धि होगी एवं वर्तमान में स्थापित टैक्सराइजिंग उद्योग बंद होने से बच सकेंगे।
6. उक्त संदर्भ में भीलवाड़ा टैक्सटाइल ट्रेड फैडरेशन की ओर से पूर्व में राज्य सरकार को उच्च स्तर पर लिखित में प्रतिवेदन दिया जा चुका है।

(श्री विट्‌ठल शंकर अवस्थी)

अत: बजट घोषणा में माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा राजस्थान की आर्थिक विकास दर 12 प्रतिशत लाने का लक्ष्य अर्जित किया जा सके इसके लिए विशेष उल्लेख के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री नानालाल अहारी।

खैरवाड़ा के ऋषभदेव रैफरल हास्पिटल में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरा जाना

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के ऋषभदेव के आस पास कम से कम 30-40 हजार की आबादी का क्षेत्र है जहां पर आस पास करीब 15 ग्राम पंचायतों के मरीजों का आना-जाना होता है। ऋषभदेव में रैफरल हास्पिटल स्थित है, जहां पर करीब सभी चिकित्सक के पद हैं और क्षेत्र का सबसे बड़ा हास्पिटल ऋषभदेव है जहां पर सारे उपकरण व संसाधन सम्पन्न हास्पिटल ऋषभदेव है, मगर पूर्व सरकार ने वहां पर कोई ध्यान नहीं दिया और सभी पद रिक्त हैं। यहां के मरीज इलाज के लिए इधर-उधर तड़फते रहते हैं। उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें विवश होना पड़ता है और विवश होकर मरीज या तो गुजरात जाएंगे, गुजरात वहां से करीब 250 किलोमीटर पड़ता है, नहीं तो उसे उदयपुर जाना पड़ता है। यहां ऋषभदेव ग्राम पंचायतों को छोड़कर और सभी पंचायतों में एसटी व एससी के गरीब तबके के लोग निवास करते हैं जिन्हें बाहर जाने के कारण पर्याप्त सुविधा नहीं मिलने से मरीज अंत में दवाइयों से वंचित रह जाते हैं एवं ऋषभदेव के आस पास में जो भी बस्तियां या ग्राम पंचायतें हैं करीब सारी की सारी नेशनल हाइवे 8 पर स्थित हैं जहां आये दिन एक्सीडेंट होते रहे हैं, जहां पर मरीज को शीघ्र ही इलाज नहीं मिलने व कई मरीजों की उदयपुर ले जाते समय मृत्यु हो जाती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि ऋषभदेव रैफरल हास्पिटल में सारी व्यवस्था है, लेकिन डाक्टर्स के पद रिक्त रहने के कारण जनता को लाभ नहीं मिल पाता। यदि डाक्टर के पद भर जाएंगे तो लोगों को राहत मिलेगी। अतिशीघ्र रिक्त पदों को भरा जाय।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप लाल भील।

गोगुन्दा की पेयजल समस्या के समाधान हेतु प्रस्तावित योजनाओं की क्रियान्विति

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध हेतु विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। क्षेत्र की उत्तर पश्चिम दिशा का सारा पानी बनास नदी में तथा दक्षिण पूर्व दिशा का सारा पानी बहकर सेई, बाकल एवं साबरमती नदी में जाता है। उपरोक्त सभी तीनों नदियों का उद्गम स्थल गोगुन्दा से है।

गोगुन्दा क्षेत्र जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है जहां अधिकतम लोगों के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होने से पीने के पानी की समस्या रहती है एवं आदिवासी ग्रामीण जनता को पीने के लिए तीन से पांच किलोमीटर दूरी से पानी सिर पर रखकर लाना पड़ता है।

विगत कई वर्षों से पेयजल हेतु छह पेयजल योजनाएं प्रस्तावित की गई थीं:-

1. दमदमा पेयजल योजना	आर.एस. लागत	भराव क्षमता
2. सरी का नाका पेयजल योजना	800 लाख	25 एमसीएफटी
3. शोभावास पेयजल योजना	700 लाख	23 एमसीएफटी
4. जग्गा आम्बा पेयजल योजना	600 लाख	35 एमसीएफटी
5. बरू का नाका पेयजल योजना	700 लाख	23 एमसीएफटी
6. जरगाजी का नाका पेयजल योजना	1800 लाख	30 एमसीएफटी
7. भादजीगुडा तालाब पेयजल योजना	1500 लाख	20 एमसीएफटी

दमदमा एवं शोभावास दोनों पूर्व के स्टेट के समय के निर्मित तालाब हैं जो अतिवृष्टि में टूटकर क्षतिग्रस्त हो गये हैं जिनका पुनरुद्धार कर पेयजल हेतु उपयोग किया जा सकता है व क्षेत्र की जनता लाभान्वित हो सकती है। पूर्व में इन तालाबों से सिंचाई की जाती थी।

उक्त योजनाओं को उपादेय नहीं मानते हुए विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र के जलग्रहण क्षेत्र को अन्य परियोजना में पूर्व में सम्मिलित करने के उपयोगी

(श्री प्रताप लाल भील)

नहीं माना जाता है। कृपया निर्मित परियोजना से क्षेत्र की मांग के अनुरूप निर्णय करके छूट प्रदान कर इनको स्वीकृत किया जाये।

क्षेत्र की ग्रामीण जनता प्यासी रहे एवं उनका पानी अन्य क्षेत्र की प्यास बुझाने हेतु उपयोग में लिया जाता है तो इस क्षेत्र की ग्रामीण जनता के साथ भेदभाव दर्शाता है व इस क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय है।

इस क्षेत्र की ग्रामीण जनता की आवश्यकता की पूर्ति के अलावा शेष जल का उपयोग अन्य क्षेत्र हेतु किया जाता है तो इस क्षेत्र की जनता को कोई आपत्ति नहीं होगी। पूर्व में बड़ी पेयजल योजना बनाते समय इस क्षेत्र की मांग को क्यों ध्यान में नहीं रखा गया है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सोनादेवी।

रायसिंहनगर के चिकित्सालयों में चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ की कमी

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के राजकीय चिकित्सालय, रायसिंहनगर में काफी समय से अस्थि रोग व स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद रिक्त पड़े हैं। चिकित्सालय में सोनोग्राफी मशीन भी काफी समय से रेडियोलोजिस्ट के अभाव में बंद पड़ी है जिससे मरीजों को भारी पैसा चुकाकर निजी सोनोग्राफी सेंटरों से सोनोग्राफी जांच करानी पड़ रही है।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र सीमान्त क्षेत्र होने से पहले से ही कई समस्याओं का सामना स्थानीय जनता को करना पड़ रहा है। करीब चार वर्ष पूर्व इस चिकित्सालय में जननी सुरक्षा योजना के तहत भवन निर्माण कराया गया था, परन्तु स्टाफ की कमी के कारण क्षेत्र की जनता को इस योजना का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। तहसील क्षेत्र रायसिंहनगर में लगभग 408 गांव हैं, जहां कोई सरकारी सुविधा नहीं है। क्षेत्र के अन्य चिकित्सालयों में भी चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी है।

अत: प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं मांग करती हूं कि इन चिकित्सालयों में रिक्त चल रहे विभिन्न पदों को शीघ्र भरा जाय ताकि क्षेत्र की जनता को चिकित्सा का समुचित लाभ मिल सके।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश भंसाली।

जोधपुर शहर के कतिपय स्थानों पर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जोधपुर शहर में बढ़ती आबादी एवं बढ़ते व्यापार स्थल को मद्देनजर रखते हुए आमजन की सुविधा हेतु भीड़भाड़ वाले इलाके एवं व्यापारिक स्थलों के आस पास दूर-दूर तक सार्वजनिक शौचालयों का अभाव है जिस कारण आमजन एवं व्यापारियों को अपना व्यापार स्थल छोड़कर काफी दूर-दूर तक लघुशंका पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है या फिर शहर की खाली दीवारों, विद्युत पोलों के साथ अन्य स्थानों पर जगह-जगह पेशाब कर गंदगी फैलाने पर मजबूर हो रहे हैं जिससे शहर को साफ-सुथरा नहीं रख पाने के साथ सौन्दर्यता को भी बट्टा लग रहा है एवं बदबू के मारे बुरे हाल हो रहे हैं। जोधपुर शहर में निम्न स्थानों पर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। निम्न स्थल वे स्थान हैं जहां पर आमजन का आवागमन एवं जमावड़ा हमेशा लगा रहता है। अत: मैं चाहूंगा कि आप निम्न स्थलों पर या उसके आस पास जगह चिह्नित कर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण जनता की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए करवाएं ताकि जोधपुर स्वच्छ एवं सौन्दर्यता का प्रतीक बन सके।

1. रेलवे स्टेशन के आगे दो-दो के सैट महिला एवं पुरुष
2. ओलम्पिक गांधी स्कूल के पास
3. भैरू बाग़ के सामने
4. तारघर के पास
5. नेहरू पार्क के पीछे दुर्गाबाड़ी के सामने
6. सरदारपुरा सी रोड एवं द्वितीय रोड चौराहा
7. जलजोग चौराहा पुरुष/महिला शौचालय
8. मेडिकल कालेज के बाहर
9. मथुरादास माथुर अस्पताल के बाहर
10. आईटी चौराहा
11. महावीर सर्किल, शास्त्री नगर
12. रावण का चबूतरा बस स्टैण्ड के सामने पुरुष/महिला दो-दो

(श्री कैलाश भंसाली)

13. गांधी मैदान के बाहर भंसाल मैचिंग के सामने
14. गोल बिल्डिंग के पास प्लास्टिक का लगाया हुआ है, परन्तु कार्य में नहीं आ रहा है
15. जालौरी गेट जलते दीप के पास
16. शनिश्चरजी के थाने के पास
17. आसोपा चौराहा
18. उम्मेद अस्पताल के बाहर
19. उम्मेद अस्पताल काटेज वार्ड के बाहर
20. महात्मा गांधी अस्पताल के बाहर
21. जालौरी गेट दूध के चौहटे के पास
22. खाण्डाफलसा
23. जूनी मण्डी राम रसोड़ के बाहर पुरुष/महिला
24. राखी हाउस के पास
25. लखारा बाजार पुरुष/महिला
26. कटला बाजार
27. कन्दोई बाजार गिरदी कोट के बाहर पुरुष/महिला
28. गोरुन्दा बावड़ी पुरुष/महिला
29. नई सड़क शाही समोसा के पास
30. राजीव गांधी चौक नई सड़क पुरुष/महिला
31. मोहनपुरा चौराहा
32. सर्किट हाउस के सामने
33. भाटी चौराहा
34. सब्जी मण्डी रातानाडा
35. भास्कर चौराहा के पास
36. शिवमंदिर रातानाडा
37. देवनारायण मंदिर के पास भगत की कोठी
38. न्यू कैम्पास गेट के पास भगत की कोठी
39. मधुबन कालोनी बाजार क्षेत्र
40. रामेश्वर नगर बाजार क्षेत्र

(श्री कैलाश भंसाली)

41. महावीर उद्यान कलेक्ट्रेट के सामने

इन समस्त स्थलों पर राजकीय जमीन तथा संस्थान के पास जमीन उपलब्ध है तथा आवश्यकता होने पर जिला प्रशासन से भूमि उपलब्ध करवायी जा सकती है। स्थानीय लोगों का विरोध होने पर आपसी रजामंदी से स्थान चुना जा सकता है। इस हेतु मेरा सहयोग जहां भी चाहें हमेशा तत्पर रहूंगा।

श्री अध्यक्ष: डा. जसवंत सिंह यादव। आप आये, गये। पहले नाम बोला फिर नहीं थे। बोलिये, बोलिये। जसवंत सिंह यादव।

बहरोड़ के उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार की उपलब्धता

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैं कागज लेने गया था। अध्यक्षजी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के अन्तर्गत निवेदन है कि वर्तमान सरकार प्रदेश में उद्योगों को काफी बढ़ावा दे रही है लेकिन जो उद्योग हमारे बहरोड़ एवं नीमराणा तहसील में लगाये गये हैं चाहे वह जापानी जोन हो या कोई अन्य हों, उनमें स्थानीय युवाओं को नौकरी नहीं दी जाती है जबकि ये युवक उद्योगों में कार्य करने की योग्यता रखते हैं। बहरोड़ व नीमराणा तहसील के जिन गांवों की जमीन उद्योगों में ले ली गई है उन गांवों में बी.टेक., पालिटेक्निक डिप्लोमा, आई.टी.आई. किये हुए काफी नौजवान बेरोजगार हैं। इन गांवों की जमीनें भी उद्योगों के लिए अधिग्रहित कर ली गईं एवं स्थानीय नौजवानों को नौकरी भी नहीं देते जिससे बहरोड़ व नीमराणा तहसील के गांवों में युवा बेरोजगारों में भारी आक्रोश व्याप्त है व जन आंदोलन की तैयारियों में हैं। अत: उपरोक्त लोक महत्व के विषय को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री महोदय और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन उद्योगों में स्थानीय नौजवानों को नौकरी दी जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री भंवर सिंह।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

बीकानेर में विद्युत सम्बन्धी समस्याएं

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बीकानेर जिले में बिजली से सम्बन्धित कुछ समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो भारतीय

(श्री भंवरसिंह)

जनता पार्टी के घोषणा पत्र में 24 घंटे घरेलू बिजली देने की बात की गई थी और 8 घंटे कृषि कुओं पर बिजली देने की बात की गई थी।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर जिले में ग्रामीण क्षेत्र की यदि हम बात करें तो 12-13 घंटे से ज्यादा घरेलू बिजली नहीं रहती है। वहीं कृषि कुओं की बात करें तो अधिकतम चार घंटे बिजली रहती है और उसमें भी काफी ट्रिपिंग होती है। महोदय, ट्रिपिंग होने की वजह से किसानों की मोटरें जल जाती हैं और किसानों पर काफी आर्थिक भार भी आता है। इसलिए इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करके निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम जितनी भी बिजली दी जाए वो पूरी गुणवत्ता से दी जाए जिससे कि किसान 4 घंटे, 5 घंटे अपने कुओं को चला सके और मोटरों पर यदि सही वोल्टेज रहता है तो कम से कम उसको आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़े।

इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बीकानेर जिले के किसान ही नहीं, पूरे राजस्थान के किसान जो खेतों में रहते हैं, जिन्होंने वहां ट्यूबवैल बना लिया है तो उनका पूरा परिवार खेत में रहता है। महोदय, कृषि कुए बनने के बाद लोग गांव से पलायन करके खेतों में रहने लग गये हैं क्योंकि साल में दो फसलें होती हैं और वो सब खेती पर ही निर्भर हैं। उनका पूरा परिवार खेत में रहता है लेकिन उनको 4 घंटे या 6 घंटे जो भी थ्री फेस की बिजली मिलती है उसके बाद में बिजली की बड़ी समस्या हो जाती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज से पहले 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के दौरान बीकानेर सम्भाग में पिछले दिनों 19 से 30 जून तक सरकार का दौरा रहा था। राजस्थान सरकार के सभी मंत्री वहां पधारे थे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसी दौरान बिजली विभाग की सभी कम्पनियों के चेयरमैन आर. जी. गुप्ताजी वहां बीकानेर सम्भाग के कुछ गांवों में गये थे और उन्होंने दौरा करने के बाद एक आदेश निकाला। उस आदेश के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो किसानों को 4 घंटे, 5 घंटे थ्री फेस बिजली मिलने के बाद एक सिंगल फेस चालू रहता था जिससे किसान ट्यूबलाइट जला सके या पंखा चलाकर परिवार को वहां रख सके। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आर. जी. गुप्ता साहब ने एक ऐसा आदेश निकाला है जिसके तहत बीकानेर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के तमाम किसानों को सिंगल फेस का जीरो वोल्टेज की तरह एक फेस दिया जाता था जिससे किसानों के बच्चे वहां रात में पढ़ाई कर सकते थे या पंखा चलाकर रह सकते थे। लेकिन जो इन्होंने एक आदेश निकाला है उस

(श्री भंवरसिंह)

आदेश की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 7.7.2014 को आर.जी. गुप्ताजी ने एक आदेश निकाला है कि The agricultural consumers are reported to be using air conditioner on their houses built near their wells and they are using agricultural connections for running the domestic load. इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसान अपने कृषि कुओं पर रहते हुए एयर कंडीशनर का प्रयोग करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही हैरानी की बात है कि इतने बड़े जिम्मेदार पद पर बैठे हुए अधिकारी यह कहे कि किसान खेतों में एयर कंडीशनर का उपयोग करता है, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की बात कहना राजस्थान के आम किसानों का अपमान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान अपने खेत में खेती करेगा, खेत का काम करेगा या वो ए.सी. चलाकर उसमें आराम करेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन रहेगा कि जब तक इन ट्यूबवैल पर रहने वाले किसानों को कनेक्शन देने की कोई योजना सरकार नहीं बनाती है तब तक केवल सिंगल फेस की एक लाइन चालू रखें जिससे किसान का परिवार एक पंखा चला सके, एक लाइट चला सके।

इसके अलावा मैं सुराज संकल्प पत्र 2013 के पेज नम्बर 7 की क्रम संख्या 4 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें यह लिखा है, पिछले वर्ष हमारी भारतीय जनता पार्टी के सुराज संकल्प पत्र में कि इस वर्ष 2013 में कांग्रेस सरकार ने बूंद-बूंद सिंचाई योजना के लिए प्रार्थना पत्र यह कहकर आमंत्रित किये कि तीन माह में विद्युत कनेक्शन रिलीज कर दिये जायेंगे। इन कनेक्शनों को प्रदान करने के लिए ढाई से तीन लाख रुपये जमा कराये गये हैं और कनेक्शन लेने के बाद उन्हें दो माह में 24 हजार रुपये के बिल का चुकारा करना पड़ता है जो साधारण कनेक्शन की रेट से तीन गुना से भी अधिक है। भाजपा घोषणा करती है कि बूंद-बूंद सिंचाई योजना में इस वर्ष 2013 तक रिलीज किये गये सभी कनेक्शनों को साधारण कृषि कनेक्शन ही माना जाएगा। महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की इस घोषणा के बारे में बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि 2013 तक के जो बूंद-बूंद सिंचाई योजना के कनेक्शन थे जिनमें यह माना गया था कि किसानों से बूंद-बूंद सिंचाई योजना में सामान्य कनेक्शन के बदले तीन गुना ज्यादा पैसा लिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: रेस्पोंड करेंगे, आप विराज जाइये। ऊर्जा मंत्रीजी रेस्पोंड करेंगे?

श्री भंवरसिंह (कोलायत): इसके अलावा मैं 2-3 बातें और कहना चाहूंगा। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने बजट 2014 में 3 लाख 11 हजार कृषि कनेक्शन देने की घोषणा की है जो निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य घोषणा है लेकिन साथ में बूंद-बूंद सिंचाई योजना से कनेक्शन देने की भी बात की गई है। महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार यह स्पष्ट करे कि 3 लाख 11 हजार कनेक्शनों में से 2013 तक के जो लम्बित कनेक्शन हैं उनमें से कितने सामान्य श्रेणी के कनेक्शन देंगे और कितने बूंद-बूंद सिंचाई योजना के तहत कनेक्शन देंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में बूंद-बूंद सिंचाई योजना को बन्द करने की और उसको सामान्य योजना में तब्दील करने की बात की गई है, इस सम्बन्ध में भी मैं आपके माध्यम से सदन में जानकारी लेना चाहूंगा।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ष 2008 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युतीकरण योजना गांवों में, ढाणियों में, रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए शुरू की गई थी। उसके तहत 6 के समूह में किसानों ने लाखों की संख्या में आवेदन किये थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि उसमें से काफी हद तक 6 के ग्रुप के कनेक्शन कर दिये गये हैं लेकिन आज 6-7 साल बीत जाने के बावजूद भी

(12.00 बजे)

आज भी काफी ऐसे समूह हैं, काफी ऐसे किसान हैं, जिन्होंने 2008 में ''मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युतीकरण योजना'' में आवेदन किया था लेकिन आज तक उन किसानों को गांव में रहने वाले, ढाणियों में रहने वाले किसानों को कोई कनेक्शन नहीं दिये गये...

श्री अध्यक्ष: अब जवाब आ जायेगा, आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): दो मिनट का समय और लेना चाहूंगा। वर्ष 2011-12 में पांच के समूह में कांग्रेस की सरकार ने भी ''मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युतीकरण योजना'' चालू की थी। उसमें भी बीकानेर सम्भाग में डेढ़ लाख से ज्यादा किसानों ने कनेक्शन के लिए, ढाणियों में रहने वाले किसानों ने कनेक्शन के लिए आवेदन कर रखा है। मेरा निवेदन रहेगा कि पिछले सात-आठ महीनों से इस योजना को बिलकुल ठप कर दिया गया है। इसमें न तो

(श्री भंवरसिंह)

डिमांड नोटिस निकाले जा रहे हैं, न इस योजना में आगे कोई आवेदन लेने की कार्यवाही की जा रही है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि पांच के समूह में ''मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युतीकरण योजना'' में अब जितने भी पैंडिंग आवेदन हैं, कम से कम उन आवेदनों के डिमांड नोटिस निकाले जायें और उनकी एक प्रायोरिटी बनाकर उन्हें कनेक्शन देने की कार्यवाही की जाये।

इसके अलावा एक-दो बातों की ओर मैं और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: बहुत ध्यान आकर्षित कर दिया। बहुत कर दिया, बहुत है। अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): एक एलटी कनेक्शन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। किसी किसान के पास 50 बीघा जमीन है, एक कनेक्शन ले लिया है और एक साल के बाद में उसी खेत में 50 के ट्रांसफार्मर को 100 के ट्रांसफार्मर में तब्दील करके एलटी कनेक्शन होता है, वह सैकण्ड कनेक्शन माना जाता है उसी किसान का, तो उस पर भी सरकार ने अघोषित रोक लगा रखी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर सम्भाग में ऐसे हजारों मामले हैं कि किसानों ने अपने ट्यूबवैल खुदवा लिये हैं, 10-10 लाख, 7-7 लाख, 8-8 लाख रुपये खर्च कर दिये, किसान कर्जे के बोझ के तले दब गये। हालांकि बूंद-बूंद योजना इन्होंने चालू की थी और इसमें किसानों को कनेक्शन दिये हैं लेकिन एलटी कनेक्शन के तहत भी जिन किसानों ने अभी जून तक कुए खुदवा लिये हैं, उन्हें एलटी कनेक्शन देने की छूट प्रदान की जाये।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। आप रेस्पोंड करेंगे?

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्युत विभाग की करीबन इन्होंने पूरी हिस्ट्री मांग ली है, 12 विषय पर बोले हैं ये। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा, आप मेरे चैम्बर में पधारें, आपको बढ़िया काफी पिलाऊंगा और आपके सब सवालों के अच्छी तरह से जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से माननीय सदस्य खड़े हुए हैं। माननीय सदस्य आपकी अनुमति से खड़े हुए हैं और मंत्रीजी ऐसे कह रहे हैं कि चैम्बर में आ जाना, काफी पिलाऊंगा। 12 विषय पर कैसे बोले। (व्यवधान) यह विशेषाधिकार है अध्यक्ष महोदय। यह हमारे सदस्य का विशेषाधिकार है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आप बैठिये। (व्यवधान) अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ×××

श्री अध्यक्ष: लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य नये हैं। उन्हें परम्परा मालूम नहीं है। मंत्री महोदय किसी को सैटिस्फेक्शन के लिए अपने चैम्बर में बुला सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। (व्यवधान) आप बैठिये, आप बैठिये। हो गया आपका।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ×××

श्री अध्यक्ष: बैठिये। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ×××

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) श्री अमरा रामजी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। देखिये, मैं आपको नाम लेकर पुकारूंगा। बार-बार आप खड़े हो रहे हैं। नहीं, आपके स्प्रिंग लगी है कि क्या बात है। बैठिये। इधर का इनका अंकित मत कीजिये। क्या मतलब है यह। नहीं, आप भी बैठिये। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बोल चुके हैं। आप बैठिये। आप बैठिये, बोल चुके हैं। नहीं, बिलकुल नहीं। अब अमरा रामजी बोलेंगे। अमरा रामजी के अलावा किसी का भी अंकित नहीं होगा। श्री अमरा रामजी। (व्यवधान) इनको कंट्रोल करो आप। कैसा सचेतक बनाया है, जैसे स्प्रिंग लगी हो। क्या बात कर रहे हैं। (व्यवधान) बैठ जाइये। नहीं, बैठ जाइये। खतम कर चुके। नहीं, बार-बार नहीं दूंगा इजाजत। बैठिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, गुस्सा नहीं आया। मुझे हाउस को चलाना है। हर बार, हर एक मिनट में ही कोई खड़ा हो जाये, यह कोई व्यवस्था है क्या? आप इनको कंट्रोल कीजिये, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। ये बार-बार जिस तरह खड़े हो रहे हैं। श्री अमरा रामजी।

इन्दिरा गांधी नहर में पंजाब एवं हरियाणा से आ रहा प्रदूषित एवं जहरीला पानी

श्री अमराराम (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार का इस पर्ची के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी नहर में पंजाब से, हरियाणा से हमारे व्यास और सतलज की नदियों में प्रदूषित पानी ही नहीं, अशुद्ध पानी भी नहीं, बल्कि जहरीला पानी डाल रहे हैं जिसके कारण यह सतलज और व्यास का पानी हरिके बांध के अन्दर आ रहा है। ऐसा जहरीला पानी, यहां तक कि चमड़ा उद्योग का पानी भी हमारे इस बांध में आ रहा है और उससे हमारी इन्दिरा गांधी नहर...

श्री अध्यक्ष: आपसी चर्चा नहीं करें। माननीय घनश्यामजी, आपसी चर्चा नहीं करें। इधर देखिये।

श्री अमराराम (पचपदरा): ... का पानी अशुद्ध, प्रदूषित और यहां तक कि जहरीला हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन्दिरा गांधी नहर से बाड़मेर तक पानी आता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय बैठिये। यह कोई बोलने की बात है क्या? मैंने टोक दिया और आप यहां आ गये, बस बात खतम।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, मैं आ गया। मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया पर इतनी ईर्ष्या ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: ईर्ष्या। (व्यवधान)

श्री अमराराम (पचपदरा): यह इन्दिरा गांधी नहर जो हमारी जीवनदायिनी है और इसका पानी बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर, बालोतरा तक आता है। जो पानी हमारे यहां आ रहा है, वह बहुत ही जहरीला पानी आ रहा है और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस भयंकर रूप से प्रदूषित पानी से कैंसर, हेपेटाइटिस, पीलिया और डायरिया जैसी गम्भीर बीमारियां फैलने का खतरा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार पर और जो भी इसमें प्रदूषित पानी डाल रहे हैं, जहरीला पानी डाल रहे हैं, उनको पाबंद किया जाये, उनको बाध्य किया जाये कि यह पानी नहीं डालें।

(श्री अमराराम)

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, इसमें हमारे राजकोष की भारी रकम है, इस पानी के लिए हरिके बांध में मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है, उसमें राजस्थान का कोई भी सेक्रेटरी या सदस्य नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पैसा जब हम दे रहे हैं और उसकी देखरेख के लिए मैनेजमेंट में हमारा कोई सदस्य नहीं, हमारा कोई सेक्रेटरी नहीं, आज इस प्रकार का दूषित और जहरीला पानी हमारे बांध में आता है और वह नहर हमारे यहां आती है, जिससे लोगों में बहुत ही गम्भीर बीमारियां हो रही हैं। मैं आपसे अध्यक्ष महोदय के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी जीवनदायिनी नहर में ऐसा पानी नहीं आये और कोई बीमारियां नहीं फैलें। इसके लिए मैनेजमेंट कमेटी के अन्दर हमारा आदमी होना बहुत जरूरी है। हम अपना हिस्सा देते हैं। उसके बावजूद भी हमारी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। इसलिए सरकार से विशेष तौर से निवेदन है कि हमारे मैनेजमेंट के अन्दर हमारा सदस्य मुकर्रर करें, हमारा कोई सेक्रेटरी मुकर्रर करें ताकि यह देखभाल कर सके और हमारी केन्द्र सरकार को भी आप निवेदन करें कि यह जो पंजाब, हरियाणा का पानी है, वह गंदा पानी, अशुद्ध पानी, जहरीला पानी, प्रदूषित पानी अन्दर नहीं आये क्योंकि यह हमारे जीवन-मरण का सवाल है। जल ही है तो जीवन है और शुद्ध जल नहीं है तो कोई जीवन ही नहीं है। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक गम्भीर मसला उठाया है। यह सही है अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में जालंधर के पास से सीवरेज और ड्रेनेज का पानी डाला जा रहा है और यह भी सही है कि इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी चिंतित भी हैं और उन्होंने पंजाब के मुख्य मंत्री को पत्र भी लिखा है, बात भी की है। और यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में कुछ रिट याचिकाएं विभिन्न न्यायालयों में भी चल रही हैं और अध्यक्ष महोदय, यह भी सही है कि पंजाब री-आर्गेनाइजेशन एक्ट बना था। उसमें बीबीएमबी में राजस्थान का प्रतिनिधि हो, यह उसके अन्दर तय किया गया था।

श्री अध्यक्ष: प्रावधान है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): परन्तु लम्बा समय बीत जाने के बाद भी आज तक बीबीएमबी में राजस्थान का प्रतिनिधि नहीं है। परन्तु हम लोगों का पहले शुरू से ही यह फैसला रहा है और जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब-तब कोशिश हुई है। हम इसके लिए भी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कोशिश करेंगे और आपकी भावना के माध्यम से मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा इसलिए पहले भी माननीय मुख्य मंत्रीजी जब प्रतिपक्ष में थीं तो एक अध्ययन दल बना था। जिसके अन्दर हमारे गुरजंट सिंहजी सहित सभी लोग गए थे। उसमें भी हमने पंजाब सरकार को लिखा था, अब दुबारा लिखेंगे और कोशिश करेंगे। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, छह ज़िले इस कैनाल से पानी पीते हैं और यह भी सही है कि कई प्रकार बीमारियां भी इससे पैदा हो रही हैं। इसलिए आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सरकार इसमें गम्भीर है और दुबारा लिखेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अमृता मेघवाल।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, सांवरमलजी का....

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

केसावणा ग्राम (जालौर) स्थित कृषि अनुसंधान केन्द्र की मान्यता

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र जालौर के उपखण्ड ग्राम केसावणा में स्थित कृषि अनुसंधान केन्द्र है। जोधपुर सम्भाग में 700 बीघा जमीन पर पर्याप्त मात्रा में भवन भी बना हुआ है, वहां पढ़ाने के लिए वैज्ञानिक, डाक्टर, स्टाफ भी पर्याप्त संख्या में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरा क्षेत्र कृषि क्षेत्र है और कृषि अनुसंधान केन्द्र को अगर आप मान्यता दें तो पूरे जोधपुर सम्भाग में एक सरकारी केन्द्र होगा यह। मैं यह कहना चाहती हूं कि अगर इसको मान्यता देंगे तो राज्य सरकार पर किसी प्रकार का वित्तीय भार भी नहीं होगा। क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में सभी प्रकार की चीज़ें उपलब्ध हैं और मैं आशा करती हूं कि इस अनुसंधान केन्द्र को मान्यता मिलेगी। अगर इसको मान्यता मिलेगी तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में एक नई उपलब्धि होगी। इस मामले में मैं माननीय मंत्री महोदय से जवाब मांगना चाहती हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोतम कुमार।

बड़ी सादड़ी क्षेत्र में स्थित जाखम बांध के अधिशेष पानी से पेयजल उपलब्ध कराना

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में जाखम बांध स्थित है। उसका पानी सिंचाई के काम में भी आता है और सिंचाई के बाद कुछ पानी इसमें अधिशेष रह जाता है जिसका समुचित उपयोग नहीं हो रहा है और आस पास के जो गांव हैं, वो पानी से वंचित रह रहे हैं। मेरा माननीय मंत्री से आग्रह है कि यदि इस अधिशेष पानी को नया सर्वे करवाकर के कुछ गांवों में तो वह पानी जा रहा है। अगर कहीं एक किलोमीटर, कहीं दो किलोमीटर उन पाइप लाइनों को और बढ़ा दें तो उस क्षेत्र में जो पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं और पानी पड़ा हुआ है, जो काम नहीं आ रहा है, अधिशेष है। उन गांवों में जो मई, जून में और अप्रैल में दो-दो किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाते हैं और उनके फिर भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि नए गांवों का सर्वे करवाकर के मंत्रीजी इसमें नए गांवों को जुड़वायें जिससे पानी की समस्या से जूझ रहे गांवों को निजात मिल सके। मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। मंत्रीजी को मैं कम्पेल नहीं कर सकता। वो चाहे तो रेंस्पोण्ड करें, नहीं चाहे तो नहीं करें, कम्पेल नहीं किया जा सकता है।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13

1- मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 1962 की धारा-39 के अन्तर्गत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013.

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14

2- महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर अधिनियम, 1987 की धारा-38 (4) के अन्तर्गत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014.

(श्री कालीचरण सराफ)

कोटा विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14

3- कोटा विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2003 की धारा-43 के अन्तर्गत कोटा विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 एवं 2013-2014.

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2013-14

4- राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 1999 की धारा-25 (2) के अन्तर्गत राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014.

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। अनीताजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, न श्री है और न श्रीमती कुछ तो अध्यक्ष महोदय, श्रीमुख से फरमायें। ना श्री है, ना श्रीमती कुछ तो हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सिर्फ यही व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय जब प्रतिवेदन रखें तो उसको पढ़कर आना जरूरी है कि नहीं उनके लिए।

श्री अध्यक्ष: यह तो अपेक्षित है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अपेक्षित है ना। तो इसमें कुछ जो मूलभूत बातें हैं उन पर अगर आप ध्यान डाल सकें तो....

श्री अध्यक्ष: अभी नहीं, बाद में डालेंगे। मैंने अनिजी बोलकर के सुश्री, श्रीमती इस झगड़े को ही मेरी तरफ से मेट दिया है। इसलिए मैंने अनीताजी को पुकारा है।

याचिका

श्रीमती अनीता (नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करती हूं:-

नगर (भरतपुर) नगरपालिका में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना

(1) नगरपालिका नगर (भरतपुर) में राजकीय महाविद्यालय खुलवाने बाबत।

(श्रीमती अनीता)

बृज चौरासी कोस के परिक्रमा मार्ग में यात्रियों के लिए सुविधाएं

(2) बृज चौरासी कोस के परिक्रमा मार्ग में यात्रियों के लिये जन सुविधाएं उपलब्ध कराने बाबत।

नगर कस्बे व गांवों में चम्बल योजना का पानी पहुंचाना

(3) कस्बा नगर व गांवों में चम्बल योजना का पानी पहुंचाने बाबत।

श्री अध्यक्ष: डा. मंजू बाघमार।

डा. मंजू बाघमार (जायल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में उल्लेख किए गए अनुसार निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करती हूं:-

जायल तहसील की ग्राम पंचायत रोटू से ग्राम घाटीयाद सड़क का डामरीकरण

(1) ग्राम पंचायत रोटू से ग्राम घाटीयाद, तहसील-जायल, जिला नागौर का डामरीकरण करने बाबत।

जायल तहसील के ग्राम रोटू से टौकी धौरा तक सड़क का डामरीकरण

(2) ग्राम पंचायत रोटू, तहसील-जायल, जिला नागौर के ग्राम रोटू से टौकी धौरा तक डामरीकरण करने बाबत ।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

सीयाणा (तहसील जालौर) को उप तहसील बनाना

(1) तहसील जालौर के सीयाणा को उप तहसील बनाने बाबत ।

रामा से घुम्दड़ा माताजी तक सड़क निर्माण

(2) रामा से घुम्दड़ा माताजी तक सड़क के निर्माण बाबत।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीर सिंह भायल।

जालौर चौराहे से रामदेव मंदिर पुराना बाजार तक सड़क निर्माण

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार जालौर चौराहे से रामदेव मंदिर पुराना बाजार तक खस्ता हाल सड़क के निर्माण करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र में कतिपय स्थानों पर सड़क निर्माण

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में कतिपय स्थानों पर ग्राम पसून्दा से तासोल, आत्मा से तलाई, मोरचना के नाल से मुण्डोल एवं राज्यावास से ओड़ा सड़क निर्माण बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

व्यवस्था

अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण आय व्ययक अनुमान वर्ष 2014-2015 की अनुदान मांगें 19 और 21 पर चर्चा प्रारम्भ करेंगे। उसके पहले अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पर आपका ध्यान आकर्षित करुंगा और व्यवस्था देना चाहूंगा।

अनुदान की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस सदन की परम्परा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव जिस दिन की मांग आती है, जो प्रस्तुत होते हैं, वे यह मान लिए जाते हैं कि सदन में पेश हो गए हैं और बोलने के लिए उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाजत दी जाती है जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय द्वारा आसन को प्रस्तुत किए जाते हैं। विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय बोलने के लिए प्राथमिकता उन्हीं माननीय सदस्यों को दें जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं, ऐसा मेरा अनुरोध है। जब मांग मतदान के लिए आती है उस समय भी स्वत: यह मान

(श्री अध्यक्ष)

लिया जाता है कि वे कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किए गए हैं, वे वापस ले लिए गए हैं, यह परम्परा इस सदन की रही है। जिन माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाये, वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ ही उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें, वे भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गए प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिए जाएंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके, उनके लिखित उत्तर सम्बन्धित माननीय सदस्यों को सरकार की ओर से मिल जायें, ऐसा मेरा निवेदन है।

मैं इसके साथ एक निवेदन और करना चाहता हूं। हम बहस लम्बी करें, ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य बोलें, यह तो हमारी सबकी इच्छा है लेकिन एक समय-सीमा निर्धारित होनी चाहिए जब कि मंत्रीजी अपना उत्तर दें क्योंकि बहुत रात को 11-12 बजे तक बैठेंगे, 6-7 बजे के बाद आने वाले माननीय सदस्य बोलते हैं उनका कई तरह से प्रकाशन नहीं होता, प्रचार नहीं मिलता और मंत्रीजी का भाषण दब सा जाता है जबकि मंत्रीजी के भाषण से ही हमारे इस सदन में व्यक्त किये गये माननीय सदस्यों के विचार भी प्रेस में जाने चाहिए, उनका प्रसार भी होना चाहिए और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अभी हमारे पास सवा छह घंटे के करीब हैं और इन सवा छह घंटे में आप अपना जितने भी बोल सकें नाम भी आये हैं। दोनों सचेतक महोदयों से विनम्र प्रार्थना करता हूं, दोनों नेताओं से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि वे अपने वक्ताओं को, स्वयं ही अपना कम से कम समय लें बोलने, तो आज की तारीख में सात बजे मंत्रीजी का उत्तर होगा और सात बजे तक जो बोल सकें वो बोल सकें उसके बाद जो रह जाएंगे उसके बारे में मेरे से कोई शिकायत नहीं करेंगे और न मैं सात बजे के बाद किसी को बोलने की इजाजत दूंगा। यह मैं एक रूलिंग देता हूं। मंत्रीजी सात बजे अपना जवाब देंगे और अब अनुदान की मांगों पर विचार चालू करेंगे। सबसे पहले आप रखिये मांग, मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था रह गयी इसमें। कटौती प्रस्ताव पर आपने व्यवस्था दे दी लेकिन कोई माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव पर अगर मतदान करना चाहे तो उसके लिए आपकी क्या व्यवस्था है?

श्री अध्यक्ष: मेरा ऐसा मानना है कि कोई मांग करेगा नहीं। कोई करेगा नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वो तो ठीक है पर करा सकते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): रास्ता सुझा रहे हैं। मेरे कटौती प्रस्ताव के ऊपर डिवीजन कराने का रास्ता सुझा रहे हैं तिवाड़ीजी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल आपकी रूलिंग बात-बात में आ रही है कि मैंने कह दिया कि सात बजे मंत्रीजी का जवाब होगा यह मेरी रूलिंग है। आप कहते मेरा ऐसा निर्देश है कि सात बजे आ जाए।

श्री अध्यक्ष: रूलिंग का शब्द वापस लेता हूं। मान लिया आपकी बात को। आप वरिष्ठ हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ना-ना, आप मेरी बात सुनिये।

श्री अध्यक्ष: आप वरिष्ठ सदस्य हैं और आपके सुझाव को मानने में मुझे कोई एतराज नहीं है। रूलिंग नहीं यह मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि सात बजे तक...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, आजकल आप एक तो अंकित नहीं होगा, यह मेरी रूलिंग है। देखिये ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है श्रीमान्।

श्री अध्यक्ष: नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): सात बजे के बाद ऐसे-ऐसे मौके आये हैं जब सात बजे ...

श्री अध्यक्ष: मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप शायद लोक सभा में नहीं गये। लोक सभा में बहस खतम होने का, मंत्री का जवाब आने का फिक्स टाइम है और उस टाइम पर हो जाता है बिलकुल। जवाब भी हो जाता है और फिक्स टाइम के हिसाब से बहस भी समाप्त हो जाती है। चाहे कम रहे या ज्यादा रहे इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं मैं लोक सभा में तीन बार सदस्य रहा हूं और उस समय बहस भी खतम करनी पड़ती है अधूरी रह जाए तो भी। जिस समय वोटिंग होना है होगा, जिस समय मंत्री का भाषण होना है होगा और इसलिए मैं विनम्र निवेदन करता हूं, रूलिंग नहीं कि सात बजे हम सब मंत्रीजी का भाषण सुनने के लिए तत्पर रहें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं, हम भी उत्सुक हैं लेकिन मेरा आपसे निवेदन है श्रीमान्। मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि सदन के अन्दर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

डिमाण्ड्स के ऊपर चर्चा आप उठा कर देख लें। मैं 1967 में पहली दफा विधान सभा में आया था। रात को बारह-बारह, एक-एक बजे तक चली है। (व्यवधान) मेरी बात सुन लें प्लीज। ज्ञानदेवजी, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं मैं आपके लंग पावर को मैच नहीं कर सकता हूं। आप सुन लें मेरी बात। मेरा आपसे निवेदन है कि इतना आपका एक निर्देश है इसकी पालना करने की चेष्टा की जाएगी अगर आधा एक घंटा बढ़ता है मैंबर्स को एकमोडेट करने के लिए, एक साल में एक मौका पीडब्ल्यूडी के ऊपर लोगों को बोलने का मिलेगा तो कृपया इतना हार्ड एंड फास्ट आप रूल न बनायें, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखें। यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे। आपकी बात मान ली।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है और उस सम्बन्ध में राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो निवेदन किया है मैं भी उसमें आपके रुख में और समय दिये जाने में कुछ लचीलेपन का निवेदन करता हूं। आखिर तो यह लोकतंत्र है और इसमें बात कहने की आजादी न हो और खास तौर पर एक विधायक को न हो। कृपया इस बात की सुरक्षा कर लें कि विधायक बोल भी जाएं और मंत्रीजी का जवाब भी ठीक टाइम पर हो जाए। सात बजे की बजाय यदि आठ बजे भी हो तो आठ बजे ऐसी कोई देरी नहीं है कि आठ बजे मंत्रीजी के जवाब में कोई नहीं रहेगा। मेरा एक निवेदन यह है मुझे बड़े दुख के साथ आपको अर्ज करना पड़ता है कि कल जब माननीय मुख्य मंत्रीजी का भाषण होना था उस वक्त सारी दर्शक दीर्घा खाली करा ली गई थी पांच बजे। माननीय अध्यक्ष महोदय, दर्शक दीर्घा में दो बजे जो लोग आते हैं वो कल जो आये वो निश्चित रूप से उसमें आधे तो मुख्य मंत्री को सुनने ही आये। मेरा निवेदन है कि दो से पांच के बाद में जो आपके गार्डस के द्वारा दर्शकों को बाहर निकाल दिया जाता है यदि सदन की कार्यवाही चलती है तो दो बजे जो आते हैं उनको निश्चित रूप से सुनने का अवसर दिया ही जाना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि आज से ही इस व्यवस्था में कृपा करके कुछ मूलभूत परिवर्तन करा दें और मंत्रीजी का जवाब आठ बजे आए, सात बजे आए तो दर्शक दीर्घा वाले भी यदि सुनना चाहें, रहना चाहें तो उनको यह आजादी दी जाए कि वो सुन सकें और उससे लोकतंत्र में जनमत भी जागृत होगा और सूचनाएं भी अधिक से अधिक लोगों को उपलब्ध होंगी। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: सुझाव आपका उत्तम है अच्छा है इस पर गम्भीरता से विचार किया जाए। माननीय युनुस खानजी।

सूचना

राजस्थान से अमरनाथ यात्रा पर गये यात्रियों की सुरक्षा

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। कल बालटाल में राजस्थान से गये अमरनाथ यात्रा के लिए, 28 तारीख से अमरनाथ यात्रा चल रही है, वर्षों से चल रही है। शाम को अचानक कल सूचना आई कि अजमेर से गये हुए सौ अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ है। राजस्थान के यात्री हैं अजमेर के हैं और मैंने तुरन्त माननीय सी.एम. साहब के पी.ए. साहब को भी सूचना करवाई, हाउस में भी और रेजीडेंस पर भी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनमें से लगभग तीस-पैंतीस लोग इंजर्ड हैं और आठ-दस गम्भीर हैं। उनके बारे में केन्द्र सरकार ने भी लिया है लेकिन राजस्थान सरकार को राजस्थान के चूंकि अमरनाथ यात्री हैं और सौ के लगभग गये हुए हैं उनको और संरक्षण देकर के जैसे इराक के यात्रियों को लाया गया, लाया जाए। वहां एक समुदाय विशेष के कुछ गुंडा तत्व, अराजक तत्व हैं उनका भी क्या इलाज करें वो तो केन्द्र सरकार करेगी। मुख्य मंत्री, जम्मू कश्मीर से भी बात की गई है लेकिन राजस्थान के जो यात्री गये हुए हैं उनको संरक्षण, संवर्धन देकर के लाया जाए। यह मेरी सूचना है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, दो मिनट, मैं इसी के साथ में कहना चाहती हूं। पैंतालीस लोग मेरे विधान सभा क्षेत्र के हैं उसमें जो फंसे हैं। मेरे पास भी आज सुबह समाचार आया है। पैंतालीस लोग जिनको मैं खुद हरी झंडी दिखा करके आयी थी यहां विधान सभा में वो लोग भी फंसे हैं तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उनको बचाने की किसी तरह की कोशिश की जाए और वो सुरक्षित रूप से अजमेर पहुंच जाएं। मेरा यह निवेदन है। (व्यवधान) पैंतालीस लोग हैं अजमेर के।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अजमेर के कार्यकर्ता श्री तुलसी सोनी ने सूचना दी है अधिकृत रूप से।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र से भी साठ-सत्तर लोग हैं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, उसमें ब्यावर से भी हैं अजमेर जिले से जो गये हैं वो सकुशल वापस पहुंचे, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): कल पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के माध्यम से मैंने आपको सूचना देना चाहा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान से गये हुए सभी लोगों की रक्षा करने का दायित्व है तो मेरा निवेदन है अजमेर से सम्बन्धित था इसलिए मैंने निवेदन किया। मेरे विधान सभा क्षेत्र के ही पैंतालीस लोग हैं उसमें।

श्री अध्यक्ष: इसीलिए मैंने आपको अलाउ किया है, विराजिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्षजी, मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटा के काफी लोग कम से कम साठ-सत्तर लोग वहां पर गये हुए हैं। लगातार कल बारह बजे से उन लोगों का फोन हम लोगों के पास आया। मैंने पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के माध्यम से कल भी आपको सूचना देना चाहा लेकिन हो सकता है कि आपका ध्यान उस ओर नहीं गया। मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि हम जितनी सहायता उनकी कर सकते हैं उतनी सहायता उनकी करवाने का प्रयास करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): वहां के कैम्पों पर भी हमला किया गया है ऐसा दुबारा से न हो रिपीटेशन, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की भावना का सम्मान करते हुए आज सदन समाप्त होने से पहले जो भी रिपोर्ट मैं कलेक्ट कर सकता हूं वो कलेक्ट करके इस सदन को जानकारी के रूप में दूंगा।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य की प्रस्तुति

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 19, लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,09,25,93,000/- (अठारह अरब नौ करोड़ पच्चीस लाख तिरानवे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(कटौती प्रस्ताव के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

अध्यक्ष महोदय, दूसरी भी साथ ही बोल दूं?

श्री अध्यक्ष: दूसरी भी साथ ही बोल दीजिये।

मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल की प्रस्तुति

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-21, सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 50,02,64,31,000/- (पचास अरब दो करोड़ चौंसठ लाख इकत्तीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(कटौती प्रस्ताव के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अध्यक्ष: आज की बहस का प्रारम्भ श्री रमेशजी करेंगे, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह अपना वक्तव्य प्रारम्भ करें।

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पीडब्ल्यूडी पर चर्चा होने जा रही है तो इस सन्दर्भ में सबसे पहले मैं मेरे विचार से पहले मेरे क्षेत्र की मांग रखना चाहता हूं। हमारी सदन की नेता माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मंडरायल के पास चम्बल नदी पर पुल बनाने की घोषणा भरतपुर सम्भाग में की थी और उसके रिप्लाई में इन्होंने कहा कि हमने एनओसी के लिए सीडब्ल्यूसी भारत सरकार को भेज दिया गया है लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय बताना चाहता हूं कि न तो आपने बजट में पैसा दिया, न कोई जानकारी दी। पिछले वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था किस प्रकार किश्तों पर बीओटी सिस्टम पर यह पुल बनाएगी। हमारी सरकार का इसमें क्या योगदान है, सिर्फ एनओसी देंगे। अच्छा होता कि इस पुल को राजस्थान सरकार बनाती तो अच्छा रहता। इसमें रिप्लाई में माननीय मंत्री महोदय मुझे बताएं कि राजस्थान सरकार का इसमें क्या पार्ट रहेगा, केवल एनओसी देंगे, मध्य प्रदेश सरकार बीओटी सिस्टम पर इस पुल को बनाएगी।

दूसरा मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा की मुख्य सड़कें उडगाम बाया सपोटरा, नारोई डांग सपोटरा टू कैलादेवी, ग्राम पंचायत मुख्यालय रहर को मेन रोड से जोड़ा जाए। करणपुर मंडरायल पर विश्राम गृह यह मेरी चार-पांच मांगे हैं। सपोटरा में भी विश्राम गृह बने।

(12.33 बजे)

(श्री प्रद्युम्न सिंह, सभापति, पदासीन)

(श्री रमेश)

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में घोषणा की थी कि पीपीपी माडल पर 20 हजार सड़कें बनेंगी और सम्भागवाइज जो टैण्डर होंगे जिसमें इंटरनल विलेजेज की रोड्स होंगी, अदर्स काम भी होंगे, 5 हजार किलोमीटर की, तो मैं कहना चाहूंगा कि पीपीपी माडल पर जो सड़क बनेगी, मेरा सुझाव है, इसमें यह नहीं है कि पीपीपी माडल पर आप क्यों बना रहे हैं, पीपीपी माडल पर आप निश्चित रूप से सड़कें बनाएं लेकिन बनाने से पहले आप कम्पनी से एमयूओ करेंगे या आपका कान्ट्रैक्ट साइन एग्रीमेंट होगा, उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि आप किसी कम्पनी को काम देने जा रहे हैं, वही कम्पनी या कान्ट्रैक्टर इस सम्भाग का होगा या पीपीपी माडल पर होगा? वहां के छोटे-छोटे ठेकेदार हैं या पहले ही वहां काम करते थे...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में बात न करें प्लीज। मुख्य सचेतकजी, प्लीज, डिस्टर्ब न करें प्लीज। अपना स्थान ग्रहण करें। हां कन्टीन्यू करें।

श्री रमेश (सपोटरा): सभापति महोदय मेरा निवेदन है कि पीपीपी माडल पर जो सड़कें आप बनाने जा रहे हैं उसमें कहीं ऐसा न हो कि छोटे-छोटे ठेकेदार जो गुणवत्ता और क्वालिटी को खराब करते हैं, वही लोग काम करने आ जाएं और इस पीपीपी माडल का भार जनता को सहना पड़े तो इसमें यह विशेष चीज का ध्यान रखा जाए। जहां पर पीपीपी माडल पर सड़के बनाई जाएंगी, मान लीजिए खनन एरिया है या ओवरलोड जहां वाहन चलते हैं, रेती का खनन होता है वहां विशेष रूप से सर्वे करवाया जाए। ग्रामों में उन सड़कों को चिह्नित किया जाए जहां ज्यादा भार है। रोजाना खबर आती है, टोंक जिले की ओवरलोड ने यह स्थिति कर दी सड़कें थी, सड़कें दिखाई ही नहीं देती हैं कि सड़क भी है, कच्चा रास्ता बन गया। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से इस बारे में कहना चाहूंगा कि आप एक्सल रोड सर्वे करवाएं। उन रोड्स को चिह्नित करवाएं। वहां पर आप पीपीपी माडल पर देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से दें लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा संदेह है, आज ही अख़बार में आया था भारत सरकार का कि पीपीपी माडल के बजाए गवर्नमेंट पैसा देगी। पीपीपी माडल आए, अपनी डिजाइन दें और काम करें, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हम पीपीपी माडल के आधार पर वेट करते रहे और राजस्थान को सड़कें नहीं मिले तो इस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है।

(श्री रमेश)

तीसरा बिंदु मेरा यह है कि पीपीपी माडल पर आप जो सड़क बनवाने जा रहे हैं, इस पर ज्यादा से ज्यादा आप टोल लगाएंगे, लोगों के लिए, किसानों के लिए, जनता के लिए एक अतिरिक्त भार हो जाएगा, इसमें भी मिनिमाइज या सरकार उसमें अनुदान दे सकती है तो वहां की जनता को ज्यादा भार नहीं लगे। तीसरी बात मेरी यह है कि इस बजट घोषणा में 9 हजार ग्राम पंचायत में हाफ किलोमीटर से टू किलोमीटर तक सड़कें गौरव पथ के नाम से बनाई जाएंगी। आपका गौरव पथ में स्वागत है लेकिन राजस्थान 9177, मैं पांच-दस की नहीं कह सकता, पंचायत हैडक्वाटर पर, सभी पर पहले से ही सीसी रोड बन चुकी है चाहे पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बनी है या अन्य किसी योजना के माध्यम से बनी है, नरेगा के माध्यम से बनी है, बीआरजेएफ के माध्यम से बनी है, डांग विकास बोर्ड के माध्यम से बनी है, या ग्राम पंचायत की किसी एसएफसी और टीएफसी हैड के माध्यम से, सभी गांवों में ड्रेनेज और रोड की बात की है तो वह बन चुकी है। आप उन पर दोहरी तीहरी परत चढ़ाकर जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि हमने सीसी सड़क बना दी, ड्रेनेज बना दिया, सफाई व्यवस्था अच्छी हो गई तो इससे जनता पर ही भार पड़ेगा। आज आपकी सरकार की स्थिति है, वित्तीय प्रबंधन की बात चल रही है, हम पहले ही घाटे में चल रहे हैं। अभी आपका दो महीने का आया है, सीएजी की रिपोर्ट है अप्रैल और मई की उसमें आपका 1155 करोड़ का राजस्व घाटा और आप बात कर रहे हैं कि हम यह करेंगे, वह करेंगे। मेरा निवेदन है कि यदि आपको सड़कें ही बनानी हैं तो सड़क उस जगह बनाएं जो हमारा राजस्व गांव का पार्ट, ढाणी और मजरे हैं और राजस्व गांव का पार्ट होने की वजह से उनकी लम्बाई किलोमीटर में है वह दो से तीन किलोमीटर दूर है, सड़क से नहीं जुड पाते हैं। उन्होंने ऐसा कौनसा अपराध किया है, उनको भी सुविधा मिलनी चाहिए। जो 100 से 300 तक आबादी की ढाणियां हैं, जो सड़क से नहीं जुड पाई हैं तो वहां आप गौरव पथ के माध्यम से यह सड़क बनवाएं, तो उनको भी लगेगा कि इस सदन में आने वाले लोगों ने हमारे हितों की रक्षा की है, इस प्रकार का मेरा यह सुझाव है।

इसके अलावा मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, जो विभाग के द्वारा बीएसआर बनाई गई है, शिडयूल है, बीएसआर में रेट तय हैं कि यह काम इतने पैसे में, इतने रुपये में होगा एक किलोमीटर पर। जब टैण्डर डालते हैं तो 10 परसेंट बिलो, 20 परसेंट बिलो, काम निकल जाता है और इंजीनियर जो

(श्री रमेश)

एल वन होता है उसको सैंक्शन कर देता है। उसी दिन से यह तय हो जाता है कि इंजीनियर और कान्ट्रैक्टर में यह कम्प्रोमाइज हो गया और क्वालिटी के साथ समझौता हो जाता है। इन सड़कों के लिए हम वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, अन्य व्यवस्थाएं करते हैं तो उसकी टैन ईयर्स की ऐज मानकर हम जो काम कर रहे हैं और वह पांच साल नहीं चल पाती है। माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि इस संदर्भ में एक ऐसा कड़ा रूख अपनाया जाए जिससे क्वालिटी में कम्प्रोमाइज नहीं हो, गुणवत्तापूर्वक सड़क बने, जो भी जिम्मेदार चाहे कान्ट्रैक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और कान्ट्रैक्टर के मन में यह भाव पैदा हो जाए कि अब काम करना पड़ेगा नहीं तो मुझे बख्शा नहीं जाएगा, तो यह मेरा निवेदन है। नहीं तो जो आपका सिस्टम पुराना चल रहा है, कितनी ही सड़क बना दो, कितनी ही घोषणा कर दो वही दो-तीन महीनें में आपकी सड़कें टूट जाती हैं।

एक बात और, आज जमाना वैसे राइट टू इन्फार्मेशन का है, कोई भी सड़क बनती है, कोई भी वर्क होता है, जो जिज्ञासु लोग होते हैं वे राइट टू इन्फार्मेशन के माध्यम से, जैसे रूल, कितने का वर्क अलाट हुआ? कैसे काम होगा? वह सारी जानकारी तो उन लोगों को मिल जाती है लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि जहां पर जो भी वर्क आप अलाट करें और उस साइट पर उस बोर्ड में यह लिखवा दें कि इस सड़क पर, इतने किलोमीटर की आप लिखवाते ही हैं, इतनी अनुमानित लागत होगी लेकिन उसमें साफ-साफ यह भी लिखवा दें कि यदि डामर की सड़कें हैं तो इसमें एग्रीगेट क्लियर डब्ल्यू.बी.एम. और डामर जो भी लगेगा या अर्थ वर्क कितना होगा और उसका कोई प्रोटेक्शन वाल है तो किस रेश्यो में काम होगा। आम जनता को पता होना चाहिए कि जो ठेकेदार यहां पर काम करने आया है वह किस रेश्यो में काम कर रहा है। सीमेंट सही लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? सीमेंट भी लगा देता है लेकिन समय पर तराई नहीं करने की वजह से, क्योरिंग नहीं करने की वजह से वह सारा बना हुआ प्रोटक्शन-वाल अगर तराई नहीं करोगे तो खराब हो जाता है।

तो मेरा निवेदन है कि स्पेसिफिकेशन जो-जो शिड्यूल में दिया है वह बोर्ड पर शार्ट मात्रा में चिह्नित होना चाहिए।

कुछ चीजें ऐसी हैं कि सबसे ज्यादा गड़बड़ कहां पर होती है? बिटुमन का लेयर होता है पेवर की, उसमें थिकनैस कम कर दी तो निश्चित रूप से

(श्री रमेश)

एक बड़ा घोटाला हो जाता है तो इस पर विभाग के द्वारा जो बिटुमन का वर्क है उसकी सी.आर.सी. मथुरा रिफाइनरी से या बाम्बे से, जहां से भी आती है उसका इंजीनियर के माध्यम से भौतिक सत्यापन करवाएं कि वास्तव में डामर आया है या नहीं आया है? यदि, नहीं आया है तो उसका भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि, इस बारे में मैं माननीय सभापति महोदय, बताना चाहूंगा कि मेरे करौली जिले में सड़कें बिलकुल खतम हो चुकी हैं और हमारे माननीय सहकारिता मंत्री भी मेरे क्षेत्र में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में इन्होंने देखा है कि सेंड का, बजरी का ओवर-लोड चलने की वजह से एक भी रोड साबुत नहीं है। तो जहां रोड पर ज्यादा लोड है वहां पर थिकनैस बढ़ाएंगे तो कोस्ट भी ज्यादा आएगी, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ठेकेदार सही मात्रा में, सही क्वालिटी में गुणवत्तापूर्वक काम करें ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी नीति बनायें। नहीं तो यह कम्प्रोमाइज इंजीनियर और ठेकेदार के बीच में होता रहेगा और आप पैसा देते रहेंगे और पैसे का साइफन होता रहेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखिएगा।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, जो मेंटिनेंस का वर्क है उसमें भी पेचेज का जो काम होता है वह भी अनड्यूलेशन में कर दिया जाता है। ऊपर नीचे कर दिया जाता है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जो हमारी रोड्स हैं, आज सवाई माधोपुर से कोटा ले लें, मेगा हाई-वे है। कितनी बदतर स्थिति उसकी है? आप टोल वसूल रहे हैं। कोटा से जयपुर की बात कर लें। हमारे महवा से करौली की बात कर लें। आप टोल वसूल रहे हैं और उन रोड्स पर जो सुविधाएं टोल की होनी चाहिए कि जैसे मेडिकल की व्यवस्था हो, दुर्घटना हो जाए तो पानी की व्यवस्था हो, अन्य नोर्म्स के अनुसार जो टोल पर व्यवस्था होनी चाहिए वह टोल पर व्यवस्था नहीं हो पा रही है और जहां पर अभी सड़कें पूरी नहीं हैं, आपके ओवर-ब्रिज नहीं बने हैं, सड़क पूरी नहीं बनी है उन पर आप टोल वसूली रुकवाएं, यह मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आखरी बात कह दें आप।

श्री रमेश (सपोटरा): सड़कें हम कांट्रैक्टर के माध्यम से बनवाते हैं। मैं एक निवेदन मंत्री महोदय से करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि हमारे विभाग में जे.ईएन. से लेकर चीफ इंजीनियर तक बैठा हुआ है और सबका काम है उसका सुपरविजन करना। मेरा सुझाव यह है कि

(श्री रमेश)

सम्भाग लेवल पर एक इंजीनियर जिनके पास लेबोरेटरी है, क्वालिटी कंट्रोल है, सारी व्यवस्था है तो हर सम्भाग पर इनको भी 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की रोड दे दी जाए और विभागीय स्तर पर यह रोड बनायें और उसके बाद जो कांट्रैक्टर रोड बनाता है तो दोनों का हम कम्पेरिजन करें, तुलनात्मक विश्लेषण करें कि कौन-सी रोड बैटर है? इससे पता लग जाएगा कि हमारी क्वालिटी के साथ समझौता हो रहा है या नहीं हो रहा है। खराब सड़कें बन रही हैं इस बी.एस.आर. पर या नहीं बन रही हैं?

तीसरी मेरी बात है कि इस विभाग में पहले थ्री-टायर सिस्टम था। जे.ईएन., एईएन. और एक्स ईएन., जो काम करता था। अब टू-टायर सिस्टम हो गया है। ए.ईएन. जो एम.बी. भरता है, मेजरमेंट बुक, वह थोड़ा सा ऐसा महसूस करता है कि मैं बड़ा आफिसर बन गया और उसको थोड़ी सी शर्म सी आती है। जो साइट पर काम चलते हैं उनकी पूरी तरह से देखभाल नहीं हो पाती। देखभाल नहीं हो पाती तो जो ऐसे इम्पोर्टेंट वर्क रहते हैं। कंक्रीट वर्क है या कोई ऐसा ब्रिज का वर्क, कोई ऐसे अति इम्पोर्टेंट वर्क होते हैं उनमें साइट पर इंजीनियर रहना चाहिए लेकिन वह साइट पर इंजीनियर नहीं रहता है।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री रमेश (सपोटरा): मेरा निवेदन लास्ट में यह है कि इतनी बड़ी फौज हमारे पास है। जे.ईएन. से लेकर चीफ इंजीनियर तक बैठे हुए हैं और एक सुपरविजन का काम करते हैं और एक ठेकेदार है उसके पास भी एक इंजीनियर रहता है। वह एम.बी. भी भरता है, सारे काम करता है। यह सिर्फ सुपरविजन चैक करते हैं। तो इतना बड़ा अमला हमारे पास है। उसके बावजूद भी बड़े शर्म की बात है कि हमारी क्वालिटी घटिया है। रोड समय से पहले टूट जाती है। मेंटिनेंस के नाम पर फार्मेलिटी की जाती है तो मैं यह कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से कि इसमें एक ऐसी व्यवस्था दें जो क्वालिटी में सुधार हो, रोड अच्छी बने और मैंने जो मेरे क्षेत्र के चम्बल ब्रिज का जो रखा है उस बारे में मुझे उत्तर दें। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय भवानी सिंहजी राजावत।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से मांग संख्या-19 और 21 पर सदन में अपनी बात रखना चाहूंगा।

(श्री भवानी सिंह राजावत)

माननीय सभापति महोदय, सड़क और पुलिया की ऐसी महत्वपूर्ण मांग है जो हमारे विकास की रीढ़ तो है ही, जन-जीवन का अभिन्न अंग भी है। सड़कें हमारी जीवन रेखाएं हैं और सड़कों का प्रदेश में बिछा हुआ जाल शरीर में धमनियों की तरह प्रदेश के विकास को गति देता है।

माननीय सभापति महोदय, सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य अभी अपनी बात रख रखे थे और कई सड़कों के खड्डों की बात कह रहे थे। लेकिन, हम देखें आजादी के बाद अब तक के काल को तो लगभग 45-50 साल सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य की पार्टी ने राजस्थान में राज किया और इसलिए सड़कों का इतिहास राजस्थान का कोई अच्छा नहीं रहा। लम्बे इस कार्यकाल में, 40-50 साल के कार्यकाल में 50-50 किलोमीटर तक लोगों को पैदल दूरी तय करनी पड़ी। लोग बैल-गाड़ी में, ऊंट-गाड़ी में, ऊंट पर बैठकर एक जगह से दूसरे जगह पर जाते थे। आज तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं और इस मांग पर चर्चा करते हुए अगर आत्मचिंतन करते हैं तो आत्मा रोती है कि आखिर राजस्थान की जनता ने क्या गुनाह किया था कि 40-50 साल तक सड़कों के अभाव में राजस्थान की जनता को पीड़ा भोगनी पड़ी। मोहनलालजी सुखाड़िया से लेकर बरकतुल्ला खांजी, हरिदेवजी जोशी, शिवचरणजी माथुर लगातार राजस्थान के मुख्य मंत्री रहे लेकिन माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के मुख्य मंत्री सड़कों के मामले में धृतराष्ट्र बने रहे और इसीलिए आज 20-20 हजार किलोमीटर सड़कें बनाने का निर्णय लेना पड़ रहा है। पड़ौसी प्रांत हरियाणा और पंजाब में जब प्रताप सिंहजी वहां के मुख्य मंत्री बने थे तो 35 साल पहले हरियाणा और पंजाब का एक-एक गांव सड़कों से जुड़ गया। आज हमें सड़कों की लम्बी दूरी तय करनी पड़ रही है। इसलिये, माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस को सड़कों के मामले में कुछ कहने का अधिकार नहीं है। इस राजस्थान को पतन के गर्त में डाला। सड़कों के मामले में राजस्थान को पूरे हिन्दुस्तान में पिछड़ा कर दिया। हां, सड़कों के मामले में राजस्थान का सुनहरा काल आया तो 1977 में आया। जब शेरे राजस्थान स्व. भैरोंसिंहजी शेखावत राजस्थान के मुख्य मंत्री बने। भैरोंसिंहजी शेखावत राजस्थान के छोटे से खाचरियावास गांव में पैदा हुए। उन्होंने गांवों की दुर्दशा देखी। उन्होंने देखा कि 50-50 किलोमीटर तक गांवों में आवागमन के साधन नहीं हैं। लोगों को ऊंटों से, बैलगाडियों से अपना सफर तय करना पड़ रहा है और इसीलिये उनके मन में पीड़ा थी, दर्द था। जब

(श्री भवानी सिंह राजावत)

मुख्य मंत्री बने और मुख्य मंत्री बनने के बाद उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिया कि राजस्थान का हर पंचायत हैड क्वार्टर सड़कों से जोड़ा जायेगा। यह पहला कदम था आजादी के बाद, जब भैरोंसिंहजी शेखावत राजस्थान के मुख्य मंत्री बने। जब पंचायत हैड क्वार्टर जुड़े तो बीच के गांव सड़कों से जुड़ते चले गये। राजस्थान में सड़कों का जाल बिछने लगा और यही नहीं काम के बदले अनाज योजना में भैरोंसिंहजी शेखावत ने ग्रेफल सड़कें बनाना भी शुरू कीं। राजस्थान में सुनहरा काल शुरू हुआ।

माननीय सभापति महोदय, हमने इतिहास में पढ़ा कि शेरशाह सूरी ने अपने कार्यकाल में सड़कों का निर्माण करवाया, सड़कों के जाल बिछाये। लेकिन जब देश के करोड़ लोगों के हृदय सम्राट अटल बिहारी वाजपेयीजी देश के प्रधान मंत्री बने, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस हिन्दुस्तान की धरती पर विदेशों की तरह सिक्स लेन बनेगी, फोर लेन बनेंगी। स्वर्ण चतुर्भुज योजना बनेगी। पूरे हिन्दुस्तान को एक सूत्र में बांध दिया जायेगा। शेरशाह सूरी को अटल बिहारी वाजपेयीजी ने बहुत पीछे छोड़ दिया। सड़कों का जाल बिछने लगा। गांव के लोग देखकर चकित हो गये। देश और दुनिया के लोग हिन्दुस्तान की धरती पर वाजपेयीजी की योजना को देखने लगे। चकित हो गये।

मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आप भी कर सकते थे। पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव जी गांधी से लेकर, नरसिम्हाराव तक देश के बहुत सारे प्रधान मंत्री आपकी पार्टी के बने। वह नहीं कर सकते थे क्या? हिन्दुस्तान की तकदीर और तस्वीर नहीं बदल सकते थे क्या? लेकिन कांग्रेस ने कभी सोचा नहीं। गांव, गरीब और किसान की काया पलट हो और सड़कों का जाल बिछ जाये। हिन्दुस्तान तरक्की के रास्ते पर जाये, हिन्दुस्तान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता हुआ सफलता के शिखर पर चढ़ जाये। यह कांग्रेस की सोच नहीं है।

अब मैं कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की लोकप्रिय जन-नायिका आदरणीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी राजे जब 2003 में मुख्य मंत्री बनीं, उन्होंने उठाकर देखा पी.डब्ल्यू.डी. का इतिहास, उससे पहले पांच साल तक अशोकजी गहलोत ने जब राज किया, कितने किलोमीटर सड़कें बनीं? केवल 6 हजार किलोमीटर। वसुन्धराजी ने आते ही प्राथमिकता तय की, कि सड़कें जीवन रेखा हैं, सड़कें विकास का रास्ता है और इसलिये वसुन्धराजी

(श्री भवानी सिंह राजावत)

ने अपने कार्यकाल में 26 हजार किलोमीटर सड़कें इस राजस्थान में मुख्य मंत्री, पहली वसुन्धरा राजेजी थीं, जिन्होंने 26 हजार किलोमीटर सड़कें बनायीं।

माननीय सभापति महोदय, सार्वजिनक निर्माण मंत्री उस समय राजेन्द्रजी राठौड़ का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा। माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी ने कहा था, आप वरिष्ठ हैं, पुराने हैं, आपको सबको जानकारी है इतिहास की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। तरक्की का रास्ता गांवों की चौपाल, खेत और खलिहानों से निकलता है। महात्मा गांधी का सपना कांग्रेस साकार नहीं कर पायी आजादी के बाद से। महात्मा गांधी का सपना राजस्थान की धरती पर अगर किसी ने साकार किया, तो राजस्थान की लोकप्रिय जन-नायिक यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी ने साकार किया।

अभी बजट में वसुन्धराजी ने जो निर्णय लिया, ढाई किलोमीटर सड़क, कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा राजस्थान का, जिसमें सी.सी. रोड नहीं हो, जिसमें नालियां नहीं हो, हम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ गांव की सूरत शहर में बदलना चाहते हैं और इसीलिये यह निर्णय लिया है। चकित हो गये पूरे राजस्थान के लोग। पूर्व मुख्य मंत्री यहां पर बैठे थे आदरणीय गहलोत साहब, मूक-दर्शक बने रहे। बोलते, धन्यवाद देते कि 20 हजार किलोमीटर सड़क बनाने का निर्णय, यह राजस्थान का इतिहास बनेगा, तकदीर और तस्वीर राजस्थान की बदल देगी। यह कोई साधारण निर्णय नहीं है। जब 20 हजार किलोमीटर सड़कें बन जायेंगी राजस्थान में 70 हजार करोड़ रुपये खर्च करके, तो लोग देखने आयेंगे राजस्थान को और देश के दूसरे प्रान्तों के लोग उसका अनुकरण करेंगे, प्रेरणा लेंगे कि हम भी ऐसी सड़कें बनायें।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं आज प्रतिपक्ष चाहे आलोचना कर ले, लेकिन वह औपचारिकता से आलोचना कर रहे हैं। आज कृतज्ञ हैं, आज आभारी हैं, आज सदन का एक-एक सदस्य अभिभूत है कि राजस्थान में पहली बार सड़क क्रान्ति आई है। वसुन्धरा राजेजी ने सड़क क्रान्ति का सूत्रपात किया है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य से यह पूछो कहां है वह क्रान्ति? एक किलोमीटर सड़क इन

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)
सात महीनों में आपकी सरकार ने बनाई हो तो बता दो। एक किलोमीटर का नाम बता दो।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): आप चश्मे के नम्बर बदल लो और देखो कि राजस्थान में पहली बार सड़कें किसने बनाई हैं।

श्री सभापति: कृपया व्यवधान पैदा नहीं करें।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहूंगा और माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि पी.पी.पी., बी.ओ.टी. हम फार्मूला लायें। यह बहुत अच्छा है। यह विकास को गति देगा। लेकिन मैं यह आग्रह करना चाहूंगा और सुझाव देना चाहूंगा। अभी मेरे पास मेरे कोटा डिवीजन के लोग आये। मेरे यहां 4 हजार करोड़ रुपये का एक टैण्डर लगा हाड़ौती का। हाड़ौती की काया बदल जायेगी, लेकिन मैं यह चाहूंगा कि जब छोटे ठेकेदार हैं, उनको भी काम दें। 4 हजार करोड़ का जो काम हो रहा है, वहां बड़ी कम्पनियां आयेंगी, गुणवत्ता का काम करेंगी, लेकिन छोटे ठेकेदारों के सामने कहीं भूखे मरने की नौबत नहीं आ जाये। उनकी आजीविका सार्वजनिक निर्माण विभाग के इन निर्माण के कामों पर निर्भर है। इसलिये उनका ध्यान रखा जाये।

अब मैं माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ बातें दो मिनट में आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप दो मिनट में कर दीजिये।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय सभापति महोदय, जयपुर में बाइपास है, उदयपुर में बाइपास है, जोधपुर में बाइपास है, अजमेर में बाइपास है। चम्बल नदी होने के कारण कोटा में बाइपास नहीं बनता। हैंगिंग ब्रिज टूट गया। 40-50 लोग मर गये और इसलिये हैंगिंग ब्रिज में अभी भी चार साल का टाइम लगेगा। कोटा में नोर्दन बाइपास, जिसकी आधारशिला भारतीय जनता पार्टी के राज में रखी थी और पिछली सरकार में कोटा का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय मंत्री शांति धारीवाल साहब ने उसको गति देने का प्रयास किया था। उनकी जिस तरह की सोच थी, मैं आलोचना नहीं करना चाहता, बहुत अच्छी थी। लेकिन अब वह नोर्दन बाइपास, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, उसका काम अटका हुआ है, लगभग 150 करोड़ की योजना है। अगर चम्बल के डाउन-स्ट्रीम में वह नोर्दन बाइपास बन जाता है, चम्बल पर पुलिया बन जाती है छोटी, तो कोटा का 50 प्रतिशत से ज्यादा

(श्री भवानी सिंह राजावत)

ट्रैफिक सड़क से डाइवर्ट हो जायेगा। आज 10 हजार लोग दुर्घटना में मरते हैं। उसमें लगभग 3 हजार कोटा के लोग मौत के घाट उतरते हैं, दुर्घटना में।

मैं माननीय सभापति महोदय, कुछ बातें हैं मेरे क्षेत्र की, कैथून बाइ-पास के निर्माण कार्य की, कृषि उपज मण्डी की सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। सभी सड़कें टूटी हुई हैं, उनके लिये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उनको प्राथमिकता से लें। ठेकड़ा से एन.एच. 27 बाइ-पास की सी.सी. रोड का निर्माण कार्य। कैथून से आर एम सी के किलोमीटर 2 पर ऊंची पुलिया का निर्माण कार्य, कोटा जिले की सी ए डी की सड़कों की स्थिति खराब है। सी ए डी की सभी सड़कें, अगर सार्वजिनक निर्माण विभाग ले लेता है तो कोटा की जनता के साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। मिसिंग लिंक की कुछ सड़कें हैं।

इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, मैं अन्त में निवेदन करना चाहता हूं कोटा में काली जमीन है, उपजाऊ जमीन है और बरसात में काली मिट्टी सड़क पर आती है। हर साल करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। सड़कों का नवीनीकरण होता है, लेकिन वह करोड़ों रुपया पानी में बह जाता है। सड़कें काली मिट्टी होने के कारण टूट जाती हैं इसलिये कोटा सम्भाग के लिये यह कन्सेप्ट लिया जाये। माननीय मंत्री महोदय, कोटा सम्भाग में सी.सी. रोड ही बने ताकि खजाने का करोड़ों-अरबों रुपया बरबाद नहीं हो।

(13.00 बजे)

अंत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा में लगभग 20 नदियां हैं जो बरसात में उफान पर आती हैं, पुलियाएं बनीं लेकिन पुलियाओं की बहुत कमी है। लोग पानी में बह जाते हैं इसलिए आने वाले समय में, माननीय मंत्री महोदय, सर्वे करायें कि किस-किस नदी पर कहां-कहां पुल की आवश्यकता है, वहां पुल बनें। गेता और माखिदा पुलिया का भारतीय जनता पार्टी के राज में शिलान्यास हुआ था लेकिन कांग्रेस के पांच साल के राज में राजनीतिक दुर्भावना से उसको रोक दिया, कोटा और बूंदी को जोड़ने वाली गेता माखिदा पुलिया का भी निर्माण करवाया जाए।

यही निवेदन करता हुआ, माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री सभापति: धन्यवाद। राजकुमारी दियाकुमारी।

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सवाई माधोपुर विधान सभा क्षेत्र के गांव मकसूदनपुरा में राजकीय माध्यमिक विद्यालय के जर्जर भवन के बारे में माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूंगी।

महोदय, यह विद्यालय ग्राम पंचायत, मकसूदनपुरा में है और यहां 208 विद्यार्थी पढ़ते हैं। इस विद्यालय की बिल्डिंग बिलकुल जर्जर अवस्था में है, यहां तक कि इसमें प्रवेश भी नहीं कर सकते। बच्चे भवन के बाहर जो मैदान हैं वहां अपनी पढ़ाई करते हैं तो बच्चे पढ़ने भी नहीं जाते। ना टीचर्स आते हैं, ना बच्चे आते हैं और पढ़ाई बिलकुल भी नहीं हो रही है। तो मैं आपसे यह रिक्वैस्ट करना चाहूंगी, अनुरोध करना चाहूंगी कि इस बिल्डिंग का जल्द से जल्द सर्वे भी हो और चूंकि इतनी जर्जर हालत में है, दीवारों पर बिलकुल दरारें हैं और ऐसा लगता है कि कभी भी छत गिर सकती है और कभी भी वहां कोई दुर्घटना भी हो सकती है तो, मंत्री महोदय, मैं आपको सभापति महोदय के माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि आप इसको गम्भीरता से लें और जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को ध्वस्त करा कर यहां नई बिल्डिंग का निर्माण कराया जाए ताकि बच्चे भी पढ़ाई करें, ऐसा ना हो कि बच्चे पढ़ने ही नहीं जाएं।

मंत्री महोदय, मैं आपको एक और चीज से अवगत कराना चाहूंगी कि जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है सवाई माधोपुर केवल यही नहीं हमारे पूरे जिले में विद्यालयों के जो भवन हैं उनकी व्यवस्था बिलकुल भी सही नहीं है। ऐसे काफी और भी विद्यालय हैं जिनकी जर्जर अवस्था है। पिछली सरकार ने इस बात पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया। ना तो शिक्षा पर ध्यान दिया, ना स्कूल की बिल्डिंग्स पर ध्यान दिया इसलिए आज हमारा यह हाल है कि कई बच्चे स्कूल तक पहुंचते ही नहीं और शिक्षा पर इतना महत्व भी नहीं दिया जा रहा, पेरेंट्स ही बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं तो, मंत्री महोदय, मैं आज आपको कहना चाहूंगी कि कम से कम हमारी स्कूल की बिल्डिंग्स तो ऐसी हों कि उसमें बच्चे सुरक्षित महसूस करें। अगर बच्चे अपने आपको सुरक्षित ही महसूस नहीं कर सकेंगे तो पढ़ाई कौन करेगा?

इस तरह के रोल माडल स्कूल्स, जैसे हमारी मुख्य मंत्रीजी भी चाहती हैं कि यहां पर रोल माडल स्कूल्स के माडल स्कूल्स बनें, उस तरह के माडल स्कूल्स तो तब ही हो पायेंगे अगर हम लोग स्कूल्स की बिल्डिंग पर ध्यान देंगे। उनमें कोई भी कमी नहीं हो और बच्चे पढ़ने के लिए ज्यादा अट्रैक्ट हों।

(राजकुमारी दियाकुमारी)

मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कें व पुल के सम्बन्ध में मांग संख्या 21 में एक और मांग है सवाई माधोपुर मलारना डूंगर से मलारना स्टेशन तक सड़क निर्माण एवं हम्मीर सर्कल से भैंरू दरवाजे तक सड़क सहित डिवाइडर निर्माण। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी यह बताना चाहूंगी कि मलारना स्टेशन और मलारना डूंगर, इसके बीच की जो सड़क है वह मुझे लगता है कि आज तक बनी ही नहीं और अगर कभी बनी थी तो यह सड़क आज ऐसी है कि लगता है यहां पर कभी भी सड़क का निर्माण हुआ ही नहीं था। किसी भी सरकार ने नहीं किया, हमारी सरकार के समय हुआ था लेकिन उसके बाद कांग्रेस सरकार ने बिलकुल ध्यान नहीं दिया और आज वो ऐसी दुर्गति में है, उस सड़क का ऐसा बुरा हाल है कि वहां पर ट्रैफिक बिलकुल भी जा ही नहीं सकता और वहां पर ओवर लोडेड ट्रक्स का भी काफी रहता है तो अगर उस सड़क को प्राथमिकता पर ले लिया जाए और उसका निर्माण काम भी जल्द से जल्द ले लिया जाए। यह भी आपको विनती करूंगी।

इसके अलावा, हमारे शहर में एक डिवाइडर की सड़क है, डिवाइडर के साथ जो हम्मीर सर्कल से भैंरू दरवाजे तक की सड़क है वो बिलकुल ही सवाई माधोपुर शहर के बीचों बीच है और क्योंकि सवाई माधोपुर एक ट्यूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहां पर पर्यटन के लिहाज से भी काफी ट्यूरिस्ट का आना जाना रहता है और यह सड़क इस तरह से बनायी गयी है कि यहां पर भी कभी भी दुर्घटना हो सकती है और कई बार हुई भी हैं, एक्सीडेंट्स भी कई हुए हैं। तो इसके लिहाज से भी मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस सड़क का कार्य भी जल्द से जल्द आप शुरू करें।

गुणवत्ता का जहां तक सवाल है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिये। अगर आप अधिकारियों को कहें और जो भी ठेकेदार हैं वो थोड़ा सा क्वालिटी कंट्रोल पर भी ध्यान दें, क्योंकि सड़कें तो बनती हैं लेकिन वो कुछ समय बाद टूट जाती हैं तो ऐसी सड़कों का क्या फायदा? तो इसके लिए भी मैं आपको कहना चाहूंगी कि उस चीज पर भी ध्यान दिया जाए, हमारे पूरे क्षेत्र के लिए इस चीज पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जगसी रामजी। (अनुपस्थित)

श्री शैतानसिंहजी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, सड़क की क्रांति आ गयी, 20 हजार किलोमीटर सड़कें बन गयीं इसलिए सारे संतुष्ट हैं शायद। दसेक परसेंट हैं।

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज। (व्यवधान) श्री शैतानसिंहजी, आरम्भ कीजिए।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): माननीय सभापति महोदय, मैं सदन को यह अवगत कराना चाह रहा हूं कि अभी इस घोषणा पत्र में रामदेवरा से जोधपुर जो पैदल पथ निर्माण की घोषणा की है उसमें मेरा निवेदन है कि यह पैदल पथ यात्रियों के लिए बनाया जाए यह ग्रेवल से ना बनावें क्योंकि ग्रेवल पर यात्री पैदल चल नहीं पाते हैं। बहुत दूरी से आते हैं, कई लोग तो 1200-1200 किलोमीटर से मध्य प्रदेश से। अधिकांश लोग इस रास्ते पर मध्य प्रदेश से आते हैं फिर अपने पूरे राजस्थान के क्षेत्र के लोग, कोटा, झालावाड़, बूंदी, इस बैल्ट में जो लोग रामदेवरा पैदल आते हैं वो इस सड़क पर हाइवे पर चलते हैं, वो बहुत थके हुए होते हैं इसलिए रोड पर चलने की कोशिश करते हैं और कई बार रात्रि में दुर्घटनाएं होती हैं। कई बार मेले के टाइम में लाखों लोग आते हैं, लाखों-लाखों लोग पैदल आते हैं। इसके लिए मेरा, माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि इस पथ को छह फीट की चौड़ाई में करें क्योंकि उससे ज्यादा चौड़ा होता है तो गाड़ी वाले उसमें गाड़ी चलाना शुरू कर देंगे और उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। गाड़ी वाले उस पर नहीं चलें इसके लिए छह फीट की इन्टर लोकिंग टाइल लगा कर इस पैदल पथ को तैयार करें ताकि वो पथ खाली पैदल यात्रियों के लिए ही उपयोग में लिया जावे। बहुतायत में, यों तो छठ, बारह मास लोग पैदल आते हैं पर विशेषकर भादवा में और यह अभी जो सावन चल रहा है, एक महीने लगातार लाखों-लाखों लोग रामदेवरा में पैदल आते हैं। इसके लिए मेरा विशेषकर निवेदन है। शायद एस्टीमेट ग्रेवल का आया है पर ग्रेवल न कराकर इन्टर लोकिंग टाइल लगावें। वो रेत में लगती है, उसकी साइड ब्लाकिंग कर दें और उसकी विड्थ छः फीट रखें तो जितना भी काम हो वो काम पुख्ता हो और वो यात्रियों के लिए उपयोग में आये। छः फीट की चौड़ाई पर जीप और कार नहीं चलेगी मात्र कोई मोटर साइकिल वाला चले लेकिन फिर वो उस हाइवे को छोड़ कर नहीं चलेगा और उस पथ का सदुपयोग हो। यह मेरा विशेष विशेष निवेदन है।

रामदेवरा मेले के लिए घोषणा भी हुई है। वह पूरे राजस्थान का बहुत बड़ा आस्था का स्थान है जिसमें भारत के सभी प्रांतों से लोग आते हैं। गुजरात से बहुतायत में आते हैं परन्तु इस तरफ से आने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश से और झालावाड़, कोटा, बूंदी इस बैल्ट से आने वाले लोग हैं, जोधपुर से भी आते हैं। यह लोग बहुत थके हुए होते हैं। नजदीक वाले तो

(श्री शैतानसिंह)

इतने थके हुए नहीं होते तो वो कच्चे में भी चल पाते हैं, जो दूर-दूर से आते हैं फिर वो रात को डामर सड़क पर चलने की कोशिश करते हैं, रात्रि में पता नहीं लगता है, दो गाड़ियां जब क्रास करती हैं तो कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस पथ के निर्माण की घोषणा की है तो मेरा यह विशेष-विशेष निवेदन रहेगा कि विभाग ने जो ग्रेवल के एस्टीमेट भेजे हैं, ग्रेवल न कराकर इन्टर लोकिंग टाइल लगवाएं ताकि यात्री आराम से चल सकें। मेरा इतना ही निवेदन है। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 19 और 21 लोक निर्माण विभाग, निर्माण कार्य सड़कें एवं पुल पर चर्चा हो रही है। इस बजट के अन्दर काफी सड़कों के लिए बताया गया है। अभी लाड़पुरा से आने वाले विधायक महोदय ने लम्बी-चौड़ी बात बतायी कि हमने यह किया, वह किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वह जो सड़कों का जाल बिछा है वह अटल बिहारीजी वाजपेयी प्रधान मंत्री थे उस समय यह प्रधान मंत्री सड़क योजना बनी और पूरे भारत में उससे लगाकर आज तक सड़कों का जाल बिछा, यह बात तो सही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस बजट के अन्दर 20 हजार किलोमीटर पीपीपी मोड पर सड़कों का निर्णय लिया, इसका तो हम स्वागत करते हैं लेकिन पीपीपी मोड पर जो सड़कें बनेंगी, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर से बस रवाना होती है वह जाती है गुजरात, महाराष्ट्र की ओर जब पहुंचती है तो 25 सौ से 3 हजार रुपये टोल के उसके लगते हैं तब जाकर के एक बस पहुंचती है। पीपीपी मोड के आधार पर जहां टोल लगे हैं, उसकी वजह से यह रोड्स बनी हैं और इतना टोल एक गाड़ी पर ही लग जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि आप सड़कें बनाओ, चाहे पीपीपी मोड पर ही बनाओ लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जनता पर भार कम से कम पड़े।

माननीय सभापति महोदय, एक रोड पचपदरा, सिंदरी और गुढामालानी आपके समय में बनी। अच्छी बात है कि रोड बनी, अच्छी रोड बनी। लेकिन उस पर 4 जगह टोल लगे हुए हैं। 6 साल हो गये और उसके बाद में भी टोल वसूल रहे हैं और कितने साल वसूलेंगे उसका भी पता नहीं है। अब उस रोड की हालत भी खराब है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पीपीपी मोड

(श्री मेवाराम जैन)

पर जो रोडें बनाने जा रहे हैं तो टाइम बाउंड प्रोग्राम हो कि इस पर इतने साल टोल लगेगा और इतना लगेगा। जनता पर ज्यादा भार नहीं पड़े इस बात का जरूर ध्यान रहे।

माननीय सभापति महोदय, प्रधान मंत्री सड़क योजना में अभी जो सड़कें बननी हैं, इसके अन्दर सिर्फ 3 मीटर चौड़ाई है और ना ही उसमें पटरियां बननी हैं। अब 3 मीटर चौड़ाई में वह सड़क बनेगी और 5 साल की उसमें गारंटी है। 3 मीटर पर अगर पटरियां नहीं बनें तो यह रोड्स शर्तिया ही टूट जायेंगी। इसलिए पौने 4 मीटर पहले जैसी गाइड लाइन थी, उस हिसाब से बननी चाहिए। आजकल तो आप देख रहे हैं कि जो रोड बनती है उसकी कैपेसिटी है 15 टन के व्हिकल तक और उस पर 50-50 टन के टर्बे चल रहे हैं तो 5 साल वह रोड नहीं रह पा रही है। इसलिए इसमें भी सुधार की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि विलेज रोड हैं या अन्य रोड्स हैं, हमारी सरकार में पिछले समय 25 किलोमीटर और 5 किलोमीटर धार्मिक रोड भी सभी एमएलए को दी थी। उसमें पूरे राजस्थान की रोड ठीक हो चुकी थी। इस प्रकार से सभी एमएलए को 50-50 किलोमीटर रोड दी जायें और जो मिसिंग लिंक हैं, दोनों साइड रोड बन चुकी बीच में खांचा जहां भी है 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ऐसे जो छूटे हुए हैं, उनको प्राथमिकता से किया जाये ताकि उन गांवों में रोड का महत्व बना रहेगा। वह दोनों साइड़ों में जुड़ जायें।

रिपेयर के लिए जोन वाइज हम कांट्रेक्ट करेंगे उसमें भी मैं कहना चाहूंगा कि जोन वाइज नहीं करके, जिले वाइज करें। उसमें भी टुकड़ों में करें ताकि अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि छोटे कांट्रैक्टर जहां हैं उनको भी रोजगार मिले। बाहर की कम्पनीज आ जायेंगी तो छोटे कांट्रैक्टर सारे वंचित रहेंगे। इसका भी ध्यान रखा जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की बात करुंगा कि बाड़मेर शहर के अन्दर 2 ओवरब्रिज तो पहले ही बन चुके हैं। बाड़मेर में अभी तेल, रिफाइनरी के कारण बाहर की कम्पनीज आयी हुई हैं। वहां दुनिया भर का ट्रैफिक है। बाड़मेर शहर में ही एक चौहटन फाटक है, रेलवे क्रासिंग है, वहां एक अंडरब्रिज बन जाये तो वहां एक-एक, दो-दो घंटे का जो हमेशा शहर के

(श्री मेवाराम जैन)

अन्दर जाम रह रहा है, वह नहीं रहे। बाकी छोटे-मोटे जो मैंने पहले मिसिंग लिंक के दिये हैं उनको ठीक करायें।

एक बाड़मेर-सिंदरी-जालौर स्टेट हाइवे है उसको शायद नेशनल हाइवे में लेने का आपने प्रपोजल लिया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। दूसरी बात और कहना चाहूंगा कि जोधपुरपचपदरा-बाड़मेर नेशनल हाइवे 112 है और अभी तैयार हुई है, इन 4-6 महीनों में ही कम्पलीट होकर के नई सड़क बनी है, वह 7 मीटर बनी हुई है और शायद आप उसको 3 मीटर और बढ़ाकर 10 मीटर करना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, हम स्वागत कर रहे हैं उस बात का। लेकिन उसको आप एनएचएआई को देकर उस पर टोल नहीं लगायें, क्योंकि वह एक अच्छी रोड अभी बनी है और 3 मीटर चौड़ी करके फिर उस पर टोल लगायेंगे तो जनता को इसमें बहुत भारी नुकसान होगा। मैं आपसे इसमें निवेदन करुंगा कि यह बहुत अच्छी बात है, मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आप इस रोड को बढ़ाओ, अच्छी करो। उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अभी यह नेशनल हाइवे नई ही बनी है। उसमें 3 मीटर बढ़ाकर फिर टोल लग जाये तो जनता को नुकसान होगा।

सभापति महोदय, मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि आपने बजट के अन्दर जितनी भी रोड्स को लिया है, अच्छी बात है, 250 से 500 जोड़ने वाली बात है, वह भी अच्छी बात है। इससे नीचे वाले गांव हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करें। रोड बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनकी गुणवत्ता अच्छी हो इस बात का भी ध्यान रखें।

अभी एक और मुद्दा भी आयेगा शायद, पहले जो डामर और इमल्शन आता था, सी फार्म पर आता था, अब उस पर शायद 14 परसेंट वैट लगा है। इससे एक से डेढ़ लाख कास्ट बढ़ेगी एक किलोमीटर पर। इस हिसाब से कांट्रैक्टर उस काम को घटिया स्तर पर करेंगे, क्योंकि घर से तो भरने से रहे। इसलिए आप इसका बीएसआर में कोई प्रबंध करें या फिर वापस उस वैट को कम करें ताकि सड़क की गुणवत्ता बनी रहे और इसमें ठेकेदार चोरी नहीं करें। इस बात का भी आप ध्यान रखें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हीरालाल नागर।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बजट में प्रस्तुत माननीय मुख्य मंत्री महोदया के द्वारा जो लोक निर्माण विभाग में प्रस्ताव किये गये हैं और इस राजस्थान को एक सपनों का राजस्थान बनाने का जो प्रयास हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने किया है, उसमें 20 हजार किलोमीटर सड़कों के प्रस्ताव दिये हैं। इन सड़कों के माध्यम से राजस्थान में एक औद्योगिक क्रांति आयेगी। हमारे यहां पर्यटन का विकास होगा और यह जो राजस्थान पटरी से उतर गया था, इसको वापिस पटरी पर लाने में यह महत्वपूर्ण बजट सड़कों के माध्यम से काम करेगा।

आज इस प्रांत में इस तरह की हालत पिछले 5 सालों में सड़कों की हुई कि सड़कों पर चलना ही मुश्किल हो गया। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने पूरी अपनी परिवर्तन यात्रा में हर गांव, हर ढाणी में और पूरे राजस्थान में देखा कि सड़कों की स्थिति कितनी भयावह है। उन सड़कों में जहां दो-दो फुट के खड्डे थे। उन पर भी माननीय वसुन्धराजी ने अपनी परिवर्तन यात्रा में यात्रा की, और उन्होंने जो दृश्य देखा उसी का नतीजा है कि उन्होंने इस विभाग के माध्यम से राजस्थान में परिवर्तन का एक बिगुल बजाया है। मैं मेरे क्षेत्र के लिए आपको बताऊं कि मेरा सांगोद विधान सभा क्षेत्र माननीय पूर्व सार्वजनिक निर्माण मंत्री का क्षेत्र रहा है और पूर्व में कल भी यहां कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था कि रामगंजमण्डी से जाने के लिए पूर्व मुख्य मंत्री को ट्रेन का सहारा लेना पड़ा और रामगंजमण्डी से वापस सांगोद आने के लिए माननीय पूर्व मुख्य मंत्रीजी को वापस कोटा आकर 80 किलोमीटर और फिर कोटा से 90 किलोमीटर बारां से अंता होते हुए सांगोद पहुंचना पड़ा। 150 किलोमीटर, जो मात्र रामगंजमण्डी से 35 किलोमीटर है सांगोद, उसके लिए 150 किलोमीटर वह मुख्य मंत्री होते हुए वहां ट्रेन के माध्यम से, सड़क के माध्यम से चल कर गये। वह क्षेत्र था उस समय के सार्वजनिक निर्माण मंत्री भरत सिंहजी का। ऐसी स्थिति सार्वजनिक निर्माण मंत्री के क्षेत्र में उस समय थी, ऐसी भयावह स्थिति कि मुख्य मंत्री भी उस सड़क से नहीं चल सकते थे। उस सड़क पर चलते हुए हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया गईं और उन्होंने देखा कि यहां तो खड्डे हैं, सड़क का कहीं पता ही नहीं चल रहा, ऐसी स्थिति उस समय पांच साल में सड़क की की गई। इस देश में हमारे जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधान मंत्री, जिन्होंने एक सोच के साथ प्रधान मंत्री सड़क योजना शुरू की, अगर वह उसको शुरू नहीं करते तो आज इस देश की हालत क्या होती? उन्होंने जनसंख्या के आधार पर सड़कों के लिए निर्माण का

(श्री हीरालाल नागर)

कार्य प्रारम्भ किया और गांव का एक व्यक्ति जिसको एक किलोमीटर की भी सड़क की आवश्यकता होती थी वह नेताओं और अधिकारियों के चक्कर लगाते-लगाते उसकी पांव की चप्पलें घिस जाती थीं लेकिन उसको सड़क नहीं मिलती थी और नतीजा वह हार थक कर गांव का व्यक्ति उसी पथ पर पैदल यात्रा करता रहता था लेकिन हमारे पूर्व प्रधान मंत्री, अटलजी ने गांव के उस आम आदमी की सोच के साथ में जुड़कर देखा था कि इस देश में नेताओं के द्वारा आम आदमी के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, अब वह भेदभाव नहीं होना चाहिये और उन्होंने इस जन संख्या के आधार पर प्रधान मंत्री सड़क योजना की घोषणा की। आज जो देश में सड़कों में सुधार हुआ है उसमें बहुत बड़ा कारण अगर एक है तो हमारा बीजेपी का शासन आने के बाद प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी की सोच के कारण देश में सड़कों की स्थिति सुधरी है और कार्यकाल जो पूर्व में कांग्रेस का रहा, वापस हम सड़क के मामले में पीछे चले गये।

हाड़ौती के बारे में मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को बताना चाहूंगा और लाडपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा, वास्तव में हाड़ौती में काली मिट्टी है। राजस्थान में इस तरह सड़क की स्वीकृति होती है तो जनरली 40 लाख, 45 लाख का एक थम्ब रूल के साथ स्वीकृति जारी की जाती है, चाहे पश्चिमी राजस्थान हो, चाहे पूर्वी राजस्थान, एक ही अधिकारी उसी तरह से स्वीकृति जारी कर देता है। हाड़ौती में पश्चिमी राजस्थान में सड़क के निर्माण में खर्चा अधिक होता है।

मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहूंगा कि हाड़ौती में सड़कों के निर्माण में विशेष सामग्री का ट्रांसपोर्टेशन करके वहां मोरम और मिट्टी मंगवाई जाये। ब्लैक कोटा सोयल को हटाकर वहां पर अन्य क्षेत्रों से लाकर ट्रांसपोर्टेशन का जो एडीशनल खर्चा लगता है वह भी जोड़ा जाये ताकि वहां की मिट्टी जो हाड़ौती की काली मिट्टी है उसके कारण से बरसात में एक स्पंजिंग जैसा आ जाता है और पूरी सड़कें बैठ कर बरसात के टाइम पर नष्ट हो जाती हैं। कई सड़कें तो गारण्टी पीरियड में हैं लेकिन गारण्टी पीरियड के बाद भी उस सड़का का निर्माण जिस ठेकेदार ने किया है, पूरी सड़क दुबारा बना दे और वह पूरी कोस्ट लगा दे तब भी उसकी कोस्ट में वह काम नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति कई सड़कों की है, उन पर आज चलना दूभर हो गया। उन सड़कों पर आज इतने खड्डे हैं कि वह ठेकेदार अपनी गारण्टी भी जब्त

(श्री हीरालाल नागर)

करा चुका, अपनी एसडी भी जब्त करा चुका, फिर भी उसका निर्माण नहीं करवा पा रहा है और नतीजा यह हो रहा है कि वह सड़कें बिना आज निर्माण के ऐसी स्थिति में है कि उन पर फोर व्हीलर, टू व्हीलर चलना भी मुश्किल है। इसलिए उस पर विशेष प्रावधान किया जाये और उन सड़कों को इस तरह से बजट दिया जाये कि हाड़ौती क्षेत्र में जिस तरह की बरसात होती है और जिस तरह की मिट्टी के अनुपात में जिस तरह का काम्पैक्शन किया जाये, उस अनुपात में सड़कों का बजट दिया जाये तो ही सड़कें सम्भव हो पायेंगी। वहां पर एक बार भी ओवर लोड ट्रक निकल गया तो उसके बाद वह सड़क खतम हो जाती है। ऐसी स्थिति आज आम सड़कों पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो गई। वहां पर भी ओवर लोड ट्रक जाने लगे और उसका कारण है कि गांवों में जो सड़कें पहले दस-दस, पांच-पांच साल से खतम नहीं होती थीं अभी ओवर लोडिंग के कारण वह महीने पन्द्रह दिन में ही खतम हो गईं। ओवर लोडिंग के कारण चाहे वह बनास की रेत जा रही हो या गांव से मिट्टी भर कर डम्पर आ रहे हों, उनसे स्थिति हो गई है और यह स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है इसलिए सड़कों के मामले में गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए हमें इस मामले में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं मेरे क्षेत्र की जो कुछ सड़कों का निर्माण पूर्व में स्वीकृत था, उन पर रोक लगा दी गयी उसके लिए सुझाव देना चाहूंगा कि उन पर से रोक हटा करके और उन सड़कों का निर्माण पुन: प्रारम्भ किया जाता है तो निश्चित रूप से ग्रामीणों को फायदा होगा। ऐसी कई सड़कें हैं, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन पर से रोक हटा कर चालू करायें।

एक और मेरा सुझाव है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कैथून से लेकर सांगोद और कवाइद तक का एक रोड स्वीकृत हुआ है जो बी ओ टी के आधार पर आर एस आर डी सी के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। इस रोड पर तीन ऐसे प्रमुख कस्बे पड़ते हैं, अभी लाडपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा, चाहे कैथून हो, चाहे सांगोद और बपावर, तीनों जगहों पर 180 करोड़ के रोड में बाइपास के कोई प्रावधान नहीं दिये गये हैं, इसके कारण से वह बी ओ टी रोड है और मेरा सुझाव है कि बी ओ टी में उसकी वायबिलिटी इसलिए नहीं आयेगी कि तीनों जगह लम्बा ट्रैफिक उन तीनों कस्बों से गुजर नहीं सकता और उसका नतीजा रहेगा कि वह रोड बायबिलिटी नहीं आने के कारण से उसकी उपयोगिता पूरी नहीं हो पायेगी इसलिए उन तीनों कस्बों कैथून, सांगोद

(श्री हीरालाल नागर)

और बपावर में भूमि अधिग्रहण करके बाइपास का निर्माण किया जाता है, तभी उस रोड की उपयोगिता सम्भव है। इस कार्य को तुरन्त प्रारम्भ करने के लिए मेरा सुझाव है। एक ईस्ट-वेस्ट कारिडोर के रूप में जिस तरह से हमारे हाड़ौती में भी काम हो रहा है, मेरा यह सुझाव है कि कनवास से इसको आगे बढ़ाकर और हमारा आवा, दीगोद तक इसको जोड़ा जाये जिसमें देवली, आवा, कनवास के बीच की जो सड़क है जो पूरा यह कारिडोर जुड़ता है तो इसको मध्य प्रदेश के श्योपुर के द्वारा ग्वालियर तक का सीधा लिंक मिलता है। मेरा सुझाव है कि उसी के साथ इसको भी जोड़ कर निर्माण किया जाये। मेरे क्षेत्र में कैथून से बानेड़ा होते हुए रेल, चार चौमा, बालाजी की थाक होते हुए अड़ूसा की जो रोड है वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त है उस पर आवागमन भी कहीं आज की तारीख में कोई सम्भव नहीं है। भांडाहेड़ा के गांव में बाइपास की आवश्यकता है उसको भी सम्मिलित करते हुए योजना में निर्माण कराया जाये।

उपखण्ड कनवास में कालोनी रावजी की बाड़ी होते हुए सावन भादो, गोपालपुरा झालरी, बालूहेड़ा, खेड़ली, काकूनिया, कचोलिया, गरड़ाना और कनाफल को जोड़कर सांगोद उप खण्ड तहसील को सीधा जोड़ा जाये ताकि लोगों को आवागमन का सीधा रास्ता अपने तहसील और उप खण्ड मुख्यालय तक सम्भव हो सके।

मेरे विधान सभा क्षेत्र सांगोद में ही बिनोदखुर्द की पुलिया इतनी नीची है कि उस पर बरसात में कम से कम तीन चार मौतें हो जाती हैं और बारह महीने उस पर पानी रहता है, उसकी ऊंचाई बढ़ाई जाये ताकि लोगों को उस पर छह से एक फीट से डेढ़ फीट तक पानी रहता है और छोटे-छोटे बच्चों को भी पढ़ाई के लिए भी उस पानी में से गुजरना पड़ता है और पुलिया इतनी संकरी है कि उसका निर्माण भी ऊंचा करके पुनर्निर्माण किया जाये। कुन्दनपुर में भी इसी तरह की स्थिति है कि वहां पर भी पानी भरता रहता है और सड़क की उस पुलिया को भी ऊंचा करके निर्माण किया जाये।

बिरद माताजी जो केशोरायपाटन और दीगोद को जोड़ती है उस पर भी चम्बल नदी पर एक पुलिया का निर्माण करना प्रस्तावित है उसकी भी स्वीकृति जारी की जाये और उसी के साथ मुझे जो हमारी मुख्य मंत्री ने यह बजट दिया है, पुन: मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरह से कोटा के पूरे जोन में एक 4 हजार करोड़ का टैण्डर करके जिस तरह से सड़कों पर मुख्य मंत्री ने, हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने एक प्रयास किया है कि हाड़ौती का

(श्री हीरालाल नागर)

इस तरह का जो बड़ा टैण्डर करके निश्चित रूप से उससे आने वाले समय में सुदृढ़ीकरण होगा और हाड़ौती में जो सड़कों के मामले में काफी स्थिति खराब थी उसमें सुधार होगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, कटौती प्रस्ताव के द्वारा मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जालौर जिला विकास की दृष्टि में राजस्थान में काफी पीछे है, चाहे सड़कें हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे पेयजल हो, या चाहे चिकित्सा हो, या सरकार की अन्य योजना, जो पूरे राजस्थान में दूसरे जिले को लाभ मिलता है वह जालौर जिले को नहीं मिलता है। सुराज संकल्प यात्रा में हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने हर गांव, ढाणी, मजरे का दौरा किया और राजस्थान की पिछले 5 साल में जो सड़कों की स्थिति थी उनको अपनी आंखों के द्वारा उन्होंने देखा और उनके मन में एक पीड़ा आयी। 2003 से 2008 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय वसुन्धरा राजे जी ने जो काम किये थे, पिछले 5 साल में पिछली सरकार में वे सारे काम जिस गति में छोड़े थे वैसी स्थिति में रहे। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 2014-15 का बजट विधान सभा के अन्दर पेश किया और इस बजट में 20 हजार किलोमीटर सड़कें बनाने की घोषणा की जिससे आम नागरिक को राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, गांवों में विकास सड़कों के माध्यम से ही हो रहा है। सड़क होगी तो आवागमन के साधन होंगे और जो गांवों से लोग पलायन करके शहर में जा रहे हैं वह पलायन रुकेगा। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि इस बजट में गौरव पथ बनाने की बात कही है, गौरव पथ पहले शहरों तक सीमित था, मुख्य मंत्रीजी का जो विजन है उन्होंने देखा कि गांवों का सही मायने में विकास कैसे हो। गांवों के अन्दर गौरव पथ बनाने की बजट में बात कही है 0.5 से 2 किलोमीटर तक गांव में सड़क बनेगी, सीसी रोड की जहां आवश्यकता है वहां सीसी रोड बनेगी, यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। हर ग्राम पंचायत मुख्यालय को सड़क से जोड़ने की बात कही है वह भी स्वागत योग्य कदम है। राजस्थान स्टेट हाइवे का गठन कर हाइवे के अन्दर होने वाली जितनी भी परेशानियां हैं इनसे भी

(श्री नारायण सिंह देवल)

निश्चित तौर पर एक निजात मिलेगी। 5 हजार किलोमीटर धार्मिक पर्यटन को जोड़ने की बात कही है वह भी स्वागत योग्य कदम है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से विनती करता हूं कि जालौर जिला जो पिछड़ा जिला है उसको ध्यान में रखते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र में साकड़ से खारा की सड़क है, निवेदन करना चाहूंगा वह 2001 में बनी हुई है, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है और पिछली सरकार ने राजनैतिक द्वेषता के कारण इस सड़क के ऊपर कोई काम नहीं किया है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सड़क का नवीनीकरण प्राथमिकता के आधार पर आप करें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक सड़क भीनमाल से सांचौर जाती है, वो सड़क ओडीआर-12 के अन्दर आती है। इसकी चौड़ाई 5.5 मीटर है और दो उपखण्ड कार्यालय को जोड़ती है भीनमाल व सांचौर को। यह सड़क भी काफी क्षतिग्रस्त है, यातायात का काफी दबाव रहता है, इस क्षेत्र में काफी माइनिंग एरिया भी है, बड़े-बड़े गांव जुड़ते हैं जिसमें करड़ा है, चाटवाड़ा है, खारा है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन है कि इस सड़क को भी प्राथमिकता के आधार पर लें।

तीसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक सड़क पावली से शिवगढ़ है जो करीब 7 किलोमीटर है। यह सड़क काफी पुरानी है और 2006-07 में बनी हुई है। यह काफी क्षतिग्रस्त है। हमारे जालौर जिले में जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है सुंधामाता मंदिर उसको यह सड़क जोड़ती है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विनती करता हूं कि इस सड़क का भी नवीनीकरण कराया जाय। एक सड़क मनोहरजी से गजीपुरा है, वह भी 2004-05 में बनी हुई है और काफी क्षतिग्रस्त है, इसलिए इसके ऊपर भी प्राथमिकता से ध्यान दें।

(13.36 बजे)

(श्रीमती किरण माहेश्वरी, सभापति, पदासीन)

अंतिम बात मेरे विधान सभा क्षेत्र में रानीवाड़ा स्टेट हाइवे से चाटवाड़ा, जो करीब 20 किलोमीटर सड़क है, यह सड़क चलने लायक भी नहीं है। इस सड़क पर यातायात काफी है और नान-पेचेबल श्रेणी में आती है। यहां पर यातायात का काफी दबाव है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि जालौर जिले के पिछड़ेपन को देखते हुए इन सड़कों

(श्री नारायण सिंह देवल)

की प्राथमिकता के आधार पर आप स्वीकृति दिलाएंगे। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री जगसीराम जी।

श्री जगसी राम (रेवदर): सभापति महोदय, मांग संख्या 19 लोक निर्माण कार्य, मांग संख्या 21 सड़क एवं पुल पर बोलना चाहूंगा। सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार ने जो वर्तमान में प्रदेश के लिए सड़कों के बारे में कदम उठाये हैं वे बहुत सराहनीय हैं। पूर्ववर्ती सरकार में पूरे 5 साल के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में ही नहीं मेरे विधान सभा क्षेत्र में, मैं विधायक था, एक भी सड़क ऐसी नहीं बनी जिसके लिए जनता के बीच जाकर बता सकें। 2003 और 2008 के बीच भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वसुन्धरा जी की सरकार में मैं विधायक था उस समय में जब भी मेरे क्षेत्र की सड़कों के बारे में जो भी मांग रखी, सरकार के ध्यान में बात दिलायी तो निश्चित रूप से सड़कें हुईं और कार्य हुआ।

मेरे रेवदर विधान सभा क्षेत्र में आबूरोड रजवाड़ी ब्रिज बना हुआ है वह उस कार्यकाल में बना। इसी तरह पूरे विधान सभा क्षेत्र में कई सड़कें बनीं, जो धार्मिक सड़कें बनीं वे उस समय विधायकों की अनुशंसा पर बनती थीं। आज माननीय मंत्रीजी व सरकार ने जो कदम उठाये हैं वे बहुत सराहनीय हैं।

मैं इस अवसर पर आबूरोड से सांचौर के बीच में जो मेगा हाइवे की सैंक्शन हुई है, मंत्रीजी ने स्वीकृति दी है उसके लिए में मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि लम्बे समय से मैं मांग करता आया हूं कि रेवदर और मण्डार बाइपास को यदि जोड़ा जाए, यह सड़क सैंक्शन हो गई है, रेवदर और मण्डार बाइपास को जोड़ा जाय क्योंकि आये दिन वहां बहुत दुर्घटना होती आ रही है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जब आप जवाब दें उसमें हमारे रेवदर मण्डार बाइपास के बारे में निश्चित रूप से बताएं ताकि क्षेत्र की जनता जो दुर्घटना आए दिन होती है उन दुर्घटनाओं से बच सकें।

मैं आज इस अवसर पर विशेष तौर से निम्बज, अनापूर, वड़वज, केशुवा रायपुर, हड़मतिया और बड़गांव जो जालौर से लगता हुआ एरिया है इनके बीच में एक बड़ी पुलिया आ रही है वहां पर केशुवा जो नन्दगांव गौशाला के नाम से जाना जाता है उसमें हजारों गायों के लिए चारा-पानी लाने में दिक्कत रहती है इसलिए वहां पर पुलिया के निर्माण की आवश्यकता है। मंत्रीजी उसके ऊपर विचार करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई ऐसी सड़कें हैं जो

(श्री जगसी राम)

ग्राम पंचायत और गांवों से जुडी हुई नहीं हैं, मैं आज के इस अवसर पर आबू रोड-रेवदर सम्पर्क सड़क से जो क्यारिया ग्राम पंचायत धवली के अन्दर है, उसको भी जोड़ने का निवेदन कर रहा हूं। इसी तरह ग्राम पंचायत भटाना में सिवराखेड़ा और कम्बोइया, भैरूंगढ़ से जावल ग्राम पंचायत मगरीवाड़ा, कुछ ढाणियों को जोड़ना है जैसे ग्राम पंचायत पादर उसके अन्दर कालतरावड़ी है, ग्राम पंचायत जीरावल में देवका है, ग्राम पंचायत जैतावड़ा कोटड़ा जो गुजरात बोर्डर पर आया हुआ है।

इसी तरह आज लोक निर्माण कार्यों के ऊपर चर्चा हो रही है, मैं आज के इस अवसर पर मेरे विधान सभा क्षेत्र में आबूरोड का डाक बंगला बना हुआ है वह बहुत जर्जर स्थिति में है। वहां आबू पर्वत पर्यटक स्थल है, वहां पर कई अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों का आना जाना होता है इसलिए मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उसको भी आप ठीक करने के लिए आदेश करावें। मैं मेरी बात को ज्यादा नहीं कहते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कई जो छोटी-मोटी सड़कें हैं उनको आप जुड़वाने का कष्ट करें। मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): माननीय सभापति जी, मांग संख्या 19, 21 पर मैं सदन का ध्यान मेरे क्षेत्र खण्डार की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डार में एक रोड खण्डार से बहरावण्डा खुर्द तक जाता है जिसका टैण्डर हुए लगभग डेढ़ साल हो गये, 10 करोड़ के काम में आज भी प्रशासन की यह स्थिति है कि प्रशासन से जवाब मांगते हैं तो उनका जवाब होता है कि हमारी इस रोड का काम 50 प्रतिशत से ज्यादा हो गया जबकि फिजिकली जाकर उस रोड को देखा जाए तो उसका काम मुश्किल से 10 प्रतिशत भी नहीं हुआ। इसी तरह हमारे विधान सभा क्षेत्र में कई सारे ऐसे रोड हैं जिनकी जानकारी पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा, जब प्रशासन से मांगी जाती है तो 50 से 60 प्रतिशत की बताते हैं लेकिन रोड पर जाकर देखें तो स्थिति कुछ और ही मिलती है। मंत्रीजी, हमारे खण्डार विधान सभा क्षेत्र में आज भी 333 गांवों में से लगभग 50 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जहां पर एप्रोच रोड नहीं बने जबकि उनकी पापुलेशन लगभग 500 से ज्यादा है। पिछली बार हमारी केन्द्र सरकार जो अटल जी की थी उसमें उनकी ओर से एक योजना बनाई गई थी कि 500 से ज्यादा पापुलेशन के गांवों को रोड से जोड़ा जाएगा फिर भी हमारे क्षेत्र में इस तरह के बहुत सारे गांव हैं।

(श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल)

इसी तरह से मैं आपका ध्यान हमारे क्षेत्र के मेई से गण्डावर रोड की ओर दिलाना चाहता हूं जो एक करोड़ 20 लाख का काम है। उस काम की कम्पलीशन डेट 2 फरवरी, 2014 की है और रोड की स्थिति अभी तक यह है कि उस रोड का 40 प्रतिशत से ज्यादा काम नहीं हुआ। इसी तरह मैं आपका ध्यान खण्डार से रामेशर रोड की ओर दिलाना चाहता हूं जिसकी लागत लगभग 6 करोड़ की है और उस रोड के काम की गति बिल्कुल कछुआ चाल से चल रही है। मुझे नहीं लगता कि इसी गति से वो काम चलता रहा तो 2-5 साल में भी कम्पलीट हो पायेगा। मैंने कई बार प्रशासन से जानकारी लेने की कोशिश की तो हमारे क्षेत्रीय जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके पास पुख्ता जानकारी नहीं होती है। मैं आपका ध्यान चौथ का बरवाड़ा-चोरू रोड की ओर दिलाना चाहता हूं। उस रोड की स्थिति ऐसी है कि जब भी कोई वहां से गुजरता है तो वह आकर यों कहता है कि गोठवाल जी, इस क्षेत्र का नाम खण्डार की खड्डा विधान सभा क्षेत्र रख देना चाहिए। उस रोड में लगभग 2-2, 3-3 फीट के गहरे खड्डे हैं और ऐसा लगता है कि 50 साल से उस रोड पर कभी कोई काम नहीं हुआ। मैं आपकी जानकारी में एक बात और दिलाना चाहता हूं जब प्रशासन से पूछा गया कि हमारी कांस्टीट्यूएंसी में कितने काम और कितने रोड ऐसे हैं जो पी.डब्ल्यू.डी. कर रही है। तब प्रशासन द्वारा जानकारी मिली की 31 रोड ऐसे हैं जिनका काम पिछले छह महीनों में फाइनल हुआ है। जब हमने जाकर उन रोड को देखने की कोशिश की तो जिनकी कम्पलीशन डेट पिछले 2 महीने, 5 महीने पुरानी थी उन रोड में भी 2-2 फीट गहरे खड्डे हो चुके हैं। जब उनसे कहा गया कि गारंटी पीरियड के अन्दर यह काम हैं, इनको कराया जाए तो प्रशासन की तरफ से उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

अभी पिछले महीने मेरे द्वारा प्रशासन से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि 21 काम ऐसे हैं जो कि अभी प्रगति पर हैं। जब वहां के क्षेत्रीय अधिकारियों को लेकर उन कामों का विजिट करने के लिए हम और हमारे कार्यकर्ता गये तो 21 में से 4 काम काम भी ऐसे नहीं थे जिनमें काम चल रहा हो। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हमारे डिपार्टमेंट को महारानी साहिबा ने, मुख्य मंत्रीजी ने इतना पैसा दिया है कि पूरे प्रदेश के अन्दर वो चाहती हैं कि रोड की दिशा बदले, उनका मानना है कि गांवों का रोड के माध्यम से विकास किया जाता है, गांव की रोड के माध्यम से शिक्षा जाती है, गांव की

(श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल)

रोड के माध्यम से ही चिकित्सा जाती है। आज भी मेरे क्षेत्र में बालेर से लेकर सवाई माधोपुर तक किसी गर्भवती महिला को ले जाओ तो कई बार अख़बार में छपता है कि रास्ते में ऐसी स्थिति हो गई कि उस बेचारी को वो सब चीजें फेस करनी पड़ती है जबकि 40 किलोमीटर का रास्ता है और उसमें लगभग 3 घंटे लगते हैं। मंत्रीजी, हमारे क्षेत्र में अभी 52 गांव पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा बताये हैं जो चल रहे हैं या उनका कम्प्लीशन हो चुका है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन सब कामों को आप जाकर, किसी अधिकारी को भेजकर चैक करवायें जिससे कि हमारे क्षेत्र में जो पैसा सरकार के माध्यम से जा रहा है उसका सदुपयोग हो सके।

इसी तरह मैं आपका ध्यान समाज कल्याण विभाग के एक छात्रावास की ओर ले जाना चाहता हूं। देवनारायण योजना में यह छात्रावास बना, दिसम्बर, 2013 में पी.डब्ल्यू.डी. ने इस छात्रावास को कम्प्लीट करके समाज कल्याण विभाग को दिया। अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी जब भरतपुर सम्भाग के दौरे पर गईं तो उनको भी उस छात्रावास के विजिट करने का मौका मिला, हमारे समाज कल्याण मंत्रीजी को भी उस छात्रावास में जाने का अवसर मिला। मंत्रीजी, उस छात्रावास की स्थिति ऐसी थी कि चार महीने पहले कम्प्लीट हुआ छात्रावास आज जर्जर स्थिति में है और कभी भी उसमें कोई एक्सीडेंट हो सकता है। प्रशासन को बार-बार बताने के बाद में भी उसमें कोई कार्यवाही नहीं है। इसी तरह मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र के गोठड़ा गांव की तरफ ले जाना चाहता हूं। वहां पर स्कूल की एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके नीचे छात्र बैठकर पढ़ते हैं, छात्राएं बैठकर पढ़ती हैं। तीन बार वहां ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं कि छत से रोड़ी का टुकड़ा गिरता है और उन छात्र-छात्राओं के लग जाती है। कोई भी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। प्रशासन को कई बार जानकारी दी और उनसे कहा कि इस बिल्डिंग को अगर रिपेयर कराने की स्थिति में नहीं हो तो इसे तुड़वा देना चाहिए लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अन्दर सड़कों की हालत हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी अच्छी हुई थी, पिछले पांच वर्षों में उससे अधिक खराब हो गई है। मैं इसको हमारी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज मानता हूं कि हम इन पांच सालों में पिछली सरकार के किये हुए खड्डे अगर भर पायें तो मुझे लगता है कि हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री अर्जुन लालजी जीनगर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदया, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आज विधान सभा में मांग संख्या 19 और 21 पर बोलने का अवसर दिया। हमारे सदन में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विराजमान हैं। मैं आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो हमारे राजस्थान में जो सड़कों के हाल हैं, कुछ क्षेत्रों को छोड़ने के बाद बाकी राजस्थान की स्थिति सड़कों में बहुत पिछड़ी हुई है और यह स्थिति जब वसुन्धरा राजे जी ने मुख्य मंत्री बनने से पहले सुराज संकल्प यात्रा लेकर सम्पूर्ण प्रदेश का 14,000 किलोमीटर तक दौरा किया, उसमें उनको देखने को मिला कि राजस्थान में सड़कों की स्थिति बड़ी जर्जर हो गई है और स्थिति ऐसी बिगड़ी हुई है कि आज की तारीख में जैसे कांग्रेस की स्थिति बिगड़ी हुई है, वही स्थिति उस समय सड़कों की थी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सुधर रही है, सुधर रही है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): हां, अब जरूर सुधरेगी। हम जरूर सुधारेंगे। मेरा यह निवेदन है आपसे...

श्री हीरालाल (निवाई): हमारी सरकार आ गई, अब सुधरना शुरु हो गई।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): हमारी सरकार जब आती है तो विकास लाती है और कांग्रेस सरकार जब आती है तो विनाश जरूर होता है। 2008 में जब हमने सरकार छोड़ी थी, तब हमारे राजस्थान की सड़कों की तुलना गुजरात की सड़कों से की जाती थी और उससे पहले 1993 में मैं जब पहली बार आया, तब सड़कों की ऐसी स्थिति थी कि मध्य प्रदेश के साथ हमारी तुलना होती थी। राजस्थान का व्यक्ति कोई मध्य प्रदेश में जाता तो उसे पता चलता कि अब मध्य प्रदेश आ गया है और जब हमारी सरकार आई, तो सड़कें चकाचक और जानदार बन गईं। लेकिन पिछली सरकार ने, जब-जब भी मैं आया हूं तो मुझे तो सड़कों का काम ही मिला है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है तो सड़कों का सुदृढ़ीकरण होता है, नई सड़कें बनती हैं। पहले मेरी विधान सभा गंगरार थी, उस समय भी सड़कों की स्थिति खराब थी तो दोनों बार मुझे सड़क सुधारने का अवसर मिला और उस समय सड़कों का काम हुआ। इस बार भी जो सड़कें हमको विरासत में मिली हैं कपासन विधान सभा क्षेत्र में, बड़ी जर्जर हालत है।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

मैं निवेदन करना चाहता हूं, जितनी भी सड़कें अभी बनी हुई हैं मेरे क्षेत्र में, बड़े हालात खराब हैं। उसके पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं और हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस बजट के प्रावधान में 20,000 किलोमीटर सड़कें पीपीपी मोड पर बनाने का लक्ष्य अपने हाथ में लिया है। मैं यह सोचता हूं कि ऐतिहासिक कदम है और इसके माध्यम से सम्पूर्ण राजस्थान में जो सड़कें बनेंगी, क्वालिटी वाली बनेंगी और लम्बे समय तक चलेंगी और आठ वर्ष तक इसकी गारंटी भी रहेगी।

पहले के शासनकाल में हमने उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान को जोड़ने के लिए एक जीवन रेखा टाइप सड़क बनाई थी और एक सड़क का अभी ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर बनाने के लिए बजट में प्रावधान रखा है। एक बड़ा काम किया कि जिस प्रकार से शहरों के अन्दर सड़कें जानदार बनी हुई हैं, बढ़िया क्वालिटी की सीमेंटेड सड़कें, डामर की सड़कें बनी हुई हैं, रबर की सड़कें बनी हुई हैं, उसी प्रकार से गांवों के अन्दर भी गौरव पथ बने। एक कल्पना की थी वसुन्धरा जी ने और बजट में प्रावधान रखा। 0.5 किलोमीटर से लगाकर...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको डिमांड्स रखनी है अपनी, बजट पर चर्चा नहीं।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): दो मिनट में रख रहा हूं। दो किलोमीटर तक गौरव पथ बनेगा तो शहरों के मुकाबले गांव भी सुदृढ़ सड़क से जुड़ जायेगा। मैं ज्यादा बात नहीं कहता हुआ, मैं इतना ही निवेदन करूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी कई गांव गौरव पथ से जुड़ेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्राथमिकता के आधार पर लेकर इन गांवों को जोड़ें और 250 से 500 की आबादी तक के गांव मेरे विधान सभा क्षेत्र में शेष बचे हुए हैं, ये भी जोड़ने का प्रयास होगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में सांवलियाजी मंदिर मण्डल है और वहां सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए 50 प्रतिशत सरकार की और 50 प्रतिशत राशि मंदिर मण्डल के द्वारा दी गई। 1993 में हमने नौ करोड़ रुपये के लगभग सरकार के पास जमा करा दिये लेकिन वह काम बड़ा धीमी गति से चल रहा है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इन कामों को प्राथमिकता के आधार पर लेकर सड़क तुरन्त बना दी जाये ताकि वहां पर हर महीने, हर रोज हजारों की संख्या में यात्री आते हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि ये जल्दी से जल्दी पूरी हो जाये।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

मेरे क्षेत्र में जो सड़कें मुझे मिली हैं, उन सड़कों की एक लम्बी-चौड़ी लिस्ट मैंने मंत्री महोदय को दी है, लेकिन एक बार यहां पर बोलना अति आवश्यक हो गया है। जो सड़कें अभी वर्तमान में जिनको चौड़ी करने की आवश्यकता है, सात मीटर तक बढ़ाने की आवश्यकता है, कारो से कपासन वाया राशमी सड़क, नारेला से गोपालपुरा, मातृकुण्डिया से सूरजपुरा, कीर की चौकी से फतहनगर वाया आकोला, कपासन से बासोड़ा वाया शनि महाराज, राशमी से हमीरगढ़ वाया मरमी माताजी। एक धार्मिक स्थल है मरमी मातेश्वरी का और शनि महाराज का भी सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। कपासन से बासोड़ा वाया गुमानपुरा, कपासन से बोबास वाया जाशमा, कपासन से सूरजपुरा वाया दोमनी। इन सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जाये ताकि आवागमन के साधन सुलभ हो सकें।

जो सड़कें बिलकुल टूट गई हैं, आज की वर्तमान परिस्थिति में उन पर चलना बड़ा नामुमकिन हो रहा है और बार-बार लिखने के बाद भी, पिछली सरकार ने सड़कों के ऊपर क्या राशि खर्च करनी चाहिए थी, कितनी सड़कें सैंक्शन कर दी, उन पर काम भी चालू नहीं हो पाया और आज की तारीख में ठेकेदार या तो कहीं न कहीं भटक रहे हैं, उनको पैसा भी नहीं मिल पा रहा है।

मेरे क्षेत्र की जो मरम्मत करने की आवश्यकता है, वह सड़कें हैं: कारो से कपासन तक। अभी मुझे जानकारी मिली कि पीपीपी मोड पर कारों से कपासन की सड़क को हम ले रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि यह बनास नदी के किनारे-किनारे वाली सड़क है और यहां पर प्रतिदिन बनास नदी से बजरी से भरकर लगभग 100-200 ट्रक जो क्षमता से अधिक, जो 18 टन पास है, वे 40 टन लेकर जाते हैं और उससे सड़क बिलकुल जर्जर हालत में हो गई है। एक-एक, डेढ़-डेढ़ फीट के गड्ढे पड़ गये हैं तो मैं चाहता हूं कि उस सड़क को माइन्स रोड के अन्दर लेकर, खनिज विभाग के द्वारा लेकर इस प्रकार से बनाया जाये कि आम आदमी पर उसका टोल टैक्स नहीं लगे और जो बजरी से भरे हुए ट्रक जा रहे हैं, ट्रैक्टर जा रहे हैं, उनसे टोल टैक्स लिया जाये तो ठीक रहेगा।

गोपालपुरा से नारेला वाया मातृकुण्डिया 37 किलोमीटर की सड़क है। मातृकुण्डिया बहुत बड़ा तीर्थ है। वहां की स्थिति भी बड़ी खराब है। राशमी से नेवरिया वाया हमीरगढ़, राशमी से भीमगढ़ जाडाना वाया रूढ, गंगरार सड़क, उपरेड़ा से जाडाना, मातृकुण्डिया से डिंडोली, पौना से लसेड़िया, मातृकुण्डिया से

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

सूरजपुरा, कपासन से सूरजपुरा वाया धमाणा, राशमी से जाशमा, निम्बाड़ा से भीमगढ़ वाया लांगच, हीराजी का खेड़ा से कूथना लुहारिया बासोड़ा 7 किलोमीटर, सांकली से आरणी वाया सोमी, छापरी से जिद्या, आकोला से सूरजपुरा वाया भोपालसागर, कपासन से हतयाना वाया रूपाखेड़ी, आकोला से उमण्ड, हतयाना सड़क, ये शनि महाराज होकर निकलेगी। भोपालसागर से रोल्या वाया बबराना, कीर की चौकी ताणा आकोला फतहनगर सड़क, बूल का खेड़ा से रामाखेड़ा तक सड़क, जाशमा से ढाणी, मटुणिया से फलासिया, उसोल से धरेवा वाया लूणेरा, ये सीधी-सीधी राजसमन्द को जोड़ने वाली सड़क हैं। मरौली से लसाड़ियाखुर्द राशमी बाइपास, लसाड़ियाखुर्द से मरमी, आहारणी से पवनी, आकोला से गुढा, राशमी बस स्टैण्ड पर सीसी कार्य करना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पर बसों का आवागमन रहता है। प्रतिदिन 100-150 बसें वहां आती हैं और गड्ढे में उनको निकलना पड़ता है।

कुछ सड़कें ऐसी हैं, जिन पर सीसी काम कराना आवश्यक है। जो सड़कें, ठेकेदार उन पर काम कर रहे थे, वे छोड़कर चले गये तो रिस्क एण्ड कोस्ट के आधार पर उन सड़कों को आज बनाने की आवश्यकता है। कुछ सड़कें बनी भी हैं लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं, जिन पर सरकार यदि अलग से पैसा दे तो वहां पर सीसी सड़क बनाई जा सकती है। ऐसी सड़कें हमारे यहां हैं।

कुछ पुलिया हैं, जिनको रेज करना जरूरी है और चौड़ाई बढ़ानी भी जरूरी है। बनास नदी पर एक सांकली पुलिया है, जो भीलवाड़ा कपासन रोड को जोड़ती है। एक पुलिया जो शनि महाराज के पास है, हजारों की संख्या में सांवलियाजी और शनि महाराज के यात्री आते हैं। वह पुलिया सिर्फ 10 या 15 फीट चौड़ी है और आज की तारीख में उसकी चौड़ाई नहीं बढ़ाई गई तो कभी भी एक्सीडेंट का खतरा रहता है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि शनि

(14.00 बजे)

महाराज पुलिया की सड़क चौड़ी की जाए। एक सुरपुर पुलिया है वह भी एक धार्मिक स्थल को जोड़ती है यह भी चौड़ी की जाए। एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आज की तारीख में मेरे यहां रासमी उपखण्ड है, कपासन उपखण्ड है, भोबास उपखण्ड है और भदेसर उपखण्ड है। लेकिन यहां पर डाक बंगलों की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ एक डाक बंगला बना हुआ है, दो कमरे बने हुए हैं कपासन में। उसके अलावा न रासमी में, न भोपासनगर में, न भदेसर में डाक बंगला बना हुआ है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सब

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

जगह डाक बंगलों की व्यवस्था की जाए और उनके लिए एक्स्ट्रा कमरे भी दिए जाएं। कुछ सीसी सड़कों की आवश्यकता है जैसे झाडाना सड़क है इस पर सीसी की आवश्यकता है। जितने भी विलेज पोर्शन हैं उन गांवों के अन्दर यदि हम देखें तो हालात इतने खराब हैं सड़कों के कि गांव के अन्दर कीचड़ है। मैं सोचता हूं कि अभी जो ग्रामीण गौरव पथ दे रहे हैं। उन गांवों में इससे स्थिति सुधरेगी। सरकार इन गांवों को ठीक कराएगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी इन मांगों को मानते हुए सड़कों का सुदृढ़ीकरण कराया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री धर्मपालजी चौधरी (अनुपस्थित), श्री रामहेत सिंहजी यादव।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-19 और 21 के बारे में मेरी बात रखना चाहता हूं। जिस तरह से पिछले पांच साल में सड़क नीति बनाई और सड़कों की दुर्दशा रही, सारा राजस्थान भली भांति जानता है। जैसे चुनाव से पहले कुछ फैसले हुए। हमारी लोकप्रिय नेता आदरणीय वसुंधरा जी ने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान उन सब चीजों को देखा और तय किया कि राजस्थान में ऐसी सुंदर सड़कें बनाई जाएं और बजट में प्रावधान किया। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित दो-तीन बात कहना चाहता हूं। कांग्रेस के राज में किशनगढ़ बास से गढ़ी बोलनी चौक तक सैंट्रल रोड फण्ड और इंटर स्टेट में सड़क बनी। 15 करोड़ 34 लाख उसके सैंक्शन हुए। लेकिन कांग्रेस के कुछ मित्र अलवर, भिवाड़ी टोल टैक्स वालों से मिल गए। वह राशि आने के बाद भी उसमें 4 किलोमीटर का पैच छोड़ दिया। आज उसमें सेविंग आई है लेकिन नया गांव से लेकर साहरनवास तक का जो 4 किलोमीटर का पैच है वह नहीं बन पाया और उसमें जो भी गांव है। नया गांव है, साहरनवास है, बीबी रानी है, पुर है, गिकाका है, कोटकासिम है, आलमपुर है और भिलाड़ी जो बड़े गांव उस सड़क पर पड़ते हैं। उसका पानी कहां जाएगा, कैसे ड्रेनेज सिस्टम होगा, नालियां भी नहीं बनाई। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के उस त्रुटिपूर्ण व्यवहार को ठीक करके उस सड़क को बनायें।

दूसरा उदाहरण मैं बताना चाहता हूं रिडकोर द्वारा चुनाव से पहले कांग्रेस के केन्द्रीय नेता, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री ने और माननीय पूर्व मुख्य मंत्री ने घोषणा की कि हम किशनगढ़ से लेकर कोटपूतली तक एक सड़क

(श्री रामहेत सिंह यादव)

बनाएंगे और बजट में उसका 192 करोड़ का प्रावधान रखा। सड़क जो मेरे क्षेत्र में आएगी वह खैरथल में आएगी। खैरथल कस्बे के अन्दर से आएगी और जहां खैरथल नगरपालिका क्षेत्र है उसमें बीचो बीच दिल्ली जयपुर ट्रेन है। लगभग 14 घंटे रेलवे फाटक जहां से यह आवागमन के साधन गुजरेंगे, 14 घंटे तक बंद रहता है। ऐसी हालत में जब उस पर ट्रैफिक भिवाड़ी से डायवर्ट होकर कोटपूतली, किशनगढ़, खैरथल होकर के जाएगा तो उसमें बाइपास बनना आवश्यक था। उसके लिए तखमीने में 125 करोड़ लगभग अनुमानित लागत बताई गई थी।

इसी तरह से जो सड़क बनेंगी जो किशनगढ़ के अन्दर से है, किशनगढ़ बास में से बाजार के बीचो बीच वह सड़क जाएगी वहां पर भी बाइपास बनना चाहिए था। किशनगढ़ और खैरथल के अन्दर जो सीसी रोड बने हैं उसको एक हाइवे और मेगा हाइवे से जोड़ने का पाइंट था लेकिन अदूरदर्शिता का परिणाम है कि किशनगढ़ कस्बे के बीच में जो पाइंट है। जिसको तोप चौराहा कहते हैं वहां तक लाकर उस सड़क को रोक दिया। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अगर खैरथल से आने वाला व्यक्ति अलवर जाएगा तो वह तोप चौराहे के बाद आगे जब निकलेगा तो वह पुराने जो साढ़े तीन मीटर सड़क है उस पर से गुजरेगा। हैवी ट्रैफिक भी नहीं जा पाता। इस तरह से भिवाड़ी जाने वाला हैवी ट्रैफिक आएगा उसको पुरानी जो जर्जर सड़क हैं उसी से गुजरना पड़ेगा। आप टोल भी लेना चाहते हैं और उसको सुविधा भी नहीं देना चाहते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस सड़क में बहुत सारी कमियां हैं। इसमें बजट का प्रावधान है, बजट है। इसलिए खैरथल, किशनगढ़ बाइपास के दोनों सिरों को जोड़ने के लिए इस सड़क को बनाया जाए और दोनों तरफ पानी की निकासी हो। जहां से भी सीसी रोड शुरू हुआ है किशनगढ़ बास में वहां से लेकर बाइपास जो मेगा हाइवे को जोड़े, वहां तक नाली दोनों तरफ बने ताकि ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाए। इसमें जो बाइपास आवश्यक था, न किशनगढ़ में बाइपास का प्रोविजन रखा, न खैरथल में बाइपास का तो इस रोड का औचित्य क्या रहेगा? क्योंकि जहां बनने वाला है वह तो शहर बहुत संकड़ा है। चौबीस फीट से ज्यादा जगह नहीं है उसमें। अगर वहां से जाएगा तो पूरे दिन ट्रैफिक जाम रहेगा। इसलिए दोनों कस्बों खैरथल और किशनगढ़ में बाइपास का प्रोविजन करें। अभी रिडकोर बना रही है उसके बजट को बढ़ाकर के एक अच्छी सड़क यहां बने ऐसा मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। इसी

(श्री रामहेत सिंह यादव)

तरह से अलीपुर सांचोर में जहां पर बीएसएफ का कैंप है। उस अलीपुर सांचोर से जो हरियाणा है पूरा भावल क्षेत्र लगता हुआ है और वहां से खानपुर, डांगरानपुर, नीमला का कलगांव, माजरी हिंगवाडा, सलीमपुर तिजारा, फिरोजपुर तक यह सड़क अगर बन जाती है, जिसमें दो-तीन मिसिंग लिंक भी हैं। लगभग दो किलोमीटर एक जगह है और एक किलोमीटर एक है अगर इसको सारे को बना दिया जाता है तो जो एनसीआर में क्षेत्र आता है, जो बावल, शाहजहांपुर, तिजारा ट्रैफिक जाना चाहता है उसको एक अच्छा रोड़ मिलेगा। इसलिए सड़क बनी हुई है, कुछ मिसिंग लिंक है उसको अपग्रेड करके एमडीआर में चेंज किया जाए।

इसी तरह से अलवर से अगर किसी को खैरथल जाना है या हरसौली जाना हो तो वाया ततारपुर चौराहा घूमकर के लगभग 46 किलोमीटर जाना पड़ता है। इसी तरह से अलवर से किशनगढ़ होकर के जाएगा तो भी उसकी यही हालत है। जबकि अलवर से खैरथल की दूरी मात्र 17 किलोमीटर है। मेरा आग्रह है कि विजय मंदिर अलवर से और वाया बल्लभग्राम होकर के खैरथल और खैरथल से हरसौली और बीबीरानी तक सड़क इतनी महत्वपूर्ण है। यह बीच की जो आबादी है जिसमें मुण्डावर, तिजारा और अलवर ग्रामीण विधान सभा को फायदा मिलेगा। इसलिए मेरा आग्रह है इसको भी तीन मीटर से सात मीटर कर एमडीआर में कन्वर्ट किया जाए। इसी तरह से किशनगढ़ से लेकर रामगढ़ की तरफ जाने वाला व्यक्ति है, वाहन है, वहां कांग्रेस के नेताओं ने खूब घोषणा की और कहा कि जब तक हम मेवात में नहीं घुसेंगे, मेवात के वोट लेने के लिए तो हर समय रहे लेकिन एक भी सड़क पूरे पांच साल में मेवात क्षेत्र में नहीं बनाई। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि जब भी सड़क नीति आप प्लानिंग करें तो किशनगढ से मोठूका, भागौर मुबारकपुर नौगांवा तक अगर एमडीआर में सड़क बनती है तो एनसीआर के लोगों को इससे फायदा मिलेगा और इसके अलावा जो और सड़कें हैं, जैसे गंज से ईस्माइलपुर जोड़िया, भोकर से बासकृपाल नगर, जटयाणा से जाटुवास, आकोली, जगतबसी से राहतखुर्द आदि। मेरे जगताबसी जो ग्राम पंचायत हैं, वह न तो तहसील मुख्यालय से जुड़ी हुई है और ना ही उपखण्ड कार्यालय से जुड़ी हुई है।

लेकिन जब सरकार की नीति है इसलिए मैं कहना चाहता हूं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि जब भी सड़क तय करें, नीति निर्धारित करें और

(श्री रामहेत सिंह यादव)

जब भी आवश्यकता हो तो मेरी यह सड़क पर ध्यान रखें ताकि मेरा पंचायत मुख्यालय अपने उपखण्ड कार्यालय से जुड़ सके।

इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि मैं पिछली विधान सभा में पांच साल तक कांग्रेस के माननीय मंत्री और मुख्य मंत्री से कहता रहा कि मेरे यहां पर उपखण्ड कार्यालय कोटकासिम है। कोटकासिम उपखण्ड कार्यालय में पिछले आठ-दस साल से एसडीएम, एसीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार ये चार प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं। बीडीओ, एईएन वगैरह के आफिस भी सब हैं लेकिन एक भी प्रशासनिक अधिकारी का वहां पर निवास नहीं है। पिछली सरकार ने जब विधान सभा में रखा तो मात्र दस लाख रुपये एसडीएम के लिए रखा और वहां के पीडब्ल्यूडी विभाग ने कह दिया कि दस लाख में ये निवास नहीं बन सकता इसलिए प्रशासनिक अधिकारी को वहां पर रहने में असुविधा रहती है। वहां जगह नहीं है एसडीएम तो तहसील का फोर्थ क्लास का जो पहले का कमरा था उसमें एक छोटा सा कमरा और बनवाकर रहता है। इसी तरह से तहसीलदार है वो वहां पर तहसील में जो जमादार था उसके कमरे में रहता है। हालत ठीक नहीं है और एसीएम की जब पोस्टिंग हो गई थी तो यह दिक्कत थी कि एसीएम साहब को रखा कहां जाए। उसका निवास कहां हो तो बड़ी मुश्किल से आग्रह करके जिलाधीश महोदय से उनको हास्पिटल में एक डाक्टर का निवास खाली था वहां पर उनकी व्यवस्था की थी। इसलिए मेरा आग्रह है मंत्री महोदय से कि साठ-साठ लाख रुपये इनके आवास के लिए निश्चित रूप से तय करें। इसके अलावा भी न तो किशनगढ़ और न ही कोटकासिम में कोई डाक बंगले की व्यवस्था है इसलिए आये दिन प्रशासनिक अधिकारी भी आते हैं और भी कोई कार्यक्रम होता है या ट्रांसफर होने के बाद एक प्रशासनिक अधिकारी आता है दूसरा उसका निवास है उसको खाली करने में थोड़ा समय लगता है इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से दोनों जगह डाक बंगलों की आवश्यकता है।

इसके अलावा एक अलीपुर सांचोर में जो हरियाणा बार्डर पर गांव है उसमें बीएसएफ का ट्रेनिंग सेन्टर है। वहां के सैनिक अधिकारियों ने भी चूंकि यह केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है। रक्षा मंत्रालय से इसका बजट भी आ सकता है अगर पीडब्ल्यूडी नहीं बनाये तो रक्षा विभाग को भी पहले से अनुशंसा की गई है और पीडब्ल्यूडी बनाती है तो और भी अच्छा है कि वहां से अलीपुर सांचोर से और खानपुर मेवली बड़सारा कोटकासिम को जोड़ा जाए।

(श्री रामहेत सिंह यादव)

उनके आवागमन की महती आवश्यकता है, वर्ना जो भी उस ट्रेनिंग कैम्प में आएंगे बीएसएफ के अधिकारी या उनके जवान उनको हरियाणा बार्डर से घूम कर आना पड़ेगा। मेरे क्षेत्र की ये समस्याएं थीं जो मैंने आपके सामने रखीं, जब भी आप तय करें बजट तो मेरे क्षेत्र का ध्यान रखें। पिछले पांच साल बहुत उपेक्षा हुई है, उस उपेक्षा की भरपाई हो जाए और किशनगढ़ की जनता को राहत मिल जाए इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना थी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र पाल सिंह।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): मैं मैडम, खाना खाने चला गया था।

श्री सभापति: देखिये अब आपका आखिरी में आएगा नम्बर।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): पहले बताया नहीं था मैडम, इतना सख्त निर्णय न लें।

श्री सभापति: श्री सुरेन्द्र पाल सिंह। (अनुपस्थित) वो भी नहीं हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): इतना सख्त निर्णय न लें मैडम, ऐसा पता नहीं था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, पांच बोल लिये उधर से।

श्री सभापति: मेरा सरकार से यह निवेदन है कि जिनके नाम दिये जाते हैं बोलने के लिए वो सदन में बैठें। जो नाम देते हैं, उन्हें बोलना है तो उन्हें सदन में बैठना है। ये नहीं हो सकता है कि वो सदन में न रहें, अनुपस्थित हों और फिर बाद में आकर बोलें। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): खाना खाने चला गया था, मैडम।

श्री सभापति: चलिये बोलिये श्री धर्मपालजी चौधरी। आइंदा इस बात का ध्यान रखें।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): बिलकुल साहब।

माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य और 21...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, पांच को बुला दिया और लास्ट में बुलाना चाहिए था। कम से कम इतनी सजा तो इनको होनी चाहिए थी कि एक इधर से बुलाकर फिर बुलाते।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): अब चार जने आप बैठे हैं तो सारे के सारे को बुलवा देते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चीफ व्हिप महोदय ने बैठे-बैठे इशारा कर दिया बुला दो। ऐसे तो व्यवस्था भंग हो रही है।

श्री सभापति: नहीं-नहीं ऐसा नहीं है। आप बैठें। आइंदा इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उपस्थित रहें जिनको भी बोलना है, जिनका नाम है लिस्ट में।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): लक्ष्मणगढ़ से आने वाले विधायक जी हर बात में बोलना बहुत जरूरी है क्या?

श्री सभापति: चलिये बोलिये आप। माननीय सदस्य श्री धर्मपाल जी चौधरी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लेट आना जरूरी है क्या?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आसन के अधिकार असीमित हैं माननीय प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय। आसन ने जिनको पुकार लिया वो पुकारा जा सकता है इसलिए आप इसमें क्यों दखल कर रहे हो?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): स्वीकार है ना पर बात तो रख ही सकते हैं हमारी।

श्री सभापति: आप बैठें। दोनों आपस में चर्चा न करें माननीय सदस्य बोल रहे हैं सुनें।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): मांग संख्या-19 व 21 पर विचार हो रहा है उसमें आपने मेरे पर जो क्षमा बख्शी और समय दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। पुराने जमाने में सड़कों की आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि उस जमाने में गाड़ी मोटर व्हिकल्स बहुत कम होते थे। ऊंटगाड़ी और बैलगाड़ी से सफर करते थे। अब ये जमाना इक्कीसवीं सदी का आ गया। इस इक्कीसवीं सदी के जमाने में सड़कों की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ गयी क्योंकि हर घर में मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर सब साधन आज गांव में हो गये हैं। ऐसी स्थिति में सड़कों का बनना बड़ा महत्वपूर्ण और आवश्यक हो गया है। सरकार द्वारा बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बीस हजार किलोमीटर की सड़कों के बारे में कहा कि पीपीपी माडल पर इन सड़कों का हम निर्माण करेंगे। ये सब सारी सड़कें बन कर तैयार होंगी तो वास्तव में गांव में रहने वाले व्यक्ति को भी बाजार में अपना सामान ले जाने के लिए ट्रैक्टर के साधन को

(श्री धर्मपाल चौधरी)

यूज करने के लिए और आने-जाने के आवागमन के साधन का फायदा मिलेगा। राजस्थान के अन्दर जब प्रधानमंत्री सड़क योजना चालू हुई थी उस समय हमारी सरकार थी और राजेन्द्र राठौड़ जी मंत्री थे और दोनों के लिए हिन्दुस्तान में राजस्थान पहले नम्बर पर रहा था। पिछले पांच साल के राज में कांग्रेस के राज में जितनी सड़कें बनीं, हमारे राज में जब मैं पहले विधायक के रूप में था 2003 से 2008 तक जो सड़कें बनी हुई हैं वो सड़कें भी अच्छी हैं इनके पांच साल के राज से जितनी सड़कों का निर्माण हुआ वहां पर सड़क नाम की कोई चीज नहीं है इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो सड़कें गारंटी पीरियड में हैं, जिनकी गारंटी अभी बाकी है उन सड़कों के ऊपर उन ठेकेदारों से काम कराना चाहिए। वो समय निकल जाएगा पांच साल बीत जाएंगे। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी उन पर ध्यान देते नहीं हैं। ऐसी सड़कों पर ध्यान देना सबसे पहले जरूरी है।

दूसरा टोल माफिया जिस तरह से पनपा है। ये टोल आगे पीपीपी माडल पर और भी लगने जा रहे हैं लेकिन जिस तरह से पहले शराब माफिया के रूप में पूरे प्रदेश में चर्चा हमेशा रहती थी, आज टोल माफिया सबसे बड़ा माफिया हो गया। मन चाहे दाम लेते हैं। अभी नीम का थाना में टोल लगा है उस टोल पर जो लोग पहले कांग्रेस के राज में टोल वसूली करते थे गुंडागर्दी से, आज वो ही लोग दुबारा उसमें टोल वसूल करने लगे हैं। मनमाना टोल वसूल करते हैं और इस तरह की गुंडागर्दी हो रही है तो माननीय मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि इस टोल माफिया से भी राजस्थान की जनता को बचाना पड़ेगा आपको। ये टोल माफिया आने-जाने का टोल एक साथ ही ले लेते हैं, उनका बस पड़े तो कितना ही पैसा उससे वसूल कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको एक नीति बनानी पड़ेगी कि जो आपने सड़क बनायी है पीपीपी माडल पर और वहां टोल लगाया है उस टोल की वसूली अगर गलत हो रही है, शिकायत अगर मिलती है तो उन पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही करने की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। बाकी सड़कें जो बन रही हैं वो सड़कें अच्छी गुणवत्ता की बनें। जिस तरह से गुजरात में यह कहते हैं, गुजरात में भी जाने का मौका मिलता है। गुजरात, महाराष्ट्र और दूसरे प्रदेशों में सड़कों की ठीक स्थिति है। राजस्थान में भी आज जितनी भी सड़कें बनें उन सड़कों पर अगर कोई भी अधिकारी-कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उनके तनख्वाह से जिस दिन पैसा वसूल होना चालू होगा, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार इस

(श्री धर्मपाल चौधरी)

डिपार्टमेंट में है, नीचे से लेकर ऊपर तक परसेंटेज में जो काम चलता है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप मेज थपथपा रहे हैं, पांच साल में किया नहीं। सात महीने हो गये हम मंत्रीजी को कह रहे हैं कि आपने जो कुछ किया वैसा ये नहीं करें। आपने तो मेजें थपथपाई, पांच साल तक जो सड़कों की हालत रही है न आपके कार्यकाल में लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, वो सब जनता के सामने है। आप जिस तरह के खड्डे छोड़ कर गये उन खड्डों को भरने की आवश्यकता है और उन खड्डों को भरने के साथ-साथ गुणवत्ता की अच्छी सड़कें बनाने की भी आवश्यकता है। इसलिए हमारी सरकार, हमारी मुख्य मंत्रीजी और हमारे मंत्रीजी का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहते हैं कि टोल माफिया और सड़कों की गुणवत्ता दोनों पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा और ध्यान देने के बाद जो भी सड़कें बनेंगी वो लम्बे टाइम तक चले इसकी सबसे बड़ी जरूरत है।

मेरे क्षेत्र के बारे में मैंने आपको कटौती प्रस्ताव के माध्यम से, 295 के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से जो-जो भी सड़कें हैं, उन सड़कों पर काम करने के लिए लिखकर दिया है कि जो सड़कें बनी हैं उनकी हालत क्या है। आप उन सड़कों की जांच करवाएं और जांच करवाकर जो दोषी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें। चार-चार साल हो गए उन सड़कों को बने हुए। उन सारी सड़कों पर गारंटी पीरियड का समय बाकी है। अफसरों से कहकर, जो उनके ठेकेदार थे उन ठेकेदारों से उन सड़कों को ठीक करवाने का काम कर लें अन्यथा एक साल बाद उनकी समय सीमा खतम हो जाएगी। लीपा पोती होकर सरकार का वह पैसा ठेकेदार के खाते में चला गया, ऐसी स्थिति में आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि ठेकेदारों को जिस तरह से ब्लैकलिस्टेड पर डाल देते हैं और वह अपनी पत्नी के नाम से, परिवार के नाम से, रिश्तेदारों के नाम से दुबारा कोई न कोई फर्म बना लेता है और उस फर्म के माध्यम से फिर वही चोरी का धन्धा करता है। नया लाइसेंस देते टाइम भी यह देखने की आवश्यकता है कि आप जो लाइसेंस दे रहे हैं क्या दुबारा उस चोर ठेकेदार के किसी रिश्तेदार को तो नहीं दे रहे? वह ठेका जो दिया जा रहा है वह उस पुराने ठेकेदार को न मिले। उनके खिलाफ अगर सख्त से सख्त कार्यवाही होगी तभी जाकर इन सड़कों का काम पूरा होगा। इसलिए आपसे मेरा यही निवेदन है कि अच्छी गुणवत्ता की सड़कें और टोल माफिया दो के खिलाफ तो आप तुरन्त कार्यवाही करें। मैंने

(श्री धर्मपाल चौधरी)

कटौती प्रस्ताव आपको दे रखे हैं, आप स्वयं उसको देख लेंगे। मुझे आप पर पूर्ण भरोसा है। आप युवा मंत्री है, टोल माफिया, गुणवत्ता की सड़कों को बनाने पर आप ध्यान देंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री गोविन्द सिंह जी डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदया, समय देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अपनी बात 10-15 मिनट में संक्षिप्त कहूंगा। सभापति महोदय, हमारी सदन की माननीय नेता मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें पैरा 7 है उसमें सड़कों का वर्णन किया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जो दो-चार बातें उठाऊं उसका आप जब रिप्लाई दें तो जरूर उल्लेख करें कि क्या स्थिति है। आपने इसमें लिखा है कि राज्य सरकार ने लगभग 7 हजार किलोमीटर सड़कों की डीपीआर बनाने का कार्य आरम्भ किया है, इन सड़कों का विकास कार्य इस वर्ष शुरू हो जाएगा, 2017 तक सभी 20 हजार किलोमीटर की सड़कों के कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। यानी 20 हजार किलोमीटर के 2017 तक केवल शुरू किए जाएंगे, बनाये नहीं जाएंगे। दूसरा आगे लिखा है कि इस कार्यक्रम के तहत राज्य में प्रतिदिन औसतन 15 किलोमीटर सड़क की लम्बाई का कार्य होगा। पांच साल में 1825 दिन होते हैं और अब तक 7 माह में 210 तो सरकार को काम करते हुए हो गए, तो मंत्री महोदय कृपया यह भी बताने का कष्ट करें कि 210 दिन में इस राजस्थान की प्रदेश की बीजेपी सरकार ने, जिनके आप मंत्री हैं, कितने किलोमीटर की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां जारी कीं और कितने के टैण्डर कराकर कार्य चालू करा दिए, यह तो मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा।

तीसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार ने आते ही हमारे कार्यकाल में जितनी सड़कें प्रदेश में स्वीकृत की गई थीं वर्ष 2013-14 में उनमें से सीकर जिले की लगभग 35-36 सड़कें थीं, मेरे विधान सभ क्षेत्र की मात्र 3 सड़क थीं, सभापति महोदय, मंत्री महोदय भी सीकर जिले से ही आते हैं और प्रदेश की उन तमाम सड़कों को राजनैतिक द्वेषता के आधार पर निरस्त करने का काम किया। क्या उन सड़कों पर केवल कांग्रेस के लोग चलते थे, क्या आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चलेंगे, तो इस तरह की राजनैतिक द्वेषता कम से कम पानी, सड़क, बिजली में तो मत रखो। ट्रान्सफर, पोस्टिंग में रख लो। मंत्री बनाने में रख लो। जो मंत्री नहीं है उसको भी मंत्री

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

रख लो, वह काम तो आप करो, छोटा मंत्रिमण्डल रख लो, वह तो आपका विशेषाधिकार है लेकिन उन गांव के लोगों ने क्या गुनाह किया था यह मैं पूछना चाहता हूं। सभापति महोदय आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उन सड़कों की जिनकी वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई थी, जिनके टैण्डर हो गए थे और केवल एक लेकुना बताकर, टैक्नीकल कमी निकालकर कि हमने टैण्डर का एप्रूवल नहीं किया, क्यों नहीं किया आपने टैण्डर को एप्रूव? जो स्थिति बनी है वह मैं आपसे निवेदन करता हूं।

श्री सभापति: एक मिनट, माननीय सदस्य जो पीछे बैठे हैं थोड़ा सा, डिस्टर्ब हो रहा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 2013-14 में 2242.72 करोड़ के प्रावधान के अगेन्स्ट में 1886.06 करोड़ दिसम्बर तक खर्च हुए थे। जब पैसे बचे हुए थे तो आपने केवल यह कहकर कि साहब वित्तीय प्रावधान नहीं था इसलिए हमने इन सड़कों को निरस्त कर दिया। अब तो आप 20 हजार किलोमीटर बनाने जा रहे हैं, अब तो आपके पास बहुत पैसा आ गया है, तो कम से कम उन सड़कों को चालू कराने का काम करें।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपका यह पीपीपी मोड और 8 साल का सम्भागीय स्तर पर जो रखरखाव का है इसमें बहुत बड़ा घपला होने जा रहा है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो ठेकेदार यहां प्रदेश में काम कर रहे हैं वह ठेकेदार, मैं 10-20 की तो कहता नहीं बाकी कोई काम नहीं करता, छोटे ठेकेदारों को सबलेट करते हैं। एक एक जगह नहीं बल्कि तीन-तीन जगह सबलेट होता है। जो गांरटी पीरियड होता है उसमें वह सड़क ठीक नहीं करता क्यों कि वह तो सबलेट किया हुआ है, उसने जितना काम किया उतना पैसा लेकर चला गया। मूल ठेकेदार जो सबलेट करता है वह इसलिए काम नहीं करता है कि उसको तो जो पैसा आखिरी में मिलना है वह पैसा उसका प्रोफिट है, उसने तो दूसरे को काम दिया था, उसको तो कुछ करना नहीं है। इसलिए जो गारंटी पीरियड़ में होती है उन सड़कों को भी ठीक नहीं किया जाता। जब गांव के लोग, हम जन-प्रतिनिधि कहते हैं तो यह कहा जाता है कि हमारे गारंटी पीरियड़ में आपको क्या चिंता है, जैसी बनाएंगे पैसा हमारा लगेगा, दुबारा बना देंगे और गारंटी पीरियड़ में यह काम नहीं करते।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

बोर्ड लगा देते हैं कि इतने तारीख को शुरू होगा कार्य, इतने करोड़ का होगा, यह ठेकेदार होगा, एक्स ईएन के यह नम्बर है, ए ईएन के यह नम्बर है, और इतनी समयावधि में इसको पूरा कर देंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह ठेकेदार जिस दिन रोड समाप्ति की अवधि होती है उस दिन तो काम शुरू ही नहीं करते हैं और विभाग के जो अधिकारी हैं वह मिलकर उसको दो-दो साल, तीन-तीन साल जब गारंटी अवधि पूरी हो जाती है तब तक उन सड़कों को बनवाते रहते हैं। न कोई पैनल्टी है और न उन ठेकेदार के खिलाफ किसी तरह का डीबार करने का एक्शन लिया जाता है। हमारे शासन में भी मैंने बार-बार लिखा, मेरे विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में जो ठेकेदार थे उन्होंने काम नहीं किया, हमने बार बार यह कहा बोर्ड तो लगा पड़ा है, गांव वाले हमें कहते हैं आपका जन-प्रतिनिधियों का कमीशन है क्या, यह कह रहा है इतने में बना देगा और आप बना नहीं रहे हो, तो निश्चित रूप से इसमें रोक लगाने की आवश्यकता है। मंत्री महोदय में जज्बा है, जवान है, मेरी पंचायत के भी हैं, जिले के भी हैं, मैं चाहूंगा आप इन ठेकेदारों पर रोक लगाइये। तीसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, पीपीपी मोड की बात, हमारी सदन की नेता ने जो बजट रखा उसमें पीपीपी मोड की बात है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक मिनट, एक मिनट...

श्री सभापति: कुछ कहना चाहते हैं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं आपको बता दूं मैं इनके विधान सभा क्षेत्र से आता हूं इसलिए यह बार-बार चर्चा करते हैं। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं, यह मेरे से एक क्लास सीनियर थे और इनके पिताजी मेरे गुरु थे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अब तो तसल्ली हुई आपको। अब मेरी सड़कें स्वीकृत हो जाएंगी, अब मेरी सड़कें स्वीकृत करें तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, यह दोनों एक हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, यह पीपीपी मोड की बात कर रहे हैं, बजट तो रख दिया लेकिन पीपीपी मोड की क्या स्थिति है, आज हमने सुना है कि हमारे केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी 16

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे चुके हैं और कोई ठेकेदार आने को तैयार नहीं है। यह आपकी पी.पी.पी. मोड की स्थिति है। जब केन्द्र की सड़कें लेने के लिए तैयार नहीं है तो आपके यहां पर कौन आएगा? आप आठ साल के लिए ठेका दे रहे हो, सौ करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहे हो और जो शर्तें लगायी जा रही हैं माननीय सभापति महोदया, यह बहुत ही गम्भीर मुद्दा है। राजस्थान का एक भी ठेकेदार, एक भी कांट्रैक्टर उसमें एप्लाई नहीं कर सकता है। वह एलिजिबल नहीं है और ऐसे-ऐसे लोग आएंगे कि पांच-पांच, सात -सात जगह सब-लेट करेंगे। सड़कों की वह हालत हो जाएगी कि हम 21 तो आ गये, आप तो 21 भी नहीं आओगे।

अभी क्रांति आ रही थी। लाडपुरा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे पता नहीं कि क्या क्रांति आ गयी और सीना तान कर कह रहे थे, कहां क्रांति आ गयी? आपने इन सात महीने में अगर एक किलोमीटर सड़क की स्वीकृति दी हो और एक किलोमीटर सड़क बनायी हो तो ...(व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): लाडपुरा या लाडू? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके पास बैठते हैं तो आपको ज्यादा पता है।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदया, मुद्दे पर आता हूं मैं कि हमारे लक्ष्मणगढ़ से सीकर की एन.एच. जो शायद पहले 11 थी, अब 52 कर दिया, उसकी फोर लेन की स्वीकृति हो गयी। वित्तीय स्वीकृति हो गयी। टैंडर हो गया, उसके बावजूद भी, 13 दिसम्बर को माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने शपथ ली थी, आज तक एक रुपए का काम, एक इंच का काम उस सड़क का चालू नहीं हुआ है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्यों नहीं हुआ? उसको बंद कर रहे हैं? तो यह बात भी माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं।

तीसरा, जो धार्मिक सड़कें हैं। ठीक है अच्छी बात है कि धार्मिक सड़कों को ठीक कीजिए। लेकिन उनके चारों तरफ आप पेड़ लगाइए। इससे फायदा क्या है कि धार्मिक स्थलों पर पैदल ज्यादा जाते हैं। अच्छी सड़क होगी तो उनके चलने में दिक्कत नहीं होगी। उनको कहीं पर बैठना पड़े, आराम करना पड़े तो कम से कम उनके लिए भी वह ठीक रहेगा और यह अच्छा भी लगेगा। उनको सुविधा भी होगी।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो पूर्व सरकार ने सबको सड़कें दी थीं। पहले बजट में भी दी थी। दूसरे बजट में भी दी थी।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): नहीं दी दूसरे में, पहले में ही दी थी। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पहले में दी। आपने तो पहले में भी नहीं दी।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): देंगे, जरूर देंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जो हमारी सड़कें थीं, वह निरस्त कर दीं और आपने एक किलोमीटर का प्रोविजन नहीं रखा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है कि राजनीतिक दुर्भावना से यह कार्य किए जाएंगे। दूसरा काम नहीं करने जा रहे हैं, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय सभापति महोदया, मिथ्या भाषण हो रहा है। मेरी कांस्टिट्यूएंसी में 265 किलोमीटर सड़क जून के अन्दर स्वीकृत हुई है, यह मैं यहां पर बैठकर घोषणा करता हूं कि यहां पर हुआ है। 265 किलोमीटर। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, एक मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोटपूतली से लेकर कुचामन, डीडवाना तक जो मेगा हाइवे है, वह मेगा हाइवे शुरू कर रहे हैं। लेकिन, सीकर में शहर से होते हुए उसको निकाला गया है। सीकर का नवलगढ़ रोड जो पिपराली रोड की पुलिया है उसको चौड़ा करने का प्रावधान था लेकिन चौड़ा नहीं किया गया है। उसको नवलगढ़ रोड पर भी नीचे उतारना चाहिए और उस पुलिया को चौड़ा करना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वह कार्य भी करायें।

तीसरा, एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है टोल। अभी माननीय सदस्य धर्मपालजी चौधरी साहब ने एक बात रखी कि यह टोल में क्या होता है साहब, कि डोल में ही तो घोल होता है। घालमेल जितना है वह टोल में ही है। टोल में विभाग के अधिकारी ठेकेदार से मिलकर कहते हैं कि तेरे कितने में पोषाता है और मेरे को क्या दे सकता है? उस हिसाब से बजट बता दे। आकड़े जो प्रतिदिन, जो साधन वहां पर आते हैं, आज साधन तो बढ़ रहे हैं दिन-रात, वह टोल भी बढ़ रहा है तो दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? जब साधन बढ़ रहे हैं,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

इसका मतलब उनकी आमदनी ज्यादा हो रही है तो टोल का पैसा घटना चाहिए। वह नहीं घटकर यह कहते हैं कि साहब, इसमें तो महीने में पांच हजार साधन ही आएंगे। विभाग का कोई सिस्टम नहीं है। यह निश्चित रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि जहां पर आप टोल लगा रहे हो, आप लगाओगे हमारे कहने से रुकोगे तो है नहीं। हम तो कहते हैं कि मत लगाओ टोल, लेकिन लगाएंगे। अगर, टोल लगेगा तो उसमें कम से कम ऐसी एक स्वतंत्र एजेंसी मानिटरिंग करे कि टोल, जितने साधन वास्तव में वहां आते-जाते हैं उस समयावधि में, उसके हिसाब से होना चाहिए। लक्ष्मणगढ़ से धानमी तक टोल रोड बनी हुई है। आज उस टोल रोड की यह स्थिति है कि साढ़े तेरह करोड़ रुपए लगे हैं माननीय सभापति महोदया, मंत्री महोदय, उसमें आप कभी पधारो तो आप देखना कि उसमें आज हजारों खड्डे पड़े हुए हैं। वे पैसा ले रहे हैं। पांच साल के लिए पैसा लेंगे, 54 महीनों के लिए और सड़क को ठीक नहीं करते हैं। अब किस-किस से झगड़ा करो? और यह जो टोल माफिया है न यह पनपेगा इस पी.पी.पी. मोड से, इस पर चैक लगाने की आवश्यकता है।

तीसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि जो क्वालिटी है वह सड़कों की ठीक रहे। बनती नहीं है उससे पहले उखड़ जाती है। जब एक्स.ईएन. को या अधिकारी को कहते हैं तो कहते हैं कि ठेकेदार वापस ठीक करेगा, आपको चिंता नहीं है। लेकिन गांव वाले उस कष्ट को भुगतते हैं माननीय सभापति महोदया, इसलिए प्रत्येक सड़क जो आपकी बन रही हो, आपके विभाग में क्वालिटी कंट्रोल बनाया हुआ है, उस क्वालिटी कंट्रोल से आप चैक करवाइए और उसका सर्टिफिकेट देने के बाद में उस टोल के ऊपर चाहे आप टोल लगा रहे हैं, उस सड़क के ऊपर क्या कर रहे हैं वह आप जानें, लेकिन हर ठेकेदार के लिए जो सड़क बनाता है उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल विभाग, जो आपके डिपार्टमेंट में बना हुआ है, आप अनिवार्य कर दीजिए।

होता क्या है कि जो बिलकुल डैड पोस्ट चाहता है, जो आदमी बिलकुल निठल्ला, निकम्मा, कोई काम अधिकारी नहीं करता है उसको कहते हैं कि मेरे को तो क्वालिटी कंट्रोल में ही चिपका दो, बैठा-बैठा मैं गरम रोटी खा लूंगा मेरे बच्चों के पास में। इसका मतलब यह हुआ कि वहां काम नहीं होता है क्वालिटी कंट्रोल के लिए, वर्ना तो देखो आप लाइन लग जाएगी अगर अनिवार्य कर दोगे तो क्वालिटी कंट्रोल में लगने वाले अफसर मंत्री महोदय और

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

नेताओं के चक्कर लगाने लग जाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको भी दिखवाया जाए।

तीसरा, हमारे नीमकाथाना में, हमारे जिले में जो माइनिंग जोन है वहां पर सड़कों की बदतर हालत है। एक तरफ तो यह टोल वाले माफिया और दूसरी तरफ सड़कों में बड़े-बड़े ट्रोले हरियाणा और दिल्ली जाते हैं। यह सारे के सारे लोग परेशान रहते हैं।

चौथा, यह जो सीकर से जयपुर तक रोड बनी है उसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं, कि जो फोर लेन है अपनी, उसमें कहीं भी कोई सुलभ शौचालय वगैरह का प्रावधान नहीं है। फैसेलिटी काम्प्लेक्स का कोई प्रावधान नहीं है।

दूसरा, जो सम्पर्क सड़कें हैं वे भी राणौली की बंद पड़ी है। आपका पलसाना का जो बाइपास है, वह तीन दफा उसका डाइवर्जन हो गया। कभी कहते हैं कि इधर बनेगा, कभी कहते हैं सिंघानिया यूनिवर्सिटी का दबाव आ गया, कभी कहते हैं कि किसी का दबाव आ गया। आप कब तक बनाओगे इनको? सात महीने में कभी देखा क्या माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपका जिला है। आप उसको देखिए। सोभासरिया कालेज के पास में एक डिवाइडर है, वह कट है उसके बाद में आपको बाजोर, गोरिया जाकर चार किलोमीटर बाद में कट मिलेगा। रोजाना आये दिन वहां लोग रोंग साइड से जाते हैं। माननीय राठौड़ साहब भी उधर से ही आते हैं। अगर एक दिन आप देख लो कि वहां से जितने साधन जाते हैं जो यू-टर्न करने वाले लोग हैं वह तकरीबन-तकरीबन रोंग साइड आकर और चार किलोमीटर तक जाते हैं तो मैं समझता हूं कि वह ठीक नहीं है। इससे दुर्घटनाएं बढ़ती हैं तो इनको भी दिखवाने का काम माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं।

आपकी धार्मिक सड़कों में खाटू श्यामजी, रैवासा स्थित दिगम्बर जैन भवयोदय अतिशय क्षेत्र, जीर्ण माता मंदिर, हर्ष पहाड़ी मंदिर, सीकर से सालासर, लक्ष्मणगढ़ से सालासर यह जो धार्मिक स्थल हैं उनकी सड़कों को ठीक किया जाए, टोल मुक्त किया जाए, और वहां पर पेड़ भी लगाये जाएं।

तीसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लक्ष्मणगढ़ में आप तो मंत्री महोदय, बार-बार पधारते रहते हैं। जो नरोदड़ा से लेकर मालासी तक जब फोर लेन बने तो उसमें डिवाइडर बनना चाहिए क्योंकि वह शहर का हिस्सा है,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

उसमें और शहर के हिस्से में दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होने की सम्भावनाएं होती हैं इसलिए इन चीजों को देखना पड़ेगा।

एक विभाग में जितनी भी पोस्ट्स वेकेंट हैं उन पोस्ट्स को भरने का काम भी करें।

आज भवनों के मामले में, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ का भवन बिलकुल जीर्ण-शीर्ण है। तहसीलदार रेजिडेंस का भवन बिलकुल जीर्ण-शीर्ण है। वहां पर एस.डी.एम. रेजिडेंस का पैसा ही नहीं दिया जा रहा है। आपके सीकर में जो डाक-बंगला है उसमें केवल थर्ड ग्रेड या फोर्थ क्लास के लोग ही रह पाते हैं। कितनी बड़ी सम्पत्ति है अपनी? पहले तो चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्य मंत्री हो, डाक-बंगले में रहते थे। आज क्या हो गया उस डाक-बंगले का? उसमें शाम को छह बजे बाद में दो पव्वे, दो बोतल, मीट और बाकी दो-चार आदमी फोर्थ क्लास के कर्मचारी या ठेकेदार बैठकर शराब सेवन करते हैं। मीट और रोटी खाते हैं। यह स्थिति हो गयी। इसको सुधारने की जरूरत है। आप भी चूरू पधारते हैं और राठौड़ साहब भी पधारते हैं। बीकानेर भी पधराते हैं सारे लोग। तो लक्ष्मणगढ़ में मेन एन.एच. के ऊपर है, उसमें भी डाक-बंगला बनाने का काम, माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री महोदय, गनेड़ी आपका गांव है, जन्म स्थान है। आपका जन्म स्थान है। उसमें मैं कल परसों गया था। आपके घर के सामने तो अच्छी रोड बन गयी, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मंत्री हो और उसके घर के सामने अगर कीचड़ हो तो हमें भी शर्म आती है। हम भी एम एल ए थे, हम नहीं बना पाये। हम इस बात को महसूस करते हैं। अच्छी बना दी पी.डब्ल्यू.डी. वालों ने, लेकिन, माननीय सभापति महोदय, जो गनेड़ी गांव है, उसमें और बोची गांव है, वह बोंची गांव वहां से केवल एक डेढ़ किलोमीटर है, उस सड़क को भी बिलकुल ठीक कराने का काम करें, तो निश्चित रूप से आवागमन, यह स्टेट हाइवे हैं, मैं समझता हूं सालासर से लेकर डीडवाना तक, आपको रोजाना आना-जाना पड़ता है तो कम से कम उस स्टेट हाइवे को भी ठीक करने का काम करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 15 दिन में करवा देंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जय हो, जय हो राठौड़ साहब की। मेडिकल कालेज सीकर में भी जल्दी दिला दो। निश्चित रूप से इन

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

ठेकेदारों पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। पी.पी.पी. मोड पर नहीं जाना चाहिये। अगर जाते हैं तो निश्चित रूप से लोग नहीं आयेंगे, ठेकेदार नहीं आयेंगे। आपकी सड़कें नहीं बनेंगी और जो क्वालिटी कंट्रोल वाली बात है, उसको आपको देखना पड़ेगा। मंत्री महोदय, आपको देखना पड़ेगा कि क्वालिटी कंट्रोल के बगैर सड़क नहीं बननी चाहिये और जो टोल लगाकर अपन प्राइवेट को यह सड़कें दे रहे हैं, उसमें पहले अपने स्तर पर आप चैक करवाइये इस बात को, कितने साधन आते हैं, कितनी आमदनी आ सकती है और इस आदमी ने कितनी सड़क बनाने के लिये कितना पैसा मांगा है। इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं, उनको भी आप ठीक कराने का काम करेंगे तो मैं समझता हूं, चूंकि आदमी पहले तो जन्मदाता, जो माता-पिता हैं, उनका कर्जा चुकाने की चेष्टा करता है, फिर जन्मभूमि का कर्ज चुकाने की चेष्टा करता है और उसके बाद उस तहसील और जिले का कर्ज चुकाकर, उसके बाद जिस पार्टी से राजनीति में आता है, उसका कर्ज चुकाता है। पार्टी पहले नहीं होनी चाहिये। जन्म स्थान, जन्म तहसील और जन्म जिला पहले होना चाहिये। सीकर जिले को ज्यादा बजट मिले, लक्ष्मणगढ़ को सबसे ज्यादा बजट मिले। राजनीति की बात नहीं है। हम कहेंगे सभापति महोदय, हमारे मंत्री महोदय ने बनाया, हमारा कोई योगदान नहीं है। हमने जितना बनाया, उतनी बात करेंगे। जो हमने नहीं बनाया उसके लिये मंत्री महोदय को, सरकार को हम धन्यवाद देंगे इसी सदन में। इसलिये मेहरबानी करके ये जितनी बातें मेरे ध्यान में थीं, मैंने उचित समझीं, मुझे जितना समय मिला, उसमें मैंने बताने की चेष्टा की है। इसलिये माननीय केन्द्रीय मंत्री गड़करी साहब, जो हताश हैं, उस तरह से आपको कल को हताश होना पड़े, पहले से इस बात को सोच लो कि अपने को पी.पी.पी. मोड पर नहीं जाना है। 8 साल का संविदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 8 साल आप रहोगे ही नहीं, हम आ जायेंगे तो फिर आप काहे के लिये बना रहे हो। हम कह रहे हैं न।

श्री सभापति: सम-अप करें अब। आप सम-अप करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हम भी कह रहे हैं न। हम भी माननीय सदस्य हैं, आप भी माननीय सदस्य हो। इसलिये हमारी भी बात रखो। आपने समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय श्री ओटाराम जी।

श्री ओटाराम (सिरोही): आदरणीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19 और मांग संख्या 21 पर मैं विशेष तौर से माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हमारे बीच में पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब विराजे हैं, आज पूरे राजस्थान में या पूरे विधान सभा क्षेत्र में जिस तरह से सड़कों की जो हालत है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि 2007-08 के बाद में जो पांच साल का सरकार का कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में आज दिन तक एक भी नई सड़क मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं बनी और पूरे राजस्थान में सड़कों के क्षेत्र में जिस तरह से पड़ौसी गुजरात में देख लो, जब गुजरात से चलकर कोई राजस्थान में प्रवेश करता है तो जैसे नींद में सोया हुआ आदमी भी जगकर देखता है कि अब राजस्थान आ गया। सबसे पहले गाड़ी में खड़खड़ चालू हो जाती है तो पता लगता है कि अब राजस्थान आ गया। राजस्थान के अन्दर सड़कों की हालत, सरकारी भवनों की हालत, मैं तो विशेष तौर से मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो घटनाएं हुईं, वह आपने अखबारों के माध्यम से पढ़ी होंगी कि 2010 में एक सरकारी आवास गिरने से एक डाक्टर की मौत हो गयी।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी भवन पूरे सिरोही जिले में जितने भी जर्जर अवस्था में हैं, वह कभी भी गिर सकते हैं। यह कंडीशन है। आज दिन तक सिरोही में राजकीय विधि महाविद्यालय है। जोधपुर सम्भाग में दूसरा बड़ा राजकीय विधि महाविद्यालय है। उस विधि महाविद्यालय में सिरोही, जालौर, बाड़मेर, पाली व उदयपुर के बच्चे वहां अध्ययन करते हैं, लेकिन इस विधि महाविद्यालय का अपना भवन नहीं होने के कारण बार-बार बार कौंसिल आफ इंडिया के मापदण्डों के आधार पर विधि महाविद्यालय की बिल्डिंग नहीं होने के कारण यह एक प्राइवेट बिल्डिंग में चलता है। मैं तो मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने भवन हैं, जो जर्जर अवस्था में हैं। आज जितने भी डिपार्टमेंट के, शिक्षा विभाग के, सिंचाई विभाग, जितने भी आफिस हैं, इनके जो भवन बने हुए हैं, वह कभी भी जिस तरह से डॉक्टर की मौत हुई थी, उसी तरह से कभी भी वह गिर सकते हैं। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में इसकी पूरी रिपोर्टिंग कराकर जितने भी जर्जर अवस्था में जो भवन हैं, उनकी एक बार रिपोर्टिंग करा दें ताकि आने वाले समय में इसका सुधार हो सके।

(श्री ओटाराम)

दूसरा, आज जिस तरह से पूरे विधान सभा क्षेत्र में पहले डोटासरा जी, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय विधायक जी बोल रहे थे कि पहले हमारे टाइम में जो रोड्स सैंक्शन हुई थीं, मेरे वहां भी होर्डिंग लगे थे, बड़े-बड़े होर्डिंग लगे थे और कह रहे थे कि हमने सड़कें स्वीकृत कर दीं। आज दिन तक एक भी सड़क स्वीकृत नहीं हुई। मैं मंत्रीजी से मिला कि पूरे राजस्थान में 800 करोड़ रुपयों की जो सड़कें स्वीकृत की थीं, उनके लिये बजट का कोई प्रावधान नहीं किया और सड़कें स्वीकृत कर दीं। मेरे वहां भी बरलू से बराड़ा, जो दो जिलों को जोड़ती है, हमेशा उस सड़क की इतनी बड़ी समस्या है, आये दिन वहां दुर्घटनाएं हो रही हैं। बार-बार छोटी सड़क होने के कारण पटरियां ऊपर चढ़ गयी हैं। पास में खड्डे हो गये हैं तो लोगों को आने-जाने में बहुत बड़ी दुविधा होती है। यह पूरे सिरोही और जालौर जिले को जोड़ती है और हजारों यात्री चाहे नाकोड़ा जैन मन्दिर के हों, जालोर जलन्धरनाथ जी के हों, वहां से निकलते हैं परन्तु 9 किलोमीटर की रोड़ इस हालत में पड़ी है कि लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ होती है।

पहले की सरकार में एक मीणा समाज का गौतम ऋषि का मन्दिर है, उस मन्दिर की रपट बनी हुई थी, 2010 में बारिश से टूटने के बाद में आज दिन तक यह हालत है, पांच साल तक मैंने इस विधान सभा में उसके लिए क्वेश्चन लगाये। उन्होंने सब ने एक ही कहा कि अकाल राहत में बनी हुई है। मैंने खुद ने कहा एम.एल.ए. लैड से दस लाख रुपये देने को तैयार हूं परन्तु इस सरकार ने कुम्भकरण की नींद में सोकर गौतम ऋषि के मेन मन्दिर में जाने की जो रपट थी उसका आज दिन तक निर्माण नहीं किया।

दूसरा, कृष्णगंज से सियागरा और सनपुर यह बहुत बड़ी रोड है, 2003 से लगाकर 2007-08 तक एक ही समस्या आ रही थी कि यह फोरेस्ट रोड है और, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ तीन किलोमीटर रोड फोरेस्ट में है, इधर से लगाकर छह किलोमीटर और उधर से लगा कर दस किलोमीटर पूरी डामर सड़क बनी हुई है, बीच में तीन किलोमीटर रोड फोरेस्ट में होने के कारण ऐसा है, उसका डी-फोरेस्ट भी करवा दिया परन्तु आज दिन तक वो सड़क नहीं बनी इसलिए लोगों को आने-जाने में कम से कम 80 किलोमीटर का चक्कर काट कर उधर सिरोही में आना पड़ता है।

(श्री ओटाराम)

सभापति महोदय, रोवाड़ा घाटा है उसमें एक किलोमीटर फोरेस्ट रोड है और मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक किलोमीटर के कारण लोगों को 50 किलोमीटर का दौरा करके उधर दूर से घूम कर आना पड़ता है जबकि दोनों तरफ रोड बन गयी। उधर भी देवनगर तक बन गयी, इधर भी आलबा तक बन गयी और बीच में एक किलोमीटर फोरेस्ट रोड के कारण आज दिन तक लोगों को उसकी सुविधा नहीं मिल रही है।

दूसरा मेरा निवेदन था आपसे, एक जालोर जिले को मिलाने के लिए है, आहौर से आने वाले आदरणीय विधायक श्री शंकरसिंह जी हैं, जिन्होंने मलिनाथजी तक रोड बना दी और रोवाड़ा से करीब डेढ़ किलोमीटर रोड है, अगर यह डेढ़ किलोमीटर बन जाए तो दोनों जिले मिल जाते हैं।

एक बग से नागाणी है, मोबत नगर से रामसीन, पालड़ी से पीपलकी और पालड़ी एम से गणकेश्वर, बालदा राजपुरा से देवों का बेरा, यह रोड अगर पांच किलोमीटर बन जाए तो लोगों को कम से कम चालीस किलोमीटर का जो चक्कर काट कर आना पड़ता है, वो सुविधा हो जायेगी। सूली से गोडाणा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से नेशनल हाइवे बन रहा है शिवगंज से लगा कर पिण्डवाड़ा तक इसमें शिवगंज शहर और सिरोही शहर है, सभापति महोदय, शिवगंज मुम्बई का टुकड़ा है और जिस तरह से लोग बिजनस के लिए मुम्बई जाते हैं उसी तरह से सारे लोग बिजनस के लिए कपड़ा मार्केट में, ज्वैलर्स में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिटी है तो वो शिवगंज है, आपके कोटा, झालावाड़, पूरे राजस्थान से कपड़ा मार्केट के माध्यम से लोग शिवगंज में आते हैं। शिवगंज के अन्दर जो बाइपास दिया जा रहा है उसके लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि शिवगंज के अन्दर से जो रोड निकल रही है उसी रोड पर आने वाले जितने भी व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, किसान हैं वहां उनके आने के लिए व्यवस्था की जाए।

सिरोही और शिवगंज के बीच में जितने भी गांव आते हैं, पोसालिया है, अरटवाड़ा है, वेरा रामपुरा है, उतमण है, बागसीण है, चांदाणा है, जितने रोड हैं वो सब जर्जर अवस्था में हो गये हैं, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में जितने भी एन.एच. वाले हैं इन सबसे कहें कि सिरोही विधान सभा क्षेत्र में जितनी भी रोड आपके उपयोग में आये हैं उनमें क्षतिग्रस्त जो सड़कें हैं उनको ठीक करके वापस डिपार्टमेंट को दें।

(श्री ओटाराम)

जिस तरह से जावाल एक व्यापारी जोन है और उसके कैलाश नगर से लगा कर झाड़ोली, जुबलीगंज और कैलाशनगर और जावाल इस सड़क को सात मीटर चौड़ा किया जाए। यह सड़क लोगों के रोज उपयोग में आती है, छोटी सड़क होने के कारण बार-बार दुर्घटनाएं होती हैं। सबसे पहले मेरे बरलूट से बराड़ा है, यह भी सात मीटर का हो। दूसरा कैलाशनगर से लगा कर जुबलीगंज से ठेट जावाल तक, यह भी सात मीटर का हो।

इसी आशा के साथ, आप सबने मुझे लोक निर्माण विभाग के ऊपर बोलने का जो समय दिया इसके लिए मैं आपका खूब-खूब आभारी हूं। जय हिन्द। जय भारत माता।

श्री सभापति: श्री सुरेन्द्र पाल सिंह।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 21 पर जो मैंने कट-मोशन दिये थे उन पर बोलने का मुझे अवसर दिया इसके लिए आपका आभारी हूं।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान के विकास और आज की परिवहन व्यवस्था है, आने वाले समय में इतनी बड़ी संख्या में व्हीकल सड़कों पर आ रहे हैं इन सब को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम सड़कों का हाथ में लिया है। निश्चित तौर पर कहने के लिए 20 हजार किलोमीटर हम कह सकते हैं लेकिन बीस हजार किलोमीटर सड़कें बनाना और एक लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था करना, यह एक बहुत चुनौतीपूर्ण और साहसपूर्ण कार्य है।

प्रतिपक्ष के साथी कह रहे थे कि यह पी.पी.पी. माडल पर टोल टैक्स लग जायेंगे, अब हम चाहें कि पकौड़े भी खा लें और तेल भी नहीं लगे, अब तेल के बगैर तो पकौड़े बन नहीं सकते, पैसे की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी।

(15.00 बजे)

हम टैक्स पर जायें 1 लाख करोड़ रुपये के और टैक्स लगा दें डीजल पर, टैक्स लगा दें पेट्रोल पर, तो वह किसान जो सारा दिन खेती-बाड़ी के लिए डीजल खरीदता है और कभी वह एनएच पर और स्टेट हाइवे पर चलता नहीं तो उसकी जेब से पैसा निकलेगा। लेकिन अगर पीपीपी मॉडल पर कोई सड़क बनती है तो केवल उसी व्यक्ति को पैसा देना पड़ेगा जो उसका यूज करेगा। नम्बर दो, आज इतनी ज्यादा समय की कीमत हो गयी कि हर व्यक्ति पैसा देने के लिए तैयार है।

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

माननीय सभापति महोदय, माननीय राजेन्द्र जी बैठे हैं सदन में, पिछली बार इन्होंने गंगानगर से जयपुर आने के लिए हनुमानगढ़ से रतनगढ़ का मेगा हाइवे बनाया। जब हम आते थे गंगानगर से हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ से आगे जयपुर तक 12 से 14 घंटे से पहले कभी हम पहुंच ही नहीं पाते थे और आज वह मेगा हाइवे जब रतनगढ़ तक तैयार हो गया तो हम 5 बजे यहां से चलते हैं और 11 बजे रात को गंगानगर पहुंच जाते हैं। अब 6-7 घंटे समय की बचत, 6-7 घंटे ईंधन की बचत, मेंटिनेंस की बचत और 150 रुपया हमारी जेब से जाता है तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा सस्ता कोई और टैक्स हो ही नहीं सकता। जिसको भी सड़क के ऊपर 10 लाख की गाड़ी भगानी है उसकी जेब से अगर 150-200 रुपये लगेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो समय और मेंटिनेंस, डीजल की बचत होगी वह इससे कहीं ज्यादा फायदे में रहेगा। इसलिए पीपीपी माडल पर सड़कें बनी हैं यह विकास के लिए अति आवश्यक हैं।

माननीय सभापति महोदय, अभी यूएसए भी मैं जाकर आया, कनाडा भी गया, वहां भी जितनी भी सड़के हैं वह सारी इसी माडल पर बनी हुई हैं और लोग बड़े हंसकर वहां टैक्स पे करते हैं। विकास के लिए हम चाहें कि सुविधाएं मिलें और हमारी जेब से पैसा नहीं लगे यह तो सम्भव नहीं है। जो सुविधाएं मिल रही हैं उसके मुकाबले जो टैक्स या टोल वसूल होता है उसमें देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हां, यह जरुर है कि जो टोल टैक्स पर दिक्कते हैं वह ज्यादा लोगों को नहीं आनी चाहिए। मैं तो देखता हूं कि 5 मिनट अगर टोल पर रूकना पड़ जाये तो लोग झगड़ा कर लेते हैं और जो 5-5 घंटे बचत होती है उस टाइम की कीमत ही नहीं है। यह बहुत अच्छा निर्णय है और जब 1 लाख किलोमीटर सड़के बन जायेंगी तो राजस्थान की जो तस्वीर जनता के बीच में और प्रदेशों में जायेगी तो देखना इसके अन्दर कितना लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से मानव शरीर के अन्दर नाड़ियों का योगदान होता है इसी तरह का योगदान सड़कों का है। नाड़ी में थोड़ा सा ब्लड रुक जाये तो सारा अंग रुक जाता है। आज सड़कों का लगभग यही हाल है। 1 लाख व्हीकल हर महीने सड़कों पर आ जाते हैं और सड़कें अच्छी नहीं होंगी तो आने वाले समय में विकास और आवागमन कैसे कंट्रोल होगा। बहुत ही सूझवान और इस प्रदेश की प्रगति के लिए बजट में जो इतना

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

बड़ा प्रावधान है इसके लिए निश्चित रूप से मुख्य मंत्रीजी बधाई की पात्र हैं, साधुवाद की पात्र हैं।

हमारे युवा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उनमें ऊर्जा है और हमें पूरी उम्मीद है कि वह अपनी ऊर्जा से जो योजना उन्होंने हाथ में ली है, 5 साल में इस राजस्थान की तकदीर बदल देंगे। 20 हजार किलोमीटर सड़कें बनाना, 2 हजार किलोमीटर सड़कें इंडैक्स के अन्दर बनाना। इसी तरह से राजस्थान स्टेट हाइवे अथारिटी बना दी। उनकी रख-रखाव करना। अब क्या हालत है हाइवे की? हम जाते हैं तो हमारा बीकानेर का हाइवे है, जाकर देखो नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे उनकी बहुत दुर्गति है। निश्चित रूप से इसका भी लाभ होगा।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी बात, प्राइवेट बसों के जो 80 अड्डे बनाने हैं उनके अन्दर उनको भी सम्मिलित करना है। अब हमारे कितनी बड़ी दिक्कत है कि प्राइवेट जो बस अड्डे हैं वह शहर से बाहर हैं और जो रोडवेज का अड्डा है वह शहर के अन्दर है। जितना किराया हमारा गांव से शहर तक आने में लगता है उतना शहर से हमारे सैन्ट्रल बस अड्डे तक आने में लग जाता है। जब यह दोनों मिक्स हो जायेंगे तो यहां से उतरे और इधर से आपने दूसरे स्टेट के लिए बस पकड़ ली। निश्चित रुप से यह भी एक बहुत ही सराहनीय कदम है और इसका बहुत बड़ा लाभ आम जन को मिलेगा।

इसी तरीके से सबसे अच्छी बात लगी कि गांव की जो सड़कें हैं जिनको कोई सम्भालता नहीं था, ठेकेदार के माध्यम से ओपीआरसी जो पद्धति है उसके अन्दर लिया गया है। होता क्या था कि सड़क बन जाती थी और सड़क के अन्दर कोई भी खड्डा पड़ गया तो उसको कोई सम्भालने वाला नहीं होता था। देखते-देखते सड़क बिखर जाती थी। अब कम से कम 8 साल तक उसका रख-रखाव तो होगा और जो ठेकेदार बनायेगा उसको भी भय होगा कि मुझे यह सड़क 8 साल तक बनानी है इसलिए स्टैंडर्ड की बनाऊं। नहीं तो मेरे को हर बार इसके मेंटिनेंस पर, इसके पैचवर्क पर बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। जितनी भी इसके अन्दर घोषणाएं हैं वह काफी अच्छी घोषणाएं हैं। समय की मर्यादा को देखते हुए मैं यही कहूंगा कि आज राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए जितनी भी सड़कें हैं और जो भी प्रोग्राम मुख्य मंत्रीजी ने घोषित किया है इसका आने वाले समय में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरे देश में जायेगा और राजस्थान के विकास में यह मील का पत्थर साबित होगा।

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र करणपुर विधान सभा की कुछ समस्याएं हैं उनके सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। वैसे तो हमारा सौभाग्य रहा कि पीडब्ल्यूडी के मंत्रीजी और गुप्ता जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दोनों हमारे एरिये को अच्छी तरह देखकर आये हैं और उन्होंने सब कुछ देखा है। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से कुछ हमारी सड़कें हैं जिनको मैं चाहता हूं कि 1-2 साल के प्रोग्राम में लिया जाये तो परिवहन की दृष्टि से और आम गांव की दृष्टि से बड़ी लाभकारी होंगी।

हमारे यहां एक सड़क माननीय राजेन्द्र जी ने बनायी थी, क्योंकि इनका ससुराल है वहां और इनको कर्जा भी देना था। वहां से हमने मांग रखी कि आपके बार्डर के सारे गांव हैं, केवल 3 किलोमीटर की सड़क के कारण वह जुड़े नहीं थे। मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी को, उस सड़क से पूरा बार्डर का एरिया जिसमें 50-60 गांव हैं, वह सारे के सारे गांव गंगानगर तक जाते हैं। अब वह सड़क बनी, उसका इतना बड़ा लाभ हुआ कि सारा ट्रैफिक उससे डाइवर्ट हो गया, मंडियों का भी, गजसिंहपुर का भी और बार्डर का भी। वह केवल 12 फुट चौड़ी है। उसके अन्दर एक बड़ा तीर्थ स्थल है चांदना धाम, दो बार मेला लगता है और उसमें लाखों लोग जाते हैं। लेकिन उस सड़क की चौड़ाई 12 फुट है, इसलिए वहां इतनी ट्रैफिक की समस्या रहती है। मैंने माननीय मंत्रीजी को, आदरणीय गुप्ता जी को भी यह सब दिखाया था और उस सड़क की चौड़ाई अगर एक-एक मीटर बढ़ा दी जाये तो मैं समझता हूं कि हमारे सीमा क्षेत्र के लोगों को इसका जितना लाभ राजेन्द्र जी ने दिलाया उससे दुगना लाभ और मिल जायेगा।

श्री सभापति: यानी इन्होंने पूरा कर्जा नहीं चुकाया है, हैं ना।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर): उन्होंने चुका दिया। लेकिन मैं राजेन्द्र जी से भी रिक्वैस्ट करुंगा कि वह इसमें हमारी सिफारिश जरूर करेंगे। नहीं तो बहन जी को जाकर बोलूंगा कि अपना काम है, मिलकर हम करायेंगे।

दूसरा, हमारे एक बड़ी दिक्कत है कि हमारे बहुत से ऐसे गांव हैं बड़ी-बड़ी आबादी के, तीन पंचायतें हैं, एक पंचायत तो है 34 एलएनपी, एक नरसिंहपुरा, मांजूवास और लगभग 6-6 हजार वोट हैं एक-एक गांव के। वह तीनों सड़कें एनएच पास में जाता था पूर्व में उससे जोड़ दी। अब मंडी बिजबाला लगती है। उनको मंडी तीन-तीन बार जाना पड़ता है। लेकिन अब वह जुडी हुई मान ली गयी हैं। मंडी से जोड़ने के लिए कोई योजना नहीं है। हम

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

चाहते हैं कि या तो कोई मिसिंग लिंक का सिस्टम बने या कोई हमारा जो पुराना सिस्टम था कि 60 परसेंट पैसा, हम कृषि उपज मंडी के माध्यम से प्रस्ताव देते थे और उसके माध्यम से हम उन सड़कों को जोड़ देते थे। अब हमारे पास से वह भी हमारा अधिकार चला गया। अब चाहे सड़कें पीडब्ल्यूडी बनाये हमें दिक्कत नहीं है लेकिन हमारे पास अब कोई भी ऐसा फंड नहीं, कोई भी ऐसी योजना नहीं जिसमें गांव का व्यक्ति शहर जाने के लिए किसी योजना में गांव को जोड़ सके।

अब गांव के किसान को एनएच से क्या लेना-देना। उसको स्टेट हाइवे से क्या लेना? उसको तो 5 बार अपनी मंडी जाना है। इसलिए यह गांव 34 एलएनपी पूरी पंचायत, नरसिंहपुरा, मांजूवास कृषि उपज मंडी से 15 किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है पक्की सड़क से और सीधे जायें तो 3 किलोमीटर है। यही स्थिति लगभग फरसेवाला की है। सरकार इस सम्बन्ध में या तो मिसिंग लिंक के माध्यम से या फिर पैसा जो 60 परसेंट है, बोर्ड से प्रस्ताव लेकर चाहे पीडब्ल्यूडी बना दे लेकिन जो किसान का पैसा कटता है, उसके लिए कृषि उपज बोर्ड, विपणन बोर्ड में टैक्स लगता है, किसान की फसल से टैक्स लगता है और यह लिखा हुआ है बाकायदा उस एक्ट के अन्दर कि किसान की फसल बेचने के लिए, उसको मंडी तक माल ले जाने के लिए यह पैसा इस्तेमाल होगा। लेकिन वह पैसा अगर एनएच पर लगता है या स्टेट हाइवे पर लगता है और किसान की गांव की सड़क अगर अधूरी है या नहीं है तो मैं समझता हूं कि यह किसान के साथ न्याय नहीं है। निश्चित तौर पर सरकार इस ओर जरुर ध्यान दे।

हमारे दो तहसीले हैं और दो तहसीलों के बार्डर सीमा क्षेत्र पर कोई पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस नहीं है। अब हमारे मंत्रीजी गये तो हमें इनको बीएसएफ वालों के यहां रोकना पड़ता है। अगर उनका कोई आफिसर आया तो हमें जगह नहीं मिलती। कोई गैस्ट हाउस करणपुर तहसील में बन जाये तो हमारे जो भी मंत्री लोग जाते हैं, कोई वी आई पी आदमी जाता है तो उनके लिए सुविधा हो जायेगी। हमारी तहसील हैडक्वार्टर जो तहसील का आफिस है, तहसीलदार जहां बैठता है वह 1930 का बना हुआ है। अब 85 साल बाद उसकी जो स्थिति है वह यहां सदन में बताउं, पानी टपकता है और तहसीलदार बैठता है तो उसके सिर के ऊपर चूना गिरता है। निश्चित तौर पर तहसील आफिस जो पुराना है उस तहसील आफिस की या तो दुबारा छतें बदली जाएं

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

या उनका पूरा दुबारा रिनोवेशन हो या उसको गिराकर दुबारा बनाया जाये, यह भी हमारी एक मांग है।

इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट मेन रोड है हमारी, गंगानगर टू करणपुर और तहसील से डिस्ट्रिक्ट को जोड़ती है, वह ग्रेव में है। यही स्थिति पदमपुर से बूढ़ा रोड होते हुए हमारी जैतसर रोड की है, दोनों ग्रेव की सड़के हैं, और ग्रेव में कभी पांच पैसा भी उस पर नहीं लगाया है। उसी पर शुगर मिल बन गई करणपुर से गंगानगर पर। शुगर मिल बनने से गन्ना किसान का भी उधर से ही जायेगा। इतने बड़े-बड़े खड्डे हैं। वैसे मंत्रीजी ने हमको यह विश्वास दिया कि ग्रेव की सड़कें हम वापस लेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी ग्रेव की सड़कें वापस हों, यह तो बहुत जरूरी है लेकिन डीएमआर, डिस्ट्रिक्ट मेन रोड हैं उसमें करणपुर से गंगानगर वाया जेड माइनर, यह जेड माइनर हमारी नहर के साथ जाती हुई सड़क है, यह बिलकुल जीर्ण-शीर्ण है। इसी तरह से जैतसर से पदमपुर जिसके अन्दर बूढ़ा जोहड़ जो राजस्थान का बहुत बड़ा सिख तीर्थ स्थल है, जहां लाखों लोग आते हैं, ये दोनों ग्रेव से निकाल कर जो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से सड़कें हैं, चाहे पीपीपी माडल पर बन जाये, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट में रोड होने के नाते ये सड़कें जरूर सरकार अण्डर टेकिंग करे और ग्रेव से पिछली बार राजेन्द्रजी ने बहुत अच्छी सड़क हमारी थी वह सीसी हैड से लेकर हनुमानगढ़ के बीच में छूट गई। इतनी बढ़िया सड़क बनी है कि लोग आज तक इनको याद करते हैं तो ग्रेव के अन्दर कोई बजट नहीं है और ग्रेव की सड़कों के जो हालात हैं वह इतने बुरे हैं कि हम उस पर चल नहीं सकते तो निश्चित तौर पर ग्रेव की सड़कें, यह सारी सड़कें जब तक वापस नहीं आयेगी तो मैं समझता हूं कि हमारे उस क्षेत्र का भला नहीं हो पायेगा।

इसी तरह से हमारी एक सड़क है केसरीसिंहपुर से गंगानगर और वह बोर्डर के साथ जाती है, उसकी भी चौड़ाई 12 फुट है, उसके चारों तरफ, एक तरफ रेलवे लाइन है और एक थोड़ी काश्तकारों की जमीन है। वह सड़क भी 12 फुट से अगर चौड़ी हो जाये, वैसे मंत्रीजी हमें वहां हां भरकर आये थे और हमें उम्मीद है कि उसका प्रपोजल जरूर भिजवा दिया होगा, यह सड़क भी अगर बन जाती है तो मैं समझता हूं कि यह भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी।

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

अब हमारे कुछ पीडब्ल्यूडी के पुल हैं, जैसे एक रेण गांव से करणपुर जाते हैं, बहुत बड़ा ट्रैफिक पास होता है, जिस पुल से बसें निकलती हैं, दो दफा बैक करके और क्योंकि वह सड़क से हट कर बना हुआ है, दो दफा बस बैक करनी पड़ती है और कई दफा सवारियां उतार कर निकालते हैं। उस सड़क के ऊपर पुल न होने से सड़क से दूर हट कर यूं टर्न करके आना पड़ता है। बहुत बड़ी इलाके की मांग है कि यह यू टर्न करके आते हैं तो उसमें दिक्कत आती है, अगर यह पुल भी हमारा जल्दी बन जाये तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा लाभ होगा।

मेरे क्षेत्र में मात्र पांच-चार गांव हैं, केवल चार गांव बचे हैं जो सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं। दो पदमपुर के हैं, 51 जीजी, 34 एलएनपी और 36 एलएनपी, अब वह दो इसलिए नहीं बने कि नहर के साथ उनकी सड़क चलती है 50-70 साल से और नहर विभाग कहता है कि हम यहां वन विभाग से पौधारोपण करायेंगे लेकिन गांव को कोई सड़क नहीं है। पैसा 5 बीबी सड़क का मंजूर भी हो गया लेकिन वह नहरी विभाग उसकी एनओसी नहीं दे रहा है इसलिए 5 बीबी और 36 एलएनपी की सड़क जो नहर विभाग से एनओसी के कारण दो साल से पड़ी हुई है, उसमें आबादी भी पन्द्रह-पन्द्रह सौ की है तो यह टाइअप करके नहरी विभाग से परमीशन लेकर 36 एलएनपी और 5 बीबी की सड़कें, दोनों अगर नहरी विभाग परमीशन दे तो बन जायेंगी और इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है।

इसी तरह से 51 जीजी और 34 एनएनपी, दो गांव बचे हैं जो सड़क के अन्दर अभी जनसंख्या के आधार पर हो सकते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे करणपुर विधान सभा क्षेत्र की दो तहसीलें हैं, वहां के शत प्रतिशत गांव सड़क से जुड़ जायेंगे और हमारे इस इलाके में हमारे विकास के लिए सड़कों की आवश्यकता है वह पूरी हो जायेगी इसलिए मैं आपने मुझे समय दिया, आपका हार्दिक आभार पर भी प्रकट करूंगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी को पुन: बधाई दूंगा और आदरणीय यूनुसजी को फिर मैं क्योंकि नौजवान हैं और ऊर्जावान हैं, ऐसी उम्मीद करता हूं कि अपनी ऊर्जा से वह राजस्थान में सड़कों का जाल बिछायेंगे और आने वाले पांच साल में इस राजस्थान को लोग देखने आयेंगे कि अगर सड़क तंत्र है तो राजस्थान का है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

शासकीय वक्तव्य

अमरनाथ यात्रा और उत्तराखण्ड में फंसे यात्रियों की स्थिति

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, सवेरे सदन के सभी लोगों ने अमरनाथ यात्रा और उत्तराखण्ड में राजस्थान के जो लोग फंसे हुए हैं उनके बारे में जानकारी चाही थी। जो मुझसे इकट्ठी हुई है वह मैं सदन के सामने रख रहा हूं।

अमरनाथ यात्रा में फंसे राजस्थानी तीर्थ यात्रियों के सम्बन्ध में जम्मू कश्मीर के श्री अब्दुल गनी मीर, महानिरीक्षक पुलिस, कश्मीर के श्री शैलेन्द्र कुमार, पुलिस आयुक्त, कश्मीर, श्री राजेश गुप्ता, सीईओ, अमरनाथ यात्रा बोर्ड और महानिदेशक कार्यालय में पदस्थापित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री गुलजार अहमद के जरिये दूरभाष से हमारे अधिकारियों की वार्ता के अनुसार भारतीय टैण्ट वालों एवं बाहर से आये यात्रियों के समय लंगर लगाने वालों के बीच आपसी मनमुटाव हुआ था। टैण्ट वालों का कहना था कि बाहर से आने वाले लंगर वाले टैण्टों में अपने यात्री रुकवा रहे थे जो गलत है। इसी दौरान लंगर में गैस सिलेण्डर के फटने से आसपास के टैण्टों में आग लग गई। जिस कारण शुक्रवार की यात्रा स्थगित कर दी गई थी। परन्तु आज यात्रा पुन: चालू कर दी गई है। अब अमरनाथ यात्रा निर्बाध रूप से चल रही है, यात्रा किसी भी प्रकार से बाधित न होकर सुचारू रूप से संचालित है। इस घटनाक्रम के दौरान कोई भी राजस्थानी यात्री प्रभावित नहीं हुआ।

उत्तराखण्ड में फंसे राजस्थानी यात्रियों के सम्बन्ध में अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस, कानून व्यवस्था, श्री रामसिंह मीणा से हमारे अधिकारियों की हुई दूरभाष वार्ता पर अवगत कराया है कि मौसम खराब होने की वजह से यात्रा रुकी हुई है। सुरक्षित स्थान पर यात्रियों को रोका हुआ है, किसी भी प्रकार की जन हानि की कोई घटना नहीं हुई है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री हीरालालजी। नहीं है सदन में। (अनुपस्थित)।

श्रीमती अनिता भदेल।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 19 और मांग संख्या 21 पर अपनी मांगें रखने का अवसर दिया।

(श्रीमती अनिता भदेल)

मानीनीय मंत्री महोदय, कुछ ऐसे सुझाव हैं जिनको यदि हम अपनायेंगे तो निश्चित रूप से पीडब्ल्यूडी सड़कों की गुणवत्ता के बारे में गारण्टी दे पायेंगे, साथ ही समय पर कार्य पूर्ण हो उसके विषय में भी हम आगे की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के जो काम आजकल होते हैं उनकी गारण्टी आज कोई नहीं ले सकता क्योंकि जितने भी निर्माण कार्य पिछले दस-पन्द्रह वर्षों में हुए हैं, यदि अजमेर के निर्माण कार्यों की बात करूं तो मैं शुरू करूंगी, बूढ़ा पुष्कर से। जब माननीय वसुन्धराजी प्रथम बार मुख्य मंत्री बनी थीं प्रदेश की तो उन्होंने इस बूढ़ा पुष्कर की आस्था से जुड़े लाखों-लाखों लोगों की श्रद्धा को देखते हुए स्वयं उस सरोवर में से मिट्टी की तगारी अपने सिर पर उठाकर काम प्रारम्भ किया था। वह काम

(15.19 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

उन्होंने आम जनता की भागीदारी से किया। सब विभाग के मंत्री हमारे अजमेर बूढ़ा पुष्कर के कार्य में लगे और बूढ़ा पुष्कर गये। समाज के लोगों ने धन इकट्ठा करके पीडब्ल्यूडी को जमा कराया, कलक्टर महोदय के माध्यम से काम प्रारम्भ हुआ लेकिन यदि आज उस बूढ़ा पुष्कर के घाट की स्थिति हम देखेंगे तो पिछले पांच साल में चूंकि पिछली सरकार की कोई धार्मिक आस्था थी नहीं और विभाग के अधिकारियों ने भी सोचा कि अब उनकी सरकार गई इसलिए उसको देखने की जरूरत नहीं है और उन्होंने इतना घटिया काम किया कि आज यदि हम उस घाट पर जायें तो सारी पट्टियां उसकी उखड़ी पड़ी हैं, पूरे पैसे का दुरुपयोग विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया।

विभाग के अधिकारियों को यदि पूछते हैं तो वे जवाब देते हैं कि हमारे कार्यकाल में नहीं बना। आपके कार्यकाल में नहीं बना होगा, लेकिन बनाया तो विभाग के अधिकारियों ने ही है, विभाग ने ही उसको बनाया है फिर उसकी ऐसी दुर्गति क्यों हुई? इसलिए सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि पीडब्ल्यूडी के कामों की गारंटी अवधि 5 से 8 वर्ष के बीच तो होनी ही चाहिए ताकि ठेकेदार पर यह भार रहे कि उसको ठीक करना पड़े और वह पहले दफे ही काम को इस प्रकार से करे कि कम से कम 5 से 8 साल तक तो उन कामों का कुछ नहीं बिगड़े। दूसरा विषय है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कभी भी काम को सही समय पर नहीं करते। जब निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं तब उसमें समयावधि होती है कि इतने समय में उसको काम पूरा

(श्रीमती अनिता भदेल)

करना है। जितनी राशि का काम होता हैं उतनी लम्बी समयावधि उसको दी जाती है ताकि वह धीरे-धीरे उस राशि का काम पूरा कर ले, लेकिन अभी तक कामों में चाहे वह कम राशि का काम हो, अधिक राशि का काम हो, जब उसकी समयावधि समाप्त होने लगती है उसके 6 महीने पहले या 3 महीने पहले ही ठेकेदार काम प्रारम्भ करता है। विभाग के अधिकारियों को कहते हैं कि उसने काम प्रारम्भ नहीं किया तो विभाग के अधिकारी जवाब देते हैं अभी उसका समय है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, अभी उसके पास समय पड़ा है। यदि हम किसी को छह महीने का समय देते हैं तो इसका मतलब यह है कि वह छह महीने की अवधि में स्टार्ट करके उसको पूर्ण करे। न केवल वह पांचवें महीने में स्टार्ट करे और छठे महीने में पूर्ण करके आप विभाग को सरेण्डर कर दें। मेरा निवेदन है कि दोनों चीजों के लिए हमें नये नियम-कायदे बनाने पड़ेंगे और स्ट्रिक्टली विभाग को करना पड़ेगा कि वह समय पर काम को प्रारम्भ करे, समय पर काम को पूर्ण करे।

मैं उदाहरण देना चाहूंगी। एक प्रश्न का जवाब भी मेरे पास आया है 2004 में माननीय वसुन्धरा जी ने अजमेर में मूक-बधिर विद्यालय के लिए स्वीकृति जारी की, उसका बजट भी उन्होंने उसी समय जारी कर दिया, लेकिन आश्चर्य की बात है कि पिछले 5 साल निकल गये और अभी भी विभाग के अधिकारी यह कह रहे हैं कि हमें 55 लाख की और आवश्यकता है। तो यह काम कब पूर्ण होगा? 5 साल वो, 5 साल ये और अभी 11वां वर्ष चल रहा है। मैं इसको थोड़ा पढ़कर सुनाना चाहती हूं। ''माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण वर्ष 2004-05'', माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है थोड़ा सा इसे ध्यान से देखें, ''बिन्दु संख्या 32 पर मूक-बधिर एवं नेत्रहीन बालकों के लिए एक आवासीय निशक्तजन शिक्षण संस्थान बनाने की घोषणा की गयी। सचिव, नगर सुधार न्यास द्वारा अजमेर में अपने पत्र क्रमांक दिनांक 25.02.2005, एक साल बाद में जमीन के लिए तलाशी की गयी और एक साल बाद जमीन समाज कल्याण विभाग को सुपुर्द कर दी गयी। 10 लाख रुपये उस जमीन के एवज में समाज कल्याण विभाग ने उनको दे भी दिये। अब बारी आती है उसके निर्माण की। विभाग ने 18.03.2005 को नगर सुधार न्यास, अजमेर को 19 लाख रुपये के भुगतान की स्वीकृति जारी कर दी। उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग ने फोरकास्ट एस्टीमेट रुपये 31 लाख का बनाकर जयपुर में भेज दिया कि 31 लाख रुपये में यह समाज कल्याण विभाग

(श्रीमती अनिता भदेल)

का आवासीय विद्यालय बनने वाला है। समाज कल्याण विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 18091 दिनांक 30.03.2005 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता, अजमेर को 30 लाख रुपये के भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर दी। इन्होंने 30 लाख का एस्टीमेट बनाया। विभाग ने 30 लाख की स्वीकृति जारी कर दी। अब देखो, खेल कैसे हुआ। उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, अजमेर ने उक्त भूमि का निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त भूमि बनाने के लायक नहीं है, इसलिए दूसरी भूमि दी जाय उस भूमि को पहले ही नगर सुधार न्यास किसी को बेच चुका है। दूसरी भूमि की तलाश हुई, दूसरी भूमि फिर आबंटित हो गई, आबंटित होने के बाद में मई, 2008 में समाज कल्याण विभाग द्वारा भूमि का कब्जा ले लिया गया। 1 मई, 2009 को अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 1479 दिनांक 20.05.2009 से आवासीय शिक्षण संस्थान के भवन निर्माण कार्य की तखमीना राशि जो 31 लाख थी 2005 में, 2009 में वह 315 लाख रुपये हो गयी। 315 लाख की उन्होंने डिमाण्ड की कि इतनी राशि चाहिए। 315 लाख के एवज में 2009 में 315 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करते हुए 2009-10 से 2011-12 की अवधि के लिए रुपये 299.80 लाख तथा इस प्रशासनिक स्वीकृति के अतिरिक्त 2004-05 में जो राशि 30 लाख जारी की थी का भुगतान आवासीय शिक्षण संस्थान के निर्माण हेतु अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिटी डिवीजन, अजमेर को किया गया। 330 लाख का भुगतान हो गया, उसके बावजूद भी विभाग के अधिकारियों ने इसको कम्प्लीट नहीं किया। आज भी इसमें कमियां बता दीं कि कमरों की दीवारों में दरारें आ गयी हैं, विद्यालय में पहुंचने के लिए सम्पर्क सड़क नहीं है। अब बहरे, गूंगे और अंधे लोगों के लिए कोई आवास बना रहे हो तो कम से कम उसके एस्टीमेट में वहां तक पहुंचने के लिए सड़क का प्रोविजन तो पहले करना चाहिए। 330 लाख के एस्टीमेट में भी उसका प्रोविजन इन्होंने नहीं किया। फिर पीने के पानी के लिए भूमिगत टैंक का निर्माण कराया जाना है इसकी 5 लाख की और डिमाण्ड कर दी। विद्यालय के ग्राउण्ड लैवल का काम कराया जाना है, बिजली का काम पूरा नहीं है। इसके लिए इन्होंने फिर राशि मांगी है और वह राशि विभाग ने, मैंने क्वेश्चन लगाया तो विभाग ने वह राशि भी जारी कर दी, 54.60 लाख रुपये। 2003-04 की माननीय मुख्य मंत्रीजी की बजट घोषणा, उसमें इनकी डिमाण्ड पूरी नहीं हो रही है। ये एस्टीमेट ढंग से नहीं बनाते क्या? इतने इंजीनियर,

(श्रीमती अनिता भदेल)

एक्स ईएन, एसई वहां बैठते हैं, फिर क्या हाल है यह? इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस प्रकार जो अधिकारी लापरवाही बरते। अभी वह बना नहीं है, अभी वह समाज कल्याण विभाग को सुपुर्द नहीं हुआ है, फिर भी कमरों की दीवारों में क्रेक्स आये हुए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है 4 करोड़ रुपये के लगभग राशि इसमें लग गयी है। 10 साल हो गये इस काम को, कभी पूरा नहीं हुआ। कितने और सालों तक इस काम को खींचोगे। वह फटना ही है क्योंकि देखरेख के अभाव में निर्माण पूरा नहीं होना है।

इसी संदर्भ में एक बात और कहना चाहती हूं। पिछली गवर्नमेंट ने जनाना हास्पिटल, अजमेर के भार को देखते हुए अलग से आपरेशन थियेटर बने, अलग से वार्ड बने, इसके लिए भी लगभग 4 करोड़ की राशि पीडब्ल्यूडी को दी है। पीडब्ल्यूडी के लोग वही ट्रैडिशनल काम करना चाहते हैं। न तो उन्हें डाक्टर्स की आवश्यकता के अनुरूप आपरेशन थियेटर बनाने की जरूरत है। अपनी मर्जी से जैसा उनके कमीशन में ठीक बैठता है, मैं स्पष्ट कह रही हूं यह बात, उस तरह का वहां निर्माण कार्य करना चाहते हैं। मेरा निवेदन है अब तो हाईटेक का जमाना है। हमको कोई फ्लैट भी बेचता है तो वह थ्री डी दिखाकर बेचता है कि ऐसा फ्लैट हम बेचने वाले हैं तभी कोई खरीदता है। हमारे यहां जे ईएन, एक्स ईएन इतने अपडेट नहीं हैं कि वे इस प्रकार के एस्टीमेट को बना सकें। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि प्राइवेट हास्पिटल और सरकारी हास्पिटल को हम देखें तो हमें बहुत ज्यादा अंतर पता पड़ता है, क्वालिटी उसकी ठीक नहीं होती है। कम से कम हास्पिटल्स को तो बख्शो। वहां तो आप कोई कमीशनखोरी मत करो। मेरा इतना सा निवेदन है अजमेर जनाना हास्पिटल में जितना पैसा दिया है उसके काम की अवधि निकले एक साल हो गया, लेकिन आज तक विभाग के डाक्टर्स परेशान हैं, कलक्टर परेशान हैं, बार-बार आग्रह के बावजूद भी वे यह हैण्डओवर नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आपरेशन थियेटर में लाइट कैसे लगनी चाहिए इस विषय को मुद्दा बनाकर आज तक भी जनाना हास्पिटल के वार्ड और आपरेशन थियेटर सार्वजनिक निर्माण विभाग सुपुर्द नहीं कर पाया। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से सरकार की छवि भी सुधार पाएंगे और यह ठप्पा लगा हुआ है कि सरकारी काम ऐसे ही होता है, उस छवि को हम कहीं न कहीं मिटाने की कोशिश करेंगे।

(श्रीमती अनिता भदेल)

एक मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जब यहां से यह घोषणा होती है कि विधायकों को यह सड़कें दी जाएंगी, धार्मिक सड़कें या मिसिंग लिंक सड़कें तो उसमें यह नहीं देखा जाता कि कौनसा क्षेत्र शहरी क्षेत्र है और कौनसा ग्रामीण क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र के लोग बहुत जागरुक होने के नाते या ट्रेडिशन के कारण से सफाई की आवश्यकता को देखते हुए हम मैक्सिमम सड़कें चाहे वह नगर निगम बनाये या वे नगर सुधार न्यास के माध्यम से बने, नाली टू नाली सड़कों का प्रोविजन लेते हैं और बनाते भी ऐसे हैं, चाहे वह हमारी विधायक कोष की सड़क हो चाहे दोनों डिपार्टमेंट की सड़क हो। जब पीडब्ल्यूडी की सड़क मिलती है तो उसमें लम्बाई का प्रोविजन होता है कि फिक्स इतनी लम्बाई में आप सड़क बना सकते हो। चौड़ाई भी उसमें फिक्स होती है कि इतनी चौड़ाई में ही आप सड़क बना सकते हो। उसके कारण से जो हमें परेशानी आती है, शहरों में अधिकतर परेशानी अतिक्रमण की होती है। यदि हम नाली से नाली सड़क बना देते हैं तो अतिक्रमण से मैक्सिमम हम बच सकते हैं। यही चीज ध्यान देकर हम नाली से नाली सड़क बनाने का प्रोविजन, यदि शहरी क्षेत्र में कोई धार्मिक सड़क देते हैं या मिसिंग लिंक की सड़कें देते हैं तो हमें चाहिए कि हम नाली से नाली सड़क, चाहे वह कितनी ही चौड़ी सड़क हो आप उसकी लम्बाई छोटी कर दें यदि आपका एस्टीमेट बढ़ रहा है तो। लेकिन उसको नाली से नाली बनाने की स्वीकृति प्रदान करें ताकि जो परेशानियां हैं उनसे बचा जा सके।

तीसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगी डिपार्टमेंट की सड़कों की क्वालिटी ठीक नहीं होती है।

मेरा एक सुझाव है क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम मैटेरियल बेस्ड, डिपार्टमेंट मैटेरियल दे और लेबर कांट्रेक्ट करके हम सड़कों का ठेका दे सकते हैं। यदि हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है, मैं नगर परिषद की सभापति भी रही हूं, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के तहत हमने जितनी भी सड़कें बनाईं क्योंकि लेबर कांट्रेक्ट पर थी और मैटेरियल नगर निगम का था और उस कारण से आज तक वो सड़कें चाहे वो सी.सी. की सड़क हो चाहे डामर की सड़क को, पूरी तरह से मेंटेन है। आज यदि उस सी.सी. की सड़क में कोई नल का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उसको जे.सी.बी. बुलानी पड़ती है क्योंकि मैन्युअल वो खुद नहीं सकती, इतनी अच्छी क्वालिटी की वो सड़क बनी है। इसलिए मैं अपना निवेदन करना चाहूंगी कि यदि इस

(श्रीमती अनिता भदेल)

तरफ भी हम सोच सकते हैं और इस कार्य प्रणाली के आधार पर हम कुछ शहरों को ही चुन लें, कुछ छोटी सड़कों को ही चुन लें और उसमें प्रयोगात्मक रूप से करके देखें तो शायद हमें रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं।

तीसरी बात, मैं निवेदन करना चाहूंगी, मैंने अपने कटौती प्रस्ताव दिये हैं उन कटौती प्रस्तावों में अजमेर की कुछ डिमाण्ड्स हैं उनके बारे में मैंने निवेदन किया है। अजमेर में एक तो सबसे बड़ी बात है कि यातायात के कारण से ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। अजमेर में एक ही लाइफ लाइन रोड है और वो है स्टेशन रोड। उसी रोड से सारा ट्रैफिक निकलता है और लोग बहुत परेशान हैं। मैंने निवेदन किया था कि यदि हम अजमेर की कोई रिंग रोड दे सकते हैं, बाइपास होकर आदमी जयपुर जाना चाहे या अन्य शहरों में जाना चाहे तो यदि रिंग रोड अजमेर के लिए दे सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अजमेर के लोगों को जो ट्रैफिक के कारण से लेट हो जाते हैं, कई बार एम्बुलेंस फंस जाती है और हास्पिटल तक नहीं पहुंच पाते तो उस समस्या से हमें निजात मिल सकती है।

निवेदन करना चाहूंगी कि अजमेर दक्षिण विधान सभा क्षेत्र एक ऐसा विधान सभा क्षेत्र है जहां अजमेर के लिए यह कहा जाता है कि अजमेर रेलवे के कारण से बसा है, यह अंग्रेजों की टेरिटरी में थी और अजमेर में जो भी बसावट हुई वो रेल के दोनों कारखानों कैरीज और लोको के कारण से हुई। इसलिए रेलवे के मैक्सिमम डिपार्टमेंट अजमेर में हैं और रेलवे का 90 प्रतिशत हिस्सा मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है। चाहे डी.आर.एम. आफिस हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे कालोनी हो, जो कुछ भी है उनका 90 प्रतिशत हिस्सा अजमेर दक्षिण में आता है। इसके अतिरिक्त जो लाइनें निकली थीं उस समय तो चूंकि आबादी नहीं थी इसलिए आबादी से बाहर थी लेकिन अब आबादी का विस्तार इतना अधिक हो चुका है कि कम से कम 20 रेलवे के लेवल क्रोसिंग मेरे विधान सभा क्षेत्र से निकलते हैं और विधान सभा क्षेत्र भी दूर-दूर बिखरा हुआ है शहरी क्षेत्र होने के कारण से भी। तो मैंने मंत्री महोदय को निवेदन किया है कि मेरे रेल्वे क्रासिंग जिनमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है उनमें एक तो 1बी है, दूसरा 50बी है जो तोपदड़ा रेलवे क्रासिंग है, बहुत लम्बे समय से इस पर काम चल रहा है लेकिन तोपदड़ा का रेलवे क्रासिंग आज तक नहीं बना है। 46बी है, 48बी है, ये चार लेवल क्रासिंग ऐसे हैं जिन पर रेलवे का आर.ओ.बी. बनना नितांत आवश्यक है। डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर के तहत वहां

(श्रीमती अनिता भदेल)

पर अण्डर-पास बनाये जा रहे हैं लेकिन लोगों ने विरोध किया अण्डर-पास हमेशा पानी से भरे रहते हैं, बारिश के दिनों में वहां से नहीं निकल सकते इसलिए कम से कम 46 और 48 के बीच में क्योंकि इनके बीच में 47 और है, ये दोनों जो लेवल क्रासिंग हैं इनमें से किसी एक के ऊपर तो कम से कम आर.ओ.बी. बनना ही चाहिए।

इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करना चाहूंगी कि साईं बाबा मन्दिर बहुत आस्था का केन्द्र है और दूर-दूर से लोग वहां पर आते हैं। साईं बाबा मन्दिर पर जाने वाली रोड डायरेक्ट मुख्य मार्ग से कनैक्टेड नहीं है इसलिए इस मन्दिर तक जाने वाली सड़क को भी क्योंकि मैंने मंत्री महोदय को पहले लिखकर भी दिया है, यदि उसके साथ जोड़ दिया जाएगा तो शायद इसी वर्ष में उस मन्दिर तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए हम सुविधा उपलब्ध करा पायेंगे।

एक और निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में डाक बंगला है, राजकीय महाविद्यालय है लेकिन राजकीय महाविद्यालय की देखरेख के अभाव में, रख-रखाव के अभाव में आज बहुत बुरी स्थिति है। वह राजकीय महाविद्यालय है और पांच हजार से अधिक स्टूडेंट्स वहां पढ़ने के लिए आते हैं, यदि हम उनकी व्यवस्था के लिए, उस महाविद्यालय के भवन के रख-रखाव के लिए इसी वित्तीय वर्ष में कुछ राशि प्रदान करेंगे तो शायद बच्चों को फायदा होगा।

इसके अतिरिक्त एक टनल बनाने की बात मैंने कही है। अजमेर से पुष्कर जाते हैं तो पुष्कर में घाटी पड़ती है और जब पुष्कर मेला भरता है तो इतना ज्यादा दबाव होता है कि हर साल कम से कम 10-15 एक्सीडेंट वहां होते ही होते हैं। तो मेरा निवेदन है कि यदि अजमेर से पुष्कर जाने के लिए पुष्कर की पहाड़ियों के बीच में से हम टनल बना देंगे तो यह भविष्य के लिए भी ठीक रहेगा और एक्सीडेंट से भी छुटकारा मिल पायेगा। क्योंकि घाटी पर एक ट्रक, एक बस पलट जाती है तो फिर पूरा मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, दूसरा यातायात वहां से निकल नहीं सकता और वैकल्पिक मार्ग वहां पर कोई नहीं है। इसलिए अजमेर से पुष्कर जाने के लिए टनल का निर्माण बजट में तो नहीं रखा है लेकिन आने वाले समय में यदि उसकी स्वीकृति भी होगी तो अजमेर के लोगों को, पुष्कर के लोगों को और पर्यटन की दृष्टि से आने वाले लोगों को काफी फायदा मिलेगा।

(श्रीमती अनिता भदेल)

जब हम जयपुर से अजमेर जाते हैं तब आपने देखा होगा कि अजमेर प्रवेश करते हैं तो अजमेर प्रवेश करने से पहले एक बहुत बड़ा पुल बना हुआ है। हम लोगों को तो जानकारी होती है कि अजमेर आ गया है लेकिन बाहर से कोई अजनबी व्यक्ति आता है तो उसको पता ही नहीं पड़ता है कि अजमेर आ गया है और वो बहुत आगे तक निकल जाता है नये पुल के निर्माण के कारण से। इसलिए यदि अजमेर का जो प्रवेश है, जो एंट्री है उसको ठीक कर देंगे, उस पर कोई गेंट्री लगा दें और उससे एक या आधा किलोमीटर पहले ही हम यह कह दें कि आगे जाकर आप अजमेर इस तरफ मुड़ सकते हो तो शायद अजमेर के लोगों को और बाहर से आने वाले लोगों को इससे फायदा मिलेगा क्योंकि अजमेर की एंट्री आजकल बहुत बुरी हो गई है, पुल निर्माण के कारण पता ही नहीं पड़ता कि अजमेर आया है या अजमेर निकल गया।

एक और निवेदन करना चाहूंगी कि कई बार सड़कों की हम बहुत बात करते हैं लेकिन सड़कें हम विधान सभा के स्तर पर देंगे जैसे पिछले समय में मिलती आई हैं कि हर विधायक को मिसिंग लिंक की 8 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो ठीक रहेगा क्योंकि हम धार्मिक सड़कें भी उसी आधार पर यदि देंगे तो हम जो चुनाव में वायदे करके आये हैं उन वायदों को पूरा कर पायेंगे।

हमारे यहां दो-तीन विद्यालय हैं। एक राजाकोठी गुलाबबाड़ी विद्यालय है। बस सम-अप कर रही हूं। वो विद्यालय लड़कियों का विद्यालय है लेकिन उसके चारों और कोई चारदीवारी नहीं है और आस-पास रहने वालों ने अतिक्रमण कर लिया है। यदि हम उसकी चारदीवारी के लिए पैसा देते हैं तो निश्चित रूप से बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और बालिका शिक्षा को और अच्छा बनाने में हमें सफलता मिलेगी।

एक अंतिम विषय कहना चाहती हूं। हमारा जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज और अस्पताल, मैं समझती हूं कि राजस्थान का सबसे पुराना मेडिकल कालेज और अस्पताल है। इस मेडिकल कालेज और अस्पताल की जो बिल्डिंग है वो इतनी जर्जर अवस्था में है कि आये दिन प्लास्टर गिरता है मरीजों के ऊपर, रोज अखबारों में आता है। उसका नाली सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है, सीवरेज के जो टैंक हैं उनका लेवल इतना नीचे हो गया है कि बाहर तो सड़क के ऊपर सड़क बन जाती है, लेवल ऊपर हो जाता है और नीचे जो भवन है उसमें वो लेवल मेंटेन हो नहीं पाता है क्योंकि वो जब बना था

(श्रीमती अनिता भदेल)

तब का ही बना हुआ है। मेरा निवेदन है कि क्या इन पांच सालों में हम उस मेडिकल कालेज और हास्पिटल की बिल्डिंग को नई बनाने की कोशिश कर सकते हैं? क्योंकि रिनोवेशन उसमें हो नहीं सकता। अब तो पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारी भी फेल हो गये हैं कि उसको कैसे रिनोवेट किया जाए? उसकी नाली सिस्टम को, उसके सीवरेज सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए और बिल्डिंग की हालत इतनी बुरी है कि उसका रिपेयर हो ही नहीं सकता, उसके ऊपर और कोई निर्माण हो ही नहीं सकता। इसलिए यदि जे.एल.एन. हास्पिटल के बारे में हम चिंता करते हैं, मेडिकल सर्विसेज के बारे में चिंता करते हैं, रोगियों के बारे में चिंता करते हैं तो हम इसका भवन बनाने की नितांत आवश्यकता है, उसका भवन यदि बन जाता है तो रोगियों को सुविधा दे पायेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं। माननीय सभापति महोदय ने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र सिंह भादू।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19 और 21 के कट मोशन पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका हार्दिक आभार। आज सारा सदन इस बात से चिंतित है कि सड़कों का जो निर्माण कार्य है वो बहुत ही घटिया स्तर का हो रहा है। जहां भी सड़कों का या सरकारी भवनों का निर्माण होता है, निश्चित रूप से वो कम अवधि के अन्दर ही जर्जर हालत में हो जाते हैं। खासकर सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ से, हनुमानगढ़ में तो पूर्ववर्ती सरकार ने एक फोर लेन बगैर मतलब का बनाया था उसका सिर्फ एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। माननीय वसुंधरा जी की पिछली सरकार के समय में सूरतगढ़ से लेकर हनुमानगढ़ तक की बहुत अच्छी सड़क बनी, बड़ा अच्छा उसका निर्माण हुआ, अच्छी रोड चल रही थी लेकिन न जाने क्यों पिछली सरकार के क्या मन में आई, उस समय के पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री महोदय के क्या दिमाग में आई कि उन्होंने वो पूरी 55 किलोमीटर की सड़क जो मेगा हाइवे की तरह की सड़क थी उसको फोर लेन में तब्दील किया। फोर लेन बनाने में इतना घटिया निर्माण हुआ, हालांकि उसमें जब हमने बार-बार एतराज किया तो हमें कहा गया कि यह ठेकेदार की जिम्मेदारी है। अगर इस तरह का घटिया निर्माण होगा तो ठेकेदार दुबारा इसका कार्य करायेगा। लेकिन उसके बनने के बाद में जिस तरह से एकदम वह उखड़ने लगी, उसकी इतनी शिकायतें हुईं, उसकी इतनी जांच हुई मैं आपको

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

जानकारी देना चाहता हूं कि नौ इंजीनियर्स, एसई, एक्सईएन, एईएन और जेईएन आज की तारीख में सस्पैंड हैं। उनके खिलाफ जांच चल रही है। करोड़ों रुपयों का उसके अन्दर घोटाला हुआ है। अगर उनकी जांच हो जाये और उन्हें सज़ा भी हो जाये तो उसमें उन सबका कुछ नहीं जाने वाला है क्योंकि हमारी एक इतनी बड़ी महत्वपूर्ण सड़क थी, जो इतनी अच्छी हालत में चल रही थी और सिर्फ विभाग की लापरवाही की वजह से हमें वह तकलीफ सहनी पड़ रही है। चार साल उस ठेकेदार के पूरे हो गये हैं, एक साल के अन्दर उसका कार्यकाल पूरा हो जायेगा। वह अभी तक उसके पुनर्निर्माण में लगा हुआ है। पैचेज लगा रहा है लेकिन एक साल के बाद में जब उसका कार्यकाल पूरा हो जायेगा, उसके बाद में उस पर कौन लगायेगा, हमें उस सड़क को बगैर मतलब झेलना पड़ेगा। इस तरह के कारनामे पिछली सरकार में हुए हैं, उन पर ध्यान देने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, सूरतगढ़ के अन्दर बहुत पुराना कन्या महाविद्यालय बना हुआ है जो आजकल सीनियर सैकण्डरी स्कूल है। उसकी पूरी की पूरी बिल्डिंग दुबारा बनने योग्य है। छह कमरों को उसके अन्दर पीडब्ल्यूडी ने नाकारा घोषित कर दिया है। सारी की प्लिंथ नीची होने की वजह से और थोड़ी सी बारिश आने की वजह से, और बारिश न भी आये तो नालियों का गंदा पानी आने की वजह से वह बिल्डिंग भर जाती है, इसलिए उसको पुनर्निर्माण की आवश्यकता है।

इसके साथ-साथ मेरे सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के जैतसर मण्डी के अन्दर भी पिछले दिनों लड़कियों का बहुत पुराना स्कूल था, उसकी छत गिर गई और बाद में सारा का सारा गिर गया। इस तरह के जो काम हैं, उनको देखने की जरूरत है। हमारे वहां इनके निर्माण की बहुत ही आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-21 के अन्दर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पुल निर्माण के अन्दर, हमारे यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है, वह थर्मल से होती हुई अगर रावतसर और बीकानेर की तरफ जायें तो उसके बीच में घग्घर डिप्रेशन आते हैं। उन घग्घर डिप्रेशनों के ऊपर साल में कम से कम तीन महीने पानी चलता है और वहां पुल नहीं बना हुआ है। सरकार के विचाराधीन है। वसुन्धराजी के टाइम में विचाराधीन था, उसका शिलान्यास हुआ लेकिन सरकार बदलने के बाद में स्थिति ऐसी की ऐसी

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

बनी हुई है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पुल का निर्माण कराया जाये। यह पुल ठेठार और सरदारपुरा खरता के बीच में जो घग्घर डिप्रेशन का बहाव है, उस पर बना हुआ है।

इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, सूरतगढ़ से अनूपगढ़ की जो रोड है, वह बोर्डर रोड के पास है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं सदन में, ऐसी बुरी हालत की सड़क आज शायद राजस्थान में कोई नहीं होगी। बोर्डर रोड के लोग उस सड़क पर एक पैसा खर्च नहीं करते। उससे हम लोगों को आने-जाने में बड़ी दिक्कत होती है। 85 किलोमीटर का लम्बा जो सफर है, उसमें बड़ा समय लगता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में पूर्व से पश्चिम की तरफ जो रोड जुडेंगी तो बोर्डर रोड से लेकर पीडब्ल्यूडी को देकर या जो भी स्कीम हो या बीओटी की हो या अन्य जो भी हो, उसके अन्दर इसका निर्माण कराकर इस क्षेत्र के लोगों को राहत दी जाये। हमारी जो सारी मेन मुख्य धान मण्डी हैं चाहे वह सूरतगढ़ से लेकर, सूरतगढ़ है, जैतसर है, विजयनगर है, अनूपगढ़ है, घड़साना है, ये सारी की सारी मण्डियां उसी रोड से जुड़ती हैं तो यह ध्यान देने वाली है।

इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 5 की पुली से लेकर जैतसर तक की तीन किलोमीटर की सड़क है। वह बिल्कुल ही मोडरेबल नहीं है। उसके ऊपर किसी तरह का साधन नहीं चल सकता। लोग आसपास के खेतों में से होकर निकलते हैं। थोड़ी सी बारिश आने के बाद में वहां हमको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस रोड को भी बनाने की जरूरत है।

गंगानगर जिले से हनुमानगढ़ जिले, दोनों एडजोइनिंग जिले होने के कारण छोटी-छोटी दो-दो, तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर की सड़कें हैं जो आपस में जिलों को जोड़ने वाली हैं। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन रहेगा माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से कि इस ओर ध्यान देकर, यह जो दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर की सड़क है, जिससे हमें एक जिले को दूसरे जिले की कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। ऐसी सड़कों के निर्माण की भी राजस्थान सरकार स्वीकृति देकर लोगों को राहत दिलाने की व्यवस्था करे।

इसके अलावा मेरे सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर किंकरवाली जोहड़ी से 239 आरडी होते हुए जैतसर-डाबला रोड में जोड़ने के लिए नई रोड

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

की आवश्यकता है। सुरजनसर पातलिया ढेहर को जोड़ने के लिए, गोविन्दसर को जोड़ने के लिए 2 जीडीएम, 4 जीडीएम और 6 जीडीएम के लिए नई रोड की आवश्यकता है। डीडवाना से खारिया होते हुए अर्जुनसर स्टेशन तक एक रोड बनने की जरूरत है। भोजूसर दईदासपुरा रोड जोड़ना, राजियासर स्टेशन गांव से चक गोदारान, चक अमरपुरा सड़क के साथ-साथ पुलिया निर्माण फुलेजी माइनर पर कराने की जरूरत है। घमंडिया से 196 हैड तक के लिए रोड जोड़ने की जरूरत है। सिंगरासर और लदेर के लिए भी सड़क जोड़ने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा सूरतगढ़ शहर के अन्दर ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। पिछली सरकार ने उसका काम शुरु किया था लेकिन वह इतनी धीमी गति से चल रहा है जिसके बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वह कब बनेगा? इसलिए मेरा यह निवेदन है कि उस काम को भी गति देने के लिए सरकार जरूर न जरूर कोई काम करे।

इसके अलावा, सूरतगढ़ शहर जो बसा हुआ है, वह दोनों तरफ शहर है और बीच में रेलवे स्टेशन है। वहां थर्मल पावर स्टेशन होने की वजह से 18 रेलगाड़ी रोज की वहां से आवागमन करती हैं और उसके अलावा 32 सवारी रेलगाड़ियां आती और जाती हैं। इस तरह से हमारे यहां के रेलवे फाटक पूर्णतया बंद रहते हैं। रेलवे स्टेशन के भवन का जीर्णोद्धार हो रहा है, नया भवन बन रहा है, आधुनिक तरीके का स्टेशन बन रहा है। इसलिए सूरतगढ़ के पूरब से पश्चिम के जो लोग आने-जाने वाले हैं, उनको बड़ी दिक्कत रहती है। उनकी दिक्कत दूर करने के लिए हमें वहां अण्डरब्रिज बनाने की आवश्यकता है। अत: मैं यह सदन में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि दो अण्डरब्रिज का निर्माण वहां करवाने के लिए जरूर व्यवस्था कराने का श्रम करें।

इसी तरह से मोकलसर से नेशनल हाइवे जोड़ने के लिए लिंक रोड बनी हुई है लेकिन रेलवे विभाग ने पूरी तरह से इस लिंक रोड को बंद कर रखा है, क्योंकि वहां ट्रेनों का आना-जाना बहुत रहता है। अत: एक अण्डरब्रिज वहां बनाने की भी जरूरत है।

इसके अलावा सरदारगढ़ से हिन्दो से नई सड़क बनाकर जैतसर से जोड़ने का भी काम करना है। राजियासर स्टेशन से श्रीगंगानगर जोड़ने वाली 22 जीबी से श्रीविजयनगर की तीन किलोमीटर बाकी सड़क है। इसके पीछे सारी सड़क का काम हो चुका है लेकिन यह सड़क अनूपगढ़ खण्ड में होने की

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)
वजह से बीच में टूटी पड़ी है। अत: इन सब बातों के साथ जो दूसरी छोटी-मोटी सड़कें हैं, जिनमें अभी मरम्मत की आवश्यकता है, नई सड़कों के निर्माण की जरूरत है, उन्हें बनवाने का आदेश फरमायेंगे माननीय सार्वजनिक मंत्री महोदय। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री मान सिंह गुर्जर।

श्री मान सिंह (गंगापुर): आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक निर्माण एवं सड़कें-पुल विषय पर अपने कटौती प्रस्ताव रखते हुए माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से मांग करूंगा कि गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर जिले का सबसे बड़ा व्यापारिक केन्द्र है और वहां पर 'ए' ग्रेड की मण्डी होने के कारण, रेलवे का बड़ा स्टेशन होने के कारण, कपड़े का बड़ा व्यापारिक केन्द्र होने के कारण, स्कूलों के बच्चों की अधिकता के कारण वहां पर बहुत लोगों का आना-जाना रहता है और वहां का जो डाक बंगला है, वह बहुत ही छोटा है। कई बार वहां पर कोई भी अधिकारी या कोई भी बड़ा आदमी यहां सरकार की ओर से जाता है तो रूकने की समस्या रहती है तो इसलिए हम मांग करते हैं कि हमारे डाक बंगले की रिपेयर हो और उसके अन्दर कम से कम दो कमरों का विस्तार किया जाये जिससे कि उसका उपयोग हो सके।

इसी के साथ में हमारे यहां की जो हायर सैकण्डरी स्कूल की बिल्डिंग है, वह 1947 से पहले की स्कूल है और उसका जो भवन है, अब वह बिलकुल जर्जर अवस्था में हो चुका है तो उस भवन के लिए भी हम चाहेंगे कि उस स्कूल के लिए और गर्ल्स स्कूल, जो भी गंगापुर का बहुत पुराना है, उन दोनों स्कूलों के भवनों के लिए माननीय मंत्रीजी कुछ प्रावधान करें कि उनकी रिपेयर हो सके क्योंकि...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी नहीं हैं।

श्री मान सिंह (गंगापुर): सरकार के मंत्री बैठे हुए हैं। सरकार के मंत्री बैठे हुए हैं। (व्यवधान) ऐसा नहीं है, आप बैठिये।

श्री सभापति: सरकार का कोई भी मंत्री उपस्थित है।

श्री मान सिंह (गंगापुर): ये सब बातें हमको खूब ध्यान है सांचौर से आने वाले माननीय विधायक जी। आप सदन का ध्यान इस तरह से नहीं करें। मंत्रीजी बैठे हुए हैं।

(श्री मान सिंह)

सभापतिजी, इसी के साथ में हमारे यहां की जो कुछ लिंक रोड हैं, उन लिंक रोड्स का जिक्र करने से पहले और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार की सड़कों की घोषणा की है, उससे राजस्थान की जनता को जिस प्रकार की आस लगी है और हम इससे पूर्ण आश्वस्त हैं कि हमारी जो सड़कें हैं, जिसमें गौरव पथ की घोषणा की है उस गौरव पथ के अन्दर हमारे यहां की दो पंचायतें हैं। बजीपुर बड़ी पंचायत है, दस हजार की आबादी से बड़ी है। उसके लिए भी हम मांग करते हैं कि उसको सात मीटर की सड़क से जोड़ा जावे, जिससे उस सड़क के जुड़ने से श्री महावीर जी जो जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, वह उसके बिलकुल तीन किलोमीटर दूर रहता है। अगर उसको गौरव पथ से जोड़ा जाता है तो गंगापुर बजीपुर वाया श्री महावीर जी इस प्रकार हमारा जैन समाज का जो तीर्थ यात्री आता है उसको भी उसका लाभ मिलेगा। इसलिए माननीय मंत्रीजी से अनुरोध है कि बजीपुर को गंगापुर से गौरव पथ में जोड़ने से हमारा जैन समाज का जो तीर्थ स्थान है वह जुड़ता है उसके पास में रहने से। यह हमारा विशेष अनुरोध है।

हमारा जो मेगा हाइवे है मथुरा भाड़ौती, माननीय मंत्रीजी, आप जब भरतपुर सम्भाग गए तो आपने देखा होगा कि उसका काम पिछले एक साल से बंद पड़ा है और जो रिडकोर कम्पनी बना रही है। उसका कहना यह है कि पिछली सरकार ने उसके साथ में जो एमओयू किया और सरकार ने चुनाव के समय उससे कोशिश की थी कि वह कुछ दिन काम करें। पता नहीं पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने क्या उनको कोई दवा की पुड़ियां दी, थोड़े दिन तो उन्होंने डम्पर वगैरह चलाये थे और ऐसा लगा था कि सड़क बन जाएगी। लेकिन वह सड़क बिलकुल बंद पड़ी है और उस कम्पनी ने वहां से अपना काम बंद कर दिया है, तो हिण्डौन से लेकर पूरा गंगापुर तक का जो यह मेगा हाइवे मथुरा भाड़ौती है उसके बारे में विशेष अनुरोध है कि रिडकोर कम्पनी से कान्ट्रेक्ट करके गंगापुर से सवाई माधोपुर का बन चुका है। उस पर एक ही लेयर बाकी है और वह पीपीपी माडल पर है। गंगापुर का एकमात्र धार्मिक स्थल और पर्यटक स्थल है धुंदेश्वर धाम। जहां झरने बहते हैं, पूरा शहर वहां पिकनिक के तौर पर जाता है। उसकी दूरी मात्र 3 किलोमीटर है मेगा हाइवे, धार्मिक और पर्यटक स्थल के रूप में उस सड़क की भी हम मांग करते हैं कि उसको भी आप इसमें शामिल करेंगे जिससे कि गंगापुर के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ में मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे यहां जो छोटी-

(श्री मान सिंह)

छोटी लिंक रोड हैं बजीपुर से शेखपुर, मोचा का पुरा से भालपुर और रैनायल से खेड़ला जनैतपुर और दो सड़कें इसके अन्दर माननीय मंत्रीजी जब भरतपुर सम्भाग में गए थे तो उन्होंने घोषणा की थी, उनका काम भी शुरू हो गया। लेकिन उसके अन्दर थोड़ा सा वन विभाग का कोई पेच आ गया है। हम आपके माध्यम से मांग करेंगे कि वन विभाग से बात करके जो हमारा खेड़ाबाद रामगढ़ मुराडा है जिससे नारायणपुर स्टेशन को जो सड़क जाती है, उस सड़क से पूरा आवागमन लोकल ट्रेन से होता है। उसमें केवल मुश्किल से 500 मीटर का टुकड़ा वन विभाग का आता है। उस समस्या को अगर सुलझा दिया जाए तो वह सड़क हमारी पूरी हो सकती है और उसी के पास में एक गांव आता है जहां 66 साल में कभी सड़क नहीं पहुंची और सम्भाग के दौरे में जब माननीय मुख्य मंत्रीजी वहां पधारीं तो उन्होंने यह कहा कि इस गांव की सड़क बनाई जाए। उस गांव की सड़क बन रही है उसमें भी इतना ही 500 मीटर का टुकड़ा वन विभाग का है। इस मामले में आप वन विभाग से बात करके पूरा कराने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे यहां की सड़कों का गंगापुर की जनता को लाभ मिलेगा। मेरा इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे निवेदन है आप इनको शामिल करेंगे। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या-19 और 21 पर जब चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष की तरफ से हुई। सपोटरा के माननीय सदस्य आलोचना तो करना चाहते थे हमारी सरकार की, लेकिन उनके वक्तव्य से ऐसा हुआ कि वो अपनी पूर्व सरकार की आलोचना करते गए और श्रीमान गोविन्दसिंहजी डोटासरा वह तो ऐसा लगा कि बिना बाल के ही फुटबाल खेल रहे थे। यानी कहीं कोई इधर-उधर कुछ भी नहीं, यूं ही डोटे मारे जा रहे थे। वास्तव में स्थिति ऐसी है..

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, इनको बताओ आपने जो बजट में रखा है पीपीपी, वह कितने बजे से कितने बजे तक पी-पी-पी है?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अभी राष्ट्रीय औसत 100 वर्ग किलोमीटर पर 148 का है और हम वन थर्ड पर हैं यानि 57 पर ही आये हैं। वास्तव में बहुत काम करने की जरूरत है और यह भी तब है जब 2003 से 2008 तक

(श्री मदन राठौड़)

का कार्यकाल हमारी सरकार का निकला। उसमें आदरणीय वसुंधरा जी ने और आदरणीय राजेन्द्र सिंहजी ने जो विकास के काम किए, उसके कारण से थोड़ा अनुपात सुधरा। लेकिन फिर बिगड़ता गया। अब बिगड़े क्या? अभी मार्च की जो स्थिति सामने आई उसमें इनके पास में 24 तो सुपरिन्टेंडेंट इंजीनियर्स सिविल के पद खाली हैं, यही नहीं, एक्स ईएन के 60 पद खाली हैं, ए ईएन के 195 हैं और जे ईएन के 535 पद तो इनके खाली हैं और इनके जो पूर्व मंत्री थे, बड़े भले आदमी थे। वो इनको बार-बार कहा करते थे कि देखिए सुधर जाओ, सम्भल जाओ, नहीं तो हालत ऐसी खराब होगी कि हम तो हारेंगे ही, आप सब भी हारोगे। वास्तव में हुआ भी वही कि ये बिलकुल बीस के आसपास में आकर के रह गए। उनको काम करने भी नहीं दिया और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने 3 अरब 56 करोड़ 66 लाख रुपया काम में ही नहीं लिया। यह स्थिति बनी? यानि 1 लाख 95 हजार 850 किलोमीटर जो सड़क बताते हैं उसमें लगभग 37 हजार 249 तो ग्रेवल रोड हैं। उसको इन्होंने जोड़ा इसके अन्दर। मौसमी रोड 1193 इसमें जोड़ा, यानी आपने वास्तव में विकास का काम नहीं किया। इसके कारण से हम बहुत पिछड़ गए। अभी आदरणीय वसुंधरा जी का शासन आया है तो निश्चित रूप से विकास के काम होंगे। पूर्व में भी करके दिखाया, अब भी करके दिखाएंगे और राष्ट्रीय औसत से आगे बढ़ने का हम प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय औसत भी बढ़ने वाला है क्योंकि वहां पर भी गति अब तेज होने वाली है।

माननीय सभापति महोदय, मुझे आपसे थोड़ा सा डर तो लगता है क्योंकि आप थोड़ा सा ज्योंही खड़े होने लगेंगे तो मुझे बैठना पड़ेगा। इसलिए मैं कुछ अपने क्षेत्र की बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में एक धौला का डाक बंगला है। आश्चर्य होगा आपको कि पिछले पांच वर्ष में उसका ताला नहीं खुला। उसमें निश्चित रूप से कीड़े-मकोड़े का जाल बिछ गया होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय से भी कि धौला का डाक बंगले को तो आप ठीक करवाये, नहीं तो इसको बेच करके इस सम्पति का उपयोग करें। धौला में डाक बंगला बना हुआ है, एक कर्मचारी आपका लगा हुआ है, पांच वर्ष में ताला नहीं खुला, वहां है ही नहीं तो इसका उपयोग करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से पाली का जो डाक बंगला है एक म्यूजिकल चेयर बना हुआ है। यानी वहां केवल छह कमरे हैं, कोई भी आये तो ठहरने की वहां कोई व्यवस्था नहीं है। पाली एक जिला केन्द्र है। मैं सुमेरपुर के

(श्री मदन राठौड़)

लिए भी निवेदन करना चाहता हूं कि उपखण्ड केन्द्र है वहां पर आप डाक बंगला स्वीकृत करेंगे तो निश्चित रूप से वहां पर कई लोगों को राहत मिलेगी। आज दिल्ली की क्या स्थिति है? दिल्ली में जो राजस्थान हाउस है वहां पर भी कमरे मिलते नहीं हैं। मैं सोचता हूं कि वहां पर परमिशन लेनी चाहिए और इसको मल्टी स्टोरी बनाना चाहिए ताकि कोई भी माननीय सदस्य वहां जाए तो वहां पर उसको सुविधा मिल सके। इस प्रकार का प्रयास दिल्ली के राजस्थान हाउस में भी करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से बीकानेर हाउस मिला है। उसका भी पूरा उपयोग हो सके, इसके भी प्रयास होने चाहिए और राजस्थान की जो-जो बिल्डिंग्स वहां पर हैं, जो-जो हमारे भवन हैं, जो केन्द्र सरकार ने कब्जे में ले रखे हैं। प्रयास करके उनको भी वापिस अपने अधीन लेना चाहिए ताकि वहां पर भी हम किसी भी प्रकार से राजस्थान को लाभ दिलवा सकें।

माननीय सभापति महोदय, जयपुर का डाक बंगला आप देखिए। कोई भी जाकर के वहां ठहरने की स्थिति में नहीं है। वहां पर केवल दूसरे लोग ही आकर के बैठते हैं। वहां पर भी स्थिति दयनीय है। निश्चित रूप से इसका भी सुधार किया जाना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो नेशनल हाइवे-14 है वहां पर एक ऐसा काम किया है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को कि पिछले जो अपना सत्र था, उसमें मैंने जो निवेदन किया था, इन्होंने नेशनल हाइवे अथोरिटी आफ इण्डिया के अधिकारी को और राजस्थान के वहां के जो सुपरिन्टेंडेंट इंजीनियर्स हैं, चीफ इंजीनियर और कलक्टर को साथ में देकर के मेरे विधान सभा क्षेत्र में साथ में भेजा। जो -जो सुधार मैंने बताये, वो सुधार इन्होंने किए। लगभग छह अतिरिक्त पुल नेशनल हाइवे-14 में बनवाने में सफलता भी मिली। लेकिन एक पुल है हिमावास का, हिमावास वह भी टोल रोड है। उसको और इधर डेन्ड्या की तरफ से जो रोड आता है वहां पर निश्चित रूप से एक पुल बनवाना चाहिए। यह पुल आज नहीं तो कल बनवाना पड़ेगा। क्योंकि यह दुर्घटना का एक केन्द्र बन चुका है और वहां पर यह समस्या निश्चित रूप से बनेगी। ठीक इसी प्रकार से नेशनल हाइवे-65 पर जो रूपावास भावरी होकर के आहौर की तरफ मार्ग जाता है।

(16.00 बजे)

उस मार्ग पर भी पुल बनवाना बहुत जरूरी है। राजस्थान सरकार ने भी केन्द्र को लिखकर के भेज दिया है। उन्होंने कहा कि साढ़े सात करोड रुपये इसमें

(श्री मदन राठौड़)

खर्च आएगा। तो राजस्थान सरकार ने अपने हिस्से की राशि जमा कराने का भी कह दिया है। मैं सोचता हूं कि इसमें थोड़ा सा प्रयास किया जाएगा तो निश्चित रूप से ये पुल भी बन जाएगा और वहां पर एक ट्रैक्टर का ऐसा एक्सीडेंट हुआ क्योंकि वो रोड थोड़ा ऊंचा है। एक्सीलेटर दबा कर रखना पड़ता है गियर हेवी रखना पड़ता है। ट्रैक्टर वाला या कोई भी साधन वाला ऊपर चढ़ने के लिए अपनी स्पीड को बनाये रखेगा, उधर से कोई वाहन आएगा उससे टकरा करके उस ट्रैक्टर के भी तीन टुकड़े हो गये इस प्रकार की दुघटनाएं वहां हो सकती हैं, निश्चित रूप से वहां पर पुल बनवाना चाहिए।

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आपको भी एक आश्चर्य होगा अभी ये धर्मपाल जी चौधरी साहब बोल रहे थे कि ये टोल रोड में गणना करने में कहीं गलती हो जाती है। अब टोल रोड की गणना की बात मैं आपसे निवेदन करूं कि एक यहां पर ऐसा टोल रोड है दिल्ली की तरफ वहां पर इन्होंने गणना में बहुत बड़ी गलती की है। वहां इस प्रकार की गणना हुई कि एक अप्रैल, 2009 को भरतपुर-मथुरा राज्य राजमार्ग–1 जिसे बाइपास के टोल टैक्स संग्रहण हेतु दरों में इन्होंने पूर्व की दरों के आधार पर गणना कर दी जिसके कारण से 73 लाख पैंतीस हजार का नुकसान हुआ और इसमें मैं सोचता हूं कि अपने किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए 5 मार्च, 2010 से 4 मार्च, 2011 तक वहां पर एक शीशराम नाम के व्यक्ति को उन्होंने पुरानी दरों पर ठेका दे दिया इसके कारण से 41 लाख 74 हजार का इनको नुकसान हुआ। ऐसी कई त्रुटियां हुई हैं। मैं उन सब पर तो जाना नहीं चाहूंगा लेकिन एक दो निवदेन और करूंगा कि जैसे चाणोद अभी तय हुआ कि बड़ी पंचायत है उसको पंचायत समिति के केन्द्र से जोड़ने की जो योजना बनी है, जो स्वीकृति मिली है। दस हजार की आबादी वाला तो कोई पंचायत मेरे क्षेत्र में है नहीं लेकिन चाणोद, बड़गांवड़ा, कौसेला होकर के, तख्तगढ़ और सुमेरपुर तक का ये मार्ग बन जाए तो निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे क्षेत्र को भी मिलेगा। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा सभापति महोदय, कि ये जो फोर लेन की जिनको स्वीकृति मिली है, उनको जितनी राशि मिली है वो जीरो से लेकर के मिट्टी की भराई, कंक्रीट बिछाना, पेवर बनाना मतलब रोड रोलर चला कर पेवर बनाना ये सारा पैसा उनको मिला है। उन्होंने टोल रोड तो बना दिया लेकिन हमारा जो पुराना फाउंडेशन तैयार था जो बनी बनाई रोड थी वो उन्होंने काम में ली इसका लाभ तो हमको मिलना चाहिए और वह यह है कि

(श्री मदन राठौड़)

जैसे रामदेवरा के पदयात्री आते हैं रामदेवरा के पदयात्री आएंगे और सभापति महोदय, ये तेज गति के वाहन जब फोर लेन पर चलेंगे तो रामदेवरा के पदयात्रियों को दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है और इसी प्रकार से अजमेर के ख्वाजा साहब की दरगाह के लिए भी पदयात्री आते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ये सर्विस रोड दे देवें। जैसे गुजरात के अन्दर सर्विस रोड बना हुआ है इसी प्रकार से नेशनल हाइवे पर भी यदि सर्विस रोड दिलवा दी जाए तो निश्चित रूप से वहां के स्थानीय लोगों को भी लाभ मिलेगा और जो पदयात्री हैं उनको सुरक्षित अपनी पदयात्रा करने में राहत मिलेगी।

जो ये टोल रोड लगे हैं टोल टैक्स देना पड़ता है। अब आप कल्पना करें कि जिले के लोगों को तो बार-बार अपने जिला केन्द्र पर आना पड़ेगा और हर बार उनसे यदि टोल वसूला जाएगा तो मैं सोचता हूं कि उनके लिए अन्याय है इसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो जिस जिले के रजिस्टर्ड पंजीकृत वाहन हैं उन वाहनों को टोल फ्री निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था गुजरात सहित महाराष्ट्र और अन्य प्रान्तों में भी है। यदि इस प्रकार की यह व्यवस्था कर दी जाए तो निश्चित रूप से स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी, यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। कई आरओबीज हैं, इन्होंने पूर्व में स्वीकृतियां तो दी थीं लेकिन निर्माण नहीं हुए। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जवाली का, सोजत रोड का, फालना का और मेरे जवाई बांध का वो आरओबी निश्चित रूप से बनना चाहिए, नहीं तो कई घंटों इंतजार करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या है।

जैसे फोर लेन पर ये बड़े-बड़े भारी वाहन आते थे। हमारी स्टेट की रोड्स को इन्होंने खराब किया है। इसी प्रकार से माइनिंग के लिए बड़े-बड़े भारी वाहन निकलते हैं। हमारी स्टेट की रोड्स को उन्होंने खराब किया है तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आप उनसे वसूलें। उनसे पैसा वापस लें और हमारी रोड्स की रक्षा जरूर करें। एक और बहुत बड़ी समस्या है यह है कि स्टेट की रोड को हाइवे के अन्दर मीडियन नहीं दिया गया है कई स्थानों पर बाकी जगह दिया है लेकिन जो मीडियन दिया जाना चाहिए स्टेट रोड के सम्पर्क के साथ में। इन्होंने क्या किया कि स्टेट रोड वाला आएगा रोड पर उसी दिशा में क्योंकि लैफ्ट में उसको चलना है आगे जाकर के जहां दो-तीन किलोमीटर के बाद में जो मीडियन छोड़ा हुआ है वहां से उसको वापस यू-टर्न करके दूसरी तरफ की अपनी स्टेट की सड़क को पकड़ना पड़ेगा। मैं

(श्री मदन राठौड़)

सोचता हूं कि यह उसके साथ में अन्याय है। निश्चित रूप से उसकी चिन्ता की जानी चाहिए और मीडियन उस सड़क के सामने दिया जाना चाहिए। कई गांवों की इस प्रकार की समस्या है उसका निदान निश्चित रूप से किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा मैं अभी जब गांवों में दौरा करता हूं तो गिरवर के अन्दर एक पत्थर लगा हुआ है कि गिरवर से कुरणा तक की सड़क का निर्माण पूर्व की पर्यटन मंत्री ने किया, उसका पत्थर पर नाम लिखा हुआ है। वहां एक कंकर नहीं लगा है। न तो एक कंकर लगाया गया, डामर तो दिखाया ही नहीं गया। अब वो कैसे शिलान्यास दो साल पहले कर दिया। इस प्रकार का धोखा इन्होंने दिया है और आश्चर्य की बात है कि ये मंत्रीजी भी वहां चले गये विभाग के अधिकारी भी वहां मौजूद थे तब वहां शिलान्यास समारोहपूर्वक हुआ। ठीक इसी प्रकार से इन्होंने कई घोषणाएं ऐसी की हैं जो सड़कें इन्होंने बना दीं जैसे बाली से पिण्डवाड़ा बिलकुल नहीं बनी और इन्होंने अपने पिछले बजट में दिखाई है। यही नहीं, मारवाड़ जंक्शन, सरदार समन्द और जोजावर सड़क भी नहीं बनी। ठीक इसी प्रकार से सोजत रोड जवाली फालना भी नहीं बनी। कई सड़कें बनी नहीं हैं। इन्होंने केवल धोखा देने का काम किया है। इस प्रकार की व्यवस्था इन्होंने की है तो मैं सोचता हूं कि इसमें भी किस प्रकार से अपन सुधार कर सकते हैं इसकी चिन्ता निश्चित रूप से करनी चाहिए। आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय सभापति महोदय, लोक निर्माण कार्य मांग संख्या-19 और सड़क एवं पुल मांग संख्या-21 पर आज इस सदन में चर्चा हो रही है, मैं भी विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्याएं जिनको लगातार पांच वर्षों से इस सदन में उठा रही हूं लेकिन लग रहा है कि जनता को उन समस्याओं से निजात नहीं मिल रही है। पुन: यहां पर दोहराना चाहूंगी और माननीय मंत्रीजी के ध्यान में आपके माध्यम से लाना चाहूंगी। हम लोग लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करके जो जनता का पैसा है उससे हम लोग सड़कें बनाते हैं लेकिन दूसरे विभागों की गलतियों की वजह से या उनकी दादागीरी की वजह से हमारी सड़कों की क्या दुर्दशा होती है इसका जीता -जागता उदाहरण भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि झालावाड़ रोड से रावतभाटा

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

चित्तौड़ स्टेट हाइवे जो हमारा है ग्राम धरनावद में जो रेलवे फाटक नम्बर 76 स्थित है, रेलवे ने कहीं कम से कम दो या तीन वर्षों से उस फाटक को बंद कर दिया और जो हमारी सड़क बनी है उस सड़क का कोई औचित्य नहीं बचा है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहूंगी कि कम से कम हमने जो सड़क बनाई है उस सड़क का सदुपयोग हो, जनता को उसका फायदा मिले इसके लिए भी हमें कोई न कोई कार्यवाही करनी चाहिए। यह मैं कहना चाहती हूं। इसी तरह से माननीय सभापति महोदय, रेलवे गेट नंबर 81 पर राज्य सरकार के द्वारा लगभग तीन करोड की लागत से साठ मीटर चौड़ी सीसी सड़क बनाई गई ताकि भारी वाहन रामगंजमण्डी के अन्दर एंटर न हो पाएं और बाहर की बाहर ही वो निकल जाएं लेकिन कुछ दिनों पहले इस तरह का आदेश हुआ कि रेलवे फाटक नम्बर 81 को बंद किया जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि आप तीन करोड़ की लागत से सीसी रोड बना रहे हो और उसके बाद रेलवे उस फाटक को बंद करने का आदेश दे रहा है, जो मैं मानती हूं कि दो महीने पहले ही उसका काम पूर्ण हुआ होगा लेकिन अगर हमने बंद कर दिया फाटक को तो उस रोड का कोई मतलब ही नहीं रहेगा और उसके बाद जो रेलवे ने निर्णय लिया वो इस तरह का निर्णय कि गेट नम्बर 81 को बंद करके कोई एक छोटा -सा अण्डरब्रिज वहां पर बनाया जा रहा है। न तो उसके नीचे से ट्रक निकल पाएगा या कोई भारी वाहन उसके नीचे से निकल पाएंगे। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसी स्थिति में हमारी जो सड़कें हैं, सरकार का लाखों-करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, जो जनता का पैसा खर्च हुआ है उसके लिए कुछ न कुछ कदम हमें उठाने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, एनएच 12 जो कोटा टू झालावाड़ रोड है उसको फोरलेन करने का निर्णय तो ले ही रखा है लेकिन फिर भी निवेदन करना चाहती हूं कि वह कोटा से दरा होकर, सुकेत होकर झालावाड़ पहुंचे तो निश्चित है कि हमारा जो खनन क्षेत्र है, लाखों का कारोबार रामगंजमण्डी की धरती पर लोग करते हैं, इतनी बड़ी हमारी धनिया मण्डी है, कोटा स्टोन का इतना बड़ा व्यापार वहां पर है, उन लोगों को कुछ न कुछ इसका फायदा मिले। वर्ना अगर हमने इसको रामगंजमण्डी से डायवर्ट कर दिया तो मुझे लगता है कि रामगंजमण्डी का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और झालावाड़ को भी इसका नुकसान होगा।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

पुलों के बारे में भी आज चर्चा हो रही है मैं निवेदन करना चाहूंगी हम लोग बड़े-बड़े नारे स्कूलों के बाहर लिखवाते हैं कि बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन आप देखिये कि गांव की क्या हालत है। कुछ पुलिया अगर दो गांवों के बीच में बन जाए तो कम से कम एक-एक, दो-दो महीने तक बच्चों को घर पर नहीं बैठना पड़ेगा। यह हालात मेरी विधान सभा क्षेत्र के हैं। चाहे हम अमझार नदी को लें, चाहे ताकली नदी को लें, चाहे पार्वती नदी की पुलिया हो, चाहे अमझार की पुलिया हो, हमारे ईश्वरपुरा पीपल्दा की सड़क है उस पर पार्वती नदी पड़ती है अगर उसके ऊपर एक किलोमीटर का पुलिया निर्माण कर दिया, क्योंकि विगत पांच वर्षों में कितनी ही बार मैंने इसका प्रस्ताव भी बनाकर सरकार को भेजा है, पीडब्ल्यूडी के माध्यम से लेकिन हमें मात्र एक पुलिया मिली। मैं तो कहना चाहूंगी कि पूरे पांच साल में एक भी पुलिया का निर्माण करके पिछली गवर्नमेंट ने हमें नहीं दिया। इससे पूरी जनता में रोष है। आज हमारे गांव का सम्पर्क कट जाए तो हमें भी जनता को जवाब देना पड़ता है। इसके ऊपर एक पुलिया बन जाएगी तो ईश्वरपुरा के बच्चे हैं उनको पीपल्दा उच्च माध्यमिक स्कूल तक जाने का बारिश में रास्ता मिलेगा इसके लिए वह आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे। दूसरी बात कहना चाहूंगी अमझार और चेचट सड़क पर खेड़ली हमारा गांव आता है वहां पर बरसों पुरानी खरंजे के रूप में एक पुलिया बनी हुई है, वह आठ मीटर की पुलिया है, उसका निर्माण बरसों पहले हुआ था और आज बिलकुल जीर्णशीर्ण अवस्था में पड़ी हुई है। अगर उस पर हमने थोड़ा -सा भी रिपेयर कर दिया तो किसी भारी हादसे से हम लोग बचेंगे क्योंकि चेचट क्षेत्र में जो माइनिंग एरिया है वहां से अमझार रोड पर डायरेक्ट दरा तक पूरे वाहन निकलकर आते हैं इसका भी हमें विचार करना चाहिए।

दूसरी बात और निवेदन करना चाहूंगी चेचट से देवली और देवली से घाटोली रोड है उस रोड का निर्माण तो हुआ लेकिन जो पुलिया वहां पर पड़ती है, कम से कम दो किलोमीटर की सांडयाखेड़ी गांव के पास पुलिया पड़ती है गत बारिश में भी वह पुलिया इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई कि मैंने खुद ने तीन घण्टे तक खड़े रहकर, बोरियां-कट्टे आते हैं उनमें मिट्टी भरकर डलवाई। मैंने माइनिंग वालों से हैल्प लेकर वहां पर पत्थर डलवाए और पुलिया को हमने 24 घण्टे बाद चालू किया, वर्ना गांव का सम्पर्क भी हमारा कट गया। उसके बावजूद भी अगर उसकी रिपेयरिंग नहीं होती है तो मैं कहना चाहूंगी कि जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हम लोग कर रहे हैं। मैं एक

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

बात और निवेदन करना चाहूंगी कि खातुंदाबेस रोडगढ़ खेड़ारूदा और चेचट उण्डवा होता हुआ छेत्रपुरा वाला रोड है उस पर भी अगर हमने एनएच-9 ए पर अगर एक पुलिया का निर्माण कर दिया तो उसका फायदा भी जनता को मिलेगा।

अमझार है, अमझार से ईश्वरपुरा, आप देखिये पिछली बार कम से कम तीन बच्चों की मौत स्कूल जाते वक्त पिछले 5 या 6 वर्ष में इस पुलिया पर हो चुकी और उसके बावजूद भी हम लोग कोई कदम नहीं उठा पा रहे। मेरा निवेदन है कि हम इस पुलिया को भी बनाएंगे तो उसका फायदा वहां के लोगों को मिलेगा। चेचट, कोटडी और हथौना की सड़क है उसके ऊपर भी जो ताकल नदी है उस नदी के ऊपर अगर हमने पुलिया बना दी तो इसका भी फायदा वहां के लोगों को मिलेगा। कवरपुरा से नयागांव हमारी सड़क है, वहां भी ताकल नदी की वजह से इतना कटाव हो चुका है कि उन लोगों का रास्ता बंद हो जाता है, अपने खेतों तक भी वह लोग नहीं जा पाते, तो इसका भी हमें निर्माण करना चाहिए।

जो सम्पर्क सड़क पाइली है, उस पाइली तक रोड बनाने के लिए, सुकेत से पाइली तक हम लोगों ने सड़क को बना दिया लेकिन पुलिया के लिए कोई पैसा नहीं मिल पाया था। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यहां भी अगर हम पुलिया बनाते हैं तो कम से कम उन लोगों का सुकेत से सम्पर्क बना हुआ रहेगा। क्योंकि बारिश आने के बाद, खनन क्षेत्र का पानी, खान मालिक नवम्बर-दिसम्बर के महीने में उस पानी को मोटर लगाकर बहाते हैं तो बच्चों और गांव के लोगों को निकलने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। झिरीझिराला में हमारी आहू नदी है उस आहू नदी के ऊपर भी अगर एक पुल का निर्माण हो जाए तो कम से कम किसानों को गांव तक पहुंचने में कुछ राहत मिलेगी यह मैं कहना चाहूंगी। सभापति महोदय, ओनली दो मिनट और मुझे दीजिए, गांव की समस्या है उसी को मैं यहां रख रही हूं। मेरा एक और निवेदन है कि हमारा जो खनन क्षेत्र है, वैसे तो मैं किसी के ऊपर किसी तरह का कोई आरोप भी नहीं लगाना चाहूंगी लेकिन सड़कें हमारी हैं। अगर हमारी सड़कें और हमारी जनता का पैसा उसके प्रति अगर हम लोग जवाब देह नहीं रहे तो मुझे लगता है कि जनता को आपको और हमको भी जवाब देना पड़ेगा। आप देखिये, हमारा जो पीपाखेड़ी का रोड है, कितने वर्ष पहले वह स्वीकृत हुआ था, आज भी आधा अधूरा बना हुआ है। मैंने खुद ने हमारे एस ई साहब को बिठाया,

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

हमने चीफ साहब से बात की, सब कुछ बात की जानकारी है कि किस तरह से खान मालिकों ने रोड को उखाड़ कर फेंक दिया। अगर 15 साल पहले किसी ने कोई गलती की है तो उस गांव की जनता को हम कोई सज़ा नहीं दें। अब तो उन को चलने के लिए हम लोग अच्छा रोड दे सकते हैं क्योंकि हमारा पैसा भी पड़ा हुआ है, फिर हम क्यों नहीं उस रोड को बनाते। गांव वालों की जो भी इच्छा है वहां पर, जहां आपको जगह मिले वहीं बनाइये, गांव की जनता को हम रोड देंगे तो मुझे लगता है कि मेरी भी थोड़ी-सी समस्या का समाधान हो जाएगा।

खेरारूद्दा से चेचट की तरफ जो रोड आ रहा है, मोडक होता हुआ खेराबाद और उण्डवा तक जा रहा है, स्टेट हाइवे हमारा बना है, बीओटी के माध्यम से बना है स्टेट मेगा हाइवे। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जब भी कोई हम लोग बनाते हैं तो कम से कम इस बात का तो ध्यान रखें कि कहां से पाइप लाइन गुजर रही है, कहां से किस तरह का डैमेज राज्य सरकार के किसी भी विभाग का हो रहा है लेकिन इस बात को हम लोगों ने इग्नोर किया। उसी का कारण रहा कि चेचट में हमारी पचपाड़ पेयजल योजना, लाखो करोड़ों रूपये लगाकर इस योजना को लाए, रोड के नीचे पूरी पाइप लाइन को दबा दिया गया। स्थिति यह होती है कि जब भी पाइपलाइन टूटती है तो दो-दो, तीन-तीन दिन तक हमारी पेयजल व्यवस्था ठप हो जाती है। इस तरह से कोई बजट पी डब्ल्यू डी उनको देना चाहे, क्योंकि कभी तो पी डब्ल्यू डी पी एच ई डी का नुकसान करती है, कभी पी एच ई डी पी डब्ल्यू डी का नुकसान करती है, इसकी वजह से हर गांव में हमें नुकसान हुआ है तो इस ओर भी हमारा ध्यान होना चाहिए।

वैसे तो पूर्व में भी हमें मिसिंग लिंक मिले हैं और कृषि उपज मण्डी के माध्यम से भी सड़कें बनी हैं, धार्मिक स्थलों की सड़कें भी हम लोगों ने बनवाई हैं। अभी भी हम लोगों ने चुनाव के समय जनता से, चाहे कांग्रेस के विधायक हों, चाहे बीजेपी के हों, सभी ने वायदा किया होगा। अगर पुन: हमें मिसिंग लिंक और धार्मिक स्थानों पर सड़कें दी जाएंगी तो उससे बहुत बड़ा जनता का फायदा होने वाला है।

पुलों की बात आ रही है, उसमें छोटी-सी रामगंजमण्डी की एक समस्या है कि सन् 2006 में हमारा पुल स्वीकृत हुआ, 2008 में उसका कार्य प्रारम्भ हुआ लेकिन विभाग की लापरवाही मानें या जो कुछ भी मानें, आज

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

तक उसका काम पूरा नहीं किया गया। रेलवे ने अपना पूरा पैसा, जो भी उसको खर्च करना था, खर्च कर दिया लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा देना था उसकी वजह से पूरा रामगंजमण्डी का जीना दुस्वार हो रहा है, निकल नहीं पाते इतनी बड़ी परेशानी हम लोगों के सामने खड़ी है, इसको भी हम लोग तुरन्त करें तो अच्छा रहेगा।

जो हमारा खनन क्षेत्र है, आज के बाद अगर खनन क्षेत्र में माइनिंग एरिया में कहीं भी हम लोग रोड स्वीकृत करें तो इस बात का ध्यान रखें कि हम डामर रोड नहीं बनाएं। आप डामर रोड बनाते हों और मात्र दो महीने, तीन महीने में वह खतम हो जाती है तो क्या औचित्य है उसको बनाने का? आगे से इन बातों का हम ध्यान रखे कि माइनिंग एरिया में जब भी रोड का प्रस्ताव जाए तो वह सीसी रोड के मार्फत बनकर जाए, यह मेरा निवेदन है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

एक मिनट, बस एक मिनट साहब। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि जितनी भी हमारी सड़के स्वीकृत हैं, वैसे सबके नाम भी मुझे याद हैं लेकिन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी, चाहे बड़ोदिया आतरिका हो, चाहे मंदरगढ़ का हो, चाहे अखाहा का हो, चाहे गिरधरपुरा हो, चाहे दामोदरपुरा हो, चाहे किशनपुरा डोलिया हो और चाहे झामरा क्यों नहीं हो, आज देश को आजाद हुए इतने वर्ष हो गये और उसके बावजूद भी हम एक सड़क बनाकर गांव की जनता को नहीं दे सकते तो यह हमारी, मैं कहूंगी कि लापरवाही भी है। इसलिए मैं बिलकुल आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि यह जो हमारी स्वीकृत सड़कें हैं, जिनको वन विभाग ने रोक रखा है और कुछेक तो ऐसी हैं जैसे कि हमारी कुदाइला से अमरपुरा होती हुई जो सड़क जा रही है वह रोड दो साल से हमारा स्वीकृत होकर पड़ा है। उसको टैंडर हो गया। फिर उसका री-टैंडर हो गया। तो मैं कहना चाहती हूं कि हम इन सड़कों को क्यों नहीं बना पा रहे? बार-बार जनता धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करती है और हम फिर भी चुप बैठे हैं तो यह काम भी हमें बहुत जल्दी ही पूरा करना चाहिए।

जो पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से हमारे हाट-बाजारों में काम चल रहा है वह लगातार दो-दो, तीन-तीन वर्षों से चल रहा है और आज तक उसका कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है तो उसको भी हम लोग पूरा करें।

हमारा रामगंजमण्डी का राजकीय महाविद्यालय, चेचट का संस्कृत महाविद्यालय और जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, इन सारी बिल्डिंग्स

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

में भवन के अभाव में, उधर स्टूडेंट्स को परेशानी, इधर मरीजों को परेशानी तो मेरा निवेदन है कि जो हमारा जन सहभागिता का पैसा जमा था, हमने दो टुकड़ों में करवाया। भले ही हो सकता है कि आपका पी.डब्ल्यू.डी. इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो कि जो पहले पैसा जमा करवा दिया डेढ़-दो करोड़ रुपया, उसके मार्फत जो राशि हमको मिलनी चाहिए हास्पिटल की वह तो हमने ले ली लेकिन जो राशि हमने बाद में स्वीकृत करवाई उसके अनुरूप जो राशि हमें मिलनी चाहिए वह राशि आज तक नहीं मिल पायी और हमारी बिल्डिंग नहीं बन पा रही है।

जो विधायक कोष से पी.डब्ल्यू.डी. को सड़क के लिए हमने पैसा दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति: कुछ बातें आपकी ऐसी हैं जो आप सीधा उनसे ... (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): बिलकुल, बिलकुल साहब, मैं समाप्त कर रही हूं। ठीक है।

पी.डब्ल्यू.डी. को जो मैंने विधायक कोष से राशि दी। चाहे वह सामुदायिक भवन के लिए हो, चाहे वह सड़कों की हो, दो वर्ष होने के बावजूद पी.डब्ल्यू.डी. ने कहा कि हम पांच लाख रुपए से नीचे की राशि का काम नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों तो आप उनके सामने से नहीं गुजरेंगे। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): सारी। माननीय सभापति महोदय, सारी।

श्री सभापति: आइंदा ख्याल रखें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): तो जो पी.डब्ल्यू.डी. को राशि वापस पंचायतों को, जिला परिषदों को देनी थी वह दो वर्ष होने के बावजूद अभी तक उस राशि का अता-पता नहीं है कि वह राशि कहां गई? मैं बार-बार जिला परिषद में चर्चा करती हूं। सी.ई.ओ. साहब को, सी.ई.ओ. साहब पी.डब्ल्यू.डी. वालों को बोलेंगे और फिर भी वह राशि जिला परिषद के अकाउंट में नहीं पहुंच पा रही है तो माननीय मंत्रीजी से मेरा यह भी निवेदन है कि गांवों में बार-बार लोग पूछ रहे हैं कि वह राशि कहां पर गई? तो उसे तुरन्त प्रभाव से जिला परिषद को दिया जाए।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

लास्ट बात मैं अपनी कहना चाहूंगी कि चारों तरफ से रामगंजमण्डी में सड़कों के काम चल रहे हैं। चाहे खैराबाद रोड हो, चाहे कुदाइलावाला हो, चाहे जुल्मीवाला हो और चाहे ठंडवावाला हो। यह चारों रोड्स के जो काम चल रहे हैं उसमें आपने चौड़ाई की जो सड़कें ली हैं, सी.सी. रोड, उसमें मेरा यह निवेदन है कि अगर बीच में डिवाइडर बनाकर दो भागों में इस सड़क को बांट दिया गया तो रामगंजमण्डी नगर की सुन्दरता भी बढ़ेगी और जो भारी वाहन वहां से गुजरते हैं उससे भी हमें जाम लगने से निजात मिलेगी। यह कहते हुए अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुखराम विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मांग नम्बर-19 और 21 पर माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले साल 3.9.2013 को चार ब्रिज स्वीकृत किये गये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में नर्मदा नहर चलती है। उस नहर से लूणी नदी के एस्केप में पानी छोड़ा जाता है और पानी छोड़ने से चार गांव और बाकी का जो क्षेत्र है वह कट जाता है। चार ब्रिज स्वीकृत किए थे। एक चीतलवाना एस.डी.एम. हैडक्वार्टर है, उसमें स्वीकृत किया आपने डेढ़ करोड का, दो गलीफा में स्वीकृत किए गए थे, एक भादना में स्वीकृत किया गया था।

माननीय सभापति महोदय, वे ब्रिज नहीं होने के अभाव में ओवरफ्लो से जो पानी छोड़ा गया उस पानी से कम से कम पांच-पांच मौतें एक-एक नदी में जहां पर ब्रिज बनने थे, वहां पर हो चुकी थीं। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चार ब्रिज मंजूर किए गए थे। वह चारों ब्रिज 21.2.2014 को निरस्त कर दिए गए हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो चारों ब्रिज हैं, यह चारों ब्रिज एस.डी.एम. हैडक्वार्टर को जोड़ते हैं। साथ ही नहर से जो ओवरफ्लो पानी चलता है, उसमें भी लोगों को आने-जाने की सुविधा रहती है और ब्रिज नहीं होने से 9-10 मौतें तो हुई हैं, आगे कितनी मौतें होंगी, पता नहीं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस काम को पुन: स्वीकृत किया जाए।

इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र में 6-7 ऐसी सड़कें हैं जो पूरी तरह से टूटी हुई हैं, जब से बनी थीं। कोई 2001 में बनी है, कोई 1998 में

(श्री सुखराम विश्नोई)

बनी है, 14-14, 15-15 साल हो गये हैं, जब से सड़क बनी है, आज दिन तक कोई काम नहीं हुआ है। हम बात करते हैं पी.डब्ल्यू.डी. वालों से तो वे कह रहे हैं कि यह कार्य के काबिल नहीं है। यह पूरी रिपेयर के काबिल है। अभी 60 दिन की कार्य योजना में कार्य लगाने के लिए पैसे दिए गए थे परन्तु उन रोड्स पर भी काम नहीं हुआ। वह इसलिए नहीं हुआ कि वह कार्य काबिल नहीं है। उसमें से दो-तीन सड़कें मैं नाम लेकर कहना चाहूंगा। हरियाली से झाब है। करोला से दांगरा है, चीतलवाना हैडक्वार्टर, एस.डी.एम. हैडक्वार्टर से होती गांव है। इसके साथ-साथ में एक हेमागुढा गांव आया हुआ है, उस हेमागुढा गांव में पहले लूणी नहीं, सूकड़ी नदी चलती थी, सूकड़ी नदी आने से वह रपट टूट गयी। माननीय सभापति महोदय, मैं पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर से निवेदन करना चाहूंगा कि 12 साल से वह रपट अभी तक भी टूटी हुई है। साइड में से, रेत में से बड़ी मुश्किल से व्हीकल्स पार होते हैं।

इसके अलावा एक एम.डी.आर. योजना के तहत पिछली सरकार ने साल, डेढ़ साल पहले दस किलोमीटर, आजादी के पहले की रोड चली हुई थी, जो चल रही थी, यहां से मतलब सिंध जाने के लिए रास्ता था, जोधपुर सिंध का। उस सड़क पर 12 किलोमीटर एम.डी.आर. रोड, पिछले डेढ़ साल पहले स्वीकृत की थी। उस ठेकेदार ने आधा अर्थ वर्क कर दिया, थोड़ा काम कर दिया, उसके बाद में वह साल-भर से एम.डी.आर. रोड बंद पड़ी है। कोई उसमें कार्य नहीं हो रहा है। तो मेरा निवेदन है कि इस एम.डी.आर. रोड को तुरन्त चालू किया जाए ताकि लोगों के आने-जाने में सुविधा हो।

मेरा माननीय सभापति महोदय, निवेदन है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में कुल 60 गांव ऐसे हैं जो रोड से जुड़े हुए नहीं हैं। दस गांव महज पिछले साल, डेढ़ साल में जोड़ने का प्रयास किया गया। 50 गांव अभी तक रोड से जुड़े हुए नहीं हैं। वैसे इस बजट भाषण में 100 से 250 तक की आबादी को जोड़ने का प्रस्ताव लिया गया है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सांचोर मुख्यालय में एक डाक बंगला आया हुआ है। वह डाक बंगला कभी भी गिर सकता है और उसकी दीवार ईंटों की बनी हुई है। आधी टूट-टूट कर वह मतलब, उसमें होल हो गये हैं। वह कभी भी किसी के ऊपर गिर सकती है तो इस डाक-बंगले की मरम्मत की जाए। उसके ऊपर जो चार दीवारी चारों तरफ आयी हुई है, वह कीमती जमीन है। शहर के बीच में आयी हुई है। इसलिए उस डाक-बंगले की व्यवस्था दुबारा से की जाए ताकि वह एक सम्पत्ति है, वह सम्पत्ति भी काम आ जाए।

(श्री सुखराम विश्नोई)

माननीय सभापति महोदय, बाकी इस बजट में पी.पी.पी. मोड पर सड़कें देने का प्रावधान किया गया है उसके साथ-साथ ही उसको ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर ठेकेदार को सम्भाग स्तर पर गांव की सड़कों के रिपेयर के लिए भी पी.पी.पी. मोड पर देने का प्रोविजन इसमें किया गया है। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि पांच साल की ठेकेदारी पर जो रोड तैयार करते हैं ठेकदार की पांच साल उसकी गारंटी होती है। कोई भी सड़क बनाता है तो पांच साल की गारंटी है। 20 परसेंट राशि उसकी रोकते हैं। परन्तु पिछले चाहे आप दस साल का उदाहरण ले लो जब से यह सिस्टम चालू किया गया है, 20 परसेंट काटने का और 10 परसेंट की गारंटी का, तो कोई भी ठेकेदार वापस आकर उस रोड को नहीं करता है। जब तक नहीं करते हैं तब तक लोग शिकायतें, धरना, हड़ताल नहीं करते हैं और वह भी मुश्किल से जाकर छोटे-मोटे कार्य करके उस रोड को छोड़ देते हैं तो जो सम्भाग स्तर पर ठेके देने की प्रथा चालू की गई है कि हम ठेकेदार से रिपेयर कराएंगे। ठेकेदार कब रिपेयर करेगा। जो 20 परसेंट राशि रोक रहे हैं। वह भी रिपेयर नहीं कर सकता।

इस तरह का जो प्रोविजन डाला जा रहा है, उससे केवल मात्र जो आज खड्डों की हालत बनी है, वैसी हालत आने वाले समय में रहेगी। 20 हजार किलोमीटर रोड की बात की जा रही है, उस 20 हजार के अन्दर जो भी सरकार की राशि देकर दूसरी पी पी पी मोड की कम्पनीज, प्राइवेट कम्पनियों से लेकर जो रोड बनाई जायेगी, उस रोड में एक सर्वे चल रहा था, उस सर्वे में हर 50 किलोमीटर पर एक टोल आयेगा। आज टोल की लड़ाई चल रही है। मेरे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य काफी बात उठा रहे थे कि टोल माफिया तैयार हो रहे हैं। टोल माफिया आज तो कम हैं, परन्तु हर 50 किलोमीटर पर जब टोल आयेगा, निसन्देह रूप से उनकी दादागीरी बढ़ेगी और वह मजबूत होंगे। उससे आम आदमी का आना-जाना मुश्किल हो जायेगा। रोज हड़ताल, प्रदर्शन और वहां हाइवे जाम, रोड जाम करने की समस्या आयेगी। इसलिये मेरा यह मानना है जहां तक हो सके, सरकार अपने स्तर पर रोड बनाये। अगर अपने स्तर पर रोड नहीं बनाये तो कम से कम टोल पर ऐसी व्यवस्था हो कि सरकार की वहां मानिटरिंग हो। इतनी राशि वहां टोल पर आ रही है। वहां के जो लोकल लोग हैं, उनको आने-जाने की छूट हो, ऐसी व्यवस्था हो। आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री हीरालाल (निवाई)। आप पहले अनुपस्थित थे, इसलिये अब आप पांच मिनट में बोल दें।

श्री हीरालाल (निवाई): बैठा था। सर, मैं बैठा था यहीं।

श्री सभापति: अच्छा, आप बैठे थे।

श्री हीरालाल (निवाई): बिलकुल धीरे बोला और उसमें निवाई नहीं बोला।

श्री सभापति: चलिये फिर आप बोलिये।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सभापतिजी, आपने मांग संख्या 19 और मांग संख्या 21 पर मुझे बोलने के लिये मौका दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय वसुन्धराजी ने ऐतिहासिक बजट पेश किया, उसमें 20 हजार किलोमीटर की सड़कें पूरे राजस्थान में बनाने के लिये मंजूरी दी, उसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। मेरा अनुरोध है कि मेरे पूर्ववर्ती माननीय सदस्यों ने भी निवेदन किया जो सड़कें दी जायें उनमें 10 या 20 किलोमीटर सड़कें धार्मिक स्थानों के लिये भी दी जायें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग मुख्यालय में एक कमरा बी-108 श्री सूरज प्रकाश टांक, संयोजक, संघर्ष समिति को नियम विरूद्ध आबंटित किया हुआ है। मुख्यालय पर बैठकर एक राजनीतिक पार्टी की गतिविधियां आज भी चालू कर रखी हैं। 9-11-12 में अतिरिक्त सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी कि इस कमरे को खाली किया जाये, लेकिन उस कमेटी ने आज तक रिपोर्ट नहीं दी और तत्कालीन मुख्य मंत्री कार्यालय से फोन आ गया कि इस कमरे को खाली नहीं कराया जाये। सूरज प्रकाश टांक पांच वर्ष पहले रिटायर हो गया। मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो व्यक्ति पांच वर्ष पहले रिटायर हो गया और आज भी पी.डब्ल्यू.डी. हैडक्वार्टर पर जयपुर में उस कमरे में कब्जा जमाया हुआ है। इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की भी मिलीभगत है। यह व्यक्ति 1994 से हैडक्वार्टर पर बैठकर इस कमरे का उपयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिये कर रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी को निर्देश देवें कि इस व्यक्ति से तुरन्त कमरा खाली कराया जाये।

अभी 18-7-2014 को इसी व्यक्ति ने चीफ इंजीनियर के टी.ए. के साथ आफिस के समय में बदसलूकी की। उसके कमरे के शीशे तोड़ दिये, आज तक कोई कार्यवाही नहीं की और कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई। इस तरह की गतिविधियां, जो आदमी रिटायर हो जाये और पी.डब्ल्यू.डी. हैडक्वार्टर पर

(श्री हीरालाल)

बैठकर अवैध तरीके से कब्जा जमाकर राजनीतिक गतिविधियां करे, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि सूरज प्रकाश टांक, जो पांच वर्ष पहले रिटायर हो गया, उससे तुरन्त कमरा खाली कराया जाये, ताकि जो अवैध राजनीतिक गतिविधियां वहां से संचालन करना चाह रहा है, वह नहीं हो सके। मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस कमरे को तुरन्त खाली कराया जाये और जो चीफ इंजीनियर के टी.ए. के साथ जो बदसलूकी की है, उस व्यक्ति के खिलाफ तुरन्त प्राथमिकी दर्ज की जाये।

मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं रखना चाहूंगा। माननीय वसुन्धराजी सुराज संकल्प यात्रा के दौरान मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी पधारी थीं और मेरे विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का उन्होंने अवलोकन किया। उन्होंने मेरे चुनाव के दौरान यह बात भी बताई अब पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कें किस तरह की हैं। ज्यों ही राज बना और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान की बागडोर सम्भाली। मैं हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री महोदय, युनुस खान साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो सड़कें ज्यादा टूटी थीं, उन पर पैच वर्क हुआ और जिन सड़कों पर डामरीकरण नहीं था, खाली ग्रेवल था, तुरन्त उन पर डामरीकरण हुआ। जिससे जनता को लगा कि राज बना है और राज बनने से जनता को राहत मिली है। आने-जाने में उनको राहत मिली है। जिन सड़कों पर उनके वाहनों को परेशानी होती थी, कई जगह दुर्घटनाएं होती थीं, आज उन सड़कों का कायाकल्प होने से जनता को राहत मिली है और जनता को यह संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी का राज आया है, माननीय वसुन्धराजी का राज आया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे निवाई विधान सभा क्षेत्र में पीपलू उपखण्ड में आज भी सड़कों की ऐसी स्थिति है कि आजादी के 67 साल बाद भी ऐसी सड़कें हैं जहां गांव में पहुंचना बड़ा दूभर है। बरसात के दिनों में तो वहां से निकलना और बीमारों को अस्पताल तक लाने के लिये भी बड़ी परेशानी होती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में देवरी से डूंडिया तक कोथून से ब्रजलालपुरा तक, पीपलू पुलिस थाने के सामने बोरखण्डी तक, ढूंसरी से रजवास तक, गुढारामदास से बगड़वा तक, नला से हनीफपुरा तक, रायरामपुरा से पीतावास तक, बनस्थली से मोतीपुरा तक, रानोली से बीसालु तक, सैदरिया से भगतरामपुरा तक, नला से मण्डारिया तक, सिरोही से गोपालपुरा तक सड़क निर्माण कराई जाये। साथ ही रानोली से

(श्री हीरालाल)

बिसालू तक, अजीमपुरा से बोरखण्डी तक रोड का निर्माण कराया जाये, गेबोद रास्ते पर इस तरह की स्थिति है कि गेबोद में कई दफा लाखों रुपया खर्च करके सरकार ने रपटा बनाया, लेकिन कभी ज्यादा बरसात होती है, बनास का पानी आता है तो रपटा जैसे बनाया, वैसा का वैसा टूटकर नीचे गिर गया। इसलिये मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि गेबोद घाट पर पुलिया बनाई जाये। वहां पर आने-जाने में टोंक से गहलोत-पीपलू-टोडारायसिंह का सीधा रास्ता है, वहां के लोगों को बड़ी असुविधा होती है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे इस क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कराया जाए और जो गहलोत रपटा है उस पर पुलिया बनायी जाए।

साथ ही मेरे क्षेत्र में जो सड़कों की स्थिति दयनीय है उसको तुरन्त ठीक कराया जाए। आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री गोतम कुमार।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय सभापति महोदय, आज आपने मांग संख्या 19 और 21, सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में जो मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राज्य भर में जो भी सड़कें बनायी जाती हैं, वो राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं लेकिन धीरे-धीरे इन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता खराब होने से, भ्रष्टाचार, अनियमितताएं आदि होने से इस विभाग का नाम, इस विभाग की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा है। इसमें सुधार की आवश्यकता है और जो ठेकेदार गारंटी पीरियड में काम ले लेते हैं, फिर काम की गुणवत्ता ठीक नहीं रखते हैं, जो तीन साल का पीरियड हो, किसी का पांच साल का पीरियड हो उनमें वो वापस जाते नहीं हैं और जब एस.डी. लेनी होती है तो छोटा-मोटा पैच-वैच कर कराकर एस.डी. ले लेते हैं। इसमें मेरा आपसे एक सुझाव है कि जब एस.डी. रिटर्न हो तो इसके लिए कोई एक कमेटी बनाएं जो इन पर निगरानी रखें, जन प्रतिनिधियों की हो, चाहे से अधिकारी लेवल पर हो लेकिन इस विभाग से अलग हो क्योंकि इस विभाग से जितने भी लोग जुड़े हुए होते हैं उनका कहीं न कहीं कमीशन जुड़ा हुआ रहता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि

(श्री गोतम कुमार)

एक अलग कमेटी बनेगी तो निश्चित रूप से वो उस कार्य को देखेगी, उसकी गुणवत्ता देखेगी तो उसके बाद जो पेमेंट होगा निश्चित रूप से ठीक होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदयजी को हमारे विधान सभा क्षेत्र में कुछ सड़कों, पुलों के लिए भी अवगत कराना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार ने एक मंगलवाड़ से बड़ी सादड़ी तक रोड की पिछले बजट में घोषणा की थी वह पूर्ववर्ती सरकार नहीं करा पायी, वो सड़क पूरे विधान सभा क्षेत्र के बीच से गुजरती है, लगभग 45 किलोमीटर सड़क है चूंकि वो विधान सभा क्षेत्र के बीच के रास्ते से निकल रही है, विधान सभा क्षेत्र को दो भागों में बांटती है, जब आदरणीय मुख्य मंत्रीजी सुराज संकल्प यात्रा में पधारी थीं तो उन्होंने उसकी घोषणा भी की थी कि मैं पूरा करवाऊंगी तो मेरा आपसे आग्रह है कि उस योजना की डी.पी.आर. भी बन चुकी है सी.आर.एफ. में तो, माननीय मंत्री महोदयजी, जल्द से जल्दी मंगलवाड़ से बड़ी सादड़ी को जो उन्होंने फोर लेन की घोषणा की थी, मात्र टू लेन ही इस पर बनवा दी जाए और उसको इस बजट में ही स्वीकृत कराने की कृपा करावें।

दो टू लेन की सड़कें हैं, जो महत्वपूर्ण भी हैं, एक डूंगला से बान्सी वाया बोहेड़ा होकर के जाती है, अगर यह 20-25 किलोमीटर की भी सड़क बन जायेगी तो निश्चित रूप से चित्तौड़ से लगाकर के बांसवाड़ा तक की इस रोड को जोड़ेगी।

इसी प्रकार से हमारी विधान सभा के दो बड़े-बड़े गांव हैं, एक दस हजार की आबादी वाला गांव है बोहेड़ा और एक हमारी नगरपालिका है बड़ी सादड़ी, उसके बीच में एक दस किलोमीटर का गैप है अगर वो रोड भी टू लेन हो जायेगा तो उस क्षेत्र को बहुत आराम मिलेगा।

कुछ सड़कें हमारी मिसिंग लिंक में भी रह रही हैं। पूर्व में विधायकों की अनुशंसा पर साल में दस किलोमीटर के आस पास सड़कें मिलती थीं, मेरा आपसे आग्रह है कि अगर साल की 20-25 किलोमीटर मिसिंग लिंक की सड़कें सरकार विधायकों को दे तो निश्चित रूप से मेरे विधान सभा क्षेत्र में छोटे-छोटे लगभग 400-500 गांव होते हैं, 25-25 किलोमीटर भी आप सड़कें देंगे तो आने वाले पांच सालों में सड़कों का एक जोरदार जाल बिछेगा और आपके पूरे कार्यकाल को उस क्षेत्र की जनता याद रखेगी। मेरा आपसे आग्रह है, कुछ

(श्री गोतम कुमार)

सड़कों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं अगर हो सके तो इसी बजट में आप उनको स्वीकृत करवाने की कृपा करावें:- बोहेड़ा से बिलोट तक, सरथला से राणावताओं का खेड़ा मात्र दो किलोमीटर रोड है, 15 गांवों को जोड़ने वाली रोड है, वो अगर स्वीकृत हो जायेगी तो ठीक रहेगा। पिराणा से करौली, निम्बाड़ा जो हमारे क्षेत्र से बड़ा क्षेत्र है जाने के लिए, अगर घूम कर के जाते हैं तो लगभग 70 किलोमीटर होता है, अगर यह मात्र चार किलोमीटर सड़क बन जायेगी तो लोगों की कम से कम 20 किलोमीटर दूरी कम होगी। एक पालोद से पदमपुरा का रोड है। एक बड़वल से अमीरामा का। एक रतिचन्दजी का खेड़ा से करणपुर तक का रोड है, लगभग तीन किलोमीटर है, वह भी जुड़ जायेगा तो जो हमें प्रतापगढ़ जाने के लिए छोटी सादड़ी होकर के प्रतापगढ़ जाना पड़ता है, अगर यह तीन किलोमीटर सड़क दे देंगे तो निश्चित रूप से दो जिलों को भी जोड़ेगी और लोगों को कम से कम 30-35 किलोमीटर का राउंड कर के नहीं जाना पड़ेगा। मेरा आपसे आग्रह है कि यह मिसिंग लिंक में यह सड़कें स्वीकृत कराने की कृपा करावें।

लोक निर्माण में डूंगला में हैडक्वार्टर भी है, उपखण्ड स्तर का एक अगर यहां डाक बंगला हो क्योंकि हमारे छोटा गांव है, वहां पर होटल नहीं है, कभी बाहर से अधिकारी वगैरह आते हैं, अभी कलक्टर साहब भी रात्रि चौपाल में आये तो उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी कि इतना बड़ा गांव है और आपके यहां एक डाक बंगला नहीं है, तो मेरा माननीय मंत्रीजी से आग्रह है कि एक डाक बंगला डूंगला में स्वीकृत कराने की कृपा करावें।

हमारे तहसील भवन भी बहुत जर्जर अवस्था में हैं, पिछले टोंक जमाने से वह चल रहा है तो मेरा आपसे आग्रह है कि एक तहसील भवन भी बनवाने की कृपा करावें।

कुछ पुलियाएं हैं, एक सरी पीपली से ऊंटाखेड़ा पुलिया है जिसमें अगर बारिश आ जाती है, जाखम नदी पर बनी हुई पुलिया है, अभी रपट टाइप बनी हुई है, बारिश के समय लगभग एक महीने तक लोग एक-दूसरे से कट जाते हैं, इस सरी पीपली से ऊंटाखेड़ा एक महीने तक लोग किसी जगह से नहीं आ सकते हैं, अगर बीमार हैं तो उनको वहीं मरना है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि उस पुलिया को थोड़ा ऊंचा करवाकर के बढ़िया बनवा देंगे तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र की जनता आपको याद करेगी।

(श्री गोतम कुमार)

ईडरा में छोटी सी पुलिया है, वह भी स्वीकृत हो जायेगी मा बावजी ईडरा, मतलब नेशनल हाइवे 76 से ईडरा रोड की बीच में मा बावजी के नाले पर एक पुलिया निर्माण का निवेदन है।

एक भूरकिया खुर्द से चांद्राखेड़ी रोड है, वागन नदी पर पुलिया है, वह भी दो तहसील को जोड़ेगा। एक छोटी सी पुलिया है, अगर वो बन जायेगी तो निश्चित रूप से क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत लाभदायी रहेगा।

कुछ सड़कों के नवीनीकरण की भी जरूरत है। जिन रोड का मैं नाम ले रहा हूं वहां रोड है ही नहीं। रोड बनी जरूर है लेकिन आज आप वहां जायेंगे तो डामर का एक नामो-निशान नजर नहीं आयेगा, सिर्फ कहीं-कहीं गिट्टी जरूर नजर आयेगी तो मेरा आपसे आग्रह है कि इन रोड्स का जल्द से जल्द नवीनीकरण किया जाए क्योंकि उन गावों में आज भी रोड हो नहीं हो वैसी स्थिति हो गयी है। बोहड़ा से एक सुथारीयाखेड़ा गांव का रोड है, उसमें एक डूंगला से भानाखेड़ी रोड है। एक बड़ी सादड़ी निकुम्भ रोड से उम्मेदपुरा गांव को जोड़ने वाला रोड है। निकुम्भ चौराहे से भदेसर तक एक टू लेन सड़क अभी तीन-चार साल पहले बनी थी लेकिन वो भी गारंटी पीरियड में है। इस तरह से जो ठेकेदार हैं उन्होंने गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा और आज तीन साल में ही उस रोड की यह हालत हो गयी कि जगह-जगह खड्डे ज्यादा हो गये और रोड कम हो गयी है, मेरा आपसे आग्रह है कि अगर वो गारंटी पीरियड में है तो उसको ठेकेदार के मार्फत करायें नहीं तो अपने विभाग द्वारा उसका नवीनीकरण किया जाए। एक धमोतर से बोरी रोड है, प्रतापगढ़ पंचायत समिति में धमोतर गांव है, वहां से बोरी रोड जा रहा है, अभी सात-आठ महीने पहले जब मैं एक बार निकला था तो वहां पैच वर्क भी हो रहा था लेकिन पैच वर्क होने के बाद में भी जब मैं अभी महीने भर पहले वापस गया और वहां देखा तो आज वापस वहां पर रोड नजर नहीं आ रही है। चिकलाड़ से जाखम डेम तक एक रोड है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट, बस लास्ट है।

चिकलाड़ से जाखम तक का रोड है जो पहले सिंचाई विभाग के पास था, जब जाखम डेम पर काम चल रहा था तब तक तो सिंचाई विभाग उसकी देख-रेख कर रहा था लेकिन पिछले 10-12 सालों से उसकी कोई देख-रेख नहीं कर रहा है, अभी वो पी.डब्ल्यू.डी. को सुपुर्द भी कर दी है, मेरा आपसे आग्रह है चूंकि वह रोड कम से कम चार-पांच पंचायतों को जोड़ता है, मामूली सात-

(श्री गोतम कुमार)

आठ किलोमीटर है, अगर उसका भी नवीनीकरण आपके द्वारा हो जायेगा तो लाभदायक होगा। निश्चित रूप से आप हमारे युवा हैं, हमारे युवाओं की बात सुनेंगे।

आपने यहां बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुशील कुमार कटारा।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19 लोक निर्माण कार्य एवं मांग संख्या 21 सड़कें एवं पुल पर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगें रखना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र गुजरात बार्डर पर राजस्थान के लास्ट कोने में डूंगरपुर जिले में पड़ता है। पिछले 5 वर्षों में सड़कों की हालत इतनी खराब है कि इस बारे में मैं क्या बयां करुं। पूरे जिले के और मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों को रोज गुजरात अप-डाउन करना पड़ता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आधे से ऊपर लोगों की रिश्तेदारी गुजरात में है। गुजरात में सड़कें इतनी बढ़िया हैं, मोदीजी जब वहां के मुख्य मंत्री थे, अब तो देश के प्रधान मंत्री हैं। गुजरात की सड़कें हमारी सीमा तक इतनी बढ़िया हैं और हम राजस्थान की सीमा में प्रवेश करते हैं तो सड़कों की बहुत ज्यादा हालत खराब है।

माननीय सभापति महोदय, वसुंधराजी के पिछले कार्यकाल में हमारे वर्तमान चिकित्सा मंत्री आदरणीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ उस समय पी डब्ल्यू डी मंत्री थे। उन्होंने उस कार्यकाल में मेरे विधान सभा क्षेत्र में अच्छी चौड़ी-चौड़ी सड़कें बनवायी थीं। उन सड़कों पर गुजरात के लोग और राजस्थान के लोग अच्छा आना-जाना करते थे।

श्री सभापति: एक मिनट।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिए और बढ़ाया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया गया।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): मांग पारित होने तक ही बढ़वा दो न।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): जल्दी खतम हो जायेगी।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, आप मुख्य सचेतक को निर्देश नहीं दे सकते।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): निर्देश नहीं दे रहा था।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र के लोगों की रिश्तेदारी गुजरात में ज्यादा है और उनका आना-जाना लगातार बना रहता था। मैं कह रहा था कि माननीय वसुंधराजी के पूर्व कार्यकाल में राजेन्द्र जी राठौड़ साहब ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत बढ़िया-बढ़िया सड़कें बनायीं थी। पिछले 5 साल कांग्रेस के शासन में उन सड़कों की इतनी दुर्दशा है कि हम रिश्तेदारी करने अगर गुजरात जाते हैं तो गुजरात वाले हमको लड़कियां नहीं देते हैं चौरासी विधान सभा क्षेत्र और जिले में ...(व्यवधान) क्योंकि सड़कों की इतनी दुर्दशा है कि लोग वहां कहते भी हैं कि आपके राजस्थान में क्या कर रहे हो, कांग्रेस की सरकार है और आपके इतने खड्डे पड़े हुए हैं। हम हमारी लड़कियों को राजस्थान में नहीं देंगे क्योंकि हमको रोज आना-जाना पड़ता है।

सभापति महोदय, आदरणीय राजेन्द्रजी राठौड़ 7 फीट के लम्बे हैं तो हमारे 7 मीटर चौड़ी सड़कें दी थीं तो अब मुझे आशा है कि आदरणीय वर्तमान पी डब्ल्यू डी मंत्री महोदय 6 फीट के तो हैं तो 6 मीटर चौड़ी सड़कें तो हमारे विधान सभा क्षेत्र में दें ...(व्यवधान) बनेंगी तो 7 की ही, पर जो भी गांव की जर्जर अवस्था की सड़के हैं वह जरुर मरम्मत करायेंगे ऐसा आपके माध्यम से आग्रह है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्री महोदय की लम्बाई 6 फीट नहीं हो सकती लेकिन इनका हृदय 10 मीटर वाला है इसलिए आप चिंता मत करो।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): हां, धन्यवाद।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्य बहुत भोले हैं, विपक्ष के बहकावे में आ गये। 7 फीट राजेन्द्रजी की भी हाइट नहीं है। उनके कहने से इन्होंने भी कह दिया।

श्री सभापति: उनकी हाइट हम वैसे भी 1 फुट ज्यादा ही मानते हैं।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): जितनी हाइट मैं बोल रहा हूं उससे ज्यादा आप सबका हृदय है। माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने डूंगरपुर जिले में चितरी से आनन्दपुरी करोड़ों रुपयों की माही नदी पर पुलिया स्वीकृत की, जिसका अभी तक, 2-3 साल हो जाने के बाद भी नामोनिशान नहीं है। सरकार जाने के साथ में शायद वह पुलिया भी पानी की तरह बहकर के कडाणा बैक वाटर में चली गयी है, ऐसा प्रतीत होता है। उस पुलिया निर्माण को ऐसे स्थान पर लिया जहां पर अनावश्यक रुप से पैसा खर्च हो रहा था, दूरी बहुत ज्यादा थी। लेकिन वर्तमान में पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उसके स्थान पर चिकली से आनन्दपुरी पुलिया का निर्माण किया जाये, रोज लोगों को वहां आना-जाना लगा रहता है। लोग सर्विस के लिए भी आते हैं, उधर से इधर रिश्तेदारी-नातेदारी के लिए भी नदी को पार करते हैं और दिन में कम से कम 1 हजार से 2 हजार लोग नाव के द्वारा आना-जाना करते हैं। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि चिकली से आनन्दपुरी पुल का निर्माण करायें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सीमलवाड़ा उप खण्ड कार्यालय है और वहां पर अधिकारी, नेतागण, वीआईपी लोग हमेशा आते-जाते रहते हैं। वहां से गुजरात पास में पड़ता है। अहमदाबाद की दूरी बहुत कम है मेरे विधान सभा क्षेत्र से। अभी एक भी डाक बंगला सीमलवाड़ा में नहीं है। अभी तो जो वन विभाग का भवन बना हुआ है उसमें ठहराना पड़ता है अधिकारियों और वीआईपी लोगों को। एक डाक बंगला सीमलवाड़ा उप खण्ड में खोलें ऐसा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, सीमलवाड़ा उप खण्ड क्षेत्र बड़ा है, 8-9 हजार की आबादी है उसके पास में पीठ ग्राम पंचायत है और उसके पास में दम्भौला ग्राम पंचायत है, तीनों ही मिले हुए हैं, वहां आवागमन बहुत ज्यादा है, गुजरात से कनैक्टिविटी है तो वहां डिवाइडर की आवश्यकता है। अगर एक-

(श्री सुशील कटारा)

डेढ़ किलोमीटर डिवाइडर सीमलवाड़ा में बन जाये तो वहां एक्सीडेंट भी नहीं होंगे।

माननीय सभापति महोदय, केन्द्र में भी हमारी सरकार है और राजस्थान में भी हमारी सरकार है। अभी नेशनल हाइवे 8 बना हुआ है। हम गांधी नगर या सूरत जाना चाहें चित्तौड़, उदयपुर से तो किरकी चौकी से अगर सथूणा तक फोर लेन सड़क बनती है तो 100-125 किलोमीटर तक हमारी दूरी कम हो जाती है। इसकी सर्वे भी कई बार हो चुकी है, किरकी चौकी से सलूम्बर, आसपुर, डूंगरपुर होते हुए सथूणा तक अगर फोर लेन सड़क बने तो काफी पैट्रोल, डीजल की भी बचत होगी और समय की भी बचत होगी।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस बार आप विशेष ध्यान देंगे। कुछ मेरे विधान सभा क्षेत्र में मिसिंग लिंक की सड़कें हैं, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सड़कों का जाल पिछली बार हमारी सरकार ने खूब बिछाया था और बीच में कांग्रेस के 5 वर्षों में उनकी मरम्मत भी नहीं हो सकी है और मिसिंग लिंक की 1 किलोमीटर भी सड़क नहीं बनी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मिसिंग लिंक की कुछ सड़कें हैं जो एक-एक, डेढ़-डेढ़ किलोमीटर की हैं, मैं उनको पढ़ना चाहूंगा। उनमें से माननीय मंत्री महोदय कुछ सड़कें दे दें। काली घाटी से बेडसा तक, दारूधावड़ा से गुन्दलारा मेन सड़क तक, भीण्डा रामावि. से चारवाड़ा मैन सड़क तक, चारवाड़ा पीएससी से हासेला उपला रास्ता तक, गुन्दलारा छोटा से बावड़ी मैन सड़क तक, ढूंढी से खोखरवा तक डामरीकरण, सरथुना मैन सड़क से झलाई तक, इज्जतपुरा डुका से सरथुना उच्च प्राथमिक विद्यालय तक, सादडिया मैन सड़क से सरथुना तक, नीलकंठ महादेव मंदिर से गोहलिया पीएस तक, रंगपुर सांसरपुर से डिमिया तक, महुड़ी मेन सड़क से विकास नगर तक ऐसी बहुत सारी सड़कें हैं जो मेरी विधान सभा में मिसिंग लिंक के रूप में दो सड़कों को कनेक्ट कर सकती हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक आखिरी बात, सीमलवाड़ा में बालिका छात्रावास है और वह बहुत ही जर्जर अवस्था में है। वहां पर 100 बच्चियां रहती हैं और कई बार छात्रावास अधीक्षक ने कह भी रखा है। पी.डब्ल्यू.डी. को कहा है। बजट सैंक्शन हो गया है, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। 5 वर्ष कांग्रेस के शासन के निकल गये लेकिन वह भवन अभी तक नहीं बना है। बालिकाओं की सुरक्षा के लिए नया भवन बहुत आवश्यक है।

(श्री सुशील कटारा)

उसको करवाने का प्रयास करेंगे। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

(17.00 बजे)

श्री सभापति: श्री भागीरथ चौधरी।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य, मांग संख्या 21-सड़क एवं पुल पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, इस देश के प्रधान मंत्रीजी अटल बिहारीजी वाजपेयी हुए और उन्होंने ही देश की प्रगति और विकास को आगे ले जाने के लिए दो सपने संजोये। एक तो हमारा देश गांव और ढाणी से बना है, वह सब सड़क से जुडें। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, इस आधार से उन्होने पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया। परन्तु दुबारा आदरणीय अटल बिहारीजी वाजपेयी इस देश के प्रधान मंत्री नहीं बन पाये। इस वजह से पंचायत हैडक्वार्टर या कुछ गांव तो पक्की सड़कों से जुड़ गये परन्तु ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर से उस ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम अभी भी पक्की सड़क से वंचित हैं। यदि दुबारा प्रधान मंत्री अटल बिहारीजी वाजपेयी बन जाते तो आज जो हम मांग संख्या 19 और 21 की बात कर रहे हैं, शायद इस सदन में वह डिमाण्ड शून्य के बराबर रहती।

माननीय सभापति महोदय, सड़कें तो बनती हैं परन्तु तीन-चार महीने बाद ही उधड़ कर साफ हो जाती हैं। वैसे ही राजस्थान में वर्षा कम होती है, परन्तु उनकी गुणवत्ता बहुत कम होती है। पूर्ववर्ती सरकार ने या तो सड़कें बनाईं ही नहीं, और यदि बनाईं भी तो महीने, दो-महीने बाद उनका अस्तित्व ही खतम हो गया। पहले 2003 से 2008 में सदन में विराजे हुए हैं, अभी स्वास्थ्य मंत्री जो पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री थे, इनके समय में मैं यह कह सकता हूं कि मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं बचा जो पक्की सड़क से नहीं जोड़ा। माननीय सभापति महोदय, सच्चाई तो स्वीकारनी पड़ती है, परन्तु दुर्भाग्य से पिछले पांच साल में एक मीटर सड़क का निर्माण नहीं हआ। आज के सात-आठ साल पहले जो सड़कें बनी थीं वह सड़कें टूट कर ऐसे खड्डे पड़े हुए हैं कि चार पहिया वाहन तो चल ही नहीं पाता है और आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं तो आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यही कहना चाहूंगा क्योंकि यह युवा भी हैं और मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र से जो मेगा हाइवे जाता है इनका क्षेत्र भी उससे

(श्री भागीरथ चौधरी)

जुड़ता है। शायद गहलोतजी की सरकार ने सोच लिया था कि हमें तो कुछ नहीं करना है, वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयेगी, वसुन्धराजी मुख्य मंत्री बनेगी और वापस यह काम उन्हीं को करना है और इसीलिए कुछ भी नहीं किया।

परन्तु अब इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत बड़ी आशाएं हैं। माननीय सभापति महोदय, अबकी बार जितना जन समर्थन मिला है, शायद जनता को उतनी ही ज्यादा आशाएं हैं। बजट जब मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया और 20 हजार किलोमीटर सड़क बनाने का वायदा किया तो हमें खुशी हुई कि अबकी बार गांव-ढाणियों के अन्दर, शहरों में तो सभापति महोदय, सड़कें वैसे ही बनी हुई रहती हैं, जो गांव से माननीय सदस्य आते हैं उनको पता है कि गांवों में कितनी बड़ी समस्या है। गांव में सड़कों का पांच साल में बिलकुल सफाया हो गया, वैसे जनता ने भी इनका सफाया कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि अब इन सारी सड़कों की सुध आपको लेनी है और जल्दी से जल्दी क्योंकि जनता ने यह सोचा कि ज्यों ही सरकार बनेगी और सड़कें चमचमाती बनेंगी परन्तु हथेली में सरसों नहीं उगती है परन्तु अब तो हम उम्मीद करते हैं कि बजट भी पेश हो गया है और मंत्री ने कह दिया कि अब सड़कें बनेंगी। (व्यवधान) असली बात ही कहनी पड़ती है सदन में तो।

माननीय सभापति महोदय, आज जयपुर से किशनगढ़ 6 लेन है। बड़े दुर्भाग्य की बात है और सदन में कहना पड़ता है कि अन्तरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर तो सड़कें बन गई हैं परन्तु वहां जो वाहन चलते हैं जिसको थर्ड लेन में चलना होता है वह फर्स्ट लेन में चलता है और जब वह टोल देता है तो वह सोचता है कि मैं जल्दी मेरे स्थान पर पहुंचूं, वह कोशिश करता है और आजकल तो गाड़ियां भी ऐसी हैं जो सवा सौ, डेढ़ सौ की स्पीड पर चलती हैं। जब वह ओवर टेक करते हैं और एक्सीडेंट होता है तो उसमें कोई बचता नहीं है। जब हम जीवीके वालों को कहते हैं कि आपकी ड्यूटी है, आपने सड़क बनाई है तो वह कहते हैं कि यह हमारा काम नहीं है। ट्रैफिक वालों को कहते हैं तो वह कहते हैं कि हमारा काम नहीं है। पुलिस वालों को कहते हैं तो वह कहते हैं कि हमारा काम नहीं है, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आज टोल बढ़ाये जा रहे हैं, वाहनों

(श्री भागीरथ चौधरी)

की संख्या बढ़ती जा रही है और व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। आज हालात यह हैं कि किशनगढ़ से जयपुर जाने पर दो टोल प्लाजा आते हैं वहां कम से कम आधा घण्टा हर वाहन को वहां रुकना पड़ता है। वह इतना टोल भी देता है और एक घण्टा जब समय बर्बाद करता है तो मेरे हिसाब से इस पर विचार करना चाहिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, विधायक को पौन घण्टा, क्योंकि उसका कार्ड, फिर ऊपर दिखाना कैमरे में, फिर यूं करना और फिर वापस करना, पौन घण्टा।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): पहले हमारे समय में तो ऐसा नहीं था, आपके पांच साल में उनकी आदत पड़ गई, सुधरने में थोड़ा समय लगेगा, आप चिंता मत करो।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह कहना है कि देखो, वैसे तो हर डिपार्टमेंट में कैसा काम हो रहा है, आप सब समझते हैं परन्तु मैं सच कह रहा हूं कि इस पी.डब्ल्यू.डी. डिपार्टमेंट में जो काम होता है कितना गुणवत्ता से होता है वह सबको ध्यान है इसलिए इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। आज हमारा देश विकासशील देश है और जब तक सड़कें पूरी नहीं बनेंगी, ठीक ढंग से नहीं बनेंगी तो हमारा देश विकास कर नहीं सकता है। जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे यूं ही व्यर्थ में जाये, समझ में नहीं आता है।

मुझे पता है कि अबकी बार हमारे मंत्री महोदय, सभापति महोदय, युवा हैं, अब लम्बाई का तो पता नहीं है परन्तु फिर भी नौजवान हैं, काम करने का जज्बा है और वास्तव में कोई भी विधायक जाता है तो इतने मृदु भाषी हैं कि सबको निराश नहीं होने देते हैं और इन्होंने वायदा किया था कि बजट के बाद हम सब विधायकों का कार्य करेंगे।

सभापति महोदय, मेरी एक बहुत बड़ी पीड़ा है। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं वह भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की ऐसी जगह पर है जहां सिक्स लेन, फोर लेन, मेगा हाइवे, हमारी मार्बल इण्डस्ट्री है। कोई कहता है एशिया की, मैं कह रहा हूं विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, मार्बल व्यापार है, टैक्सटाइल है, दो पार्क बने हैं। आदरणीय वसुन्धराजी ने दो टैक्सटाइल पार्क के लिए वहां भूमि दी। हैण्डीक्राफ्ट्स का इतना बड़ा काम है। आज यह हालत है कि किशनगढ़ से 8 किलोमीटर इधर आएं तो टोल,

(श्री भागीरथ चौधरी)

किशनगढ़ से अजमेर की तरफ जबकि हमारा डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है उधर जाएं तो टोल, आखिर क्या है? 8 किलोमीटर शहर से उधर जाएं तो टोल चुकाना पड़ता है, किशनगढ़ से जयपुर की ओर 8 किलोमीटर आएं तो टैक्स चुकाना पड़ता है। उस टोल के आसपास में सैकड़ों गांव हैं, आज यह हालत है कि वहां मजदूरी करने के लिए आते हैं, कोई जीप से आते हैं, कोई अन्य साधन से आते हैं तो उनको टोल चुकाना पड़ता है। जीवीके वाला इतनी हठधर्मी करता है कि वह टोल में किसी तरह की रियायत नहीं करता है। माननीय सदस्य भी यहां हैं कहीं भी टोल है, जाते हैं तो रियायत कर देते हैं पर यह जीवीके वाला नहीं करता। मंत्री महोदय, मेरा कहना यह है कि इस पर विचार करना है। वहां लाइनें लगी होती हैं, टोल पर सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 8 है, मेरे किशनगढ़ में नगर परिषद में एक बजरंग कालोनी है, जहां 3 से 4 हजार परिवार रहते हैं। जब 2003 से 2008 तक मुझे विधायक बनकर यहां आने का सौभाग्य मिला, वहां परिवार रहते हैं, वह न नगरपालिका में था, न ग्राम पंचायत में था। वर्षों तक उन परिवारों की उपेक्षा हुई, बाद में वह नगर परिषद में हो गया। अब वहां एनएच 8 किशनगढ़ से ब्यावर सिक्स लेन बन रही है, पूर्ववर्ती सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। केन्द्र में राजस्थान के आदरणीय सीपी जोशी साहब मंत्री थे, उनसे भी निवेदन किया और उन्होंने कहा था यह बजरंग कालोनी भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है, इसलिए वहां आवागमन का रास्ता बंद कर दिया। इतनी कठिन समस्या है। हमने देखा कि जब प्रदेश में हमारी सरकार आ जाएगी और केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तब हमारी इस समस्या का निदान होगा। इसलिए सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर जरूर करें, क्योंकि हमने वायदा किया है कि देश व प्रदेश में हमारी सरकार आ जाएगी तो इस समस्या का निदान होगा।

सभापति महोदय, हमारा जिला हैडक्वार्टर अजमेर है। वहां जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के भवन की ऐसी जीर्ण-शीर्ण स्थिति बनी हुई है और विशेष तौर से गरीब तबके व गांव के मरीज वहां जाते हैं। सबसे पुराना चिकित्सालय है। 100 वर्ष से भी ज्यादा समय का वह जवाहरलाल हास्पिटल है। वहां हमेशा खतरा मण्डराया रहता है कि कभी हादसा हो सकता है। उसमें आउटडोर व

(श्री भागीरथ चौधरी)

इनडोर में हजारों की संख्या में मरीज आते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उसकी जरूर सुध लें।

सभापति महोदय, मुझे जरूर ध्यान है और पता है, आपसे हम सब वैसे ही कतराते हैं क्योंकि आप नियमों के...(व्यवधान) सभापति महोदय, हमारे किशनगढ़ स्थित रूपनगढ़ रेलवे ओवरब्रिज है। आदरणीय वसुन्धराजी जब मुख्यमंत्री बनीं तो उस आरओबी की 40 वर्ष से समस्या थी। वो दोनों भुजाएं बना दी गयीं। सामने बैठे हैं इन्होंने बहुत हठधर्मिता करके रेलवे ट्रैक के ऊपर वर्षों बाद में, जबकि वहां पर सभी चलते हैं, ओवरब्रिज से लेकर मकराना रोड तक, हमारे नागौर से आने वाले एमएलए साहब ने एक बार आकर मुझे कहा, हमारे नगर परिषद में पैसे की कमी नहीं है। आज भी 70-80 करोड़ रुपये पड़े हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उस सड़क की जल्दी स्वीकृति दे दें ताकि उस समस्या का निदान हो सके।

पाटन से तिलोनिया होते हुए हरमाड़ा होते हुए सुरसरा एक सड़क जाती है जो टोल को बचाने के लिए सीधे डीडवाना की तरफ निकलती है। उस सड़क की हालत यह है, भारतीय जनता पार्टी के समय वह सड़क बनी थी उसके बाद में खड्डे पड़े हैं। कभी मंत्रीजी यह सोचें कि किशनगढ़ वाले और सड़कों के लिए पीछे पड़ेंगे, सीधे निकलने की कोशिश करें तो उस सड़क की हालत बहुत खराब है। उस सड़क का निर्माण हो जाय तो बड़ी मेहरबानी होगी।

मेरा यही निवेदन है कि हमारे गांवों के अन्दर आसपास के क्षेत्र में खोड़ागणेश का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। वह नगर परिषद में भी आता है, किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में भी, कुछ पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में भी आता है। नगर परिषद तो तैयार है, लेकिन आगे वह टुकड़ा बन जाय तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां जाते हैं। उस सड़क की ऐसी हालत है कि रोजाना सभी कोसते हैं कि अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गयी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय से मैं कहना चाहूंगा हमारे शहर के मध्य में डाक बंगला है। उसमें सिर्फ दो कमरे हैं। उसका इतना बड़ा भूभाग है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं है। एक बार मैं वहां गया, बहुत सी झाड़ियां हैं, समाजकंटक वहां बैठते थे, इतनी इस तरह की वारदातें होती थीं। इतना भूभाग होते हुए भी दो कमरे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। इसके बजाय उसको

(श्री भागीरथ चौधरी)

पब्लिक यूटिलिटी के लिए वहां शादी समारोह स्थल बना दें जिससे उसका उपयोग तो हो। या उस डाक बंगले को बाहर बना लें, नगर परिषद आपको पैसे दे देगी।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की कुछ सड़कें हैं गांवों की उनके लिए आपकी मेहरबानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां बरोल से मोहम्मदगढ़, बरोल चौकी से सोयला, सोयला से 12 मील, डिगारिया से डबरेला, गुजरवाड़ा से मनोहरपुरा, रामगढ़ से सदापुर, लक्ष्मीपुरा से सरवर, बलदेवपुरा से रामसिंहपुरा, खरवड़ से श्रीरामपुरा, माण्डियावड़ कलां से मोठी, माण्डियावड़ खुर्द से आटोली, सरवर से खरवड़, मुण्डोती से लक्ष्मीपुरा, पाण्डरवाड़ा से बंथली, मण्डावरिया से गोपालपुरा, गोठीयाना से आकोड़िया, सांदोलिया से अराई, अराई पावर हाउस से अराई बस स्टैण्ड तक, छोटा लाम्बा से दादिया, माला से भोगादीत, टिहरी से भोगादीत रोड पर पुलिया का निर्माण, अलमास से डिडवाड़ा रोड पर पुलिया निर्माण। भोगादीत पुलिया तो ऐसी है बारिश हो जाती है तो 20-25 गांवों का सम्पर्क टूट जाता है। गत वर्ष तो वहां एक जने की जान भी चली गयी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये मेरे यहां तीन पुलिया का निर्माण हो जाय। डोरिया से झिरोता, गागुन्दा से सिरोज, पचीपला से मोतीपुरा, टूकड़ा से मेगा हाइवे, खातोली से रहीमपुरा, पिंगलोद से गुदली, सुरसरा से जोल की ढाणी, सुरसरा से छिर, बुहारू से हरमाड़ा, बांदरसिंदरी से पेडीभाटा, सरगांव से डिंडवाड़ा, टिकावड़ा से भुवाड़ा, मुण्डोलाव से दादिया, मुण्डोलाव से टिकावड़ा, उदयपुर कलां से गोदीयाना, इन सड़कों का निर्माण हो जाय तो बड़ी मेहरबानी होगी। सभापति महोदय, मुझे पता है कि आपकी बड़ी मेहरबानी रही, मुझे आपने ज्यादा समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, मांग संख्या 19 और 21 में आपने मेरे विचार रखने का समय दिया, उसके लिए मैं आभारी हूं। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री महोदय आप एक काम कर दीजिए कि जितने भी ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर्स हैं उनको एक बार ले लें, उन सब की डी.पी.आर. एक बार आप तैयार करवा दें। सभापति महोदय, वास्तविकता यदि हम देखें तो सड़क बनाने का काम कई प्रकार की एजेंसियां करती हैं, ग्राम पंचायत भी अपने कोटे

(श्री रामलाल शर्मा)

से सड़क बनाती है, पंचायत समिति भी बनाती है, विधायक और सांसद कोष से भी सड़कें बनती हैं, पी.डब्ल्यू.डी. भी सड़क बनाती है, जे.डी.ए. जहां पर है वहां पर जे.डी.ए. भी सड़क बनाने का काम करता है। सभापति महोदय, वास्तविक स्थिति अगर गांवों की देखें तो ग्राम पंचायत 200 मीटर की सड़क बनाती है, 200 मीटर की सड़क बनाने के बाद में पंचायत समिति से फिर उसके पास पैसा आ गया तो वो फिर सड़क को आधा फीट ऊपर बना देती है। सभापति महोदय, ड्रेन की व्यवस्था नहीं होने और उनका डी.पी.आर. नहीं होने की वजह से जो पहले बनी हुई 200 मीटर की सड़क है उसके ऊपर पानी भरा हुआ रहता है और जो बाद में सड़क बनी है वो साफ-सुथरी रहती है। थोड़े दिनों बाद यदि उस सी.सी. सड़क की रिपेयरिंग कर दें तो गांव का आदमी जिसने 15-20 लाख रुपये लगाकर मकान बनाया है, अगर बरसात के दिनों में जाएंगे तो वो अपने मकान से सड़क पर पानी फेंकता हुआ दिखायी देगा। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से पहला निवेदन है कि यदि राजस्थान के अन्दर ग्रामीण क्षेत्र के गांवों की दशा सुधारना चाहते हो तो आपको मेरे ख्याल से ज्यादा समय नहीं लगेगा, अगर आपके ए.ईएन. और जे.ईएन. एक महीने में दो ग्राम पंचायतों की भी डी.पी.आर. तैयार करे तो मेरे ख्याल से यह काम एक या डेढ़ साल में पूरा हो जाएगा। उस डी.पी.आर. की एक कापी स्थानीय ग्राम पंचायत में रहे और दूसरी कापी आपके पी.डब्ल्यू.डी. में रहे तो निश्चित रूप से उस मापदण्ड के तहत ही सड़कें बनेंगी और उसके ड्रेन की व्यवस्था भी सुव्यवस्थित तरीके से रहेगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ समस्याओं का निवेदन मंत्री महोदय से करना चाहूंगा। पहले सभी माननीय सदस्यों ने टोल की चिंता की है। सभापति महोदय, यह एक ऐसा है जिसको डायनासोर कह सकते हैं जो किसी के वश में नहीं आता। जयपुर से लेकर सीकर के बीच में फोर लेन बनाने का काम हुआ है। इनकी हिम्मत देखिये कि उस टोल के जस्ट 50 मीटर से पहले एक आनन्द लोक नाम से जे.डी.ए. ने आवासीय कालोनी विकसित की, उस जयपुर विकास प्राधिकरण की कालोनी को आज करोड़ों रुपये का नुकसान हो चुका है। जब से यह टोल लगा है उसके बाद में एक भी प्लाट उस कालोनी के अन्दर नहीं खरीदा गया है। इस टोल वाले की हिम्मत देखिये कि जे.डी.ए. ने अपनी रोड पर जो अवैध रूप से बैरिकेड लगाये थे उनको एक बार जयपुर विकास प्राधिकरण का दस्ता जाकर हटा कर आया पर दूसरे दिन

(श्री रामलाल शर्मा)

वापस लगा दिये। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जहां उस आनन्द लोक कालोनी की सड़क के ऊपर अवैध टोल वसूली की जाती है वह भी ठेके पर दी हुई है कि इसमें जो कमाई होगी उसमें से 20 प्रतिशत वो जो बाउंसर हैं वो ले जाएंगे और 80 प्रतिशत आप टोल में जमा करायेंगे। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि इसको आप कृपया व्यक्तिगत लेकर दिखायें। इस तरीके का अनैतिक और अत्याचार जनता के ऊपर नहीं होने दें।

सभापति महोदय, दूसरा, मेरा निवेदन है कि राधास्वामी बाग़ से लेकर गोविन्दगढ़ के बीच में कोई भी सम्पर्क सड़क उस हाइवे ने नहीं बनाई। किसान यदि खेत में जाने के लिए कच्ची मिट्टी डालकर रैम्प बनाता है उसको भी वो आकर अवैध रूप से तोड़ते हैं। अगर कोई मकान में जाने के लिए कच्चा रैम्प बनाते हैं तो उसको भी वो अवैध रूप से आकर तोड़ते हैं और नहीं तोड़ने के लिए अवैध रूप से पैसा भी वसूल करते हैं कि यह तो एन.एच.ए.आई. की जमीन है इसमें हम कच्चा रैम्प आपके मकान तक जाने के लिए भी नहीं देंगे, कच्चा रैम्प आप खेत में जाने के लिए भी नहीं बना सकते। इस तरह से इस डायनासोर रूपी जो है इसको आप नियमों के तहत बांधने का प्रयास करेंगे तो मैं समझूंगा कि जनता का भला होगा।

पिछली सरकार के अन्दर जिन्होंने भी प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनाओं के प्रपोजल तैयार किये, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि एक सड़क के मेरे राजस्व गांव समरपुरा से लेकर बोबासियों की ढाणी तक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रस्ताव बनकर गये। जो राजस्व रिकार्ड के अन्दर रास्ता है वो समरपुरा से लेकर बोबासियों की ढाणी तक है। पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारियों ने सम्पर्क सड़क या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क के जो प्रस्ताव तैयार किये वो चन्दवाजी रोड से लेकर बोबासियों की ढाणी तक किये। चन्दवाजी रोड से लेकर बोबासियों की ढाणी तक पहुंचने में बीच में खातेदारी जमीन आती है और उस खातेदारी जमीन के अन्दर भी भाइयों का आपसी विवाद होने के नाते उस पर स्टे लगा हुआ है। सड़क स्वीकृत होकर आ गई, सड़क का काम भी उन्होंने शुरू कर दिया लेकिन बीच में आकर वह सड़क रुक गई। अब एक तरफ जो राजस्व रिकार्ड में रास्ता है उधर से सड़क स्वीकृत नहीं है और दूसरी तरफ जहां पर रोड स्वीकृत है उसके ऊपर खातेदारी जमीन है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस समस्या का आप अविलम्ब समाधान करायें।

(श्री रामलाल शर्मा)

गुणवत्ता के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर की है। इस मामले में मेरा भी आपसे निवेदन है कि कई बार सड़कें स्वीकृत होती हैं उन सड़कों के ऊपर पहले से ही ग्रेवल सड़क बनी हुई होती है, कई बार मिट्टी के गोले भी बने हुए होते हैं लेकिन यह हमेशा देखने को मिलता है कि जो ठेकेदार होते हैं न तो जो ग्रेवल बनी हुई है या जो गोले बने हुए हैं उनका पैसा कम करते हैं और न ही स्थानीय मिट्टी को काम में लेते हैं। स्थानीय पानी को वो काम में लेते हैं तो उसका पैसा भी जो तखमीना बना हुआ होता है उसके अन्दर कम करने का काम नहीं करते हैं। गुणवत्ता के लिए तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इसका एक अलग से जो भी सड़क बने कम से कम उसका सैम्पल जरूर मंगायें और उसको लेबोरेट्री के अन्दर टैस्ट कराने का काम करें। अगर आपने 10-5 सड़कों के भी सैम्पल मंगाकर टैस्ट किये तो निश्चित रूप से ठेकेदारों में भी दहशत रहेगी और जिस बात का जिक्र सभी माननीय सदस्यों ने किया है उस चिंता से भी मुक्ति मिलेगी।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि कई गांव ऐसे हैं जो 2001 के बाद में बने हैं और 2001 के बाद में जो राजस्व गांव बने हैं उनकी आबादी भी 700-800 तक पहुंच गई है। ऐसे गांव जिनकी आबादी 700-800 की आबादी हो चुकी है उनको भी प्राथमिकता के साथ लेकर प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्दर स्वीकृत करायें। कई क्षेत्रों में आबादी अधिक होने के बावजूद भी वो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से नहीं जुड़ पाये हैं तो मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि ऐसी आबादी के गांव जो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ने चाहिए और वो अभी भी वंचित है तो उनका भी आप एक बार प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश नीचे के अधिकारियों को प्रदान करें ताकि वो बन सके।

कई बार सांसद और विधायक कोष से सड़कें बन जाती हैं। उन सड़कों की न तो कृषि विभाग रिपेयरिंग करने के लिए लेने को तैयार है और न उन सड़कों को पी.डब्ल्यू.डी. लेने को तैयार है। ऐसी ही मेरी एक सड़क है ढोढसर से लेकर देवन्दों की ढाणी तक। सांसद कोष से वह सड़क बनी थी लेकिन जब से बनी है तब से लेकर अब तक न तो कृषि विपणन बोर्ड ने उसकी रिपेयरिंग की और न पी.डब्ल्यू.डी. ने अभी तक उसकी रिपेयरिंग की। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि चाहे सांसद कोष से सड़क बनी हो और चाहे

(श्री रामलाल शर्मा)

विधायक कोष से सड़क बनी हो, वो भी राजकीय पैसे की सड़क है तो उन सड़कों को भी आप प्रस्ताव तैयार कराकर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उनकी रिपेयरिंग कराने का काम करें।

सभापति महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक निवेदन मेरा आपसे और करना है। मेरे ख्याल से जयपुर जिला नहीं, राजस्थान का सबसे बड़ा इण्डस्ट्रियल एरिया मण्ढा के अन्दर विकसित हो रहा है। एक बाइपास हाड़ौता से लेकर टांकरड़ा को जोड़ने का है उसका काम अधूरा पड़ा है, वो तो तैयार हो रहा है लेकिन क्योंकि रावण गेट सर्किल से रेनवाल रोड की तरफ जाने में आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वहां पर आये दिन जाम भी रहता है इसलिए एक बाइपास अभी से राधास्वामी बाग़ या जैतपुरा से प्रस्तावित करके कालाडेरा-रेनवाल रोड को अगर जोड़ने का प्रस्ताव तैयार करते हैं तो आने वाले समय में आबादी की जो बढ़ती हुई समस्या का समाधान बहुत जल्दी होगा।

सभापति महोदय, पिछली गवर्नमेंट ने एक नीतिगत निर्णय ऐसा किया जो किसान विरोधी है, जो नीतिगत निर्णय गांवों के लोगों का विरोधी है। चाहे कृषि उपज मण्डी की सड़कें कृषि विपणन बोर्ड बनाये, चाहे पी.डब्ल्यू.डी. बनाये लेकिन वो मिसिंग सड़कें जो पिछली गवर्नमेंट ने बन्द की थीं, उन सड़कों की भी स्वीकृति जारी करें ग्रामीण क्षेत्र में कई टुकड़े ऐसे हैं जो नार्म्स के अन्दर नहीं आते, जिनका पी.डब्ल्यू.डी. कभी निर्माण नहीं कराती ताकि उनको भी इन मिसिंग सड़कों के माध्यम से जोड़ने का काम हो सके। इसलिए आपके माध्यम से मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि इस विषय को भी आप गम्भीरता से लें।

सभापति महोदय, एक और निवेदन मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से करना चाहूंगा कि वर्तमान समय में सभी माननीय सदस्यों ने बहुत लम्बी सड़कें मांगी हैं। मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा भी की है कि राजस्थान में धार्मिक स्थलों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का हम काम करेंगे तो किशनमानपुरा से लेकर दादिया है, अगर इस सड़क का निर्माण होता है तो खाटूश्यामजी जाने का जो पदयात्री जाते हैं, लगभग 15 किलोमीटर की दूरी उनके लिए कम होगी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि किशनमानपुरा से लेकर दादिया तक इस सड़क का निर्माण आप अवश्य करें।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, कुछ सड़कें रिपेयरिंग की हैं जो काफी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और आये दिन उन सड़कों के ऊपर दुर्घटनाएं भी घटित हो सकती हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सीकर रोड से लेकर भूतेड़ा, जांटावाली से लेकर महार, ढोढसर से लेकर गुडलिया और ढोढसर से लेकर रायसिंह का बास, ये चार सड़कें ऐसी हैं जो बहुत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो चुकी हैं और आये दिन इन सड़कों पर दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं इसलिए आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि अविलम्ब इन सड़कों के प्रस्ताव तैयार कराकर इनकी रिपेयरिंग कराई जाए।

माननीय सभापति महोदय, एक सुझाव मेरा और है कि यदि डी.पी.आर. गांवों के अन्दर तैयार होती है तो निश्चित रूप से इसका लाभ ग्राम पंचायत के लोगों को भी मिलेगा। आसानी इस बात की भी रहेगी, पता भी रहेगा कि कौनसी सड़क कब बनी थी और किस सड़क की क्षमता किस प्रकार की है। इसलिए सभापति महोदय, ज्यादा निवेदन आपके माध्यम से नहीं करूंगा...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, एक मिनट माननीय सदस्य। सभापति महोदय, जब हम सीकर जाते हैं तो आपके जो चौमूं का टोल है उस टोल से जस्ट पहले इधर जो रोड जाती है उस पर भी टोल वालों ने लट्ठ लगा रखा है।

श्री सभापति: इसका जिक्र आपने कर लिया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): धन्यवाद, धन्यवाद।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आपसे पहले मैंने उसका जिक्र किया है कि आनन्दलोक की कालोनी है और जेडीए की कालोनी है।

श्री सभापति: आपने विधिपूर्वक किया है। इन्होंने...

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि कुछ सड़कें मैंने रिपेयरिंग के लिए कही है और एक सड़क बनाने के लिए कही है। वैसे तो मंत्री महोदय काफी युवा भी हैं, कर्मठ भी हैं, दबंग भी हैं और इनका भी रास्ता पड़ता है तो मेरे ख्याल से ये भी इस बात से अच्छी तरीके से जानकार हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कम से कम एक ही सड़क मांगी है, ज्यादा सड़क मांगी नहीं है तो निश्चित रूप से अपने रिप्लाई के अन्दर इस सड़क की घोषणा माननीय मंत्री महोदय जरूर करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 20,000 किलोमीटर सड़क मिल गई आपको तो, अब एक सड़क ही क्यूं मांग रहे हो?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, आपने जो समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से सड़क और भवनों के बारे में चर्चा चल रही है, पी.डब्ल्यू.डी. की ओर से मैं नोट कराना चाहूंगी कि बानसूर अस्पताल है, उसका जो आंगन है, वह बहुत गहरा है, उसमें बरसात में पानी बहुत ज्यादा भर जाता है। मरीजों को आने-जाने में परेशानी होती है तो विभाग की ओर से उसकी भी मरम्मत की जाये और जो टूटे-फूटे, जीर्ण-शीर्ण बरामदे और कमरे हैं, उनकी भी मरम्मत की जाये।

बानसूर क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी लम्बा-चौड़ा है। इसके लिए एक बालिका छात्रावास जो चाहें तो किसी योजना के जरिये लें, लेकिन उसकी आवश्यकता है।

दूसरा, जो रोड के बारे में मैंने दिया था। कुछ ऐसे रोड्स थे जो सैंक्शन थे, वापस उनको कैंसिल कर दिया गया या फिर जो रेवेन्यू विलेज हैं, उनके भी कैंसिल हो गये, ऐसा क्यों हुआ? मैंने मंत्री महोदय को भी पर्सनली लिखकर दिया है तो कुछ सड़कें ऐसी हैं जो 10-15 गांव या ढाणियों को आपस में जोड़ती हैं और एक-दूसरी तहसील को भी जोड़ती है। जिनमें से एक में तो काम भी चल रहा था बानसूर से बूचियाबास तक और यह बामनवास तोलावास, यहां काम भी चल रहा था तो किसलिए वह रूक गया और सैंक्शन के लिए आडीगेली से कोठिया होता हुआ गढ़ी तक रामपुर से नाथूसर लोच तक, बाबरिया रोड से छाबड़ीवास बाडाली की ढाणी होता हुआ मैन भगूगा बास रोड तक, तोलावास से भडाणा की बाल तक और एक मुख्य सड़क कैरपुरा से साबी नदी की ओर जो कि दो तहसीलों को जोड़ता है, जिससे कि गांवों का विकास हो सके और जो रेवेन्यू विलेज हैं, यह हाजीपुर से पापड़दा की ढाणी, हाजीपुर से धामला का बास तक भूजी की ढाणी होता हुआ, एक बलवा का बास से मंगलवा काली पहाड़ी, सबलपुरा जो कि ये रेवेन्यू विलेज हैं, 2001 की जनगणना के हिसाब से भी ये सारे ही नोर्म्स पूरे करते हैं और अभी तो शायद 2011 की जनगणना भी आ चुकी है।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

जैसा कि अभी माननीय सदस्य सुरेन्द्र पाल सिंहजी ने कहा, तो मुझे भी यह लगता है कि पी.डब्ल्यू.डी. के ऊपर शायद बर्डन ज्यादा है। सभापति महोदय, जो कृषि विपणन बोर्ड है, वह भी पहले सड़क बनाने का काम करता था तो क्यों ना इसको डिवाइड कर दिया जाये जिससे कि यह बहुत सारे पैंडिंग काम हैं, वे पूरे हो जायें। बाकी प्रस्ताव अब लिये जा रहे हैं। अभी इतनी देर से पिछली सरकार, पिछली सरकार कर रहे थे लेकिन सुनने में यहां तक आया तो पिछली जो आप वाली सरकार थी, वह भी उसमें शामिल आ रही है। पिछले पांच साल के सैंक्शन थे, जैसा माननीय सदस्या अनिताजी ने बताया तो वह भी नहीं हुआ। सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुरोध करना चाहूंगी कि अधिकारी महोदय काम करने के मूड में कम रहते हैं। उनकी मंशा कम रहती है बल्कि कागजों में जवाब देने में मंशा बहुत अधिक रहती है। आपको रिकार्डेडली सारे कागज मिल जायेंगे, आप चाहें 20 साल का रिकार्ड ले लीजिये, लेकिन उन 20 वर्षों के अन्तर्गत जो काम की गति है, वह धीरे है। हमें जवाब दे देंगे, माननीय मुख्य मंत्री महोदया को जवाब दे देंगे लेकिन काम को करने के तरीके से नहीं करते, उसको जो समयावधि है, उसका कारण लिख देंगे कि इस कारण से यह काम नहीं हुआ, लेकिन उस कारण का समाधान करने में कम विश्वास रखते हैं। जैसा अभी भी सब लोगों ने नाम नोट करवाये हैं सड़कों के लिए, बेशक वे सारे नोर्म्स पूरे करते हों, चाहे बजट भी आ जायेगा, लेकिन किसी न किसी कारणवश रोड्स, भवन निर्माण कार्य के हों।

समाज कल्याण विभाग की ओर से कई दिनों से सैंक्शन भी है, पैसा भी है, सब कुछ आ गया, लेकिन छात्रावास बन नहीं पाया, रामपुर में है। तो इस तरह के ये काम अधूरे किस मंशा से रखे जाते हैं। माननीय सदस्य महोदय कह रहे थे कि पांच साल से रह रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा भी कि जो अच्छे काम करें तो धन्यवाद दें। पूर्व प्रधान मंत्रीजी के नाम से भी जिक्र किया सभापति महोदय। वैसे तो नाम नहीं लेने दिया जाता है, लेकिन अभी बोलकर गये थे कि धन्यवाद देना चाहिए आपके मुख्य मंत्री महोदय को। आप काम तो करिये, धन्यवाद भी देंगे। अभी काम करना तो शुरु करो। अभी जब माननीय सदस्य महोदय बोल रहे होते हैं, समस्या नोट कराने की बाद में उसी पाइंट पर आ जाते हैं कि देखिये, आज भी यही हालत है। उसी पाइंट पर आ जाते हैं सब लोग, घूम-घाम कर रास्ते से वही आकर के रूक जाते हैं।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

उन्होंने जिक्र किया जवाहर लाल नेहरूजी, इन्दिराजी का नाम लेकर के कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया। शायद उनको जानकारी में नहीं है तो रिकार्ड में ये सारे काम हैं। इन्दिराजी का जहां तक जिक्र है उन्होंने तो वह काम किया, जिससे आज संसार में भारत देश की पहचान है। उनके लिए मैंने 1984-85 में देखा था टीवी की क्लिपिंग में, न्यूज में। अटल बिहारीजी वाजपेयी और इन्दिराजी जब साथ जा रहे थे। शायद जो सीनियर मोस्ट हैं, उनको तो मुझसे ज्यादा जानकारी होगी, इतना मुझे ज्ञान नहीं है लेकिन उन्होंने जब बंगलादेश अलग हुआ था, उसके बाद में जो कहा और इन्दिराजी को धन्यवाद दिया कि हे रणचण्डी, धन्य है, इस धरा की, भारत भूमि की, हम तुम्हें नमन करते हैं। तो क्या बात थी तो वे भी एक राजनेता थे, नेता थे वे लोग। (व्यवधान) नहीं, है, यह लिखा हुआ भी है। आप देख सकते हैं। बाकी, मैंने तो जो देखा है, वह बता रही हूं आपको कि वे भी एक नेता थे तो जो कार्य अच्छा करेगा तो हम आपको धन्यवाद देंगे, पूरे विपक्ष की ओर से धन्यवाद देंगे लेकिन आप कार्य तो कीजिये और जो मैंने अभी ये नोट कराये, कि आप और हम तो आते रहते हैं लेकिन आप और हमारे से अलग से यह एक डिपार्टमेंटली, सरकारी, हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, हमारे ही एक अंग हैं, लेकिन हम लोगों को ही ये धीरे-धीरे करके पार उतार देते हैं। कागजों में तो ऐसा नहीं करें। धन्यवाद सभापति महोदय। राम राम सा।

श्री सभापति: श्री शंकर लाल शर्मा।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): आदरणीय सभापति महोदय, मैं आज मांग संख्या 19 और 21 के ऊपर अपनी बात रख रहा हूं। बात चल रही थी गुणवत्ता की, बात चल रही है सड़कों के निर्माण की। मैं दौसा क्षेत्र से हूं और इसका मंत्रालय दौसा के ही हमारे विधायक महोदय के पास था। मैं दौसा क्षेत्र की ही बात करना चाह रहा हूं कि नेशनल हाइवे 11 से लालसोट बाइपास बना। आनन-फानन में बनकर तैयार हुआ, डेढ़ साल के अन्दर ही दो बार मरम्मत का काम चालू हो गया और दो बार मरम्मत का काम भी, यह नहीं कि केवल थोड़ी बहुत कोई डामरीकरण हो, पूरी की पूरी रोड, आधी नीचे से तोड़ दी गई। आज भी अगर हमारे मंत्री महोदय उधर से निकलें तो मालूम चलेगा कि आधी साइड में अब सीसी रोड बन रही है आज गुणवत्ता की ही नहीं, टैक्निकल के भी हालात यह हैं कि दौसा के अन्दर एक साइड में एनएच-11 हाइवे बन गया और एक साइड एनएच-11ए बायपास बन गया। उसका नतीजा यह निकल रहा

(श्री शंकर लाल शर्मा)

है कि दौसा का पानी निकलने के लिए कहीं स्थान नहीं है। न नाला किया और न उसके लिए जगह दी। दौसा के तीन साइड़ में हमारे यहां सूरी बांध हैं, गेटोलाव बांध हैं, झीलमिल बांध हैं वहां पानी जाया करता था। हाइवे बन गए, बाइपास बन गया, पानी निकलने को जगह नहीं है, यह वहां के टैक्निकल हालत है। मैं दौसा प्रोपर के हालत बयान कर रहा हूं कि हमारे एक गेटोलाव रोड है जिसके ऊपर से पूरा दौसा का पानी बहाव के रूप में जाया करता था। अब जाकर के वह बाइपास रोड़ बन गया। उस सड़क की हालत अगर अपन देख लें तो वह सड़क कभी रही नहीं है। बरसात आती है, डामर पूरी टूट जाती है और उसके बाद में आज पी.डब्ल्यू.डी. वाले हर समय ही कहते हैं कि जब तक नाला नहीं बनेगा, तब तक हम क्या करेंगे? अगर वह बननी चाहिए तो सीसी रोड, आखिरी में केवल मात्र हम इंतजार कर रहे हैं कि गेटोलाव हमारी कब बनकर तैयार होगी?

साथ ही जो सैंथल रोड है वहां के हाइवे के अन्दर बीच में पुलिया दी है, नाला बनाया नहीं, केवल मात्र पानी भर रहा है और दोनों साइड़ में कहीं पानी का विकास नहीं है। तो मैं मंत्री महोदय से यह भी कहना चाहूंगा कि सैंथल रोड के ऊपर दोनों साइड़ से नाला बनाकर पानी के निकास को भी रखे और उस सड़क को नहीं बनाया जाए और गेटोलाव रोड को सीसी रोड और दोनों साइड़ का बनाया जाए।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि दौसा का एक ही प्रमुख मार्केट है। आज चालीस हजार से ऊपर दौसा में लड़के पढ़ाई कर रहे हैं जो ज्यादातर पैदल घूमते हैं। दौसा जिला बन गया लेकिन अभी तक भी यह महसूस नहीं हुआ कि दौसा जिला स्तर का है। एनएच-11ए लालसोट रोड से हाइवे एनएच-11 तक एक मेन बाजार है। उसके अन्दर अभी चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। मैंने मंत्री महोदय से पहले भी आग्रह किया था कि इस रोड को नाले से नाले तक, दुकान से दुकान तक की चौड़ाई बनाकर के अगर बना दिया जाए या उसके ऊपर कोई फुटपाथ का प्रयोजन रखकर के बना दिया जाए तो जो धूल दिन भर इधर से उधर गुजरने पर आम जनता के ऊपर उड़ती है वह बंद हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि दौसा का जो मेन मार्केट हाइवे-11 से 11ए तक का अभी निर्मित चल रहा है। साढे 9 करोड़ रुपये सैंक्शन था और जो अभी काम चल रहा है, नाले से नाला और दुकान से दुकान तक पूरा जोड़कर बना दिया जाएगा तो दौसा के लिए सुनदरता के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहेगा।

(श्री शंकर लाल शर्मा)

(17.42 बजे)

(श्रीमती किरण माहेश्वरी, सभापति, पदासीन)

11ए लालसोट, चाकसू से तूंगा होता हुआ लालसोट रोड के ऊपर स्टेट हाइवे-2 है। उसको स्टेट हाइवे-2 का दर्जा भी मिला हुआ है। चाकसू से वह सीधा लालसोट रोड के ऊपर निकलता है जिसके अन्दर कोटखावदा, तूंगा, लवाण होता हुआ है। उसकी हालत यह है कि शायद उसके ऊपर ट्रक वगैरह सारे आते जाते हैं लेकिन बुरी हालत है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जो हमारा स्टेट हाइवे-2 है चाकसू से लालसोट रोड और लालसोट रोड से आगरा रोड को भी अगर जोड़ दिया जाए तो यह एक बहुत बड़ा बाइपास अपने आप में बनकर के तैयार होता है। चारों तरफ के साधन को 50 -50, 60-60 किलोमीटर का जो जयपुर होकर जाया करते हैं उनको फायदा होगा। दौसा के अन्दर एक मेन रोड है उसके चारों तरफ एक हमारे यहां अस्पताल से गणेशपुरा रोड और सोमनाथ चौराहे से होता हुआ अगर वह रोड बन जाता है तो एक छोटा रिंग रोड का काम करेगा। अगर मंत्री महोदय, इसको बना दिया जाए तो यह दौसा के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा।

दौसा के अन्दर नांगल राजावतान और लवाण के अन्दर तहसील कार्यालय खुल गया। लेकिन आज तक तहसील के लिए जो पुराना जीर्ण-शीर्ण अवस्था का कार्यालय था वहीं चल रहा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि लवाण के लिए और एसडीओ कार्यालय नांगल के भवन के लिए अगर पैसा दे दिया जाए और उसको बनवा दिया जाए तो बहुत बड़ा फायदा होगा।

साथ ही चावण्डेडा से सीतापुरा रोड ढाई किलोमीटर तथा चावण्डेडा से सीतापुरा बरखेड़ा पुलिया तक और सीतापुरा से मालपुरा तक चार किलोमीटर मिसिंग लिंक, दौसा से अलुदा पापड़दा, खवारावजी, भाण्डारेज सड़क को सिंगल से डबल करना। लालसोट बाइपास से नांगल गोविन्द को पुन: डामरीकरण करना, सिंगवाड़ा से सबलपुरा होती हुई नांगल गोविन्द तक सड़क का डामरीकरण करना। पाड़लीखुर्द से चौपाड़ा तक पांच किलोमीटर मिसिंग लिंक का निर्माण। खोराखुर्द से चौपड़ा बालाजी का डेढ़ किलोमीटर का मिसिंग लिंक, महसराकलां से जसौता तक ढाई किलोमीटर का मिसिंग लिंक, थूमड़ी रोड से लाड़लीवाला तक मिसिंग लिंक, ठीकरिया से भैंरूजी के मंदिर तक मिसिंग लिंक, कुण्डल से सूरतलाई तक दो किलोमीटर का मिसिंग लिंक। दौसा से

(श्री शंकर लाल शर्मा)

खानभाकरी कुण्डल होता हुआ बांदीकुई के लिए एक रोड मिलता है जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उसकी हालत यह है कि उसके ऊपर आज चलना मुश्किल है। बजरी ट्रक साधन पूरे आते हैं अगर हमारे इस रोड को भी बना दिया जाता है तो यहां से बांदीकुई तक का एक रास्ता बहुत ही बढिया निर्मित हो जाता है। मैं पुन: आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि इन सड़कों का काम, सड़कों का निर्माण, जहां तक बात हो रही थी पूर्व मंत्रियों की, जब दौसा के अन्दर यह हालात हैं, दौसा की सड़कें जब मंत्रियों द्वारा नहीं बनाई गई और हाइवे के लिए मैं यह चाह रहा हूं कि जो बाइपास के ऊपर हाइवे बना है। उसकी तो कम से कम यह जांच होनी चाहिए कि केवल मात्र डेढ़ साल के अन्दर ही वह दो बार क्यों बन गया? मैं आपके द्वारा यह भी चाहूंगा कि उसकी जांच करवाई जाए। मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री शंकरसिंहजी राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या-19 और 21 पर कुछ निवेदन कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, चाहे किसी गांव की ले लो, शहर की ले लो, ज़िले की ले लो, ज़िले से किसी प्रदेश की ले लो, तीन चार मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो उस प्रदेश या उस गांव को प्रभावित करती है वह है सड़क, पानी और बिजली। अब उसमें एक सबसे मूल बात है सड़क और जब सड़क का बराबर प्रबंधन होता है तो निश्चित रूप से उस गांव का विकास होकर वह गांव किसी ज़िले से जुड़ता है। जिला किसी प्रदेश से जुड़ता है और सबसे बड़ी चीज है कि प्रदेश में आज हमारा जो राजस्थान प्रदेश है। उत्तर से दक्षिण की तरफ जब जाते हैं तो उसके मध्य में यह प्रदेश आता है। यहां कि सड़क का प्रबंधन और सड़कों की व्यवस्था बाहर के लोगों को आकर्षित करती है। अब हम एक तरफ तो कहते हैं कि प्रदेश को विकास करने के लिए निवेशक चाहिए। निवेशक जब आएंगे जब हम सड़कों का जाल एक बहुत अच्छी तरह से बनाएंगे और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी मुख्य मंत्री महोदया को कि एक इस प्रकार का विजन उन्होंने सामने रखा है। मैं तो यह कह रहा हूं कि राजस्थान में अन्तरराष्ट्रीय स्तर का विजन रखा है बीस हजार किलोमीटर सड़कों का जाल फैला कर सड़कों के तंत्र में सत्तर हजार करोड़ रुपये खर्च करने की मंशा जताई है जिससे सड़कों के मामले में राजस्थान बहुत अच्छा प्रदेश हो। माननीय सभापति

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

महोदय, सारा अच्छा हुआ है और अच्छा भी होगा। सबसे बड़ी चीज है आज राजस्थान में पर्यटन की इतनी बढ़िया गुंजाइश है, पर्यटन का विकास कब होगा, जब सबसे पहले पर्यटन स्थल तक पहुंचने के लिए सड़कों का विकास हो। पर्यटन के साथ-साथ धार्मिक स्थलों, राजस्थान का पर्यटन एक ऐतिहासिक धरोहर और धार्मिक स्थान मतलब पूरे देश भर में गाथाएं आज जैसे चित्तौड़ की गाथाएं कही जाती है कि 'पद्मिनी की सुन्दरता पर जिसका मन ललचाया था सेना लेकर वो खिलजी चित्तौड़ पर चढ़ कर आया था, जीत नहीं पाया तब वो राजस्थानी वीरों से' ऐसी गाथाएं कही जाती है। पूरे देश भर में कही जाती है। मतलब देश में राजस्थान का एक ऐतिहासिक स्थान है ऐतिहासिक स्थान का विकास करने के लिए यह सड़क बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पूर्व में 2003 से 2008 में जो पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर रहे उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक बहुत बढ़िया तरीके से सड़कों का जाल फैलाया था और मैं प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय नहीं हैं, उनको यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान के इतिहास में हमने एक इतिहास बनाया था 2003 से 2008 में जब मैं विधायक था आहौर से, 2006 में अमरारामजी गृह राज्य मंत्री थे उनकी उपस्थिति में एक सरकारी कार्यक्रम में हमने यह कहा था कि सात दिनों के अन्दर ये सात से पन्द्रह दिन का पखवाड़ा दिया, टूटी हुई सड़क बताओ आहौर में और इनाम पाओ। मतलब एक-एक सड़क को देख-देख कर हमने ठीक किया था। उस समय अधिकारियों को भी हमने धन्यवाद दिया था और मंत्री महोदय ने भी धन्यवाद दिया था। यह स्थिति हम लाये और अभी भी लायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आज मंत्री महोदय का बहुत ही पवित्र त्यौहार है रोजा और रोजे के समय भी यहां पर पूरे समय बैठे हैं। ऐसी स्थिति में बिलकुल पवित्रता होनी चाहिए। मैं एक छोटी सी टैक्नीकल बात अधिकारियों से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। हम सड़कें तो बनाते हैं सड़कों के साथ-साथ जो सड़कों का ठेका दिया जाता है, सड़कों के साथ जो पटरी बनाने का काम होता है, सड़क तो पहले बना ली जाती है फिर पटरी को बाद में जेसीबी से खोद कर बनाया जाता है तो सड़क का जो बाक्सिंग लूज हो जाता है। ये टैक्नीकल बात है कि सड़क का डामरीकरण से पहले डब्ल्यूबीएम का जब काम होता है उस समय पटरी की भी खुदाई साथ-साथ हो जाए अन्यथा कई बार इनमें दो बातें होती हैं पटरी के लिए या तो सड़क बना कर महीने, दो महीने, चार महीने, छह महीने थोड़ा सा ग्रेवल डाल कर छोड़ देते हैं अब साथ

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

में खुदाई होगी तो उसकी भी प्रमाणिकता होगी। मंत्री महोदय इस बात का ध्यान रखेंगे। दो-तीन बातें हैं मेरे इलाके की वो मैं निवेदन कर लेता हूं, फिर से मुख्य मंत्री महोदय को तो सभी का धन्यवाद वास्तव में देने जैसी स्थिति है। हमने एक ऐसी सोच, ऐसा विजन और हण्ड्रेड परसेंट मैं यह कह रहा हूं कि हिन्दुस्तान के नक्शे पर बाकी के प्रदेश बार-बार एक बार नहीं दस बार कहेंगे कि सड़कें देखनी हैं तो राजस्थान की धरती पर जाकर देखो। यह स्थिति आने वाली है और यह विजन लिया है हमने।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि जब 2003 से 2008 आपने इतनी जानदार सड़कें बनाई तो फिर हारे क्यों?

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): हार और जीत का विषय नहीं है, हम बहुत अच्छे विपक्ष में थे आपके सामने। माननीय सभापति महोदय, जब इन्होंने कह ही दिया है आजादी के बाद पहली बार आहौर सीट हमने जीती थी और आजादी के बाद सडकों का जाल पहली बार हमने 2003 से 2008 में और चेलेंज के साथ आज भी पुराने अख़बार पड़े हैं हमने यह कहा था सीना ठोक कर आज दिन किसी ने कहा हो तो राजस्थान की धरती पर बताइये कि टूटी हुई सड़क बताओ और इनाम पाओ। यह कहा है हमारी सरकार और हमारे अधिकारियों के बलबूते पर।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, ये कह रहे हैं कि हारे कैसे तो आप जीते भी नहीं थे। आप बहुमत में थे क्या? आप तो यों ही चला रहे थे गोलमाल ही। (व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान स्टेट हाइवे आथोरिटी का गठन करके बहुत ही बढ़िया निर्णय लिया। इसमें हण्ड्रेड परसेंट राजस्थान के अन्दर सड़कों का विकास होगा। अब दो-तीन बातें हैं, एक तो फालना से सांडेराव...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, थोड़ा सा फास्ट। थोड़ा जल्दी।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): दो मिनट में। एकदम फास्ट सुपरफास्ट कर देता हूं। सांडेराव से रायथल होते हुए मोकलसर मतलब सांडेराव पाली जिले में आ गया और उसके बाद में लगभग सत्तर प्रतिशत हिस्सा मेरी कांस्टीट्यूएंसी में है, फिर बाड़मेर बार्डर पर जाती है तो एमडीआर में ये सड़क लेने से एक सबसे बढ़िया चीज चलेगी कि राजस्थान में, हिन्दुस्तान में जैन

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

तीर्थ नाकोड़ा जी पर जाने का एक पेरेलल रास्ता तैयार हो जाएगा और ब्रह्मा जी मंदिर आसोतरा पर जाने का तो सांडेराव से मोकलसर रोड एमडीआर में ले लेवें जिससे उस रोड का विकास हो जाएगा। दूसरी बात मैंने कहा है कि रामा से धूमड़ा माता। माननीय सभापति महोदय, अर्जुन और सुभद्राजी का विवाह जो हुआ था ये महाभारत काल की कथा है। विवाह जो हुआ था...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, कहां आ गई महाभारत? महाभारत करनी है क्या अपने को। विकास का काम करना है आपको तो। महाभारत कहां से आ गई, राठौड़ साहब? (व्यवधान) आपको धन्य हो।

श्री सभापति: आपने जब अपनी बात कही तो भी सुनी थी। (व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सुनने की आदत रखो। हम आप जो बोलते हैं वो सुनते हैं, आप चुपचाप सुनो। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य गोविन्द सिंहजी, आप विराजें अपने स्थान पर। माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): सचेतक महोदय, राष्ट्र की अस्मिता को ध्यान में नहीं रखते हैं और ये ही तो कारण है हम ये कभी नहीं कहते हैं कि आप विदेशी नेताओं को मानते हैं। हमने ये कभी नहीं कहा है लेकिन वास्तव में इस देश की भूमि से जब तक नहीं जुड़ोगे न तब तक कल्याण नहीं होगा। इस देश की भूमि से जुड़ना पड़ेगा आपको।

श्री हीरालाल (निवाई): कृष्ण भगवान को नहीं मानते हो क्या डोटासराजी, बताओ आप।

श्री सभापति: बीच में डिस्टर्ब न करें।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, मैं इसीलिये कह रहा हूं कि महाभारत काल का अर्जुन और सुभद्राजी का जो विवाह हुआ वहां पर...

श्री सभापति: आप पाइंट पर आइये। अपनी जो बात है उसको कहिये। बहुत सारे और लोगों को बोलना है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): मैं बिलकुल पाइंट पर आ रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बिलकुल माननीय सभापित महोदय, महाभारत के काल से सड़कों का निर्माण प्रारम्भ हो गया था। उस समय किस प्रकार की सड़कें बनती थीं, किस प्रकार की गुणवत्तापूर्ण सड़कें बनती थीं और अब भी वैसे की वैसे बना रहे हैं ये यों कह रहे हैं।

श्री सभापति: ठीक है। समय का ध्यान रखें थोड़ा सा। जल्दी करें।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, मैं उसी पाइंट पर आ रहा हूं। जहां सुभद्रा और अर्जुन का विवाह हुआ था वो भाद्राजून गांव हैं, मेरी तहसील में है, मैं यह कह रहा हूं वहां पर धूमड़ा माता का स्थान है। महाभारत में ऐतिहासिक स्थान है तो रामा से धूमड़ा जाने की जो सड़क है, समझा करो। थोड़ा पेशेंस रखो। शांति रखो। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक मुख्य बात रोही से जालौर एक टोल रोड बनी है जिसकी प्रामाणिकता बिलकुल जीरो परसेंट है। अब ये बन गई पिछली सरकार के समय, पिछली सरकार के जो नेता लोग हैं उनकी ठेकदारी में बनी है और वो ही टोल के मालिक भी हैं इसीलिए उस सड़क की प्रामाणिकता, जगह-जगह खड्डे पड़े हुए हैं, टोल के लायक रोड भी नहीं है। तो एक तो यह चीज और दूसरा मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि कई बार टोल का समय खतम हो जाता है लेकिन फिर भी वहां पर कुछ माफिया गैंगें टोल वसूला करती हैं तो वहां पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए कि इस साल से लगाकर इस साल के अंत तक टोल रोड है। तो ये चीज हो जाए, क्या होता है कि कई बार पूर्ववर्ती सरकार के ऐसे कुछ बड़े लोग जिनकी...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): फिर वो ही पूर्ववर्ती सरकार।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): हैं। रोही से जालौर, आपकी सरकार के नेता टोल वसूल कर रहे हैं ये मैं कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, बस एक मिनट, खाली एक बात कह रहा हूं। सिरोही से जो अभी माननीय सदस्य ने बताया है कि सिरोही से सियाला आकोली होते हुए जोधपुर की तरफ रोड जाती है तो सियाला, आकोली और सिरोही सीमा तक ये रोड बहुत ही एकदम खराब हो चुकी है उस रोड को प्राथमिकता से हमको करना है। मेरा एक निवेदन है ओर बस सभी की मांग है, सभी ने कहा है कि विधान सभा लेवल

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

पर छोटे-छोटे टुकड़े कहीं दो किलोमीटर, कहीं तीन किलोमीटर प्राथमिकता से जुड़ जाएं, मिसिंग लिंक की परमीशन मिल जाए तो ये भी काम सभी के लिए और जनता के लिए ठीक है। फिर से मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री के नेतृत्व में सड़कों का जाल और राजस्थान सड़कों के मामले में हिन्दुस्तान में नम्बर एक पर आए, हम सभी की जवाबदारी है और इसी बात को हम करेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(18.00 बजे)

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री पब्बारामजी।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, मैं बगैर कोई भूमिका बांधे मांग संख्या 19 और 21 के ऊपर अपने फलौदी विधान सभा क्षेत्र की बात रखना चाहता हूं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वसुंधराजी सुराज संकल्प यात्रा के दौरान फलौदी क्षेत्र में आई थीं, अपार जनसमर्थन को देखकर और उनके द्वारा की गई कुछ मांगें, कुछ सड़कों के निर्माण सम्बन्धी बातें उनके सामने रखी गईं तो उन्होंने कहा कि जब अपना समय आएगा तो निश्चित तौर से उसको पूरा करेंगे। इस जन दबाव के अन्दर उस समय जाते-जाते, हींग लगी न फिटकरी रंग आए चोखा इस तर्ज पर उन्होंने तीन सड़कों की स्वीकृति जारी की और वह भी शायद किसी क्लर्क से पैन लेकर, पैन की स्याही भी नहीं लगी होगी और स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। परन्तु उस स्वीकृति के अन्दर न तो बजट दिया गया था और न कुछ। निश्चित रूप से वह तीनों ही सड़कें लोक उपयोगी हैं। डड्डू से उगरास तक 5 किलोमीटर चूंकि रामदेवरा और कोलूपाबूजी दोनों ही तीर्थ स्थल हैं। गौरक्षक सूरवीर पाबूजी और रामदेवजी के इन धामों के बीच की सड़क लगभग 5 किलोमीटर है, अगर वह पूरी हो जाए तो तीर्थ यात्रियों के लिए भी ठीक रहेगा, यह स्वीकृत थी।

इसी प्रकार से टेकरा से धोडिया जैतेरी गांव होते हुए 13.2 किलोमीटर यह सीमांत दोनों बड़ी पंचायतें हैं। 30 किलोमीटर दूर से घूमकर दोनों गांवों को जोड़ती है इसलिए अगर 13.2 किलोमीटर बन जाती है तो लोगों के लिए अच्छा रहेगा, स्वीकृत सड़क है। इसी प्रकार से फलौदी में डिफेंस का बड़ा हवाई अड्डा है, डिफेंस की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। आठ किलोमीटर कच्ची सड़क को पक्की करना है और साढ़े चार किलोमीटर पक्की सड़क को चौड़ा करना है, कुल साढ़े बारह किलोमीटर है। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन लाइजनिंग कमेटी का प्रस्ताव भी सरकार के पास विचाराधीन है। इसीलिए मेरा आग्रह है कि तीनों

(श्री पब्बाराम)

स्वीकृत सड़कों पर से रोक हटाकर इनके लिए बजट जारी किया जाए ताकि निर्माण हो सके। इसी प्रकार से हमारे क्षेत्र का एक पंचायत हैडक्वाटर रोहिणा है। कहते हैं रोहिणा और गूगडी कोई समतल मैदान में नहीं है, वहां पर चारों तरफ टीबे ही टीबे हैं, वहां जाना आसान भी नहीं है, उसको जोड़ने का प्रयास गलत दिशा से हो गया। पूर्व में गलती हो गई क्योंकि सभी कार्यालय रोहिणा से पश्चिम की तरफ पड़ते हैं चाहे उप तहसील है, चाहे तहसील है, चाहे उपखण्ड कार्यालय है, पंचायत समिति कार्यालय है, सारे के सारे पश्चिम में पड़ते हैं और इस गांव का दुर्भाग्य है उसको पूर्व की तरफ से पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है, 30 किलोमीटर अधिक रन करना पड़ता है इसलिए मेरा विशेष आग्रह है कि माननीय मंत्रीजी, साढ़े छह किलोमीटर की इस सड़क को स्वीकृति प्रदान कर उन लोगों के दुख-दर्द को सुनेंगे।

इसी प्रकार से एनएच-15 फलौदी से होकर गुजरता है। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और पूरे पंजाब को जोड़ने वाली लाइफ लाइन है इसके ऊपर आरओबी का निर्माण हो जाए, फलौदी शहर के अन्दर से गुजरता है, आरओबी नहीं होने के कारण फाटक बंद होता है तो कई किलोमीटर तक वहां पर जाम लगता है, इसके ऊपर से आरओबी प्रस्तावित की जाए। इसी प्रकार से फलौदी, औसियां और जोधपुर के बीच एक टोल रोड बनाने का प्रस्ताव पूर्ववर्ती सरकार का था, वह टोल रोड बन रही थी, दुर्भाग्य उस रोड का कि अदूरदर्शिता के कारण तीन-तीन बार ठेकेदारों को ब्लेकलिस्टेड करने के बाद अब कहीं पूर्णता की तरफ अग्रसर है। परन्तु दो ठेकेदारों ने उसको खराब गुणवत्ता से निर्मित किया, नया ठेकेदार था वह भी अच्छी तरह से कुछ नहीं कर पाया। इस परिस्थिति में जब सड़क बनी है वह टोल के योग्य भी नहीं है। वहां पर समस्त सिंचित क्षेत्र है, अण्डरग्राउण्ड पानी सिंचित होता है, सभी किसानों के काम आने वाली है, तो टोल रोड के ऊपर से टैक्स माफ किया जाए यह मेरा विशेष आग्रह है।

अभी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय विधायकजी की चिंता को मैं भी परिलक्षित करूंगा, वास्तव में चिंता का विषय है, आपकी अच्छी बात है उसकी हम प्रशंसा करते हैं। आपने अपने पूर्ववर्ती कार्यकाल के अन्दर सडांध को महसूस किया था, यानी क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम को जो धरम परम हो गया था, उस समय में क्वालिटी के अन्दर कंट्रोल का सिस्टम नहीं था इसलिए खराब गुणवत्ता की सड़कें बनीं। आज स्थिति यह है। उस समय तो यह ठीक

(श्री पब्बाराम)

नहीं कर पाए परन्तु उन्हें पता है कि संवेदनशील सरकार वसुंधराजी के नेतृत्व में बन चुकी है तो निश्चित तौर से यह इनको ठीक करेंगे। मैं मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। पूर्ववर्ती सड़ांध है उसको काटकर फैका जाए ताकि अच्छी गुणवत्ता की सड़कें बन सकें। एक मेरा निवेदन यह था कि, मैं सम्मानीय मुख्य मंत्रीजी को विशेष धन्यवाद...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, कोई कैबिनेट मंत्री है ही नहीं, माननीय सदस्य बोल रहे हैं, कौन लिखेगा।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): कैबिनेट मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री भी हैं...(व्यवधान) उनको पता नहीं कैसे नहीं दिख रहा है, यह तो वो ही जाने, भगवान ही जाने क्या हुआ। (व्यवधान)

श्री पब्बाराम (फलौदी): आईजीएनपी के प्रथम और द्वितीय चरण की सड़कें बनी थीं, नहरें हैं उसके साइड में जो रोड बनी थी उसका कोई धणी धोरी नहीं था, 35 साल से बनी हुई थी। माननीय वसुंधराजी जिस समय बीकानेर के दौरे पर गई, उन्होंने दौरे पर जाने के बाद महसूस किया कि इनका कहीं न कहीं कुछ उद्धार होना चाहिए। कुछ गांव उसके साथ थे उनको जुड़ा हुआ मान लिया परन्तु वहां पर सड़क नाम की चीज नहीं, वहां पर डामर नहीं मिल रहा था। उनको लगभग 500 किलोमीटर रोड दी है, उसको पीडब्ल्यूडी के अन्दर देकर ठीक कराने का जो काम हाथ लिया मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। फैज नम्बर दो की जो नहरें हैं उसके पास की सड़कों को पहले लिया जाए, वहीं पर यह सब गड़बड़ है। हमारे वहां पर एक किसान थे, 35 साल पहले उसके खेत के पास से रोड निकली, जब रोड निकली तो उस समय यह भाव था कि अगर खेत के पास से रोड निकलेगी तो पशु खेत चट कर जाएंगे, नुकसान हो जाएगा इसलिए हमारे खेत से दूर रखें। परन्तु उस किसान रामूजी भादू ने सभी लोगों को इकट्ठा करके गोठ दी और बड़ी खुशी मनाई, रोड पर आकर उसने बोला कि अब मैं खड़ा हूं तो सीधा दिल्ली में खड़ा हूं, सीधा कलकत्ता में बैठा हूं, सीधा मद्रास और कश्मीर में बैठा हूं, यानि रोड के ऊपर आने से व्यक्ति दुनिया के हर हिस्से से जुड़ जाता है। माननीय वसुंधराजी ने एक अच्छा ड्रीम देखा और इस राजस्थान में सड़क के जाल बिछाने से, बंधुओं जहां पर सड़कें जाती हैं, सड़क एक काली गंगा है जहां से होकर विकास सामान्य व्यक्ति तक पहुंचता है। उसके साथ में वाणिज्यिक गतिविधियां भी

(श्री पब्बाराम)

चलती हैं। ऐसी परिस्थिति में यह विकास का प्रतीक है। 20 हजार किलोमीटर का जो लक्ष्य रखा है, निश्चित तौर पर राजस्थान को आगे ले जाने वाला, विकास को गति प्रदान करने वाला बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। हम सभी उनके इस लक्ष्य को नमन करते हैं तथा आने वाले समय में इस तस्वीर को बदलने का जो उनके अन्दर मनोभाव है उसको नमन करते हुए मैं एक बार पुन:, मेरी मांगों के ऊपर सरकार ध्यान दे, यही आग्रह कर रहा हूं। धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री शत्रुघ्न गौतम।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): माननीय सभापति महोदया, मांग संख्या 19 और 21, पी.डब्ल्यू.डी., सड़क निर्माण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आया हूं उस विधान सभा क्षेत्र में राजस्थान के एक लौह पुरुष जो अपने आपको विकास पुरुष कहते थे लेकिन, स्थिति यह रही कि पांच साल में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा, जो विकास के नाम पर चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति, पूरे पांच साल में यदि केकड़ी में देखा जाए और दुर्घटना के आकड़े निकाले जाएं तो कम से कम एक हजार लोग सड़क दुर्घटनाओं के कारण मौत के मुंह में चले गए। केकड़ी से चाहे अजमेर जाना हो, केकड़ी से यदि भीलवाड़ा जाना हो, केकड़ी से यदि देवली जाना हो, केकड़ी से यदि जयपुर जाना हो तो चारों तरफ खड्डे ही खड्डे। पूरी सड़कों की स्थिति बिलकुल बदतर। ऐसी स्थिति पूरे पचास वर्षों में जो पिछले पांच वर्षों में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा केकड़ी क्षेत्र में की गई, कभी नहीं हुई।

और तो और, सड़कों के नाम पर भी पेच के काम राजस्थान में यदि देखा जाए, उनकी जांच करवाई जाए तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि पेच में भी केकड़ी क्षेत्र पूरे पांच वर्ष, 2008 से 2013 में अव्वल रहा। केकड़ी क्षेत्र से गुजरने वाला मेगा हाइवे, जो पूर्ववर्ती सरकार ने भीलवाड़ा से जयपुर के लिए पी.पी.पी. माडल पर करवाया, 2008 में कार्य चालू हुआ। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि आज तक भी वह कार्य पूरा नहीं हुआ। रोड आगे बनता है तो पीछे टूटता जाता है। क्षेत्र की जनता पिछले पांच वर्ष से यह पीड़ा भुगत रही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी वसुन्धराजी जब 'सुराज संकल्प यात्रा' में केकड़ी पधारी थीं तो उन्होंने केकड़ी के हालात देखकर, दुर्दशा देखकर कहा कि ऐसा केकड़ी है, इसमें खड्डे हैं। सड़क में खड्डे ढूंढे या खड्डे में सड़क ढूंढे। ऐसी स्थिति केकड़ी की रही है। देवली से लेकर नसीराबाद तक एक मेगा

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

हाई-वे बनाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने 143 करोड़ रुपए की लागत से, पूर्व मुख्य सचेतक राजस्थान के, अपने आपको बड़े लौह पुरुष कहने वाले व्यक्ति, जिन्होंने चार-पांच चुनाव लड़े और मात्र एक जीता, चार हार गये। विकास पुरुष कहलाने वाले, उन्होंने पी.पी.पी. माडल पर नहीं जाते हुए 143 करोड़ का काम आर.एस.आर.डी.सी. से करवाया और उसकी प्लिंथ का काम 'रवि कंस्ट्रक्शन कम्पनी' को दिया। वह काम अभी पूरा हुआ है।

माननीय मंत्री महोदय को मैं आपके माध्यम से निवेदन कर देना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, कि उसमें टोल शुरू हो गया और रोड चालू होने के मात्र महज एक-दो महीने के अन्दर ही पूरा रोड उखड़ गया। ऐसी स्थिति है कि आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं। केकड़ी क्षेत्र में ढाई सौ से पांच सौ की आबादी के, कांग्रेस के, 2008 से 13 तक के बजट को पढ़ते हैं तो लगता है कि 15 हजार किलोमीटर की सड़कें जोड़ी जाएंगी और हम 250 से अधिक आबादी के गांवों की सड़कें बनाएंगे। लेकिन, मैं निवेदन करूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ढाई सौ से पांच सौ की आबादी के कम से कम साठ गांव ऐसे होंगे जो आज भी सड़क से महरूम हैं। उन गांवों में स्थिति यह है कि जब किसी महिला को प्रसव पीड़ा होती है तो बारिश के मौसम में उनको किसी साधन से नहीं ले जा सकते। मैंने खुद इस स्थिति को देखा है कि गोद में दो-चार पुरुष मिलकर उस महिला को उठाकर अस्पताल पहुंचाया जाता है, ऐसी स्थिति केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में है।

जो सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बन रही हैं उन सड़कों में तीन मीटर की चौड़ाई होती है। तीन मीटर की चौड़ाई और उनकी भी एक क्वालिटी मेनटेन करने का रेश्यो होता है लेकिन जहां पर बजरी का खनन होता है या मार्बल के जो एरिया हैं वहां पर गाड़ियां ओवर लोड चलती हैं और वह सड़क बनने से पहले ही टूट जाती है। आगे सड़क बनती है और पीछे से टूट जाती है तो मैं यह निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि ऐसा कोई सर्कुलर होना चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिसके माध्यम से ओवर-लोड पर काबू करके इन सड़कों को टूटने से बचाया जा सके।

(18.15 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि देवली से नसीराबाद सड़क बनी है वहां पर जो 143 करोड़ रुपए से जो काम खतम हुआ है, उस काम को वापस करवा कर और उसमें कोई भी

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

दुर्घटनाएं नहीं हों, ऐसी व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए। सड़कों की गुणवत्ता आये दिन देखने को मिलती है। इस क्षेत्र के अंदर सड़क पर जो भी काम चल रहे हैं, उनमें सड़कों की गुणवत्ता का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। सड़कें बनती हैं और फिर टूट जाती हैं। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके विधान सभा क्षेत्र से भी मेरा क्षेत्र सटा हुआ है। मेरा क्षेत्र तीन-तीन जिलों के अंदर आने-जाने का एक बहुत महत्वपूर्ण केन्द्र है। लेकिन उन जिलों में देखा जाए तो एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने के लिए वहां पर अपने जिले में छोड़ दिया जाता है और दूसरे जिले की बात कह दी जाती है। तो इसलिए जिलों की सीमाओं को मिलाने के लिए एक इस तरह से होना चाहिए कि टोंक जिला अजमेर जिले से, भीलवाड़ा जिला अजमेर जिले से, बूंदी जिला मेरे विधान सभा क्षेत्र के सम्पर्क में है। आपसे मेरा तो यही निवेदन है कि जो ढाई सौ से पांच सौ तक की आबादी के गांव लिए गए हैं वे सभी गांव सड़कों से जुड़ें और निश्चित रूप से हमारी मुख्य मंत्रीजी ने 20 हजार किलोमीटर सड़क बनाने का जो संकल्प लेकर इस बजट में महत्वपूर्ण घोषणा की है उससे लगता है कि राजस्थान विकास की गति पकड़ेगा और राजस्थान के अंदर समुचित विकास होगा। यह विकास के लिए नया मील का पत्थर साबित होगा। ऐसे नहीं कि जिस तरह जयपुर भीलवाड़ा रोड पांच वर्षों से नहीं बन रही और पूर्व मुख्य मंत्रीजी जिनके ऊपर खूब आरोप लगे कि हां, इस सड़क से इनका, कोठारी बंधुओं का क्या लेना-देना है? लेकिन उन पर कोई भी इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई और आज पांच वर्षों में भी वह सड़क पूरी नहीं हुई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं केकड़ी क्षेत्र के जो सीमावर्ती जिले हैं, उनसे केकड़ी क्षेत्र को जोड़ा जाए और अजमेर जिले को जोड़ा जाए। निश्चित रूप से सभी जिलों में, एक मेरा सबसे महत्वपूर्ण यह है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। आपका समय हो गया है। इसके बाद श्री भंवरसिंह। दस मिनट।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले की सड़कों के बारे में, विशेषकर मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे और सरकार से कि पी.पी.पी. मोड पर 20 हजार किलोमीटर की सड़कें वर्ष 2014-15 के बजट में बनवाने की घोषणा की गई है, निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य कदम है।

(श्री भंवरसिंह)

सड़क विकास का एक बहुत बड़ा जरिया होता है और सड़कों के जरिए ही देश और प्रदेश हमेशा आगे बढ़ता रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पी.पी.पी. मोड में सड़कें निजी कम्पनियों द्वारा, जो इंवेस्टर होते हैं उनके सहयोग से राज्य सरकार के द्वारा बनाई जानी प्रस्तावित है। मेरा यह निवेदन रहेगा कि जिन सड़कों पर आवागमन ज्यादा होता है, जहां पर ज्यादा वाहन चलते हैं उन सड़कों को तो पी.पी.पी. मोड पर बनवाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वे सड़कें तो बन जाएंगी लेकिन जहां पर आबादी कम है या जहां पर यातायात का दबाव कम रहता है, ऐसी कई महत्वपूर्ण सड़कें भी हैं। उन सड़कों को शायद, मैं जहां तक समझता हूं पी.पी.पी. मोड पर बनवाना मुश्किल रहेगा। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ऐसी महत्वपूर्ण सड़कों को यदि पी.पी.पी. मोड पर नहीं बनवाया जाता है तो ऐसी सड़कों को राज्य सरकार अलग से प्रस्ताव करके बनवाने की योजना पर विचार करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छोटे राजस्व गांव, सभी राजस्व गांवों को केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जोड़े जाने की योजना पिछले सात, आठ, दस सालों से चल रही है। तो निश्चित रूप से सभी राजस्व गांव इस योजना के तहत अच्छी सड़कों से जुड़ जाएंगे लेकिन एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली जो मिसिंग लिंक सड़कें होती हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उन सड़कों को जोड़ना भी काफी आवश्यक हो गया है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे 50 गांव हैं जिनमें दो किलोमीटर, तीन किलोमीटर या पांच किलोमीटर की सड़क बनवाये जाने पर सीधा आवागमन का रास्ता बन जाता है और लोगों को आवागमन के लिये घूमकर नहीं जाना पड़ेगा। मेरा निवेदन रहेगा कि मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण पर भी आने वाले समय में विशेष ध्यान दिया जाये।

विधायकों की अनुशंसा पर पिछले वर्षों में मिसिंग लिंक सड़कों के लिये 8 किलोमीटर प्रति वर्ष विधायक की अनुशंसा पर सड़क के प्रस्ताव दिये जाते थे और धार्मिक स्थानों को जोड़ने के लिये भी शायद पांच किलोमीटर प्रति वर्ष विधायकों की अनुशंसा पर अलग-अलग विधान सभा वार सड़कें बनाये जाने का प्रस्ताव रहा है। काफी क्षेत्रों में इन सड़कों से धार्मिक स्थानों को भी जोड़ा गया। पिछले वर्षों में और मिसिंग लिंक के माध्यम से काफी गांवों को फायदा दिया गया। लेकिन अभी भी प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में, मैं मेरे

(श्री भंवरसिंह)

विधान सभा क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, कोलायत विधान सभा क्षेत्र ढाई सौ किलोमीटर की लम्बी परिधि में फैला हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि 500 किलोमीटर की सड़कें भी यदि हम वहां बना दें तो भी पूरा क्षेत्र सड़क से नहीं जुड़ पायेगा। अन्य योजनाओं में इन गांवों को नहीं जोड़ा जा सकता तो विधायकों की अनुशंसा पर जो जरूरी सड़कें हों, कम से कम उन सड़कों को जोड़ने के लिये मैं सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के प्रावधान किये जायें।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की सड़कों के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। फलौदी से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने जो बात कही है, मैं उस बात में इस बात को जोड़ते हुए कहना चाहूंगा कि पिछले 35-40 सालों से, जब से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण हुआ था, इन सड़कों को नहर पर सामान ले जाने के लिये और आवागमन के लिये बनाया गया था। उसके बाद लगातार इन सड़कों की कोई देखरेख नहीं की गयी। उसकी वजह से यह सड़कें आज जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और अधिकांश सड़कें गायब भी हो गयी हैं। हमने भी मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया था बीकानेर आगमन पर कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की जितनी भी सड़कें हैं द्वितीय चरण की, उन सभी सड़कों को आई जी एन पी से या तो मेन्टीनेंस करवाया जाये अन्यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग को इन सड़कों को हस्तान्तरित कर दिया जाये। मैं इस बात के लिये स्वागत करना चाहूंगा कि इन सड़कों को पी.डब्ल्यू.डी. को ट्रांसफर कर दिया गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इन सड़कों के निर्माण के लिये एक विशेष कार्य योजना बनाकर नहरी क्षेत्र की जो सड़कें हैं, इनका पुनर्निर्माण करवाया जाये और इन सड़कों में जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं, उनको एम डी आर सड़कों के रूप में भी विकसित किया जाये। अध्यक्ष महोदय, बीकानेर से जैसलमेर तक जाने वाली सड़क भी इन मुख्य नहर के साथ-साथ चलती है। इसके अलावा बीकानेर से फलौदी के क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क भी कोलायत और गजनेर लिफ्ट परियोजना के साथ-साथ चलती है। कोलायत, गजनेर और बांगड़सर लिफ्ट की जो सैकण्ड फेज की सड़कें हैं, इन सड़कों का आने वाले समय में एक कार्य योजना बनाकर पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से सुदृढ़ीकरण करवाया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): दो मिनट का समय लेना चाहूंगा। फलौदी विधान सभा क्षेत्र के ओसियां से होते हुए दासोड़ी तक एम डी आर संख्या 35 है, वह पूर्व में घोषित है। मेरा निवेदन रहेगा माननीय चिकित्सा मंत्रीजी हमारे प्रभारी रहे हैं, आप गये हैं करीब 15-20 ग्राम पंचायतों में, एक ही मांग रही है कि दासोड़ी से बीकानेर तक एम डी आर सड़क घोषित की जाये तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि बीकानेर से दासोड़ी एम डी आर 35 की लम्बाई बढ़ाते हुए इसे ओसियां तक घोषित करें, जिससे बीकानेर जिले का सीधा जुड़ाव जोधपुर जिले से हो सके। इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष: हो सके तो आप लिखित में दे दीजिये। स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 19 लोक निर्माण कार्य और 21 सड़क एवं पुल के ऊपर राजस्थान के पवित्र सदन में चर्चा चल रही है। मैं भी इसमें अपने आपको सम्मिलित करते हुए निवेदन करता हूं कि 2003 से लेकर 2008 तक जो राजस्थान में सड़कें बनीं, उन सड़कों का आज भी लोग गुणगान करते हैं। कांग्रेस ने इन पांच साल के राज में उन सड़कों का पूरा-पूरा राजस्थान में भट्ठा बैठा दिया। सड़कें बिलकुल ऐसी बन गयीं कि जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं दो बार जीता तब दोनों बार अशोकजी गहलोत आये और मेरे क्षेत्र में इन्होंने एक भी काम सड़कों का नहीं किया। इन्होंने द्वेषता की भावना से काम किया। इसलिये निवेदन करता हूं कि अब की बार इस वर्ष मेरे क्षेत्र में सारा बजट केवल सड़कों के लिये दिया जाये, दूसरा कोई कार्य नहीं किया जाये तो भी चल सकता है, मगर सड़कें दुरूस्त कर दी जायें, नहीं तो चलने लायक भी नहीं है। कांग्रेस जाते-जाते स्टेट हाइवे के लिये घोषणा तो कर गयी मगर बजट का कोई पता ही नहीं है। आज 61 और 62 नम्बर जो रोड है, उनके लिये 200 करोड़ और 145 करोड़ की घोषणा तो की, मगर आज दिन तक कहीं बजट घोषणा के अलावा कुछ नहीं, थोथी घोषणाएं करके चले गये। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि स्टेट हाइवे 61 और 62 को दुरूस्त करावें और भीलवाड़ा से लेकर फलौदी वाला रूट है इसके लिये यह बहुत ही मेजर और मुख्य रोड है, इसको आप, स्टेट हाइवे के लिये जो

(श्री केसाराम चौधरी)

बजट स्वीकृति दी थी, उसके अनुसार कार्य करवायें और 62 नम्बर जो स्टेट हाइवे पर 135 करोड़ की स्वीकृति है, उसे भी लगाकर मेरे दोनों रोड ठीक करवाये जायें। स्टेट हाइवे 58 नम्बर भी मेरे क्षेत्र में आता है, उसकी भी बिलकुल टूट-फूट हो गयी है, उसको भी पेवर कराने की मांग करता हूं। इसके साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण के कार्य, जो करने हैं, उसमें एस डी ओ कोर्ट का भवन राणी में बनना है, एस डी ओ कोर्ट की स्वीकृति हो गयी और तहसील कार्यालय की भी स्वीकृति हुई है मगर उसके भवन नहीं है। एक भवन, जो दानदाता ने बनाया था, उसमें एस डी एम कोर्ट और तहसील कार्यालय चलते हैं। उनके भवनों के बनाने की भी मांग करता हूं।

साथ ही खिंवाड़ा उप तहसील की भी आपने घोषणा की है, उप तहसील तो खुल गयी, मगर उसके भवन नहीं है। इसलिये भवन की भी शीघ्र बनाने की मांग करता हूं। मारवाड़ जंक्शन डाक बंगला बिलकुल जीर्ण-शीर्ण हालत में है, मारवाड़ जंक्शन रेलवे का सबसे बड़ा कोरिडोर जंक्शन बन रहा है और इस कोरिडोर जंक्शन पर बहुत काफी लोगों का आना-जाना रहता है। मगर डाक बंगले में केवल दो कमरे ही हैं और वह भी बिलकुल अंग्रेजों के समय में बने हुए हैं। उनकी मरम्मत भी आज तक नहीं हुई है। इसलिये उसका भी सुदृढ़ीकरण और दो कमरे और बनाने की मांग करता हूं।

रानी के अन्दर एस डी ओ कोर्ट और तहसील कार्यालय नये खोले हैं, वहां पर कोई भी सरकारी आवास या रूकने की जगह नहीं है, इसलिये वहां पर सर्किट हाउस बनाने की मांग करता हूं और लोक निर्माण के जो कार्य अपने इस राज में होने चाहिये, निश्चित रूप से उनका बजट भी हो गया है और जगह भी हो गयी है, तो आपसे अनुरोध करता हूं तुरन्त प्रभाव से बनाकर उनकी स्वीकृति हो गयी है, वह जल्दी से बनाने की कृपा करावें।

इसके साथ ही मेरे क्षेत्र में जो सड़कें खराब हैं, जिनकी हालत बिलकुल जीर्ण-शीर्ण हो गयी है, मारवाड़ जंक्शन से दुधोड आठ किलोमीटर है, डेली एक्सीडेंट होते हैं। पटरियां नाम की कोई जगह नहीं है। ऐसी सूरत में इन आठ किलोमीटर की सड़क खेरवा से खारची सड़क को, बिटोड़ा खुर्द से खारची तक चार किलोमीटर की बिलकुल खराब हालत में है। राणावास से ठाकुरवास, डायलाना कल्ला से केसूली, खिंवाणा से बरदार होते हुए रायपुरिया, बिजोवा से राबड़िया होते हुए खारड़ा, देवली पाबूजी गौशाला से सांवलता, सांवलता से जीवन्त, खिंवाड़ा से पनोता, गोलाई से शेखावास से सड़कें आज से 15-15 साल

(श्री केसाराम चौधरी)

हो गये बनी हुई हैं, मगर आज तक इनका सुदृढ़ीकरण और पेवर नहीं किया गया है और पेवर किया जाता है, उसका पौन इंच का कारपेट दिया जाता है, जिससे यह सड़कें ज्यादा लम्बे समय तक नहीं टिक सकती है। इसके लिए इस कारपेट की थिकनेस को बढ़ाया जाए और कम से कम उसको डेढ़ इंच का कारपेट दिया जाए ताकि यह सड़कें लम्बे समय तक चल सकें। किशनपुरा से रानी एस.डी.एम. हैडक्वार्टर है जिसको मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से जोड़ने के लिए पांच किलोमीटर अगर रानी होते हुए मुडारा तक जोड़ दिया जाए तो एक बहुत ही अच्छी सड़क बन जायेगी।

आकड़ावास से बायोसा का मन्दिर गोधावास तीन किलोमीटर, डूठारिया से जवाली तीन किलोमीटर, मेबी से महादेव डेढ़ किलोमीटर, बीजोवा से खेड़ा महादेव होते हुए मामाजी के थान तक चार किलोमीटर, इन धार्मिक सड़कों को भी जोड़ने की मांग करता हूं।

सिंचाना से सारण चौराहा चार किलोमीटर, कराड़ी से बिचोड़ाकला चार किलोमीटर, धनला से आसापुरा तीन किलोमीटर, गुढा जैतसिंह से भिमालिया रेलवे फाटक तक तीन किलोमीटर, पांचेटिया से बांता आठ किलोमीटर, यह मिसिंग लिंक की सड़कें हैं, इनको भी करने की मांग करता हूं। इस तरह से राणावास और रामसिंह गुढा के बीच में जो सड़कें हैं, सड़कें तो बनी हुई हैं मगर पांच-सात पंचायतों का सीधा आवागमन रहता है। राणावास के पास में जो पुलिया है उसका निर्माण नहीं होने से बरसात के समय रास्ता बिलकुल बंद हो जाता है और सात पंचायतों का रास्ता बंद हो जाता है इसलिए इस पुलिया के निर्माण की भी मांग करता हूं। मारवाड़ जंक्शन के बाहर सोजत मार्ग के पास मारवाड़ से निकलते ही पुलिया है वो बिलकुल जीर्णशीर्ण हालत में है और टूट चुकी है अतः उसका भी निर्माण करने की मांग करता हूं।

मारवाड़ जंक्शन रेलवे क्रासिंग कारीडोर स्टेशन बन रहा है और इसमें चार लाइनें एक साथ निकलेगी, इस स्टेशन पर ऐसा कोई रेलवे फाटक नहीं होगा जिससे कोई रास्ता क्रास कर सके इसलिए मारवाड़ जंक्शन एक बहुत बड़ा जंक्शन बनेगा, इसके ऊपर एफ.सी.आई. के पास से ओवरब्रिज की मांग करता हूं क्योंकि इस ओवरब्रिज में आधा हिस्सा राजस्थान गवर्नमेंट का होता है इसलिए मैं मांग करता हूं कि कारीडोर के साथ-साथ आप इसकी भी स्वीकृति दिलावें। 40-50 किलोमीटर के बीच में एक भी ओवरब्रिज नहीं है और इस कारीडोर के ऊपर से निकलने के लिए नीचे से जो अण्डर पास दे रहे हैं

(श्री केसाराम चौधरी)

उसमें से कन्टेनर की गाड़ियां पास नहीं हो सकेंगी, ऐसी सूरत में मारवाड़ जंक्शन के ऊपर ओवरब्रिज की मांग करता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री नन्द किशोर महरिया। 10 मिनट।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): पांच मिनट।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले छह दिन से जिन भी माननीय सदस्यों ने बोला है, सड़कों के बारे में बड़ा अच्छा बोला है और बीस हजार किलोमीटर की जो सड़कें हैं उनको बहुत बड़ा तोहफा मानकर बोला है। यह शायद इसलिए है कि पिछले पांच साल में बहुत कम सड़कें बन पायीं वरना राजस्थान के लिए बीस हजार किलोमीटर सड़कें कोई मायने नहीं रखतीं। अपना जो स्टेट एवरेज नेशनल एवरेज से वन थर्ड है। अगर अपने को नेशनल एवरेज भी पहुंचना हो तो कम से कम चार लाख किलोमीटर सड़कों की और जरूरत है। हर सौ स्क्वायर किलोमीटर में अपने यहां सिर्फ 57 किलोमीटर सड़कें हैं और देश में 148, अब चार लाख की जरूरत में बीस हजार में किस बात की प्रशंसा हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बीस हजार किलोमीटर भी जो तय की गयी हैं वो भी पीपीपी मोड पर है।

आज सुबह ही अखबारों में खबर थी कि राष्ट्रीय लेवल पर पीपीपी मोड का क्या हाल हो रहा है? गड़करीजी को ठेकेदार नहीं मिल रहे। तो यह बहुत ही ध्यान रखने की बात है। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा मंत्रीजी को कि आपको आठ-दस गुणा मेहनत करनी पड़ेगी और इन सड़कों को कम से कम चालीस-पचास हजार किलोमीटर तो बनवाएं। बीस हजार किलोमीटर से यहां कुछ नहीं होने वाला।

अपने स्टेट में अगले पांच साल में 75 लाख नये साधन सड़कों पर आने वाले हैं क्योंकि बजट में बड़ी अच्छी चीजें दी हैं, विकास होगा और सिर्फ 15 परसेंट भी साधनों की ग्रोथ रही तो 75 लाख नये साधन सड़क पर आयेंगे। एक करोड़ 11 लाख पहले से घूम रहे हैं, एक करोड़ 77 लाख हो जायेंगे। 195 अपनी सड़कें हैं वो 216 हो जायेंगी तो एवरेज आज एक किलोमीटर पर 57 साधन सड़क पर हैं वो 82 हो जायेंगे, यानि कि डेढ़ गुणा। अब क्या हालत

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

अपने अजमेर रोड की पिछले तीन दिन से चल रही है, क्या हालत जयपुर-दिल्ली रोड की है। मेरा तो यह निवेदन है कि कम से कम चार लाख भी नहीं तो चालीस हजार किलोमीटर सड़कें तो इस डिपार्टमेंट के द्वारा अगले पांच साल में बनवायी जाएं। फिर भी अपन राष्ट्रीय एवरेज से बहुत पीछे रह जायेंगे।

मैं बहुत छोटी-छोटी, दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर की मेरे क्षेत्र की दस-बारह सड़कें बताना चाहूंगा जिनसे इनको लगभग 300-400 किलोमीटर के चक्कर लगाने का रहता है, क्योंकि पहले जब गांव जुडे तो वो सिर्फ गांव जुड़ने थे, उनमें रास्ता नहीं देखा गया कि किधर से जोड़े जाएं। तो जालेऊ से गोरास सिर्फ दो किलोमीटर। दीनारपुरा से ढाणी रामपुरा वाया थेथलिया सात किलोमीटर। गारिण्डा से हरसावा छोटा तीन। जलालसर से रूपनगर पांच किलोमीटर। देसवा से गोडपुरा चार किलोमीटर। गांगियासर से फतेहपुर हरिजन बस्ती होते हुए चार किलोमीटर। बलोद बड़ी से कायमसर वाया ठेडी दस किलोमीटर। मांडेला छोटा से फतेहपुरा साढ़े पांच किलोमीटर। बिकूसिया ढाणी से मांडेला बड़ा डेढ़ किलोमीटर। मांडेला बड़ा से ढाणी चतरदास डेढ़ किलोमीटर। मरडाटू बड़ी से हरिजन बस्ती डेढ़ किलोमीटर। तिहावली से न्यांगली तीन किलोमीटर। रिणाउ बीबीपुर मेन रोड से नाथजी का आश्रम डेढ़ किलोमीटर। ठेडी से लावण्ड चार किलोमीटर। हिरणा से बेसवा आठ किलोमीटर।

इसके अलावा जो नेशनल हाइवे बन रहा है सीकर-बीकानेर उसमें हरसावा गांव है, माननीय मंत्रीजी भी जानते हैं, वहां गांव एक तरफ बसा हुआ है और सीनियर सैकण्डरी स्कूल दूसरी तरफ, बच्चों का आवागमन भी रहता है और हर साल लगभग वहां 15-20 लोग मौत के ग्रास में जाते हैं, वहां एक अण्डर पास बनवाना है जिससे लोगों को साधन मिल सके और आराम से उधर से जा सकें।

इसके अलावा जो गौरव पथ का काम किया जा रहा है वो वाकई बहुत प्रशंसनीय है। इसकी निश्चित रूप से जितनी प्रशंसा की जाए कम है बशर्ते कि जल्दी ही शुरू हो जाए और जल्दी पूरा हो जाए। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कमसा मेघवाल।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 19 और 21 पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाह रही हूं कि भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में दो रेलवे क्रासिंग हैं, उनके नीचे से अण्डर पास, पुल तो बन गये

(श्रीमती कमसा)

लेकिन बारिश का मौसम है और अगर कोई वहां से मोटर साइकल लेकर गुजरे तो वहीं का वहीं डूब कर रह जायेगा, इतना पानी भर जाता है। उस पानी की निकासी के लिए रेलवे ने कुछ भी नहीं किया है और गांव के बीच में से वो ही रास्ता है दो गांवों के बीच का, तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उस पुल के नीचे जो पानी भरा हुआ रहता है उनका भी आप निदान कराने की कृपा करें।

गांवों के अन्दर जो सड़कें बनती हैं, सड़कें तो बनती हैं लेकिन घनी आबादी से होते हुए गुजरती है, वहां डामर सड़क नहीं रहती क्योंकि पानी इकट्ठा हो जाता है और पानी निकासी के लिए उन सड़कों के साथ कुछ भी नहीं किया जाता है, आज अगर अपन गोबर और मिट्टे के आंगणे की लीपापोती कर के रखें तो उसका भी कुछ नहीं बिगड़ता है लेकिन डामर की सड़क जो गांव के बीच में बनी है वो डामर एक महीने बाद में ही पानी के भराव के कारण हट जाता है तो मेरा निवेदन है कि जिस भी गांव के अन्दर से डामर सड़कें गुजरती हैं उनके साथ-साथ नाली निर्माण और उस गांव में सी.सी. रोड उस डामर सड़क के साथ स्वीकृत की जाए जिससे उस सड़क की वैल्यू ज्यादा होगी और ज्यादा समय तक टिक पायेगी।

भोपालगढ़ से जोधपुर जाने वाला जो रास्ता है, बैनाड़ रोड़ पर ओवर ब्रिज का गहलोत साहब ने उद्‌घाटन तो कर दिया था लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा, वो आज तक शुरू नहीं हुआ है और उसकी इतनी जरूरत है, हमारा जिला जोधपुर ही है, चाहे छोटी सी बीमारी हो, चाहे कोई भी काम हो, वहां जाना पड़ता है और आप समझ सकते हो कि बीमारी किसी का इन्तजार नहीं करती है तो अगर वहां एक घंटे खड़े रहने के बाद में कोई मौत के घाट उतर जाता है तो उसके लिए कौन दोषी है। मेरा तो निवेदन है कि जो ओवर ब्रिज है वो जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए क्योंकि वो जिले और तहसील के बीच में है।

मेरे भोपालगढ़ में बावड़ी तहसील नयी बनी है पिछली बार और उपखण्ड कार्यालय भी है लेकिन वहां अभी तक तहसील का निर्माण है वो स्वीकृत तो हो गया लेकिन पता नहीं किन कारणों से तहसील अभी तक शुरू नहीं हो रही है, पता नहीं कोई जमीन का विवाद है, तो मेरा निवेदन है कि तहसील का कार्य भी जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए।

मेरा एक यह भी निवेदन है कि हम कहते हैं कि कण-कण में भगवान है, जो धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक स्थलों की सड़कें हैं तो हमारे क्षेत्र में जो

(श्रीमती कमसा)

धार्मिक स्थल हैं हमारे लिए तो चारों धाम वहीं है। ना तो वहां के लोग कोई अमरनाथ जायेंगे और ना ही और कहीं जा सकते हैं। हमारे भोपालगढ़ में भोलारामजी की देवरी है, वसुंधराजी मैडम, हमारी सी.एम. साहिबा वहां दो बार गयी थीं दर्शन करने के लिए और तीसरी बार भी वहां वायदा किया है कि सी.एम. बनने के बाद जायेंगी। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि भोलारामजी की देवरी तक 4 किलोमीटर डबल लाइन की सड़क है वह स्वीकृत करके बनाई जाये।

मेरा एक और निवेदन है कि भगौरिया माता, माताजी का मंदिर है भगौरिया गांव के अन्दर, वहां ऊपर चढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं है। उस मंदिर तक भी आप सड़क बनायें जिससे गांव वाले दर्शन करने के लिए अच्छी तरह से जा सकें। मेरा यह भी निवेदन है कि एक आसौप गांव है, बड़ा कस्बा है और वहां ज्यादातर अल्पसंख्यक ही बसते हैं। जो वहां की मस्जिद है वह गांव के बीच में बनी हुई है। बार-बार पिछले 5 साल और अब यह 8 महीने हो गये, मस्जिद तक जाने के लिए 1 किलोमीटर सीसी रोड चाहिये। रमजान का महीना है और बड़ा हृदय रखते हुए खड़े हों तो अपने श्रीमुख से यह तो घोषणा जरुर ही कर देना, मैं यह चाहूंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बात बताना चाहूंगी कि भोपालगढ़ का जो डाक बंगला है, छोटा है, वहां 3-4 और कमरे बनवाकर डाक बंगले को और बड़ा बनाया जाये ताकि अच्छी सुविधा हो। आप भी कभी वहां आओ तो आराम से रह सकें। भोपालगढ़ में गांव है और वहां कोई होटल नहीं हैं। आपको वहां रहने की सुविधा होगी। जो भी आयेंगे उनको रहने की सुविधा मिलेगी। भोपालगढ़ डाक बंगले की अच्छी सुविधा करा दो ताकि उसका सुधार हो जाये तो आपके लिए ही सुविधा होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि कड़वासरों की ढाणी है और नागौर में पड़ती है और कड़वासरों की ढाणी से खिंडाखोर खेडापा होते हुए सड़क स्वीकृत तो है लेकिन खूब साल हो गये, पड़ी है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि उस सड़क को जल्दी से जल्दी आप स्वीकृत करके बनवा दें। पीपाड़ से भोपालगढ़ होते हुए पालड़ी रानावता और उसके बाद में खींवसर तक जो डबल सड़क है वह भी प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक बनी नहीं है तो मैं आपसे चाहती हूं कि आप उस सड़क को भी बना दें।

(श्रीमती कमसा)

मैं यह भी चाहूंगी कि पिछली बार हमें 16 किलोमीटर सड़क हर एमएलए को मिली थी। 5 किलोमीटर धार्मिक स्थल की मिली थी। अब मेरा विचार तो ऐसा है कि बड़ा सदन है, बड़ा बहुमत मिला है और अभी आपसे पहले सभापति बैठे थे उन्होंने कहा था कि मंत्रीजी का हृदय बड़ा है, तो बड़ा हृदय रखते हुए 16 दूनी 32, 32 तो हमें बड़ा हृदय रखते हुए जरूर-जरूर आप घोषणा करेंगे और 5 किलोमीटर जो धार्मिक स्थल की थीं...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्षजी का तो मंत्रीजी से भी बड़ा है।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): जब घर से किसी शादी-ब्याह में जायें और किसी अच्छी होटल में जायें, अच्छा खाना खाकर जब आप गाड़ी में बैठोगे तो आपको लगेगा ऐसा कि पेट का पानी भी नहीं हिलना चाहिए। गांवों की सड़कें ऐसी अच्छी होनी चाहिए कि पेट का पानी भी नहीं हिले। अच्छी सड़क होगी तो आत्मा बनाने वाले को आशीष देगी। सड़कों की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए और समय-समय पर उन सड़कों का निरीक्षण भी होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, हमारी ढाणियां हैं गांवों की जो 100 की है, 150 की है, 250 की है तो वह प्रायोरिटी के हिसाब से बन रही हैं लेकिन मैं चाहूंगी कि अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़े। अब कड़ी से कड़ी जुड़ गयी है। मंत्रीजी भी गांव के ही रहने वाले हैं। सबका दिल बड़ा ही है। अब ढाणियों वालों को ज्यादा इन्तजार नहीं करवाकर जो ढाणियां वंचित रह गयी हैं, वहां बन जायें। ढाणियों वाले चाहे रहे हैं कि हमें सड़क मिले। सड़क मिलेगी तो वह किसान का बेटा गांव तक पहुंच जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि पीपाड़ कृषि मंडी है, भोपालगढ़ क्षेत्र की पीपाड़ कृषि मंडी है जो बिलाड़ा में पड़ती है। भोपालगढ़ का किसान अपना कपास लेकर, चाहे प्याज की फसल हो, चाहे रायड़े की फसल हो, अपनी फसल बेचने के लिए पीपाड़ जाता है। पीपाड़ जाने के लिए हमारा कोई शोर्ट कट रास्ता नहीं है। कुड़ी से सोपड़ा होते हुए बावड़ी तक आप डामर सड़क बनवा दें।

अध्यक्ष महोदय, अब मेरी छोटी-छोटी जो मिसिंग लिंक हैं वह मैं आपको बोलकर सुना दूं, वैसे तो मैंने आपको दे रखी हैं। इसमें बोलने में जो पीछे भी रह गये, लेकिन वह दे रखी हैं वह सही है। आज अध्यक्ष महोदय ने

(श्रीमती कमसा)

सुबह फरमाया भी था कि अगर कोई भी बोले, लिखित में दे दे फिर भी उसको आप मान लेंगे।

मैं चाहूंगी कि मेरे भोपालगढ़ में तोडियाना गांव है जो 5 हजार आबादी का है और आज के दिन वहां की इतनी हालत खराब है सिर्फ एक किलोमीटर, एक किलोमीटर में भी कम सड़क चाहिए मेन सड़क से। कई गांव ऐसे हैं जो मेन सड़क तो दूर है, लेकिन गांव थोड़ा सा अन्दर बसा हुआ है। उस गांव से उस सड़क तक आने में बड़ी कठिनाई होती है। मेरा तो आपके माध्यम से निवेदन है कि तोडियाना से सम्पर्क सड़क रातड़ी तक सिर्फ एक किलोमीटर है और रामड़ावास खुर्द भी बहुत बड़ा गांव है उस गांव में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यह तो अटल बिहारीजी वाजपेयी, जो कि गांव के नहीं थे फिर भी उन्होंने सोचा कि भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या गांव में निवास करती है। गांव के आदमी की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी थी, उससे हमें बहुत फायदा मिला। ग्राम पंचायत तो जुड़ गयी लेकिन एक पंचायत के अन्दर आज भी देखो 5-5, 6-6 गांव हैं और वह बहुत दूर-दूर हैं। मैं चाहूंगी कि रामड़ावास खुर्द तक जो 2 किलोमीटर सड़क है और हीरादेसल से सोपड़ा होते हुए कुडी तक और पीपाड़ कृषि मंडी को जोड़ती हुई, उप खण्ड कार्यालय जो जोड़ती है बावड़ी, यह जो मेरी सड़के हैं वह मैंने आपको बतायीं। इन सबको आप जोड़ने की कृपा करेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री दर्शन सिंह।

श्री दर्शन सिंह (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांग संख्या 19 व 21 पर बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं वह विधान सभा क्षेत्र अति पिछड़ा हुआ डांग क्षेत्र कहलाता है। जहां पर सड़कों का नितांत ही अभाव है। विशेषकर ग्रामीण जनता अछूती रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको मेरे विधान सभा क्षेत्र करौली के उन गांवों के बारे में अवगत कराना चाहूंगा जिन ग्रामों में आजादी के 65 वर्ष बाद भी आज तक डामर सड़क व ग्रेवल सड़क नहीं डाली गयी है। जिसकी वजह से किसान को अपनी फसल को तैयार होने पर मजबूरन खेत में ही औने-पौने दामों में बेचना पड़ता है।

(श्री दर्शन सिंह)

इसी क्रम में मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ ऐसे ग्राम हैं जिनको लिंक रोड से जोड़ना नितांत आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को उनके बारे में अवगत कराना चाहूंगा कि ग्राम आरेनी से मदनपुर नवीन सड़क निर्माण कार्य, ग्राम मदनपुर से ऊंचा गांव भाबूकापुरा तक नवीन सड़क निर्माण कार्य, ग्राम खानिकी से नीमरीपुरा सड़क निर्माण कार्य, ग्राम बीचपुरी से महाराजपुरा पुल निर्माण कार्य कराया जाना है। यह दोनों ही गांव आपस में लिंक हो जायेंगे और ग्रामीण जनता को लम्बी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस क्रम में आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र करौली से गंगापुर सिटी से धौलपुर तक मेगा हाइवे निकाला जा रहा है लेकिन करौली शहर जो हाइवे के बीचों-बीच आ रहा है, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उक्त हाइवे पर गदका की चौकी से मासलपुर तक बाइपास निकाला जाये तो शहर में होने वाली दुर्घटनाओं की सम्भावना नहीं रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की मासलपुर तहसील बहुत पुरानी तहसील है जहां सार्वजनिक निर्माण विभाग का सहायक अभियंता कार्यालय भी खोला जाये। वहां के ग्रामीणों को अपनी समस्या को लेकर 40 किलोमीटर दूर करौली आना पड़ता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट में 9 हजार से अधिक की आबादी वाले गांवों में 500 मीटर से 2 किलोमीटर तक की सीसी सड़क बनवाने की घोषणा की। उनमें 9 हजार से अधिक आबादी वाले गांव के राइडर को हटाकर सभी राजस्व ग्रामों को सड़क से जोड़ने का प्रावधान करने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय मंत्रीजी का जवाब देने तक बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष: समय बढ़ाया जाता है। श्री श्रीचन्द कृपलानी।

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित)

नहीं हैं। माननीय सदस्यगण, मैं बहुत खुश हूं और आप सबको उस खुशी में सम्मिलित करना चाहता हूं कि मैंने सवेरे अपेक्षा की थी कि मंत्रीजी का भाषण 7 बजे हो जाये और वह स्थिति आप सबके सहयोग से आयी है।

इसके साथ ही हमारे टोडाभीम के माननीय विधायक श्री घनश्याम महर ने अपना लिखित वक्तव्य मेज पर रखते हुए मुझे कहा है कि इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये। मैं उसको स्वीकार करता हूं और इसको अपने रिकार्ड में ले लिया जाये। यह आप इसको अपने रिकार्ड में जैसे बोला हुआ है, इसी तरह मानें। लो, तौफिक साहब। अब मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आज की बहस का जवाब दें।

(माननीय सदस्य श्री घनश्याम टोडाभीम का वक्तव्य जो पढ़ा हुआ माना गया के लिए परिशिष्ट-3 देखें)

अनुदान की मांग

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

श्री लादूराम (गुढामालानी): मेरे को बोलने का टाइम नहीं दिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मंत्रीजी माननीय सदस्यों को मिठाई खिला रहे हैं और आपसे परमिशन नहीं ली। सब माननीय सदस्यों को मिठाई खिला रहे हैं और आपकी बिना परमिशन के।

श्री अध्यक्ष: मेरे तक भी नहीं पहुंची।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यही तो कह रहा हूं ना सबको खिलायेंगे लेकिन बिना परमिशन ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उधार रही मेरी भी ...(व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुझे तो यह पता चला है कि इनकी तरफ से आयी है वह मिठाई।

श्री लादूराम (गुढामालानी): अध्यक्ष महोदय, मेरे को बोलने नहीं दिया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मेरी उधार रही मिठाई। अब आप अपना वक्तव्य चालू करिये।

श्री लादूराम (गुढामालानी): अध्यक्ष महोदय, मेरी बारी नहीं आयी। लादूराम विश्नोई।

श्री अध्यक्ष: आपका बोलने का था क्या?

श्री लादूराम (गुढामालानी): मेरी बारी नहीं आयी और मेरा कालूलालजी ने नाम दिया था ...(व्यवधान) मेरा नाम है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, तब तक आप विराजें...(व्यवधान)

श्री लादूराम (गुढामालानी): मेरा नाम है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जितने नाम दोनों सचेतकों से आये और जितने भी आये, सबको आज बोलने का पूरा मौका दिया गया, इसलिए मैं आपको भी वंचित नहीं करता चाहता हूं, आप भी पांच मिनट में अपनी बात कहिये। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार (भादरा): हमने भी नाम दिया था माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: पहले इनका हो जाये। (व्यवधान)

श्री लादूराम (गुढामालानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़कें व पुल इत्यादि के लिए आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं पहले तो माननीय मुख्य मंत्रीजी को और माननीय मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बाड़मेर से लगाकर सांचौर तक 138 किलोमीटर हाइवे का काम बीजेपी का राज बनते ही 7 महीने के शोर्ट टाइम में, मेंटीनेंस का पूरा कार्य होने जा रहा है। उसकी गुणवत्ता की जांच माननीय मंत्रीजी अपने लेवल पर करवा लें और उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

मैं इस मौके पर निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी बहुत बैकवर्ड एरिया है और पहली बार भाजपा के कैण्डीडेट के रूप में जीत कर आया हूं इसलिए मेरी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक आप कंसीडर करें। गुढामालानी के ग्राम कोजार्स रामवास व डारों की बेरी तक पांच किलोमीटर सड़क जो चौहटन विधान सभा क्षेत्र से जोड़ेगी। गुढामालानी से सिधासरा चौहान, आठ किलोमीटर की सड़क है, जो भीनमाल से इसका कनेक्शन होगा। ग्राम रतनपुरा से मोलागरजी महाराज के थान तक तीन किलोमीटर की सड़क बनानी जरूरी है, इसमें साल में चार बार धार्मिक मेला लगता है। कोसलू से खिवालिया नाडा-सारणों की ढाणी छह किलोमीटर की सड़क बनाई जाये। इसी

(श्री लादूराम)

प्रकार धनाऊ रोड से सियागो का बास, चौहटन विधान सभा क्षेत्र से इसका कनेक्शन होता है, तीन किलोमीटर की यह पांच सड़कें बनाई जायें।

इसके सिवाय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 2012-13 में राजकीय महाविद्यालय गुढामालानी में स्वीकृत हुआ था, वहां 200 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं, उनके लिए सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में जगह खूब है, इस कालेज के भवन के लिए मैं डेढ़ करोड़ रुपये की मांग करता हूं। इसके सिवाय धोरीमन्ना में आलम गौशाला है उसके लिए मैं बीस लाख रुपये की मांग रखता हूं। धोरीमन्ना प्रोपर में अजाणियों की ढाणी में एक बहुत ही आध्यात्मिक स्थल है, उसके लिए तीस लाख रुपये की मांग करता हूं। छोटू ग्राम पंचायत है, सिणधरी पंचायत समिति में है, पुरखारामजी धर्मात्मा की समाधि पर मंदिर बना हुआ है जिसमें प्रतिदिन छत्तीस कौम के सैकड़ों लोग दर्शन करने आते हैं और चैत्र माह की पूर्णिमा में बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। वहां पर भी बीस लाख रुपये की भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके सिवाय मेरे गुढामालानी विधान सभा क्षेत्र में डीडीपी और बीएडीपी के तहत डीआरडीए को हमने सड़कों के प्रस्ताव भेज रखे हैं वह आप स्वीकृत करने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्षजी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं...

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) एक मिनट माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) आप बोलना चाहते हैं तो आप पांच मिनट बोल लीजिये, पांच मिनट, जिससे ठीक सात बजे माननीय मंत्रीजी का भाषण चालू हो जाये।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 19 और 21 पर सदन में विचार चल रहा है, मैं भी इसमें अपने आपको सम्मिलित करते हुए मेरे निर्वाचन क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे भादरा निर्वाचन क्षेत्र में भादरा से बालसमन्द, हरियाणा सीमा तक जो सड़क है, यह सड़क रावतसर से नोहर, नोहर से भादरा और भादरा से बालसमन्द हरियाणा सीमा तक जाने वाली मुख्य सड़क है और निश्चित तौर से यह गंगानगर से दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क है। इस सड़क की हालत काफी समय से बहुत खराब है। सड़क में अनेक

(श्री संजीव कुमार)

गड्ढे पड़े हुए हैं और यह सड़क रिडकोर को स्थानांतरित की हुई है। अगले महीने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गोगामेड़ी में, गोगाजी की जो पवित्र स्थली है, धार्मिक स्थल है उसमें हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से अनेक यात्री, करीब बीस लाख श्रृद्धालु मेले में आयेंगे तो ऐसे हालात में इस सड़क पर वाहनों का चलना मुश्किल है तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि रावतसर से लेकर बालसमन्द, हरियाणा सीमा तक वाया भादरा और नोहर होते हुए इस सड़क का मरम्मत काम, जो रिडकोर को स्थानांतरित किया हुआ है, किसी भी सूरत में चाहे आप विभाग से करायें, चाहे रिडकोर से करायें इसका पुनर्निर्माण करवाने का काम करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ से सादुलपुर जो रेलवे का आमान परिवर्तन हुआ है, जो मीटर गेज से ब्रोड गेज में रेलवे लाइन परिवर्तित की जा रही है। जो रेलवे क्रोसिंग है वह कई जगह आरयूबी और आरओबी बनाने की आवश्यकता है। कई जगह आयूबी मंजूर है जैसे मुंशी खतवाना सड़क, हरियाणा सीमा तक, सरदारगढ़ियां गांव के पास, पाइण्ट 103/1314, दूसरा परलिका दीपराणा सड़क, दीपराणा गांव के पास पाइण्ट 85/89, तीसरा नोहर दीपराणा सड़क दीपराणा गांव के गांव 82/12, यह आरयूबी स्वीकृत हैं और स्वीकृत होने के बाद आज तक ठेकेदार ने इनका काम चालू नहीं किया है तो निश्चित तौर से इलाके की समस्या को देखते हुए, जनता की समस्या को देखते हुए इन आरयूबी का निर्माण शीघ्र करवाने का काम करें। इसके अलावा कुछ आरयूबी पिछले काफी समय से इलाके की जनता ने आंदोलन किए तो कुछ आरयूबी और स्वीकृत करने वाले हैं। सरदारगढ़िया गांव के पास राजस्व रास्ता पाइण्ट 105/56 पर, करणपुरा सिकरोड़ी राजस्व रास्ता पोइण्ट 109/7 पर और कलराना गांव का राजस्व रास्ता 125/01 पर, ये आरयूबी आप मंजूर करके इनके निर्माण कार्य को आप शीघ्र चालू करवायें।

भादरा राजगढ़ रोड इलाके की मुख्य सड़क है, जयपुर आने के लिए हमें इस रोड से आना पड़ता है और यह जो ब्रोड गेज बन रही है रेलवे की यहां अभी भी आरओबी की आवश्यकता है, इसको स्वीकृत नहीं किया गया है, यदि यह आरओबी स्वीकृत नहीं की गई तो हमारी यह सड़क बंद हो जायेगी। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि भादरा राजगढ़ रोड पर बाडी मोड़ पर पाइण्ट 136/1314 पर इस आरओबी के निर्माण कार्य की स्वीकृति आप शीघ्र दिलवाकर काम चालू करवाने की कृपा करें।

(श्री संजीव कुमार)

इसी तरह से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भादरा साहवा सड़क जो कि बहुत ही क्षतिग्रस्त है, स्वीकृत होने के बावजूद भी माननीय मंत्री महोदय, इसका कार्य शुरू नहीं किया जा सका है तो मैं निवेदन करूंगा कि इसके पुनर्निर्माण का कार्य आप जल्दी से जल्दी स्वीकृत करवाने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि भादरा-नोहर रोड, भादरा-साहवा रोड, भादरा-राजगढ़ रोड, ये तीनों रोडों को मिलाकर शहर के बाहर यदि बाइपास का निर्माण कर दिया जाये, शहर में ट्रैफिक का भार ज्यादा रहता है तो आप इस बाइपास का निर्माण शीघ्र करवाने की कृपा करें। भादरा निर्वाचन क्षेत्र में मुनसरी-ढीलकी सम्पर्क सड़क को भी काफी लम्बे समय से इलाके के लोग मांग कर रहे हैं। मैं मांग करना चाहूंगा मुनसरी-ढीलकी, मिसिंग लिंक में लेकर के या किसी भी दूसरी योजना में लेकर सड़क निर्माण करवाने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ मिसिंग लिंक के प्रस्ताव भी हमने माननीय मंत्री महोदय को और सरकार को भिजवाये हुए हैं, कृपा करके आप उनको भी स्वीकृत करवायें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(19.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तो कमाल ही हो गया उसके लिए आपको सबसे पहले धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज मांग संख्या 19 और 21 पर सुबह मैंने प्रस्ताव रखा उस पर पूरे दिन बहुत ही सार्थक बहस हुई। इस सार्थक बहस में लगभग हमारे 37 माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया और अपने अमूल्य सुझाव सदन को दिये, मेरा भी मार्गदर्शन किया, उसके लिए मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग मांग संख्या 19 पर कुल 131 कटौती प्रस्ताव 45 माननीय सदस्यों के प्राप्त हुए। इसी प्रकार मांग संख्या 21 में कुल 292 कटौती प्रस्ताव 69 माननीय सदस्यों से प्राप्त हुए, इन सबको मैं धन्यवाद देते हुए यह विश्वास दिला रहा हूं कि वैसे तो सारे

(श्री युनुस खान)

जवाब तैयार हैं, लेकिन शीघ्र ही उनके जवाब दे दिये जाएंगे। उनकी मांग पर, उनके सुझाव पर ध्यान देकर आगे कार्यवाही करेंगे।

मानिनीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन का भी आभार करता हूं और हमारी सदन की नेता का जिन्होंने अबकी बार राजस्थान को एक माडल स्टेट बनाने के लिए सबसे पहले ठानी। आपको ध्यान होगा 8 दिसम्बर, 2003 को इसी विधान सभा के सामने जनपथ से माननीय वसुन्धरा ने पहली बार मुख्य मंत्री पद की शपथ ली तब उन्होंने एक बात कही थी कि हम कोई राजस्थान में राज करने के लिए नहीं आये हैं, हम राजस्थान में राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिए आये हैं, हम जनता के सेवक हैं उसी भाव से काम करेंगे। अबकी बार जब उन्होंने पुन: कार्यभार सम्भाला, सारे माननीय मंत्रीगण को और सबको यह निर्देश दिये कि मेरा प्रदेश पिछले 5 वर्षों में मेरी जो आशा थी उसके अनुरूप नहीं चला, अब मैं चाहती हूं हमारे माननीय मंत्रीगण न तो मालाएं पहनें, न स्वागत कराएं, न विधायक ढोल-नगाड़े बजवाएं, न गुलाल लगवाएं, सबके सब मिलकर काम में लग जाएं और इस प्रदेश को आगे ले जाएं। जो माडल स्टेट की उन्होंने बात की उसमें माडल की स्पेलिंग होती है, Model, उसकी मैं इस तरीके से व्याख्या करूंगा कि हमारा जो माडल है MODEL. M for mandate जो कि 163 सीटों के रूप में राजस्थान की जनता ने हमें दिया, ओ का मतलब आफ, डी का मतलब डवलपमेंट और ई का मतलब efficient financing and एल का मतलब least inconvenience to users यानी mandate of development, efficient financing and least inconvenience to users, इसके साथ में हमारी सरकार काम करना चाहती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक चीज आज सदन में आयी और सदन में जिस ''श्री'' की चर्चा हुई और उस ''श्री'' में आपको ध्यान होगा कि आज हमारे एक विद्वान माननीय सदस्य ने उसकी व्याख्या भी की, उससे पहले भी मैंने यह सुना हुआ था कि श्री का मतलब है लक्ष्मी। हमारी श्री योजना शुरू की है और आपको ध्यान होगा आप भी एक बार थोड़े समय के लिए कैबिनेट में रहे हैं और आपके अनुभवों के बाद में कैबिनेट ने एक फैसला किया कि श्री से हम इस सरकार का काम शुरू करेंगे। हमारे पहले एस का मतलब सेनेटेशन, एच का मतलब हैल्थ, आर का मतलब रोड, ई का मतलब एनर्जी, दूसरी ई का मतलब एजुकेशन, एम्प्लायमेंट, ये सब चीजें इस श्री के साथ यह सरकार काम करेगी और उस श्री में से आर शब्द पर बोलने का मुझे मौका मिला है, उसके

(श्री युनुस खान)

लिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आगे जाकर इस आर का भी मतलब आपसे निवेदन करूंगा, लेकिन अभी तो हाल-फिलहाल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे साथी बैठे हैं ये अभी कहेंगे क्योंकि अभी हम आए हैं, हमारा पहला बजट है और अगर समीक्षा होगी तो पिछले 5 वर्षों की समीक्षा होगी। उन 5 वर्षों में जो सरकार ने काम किया, अच्छे काम किये उनकी भी हम सराहना करेंगे, लेकिन राजस्थान जहां पहुंचना चाहिए था वहां राजस्थान नहीं पहुंचा और विशेष रूप से रोड सैक्टर की बार-बार हमारे साथियों ने चर्चा की! मैं थोड़ा सा आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क विषय के अन्दर हमारे राजस्थान में आज विशेष रूप से जितना क्षेत्रफल है, लगभग 3 लाख 42 हजार 239 किलोमीटर, उसमें जितना प्रति 100 किलोमीटर जो राष्ट्रीय औसत है 148 किलोमीटर का उससे हम बहुत पीछे हैं। लगभग 57 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर पर हमारा आज की तारीख में औसत है। जितना बड़ा हमारा क्षेत्रफल है उतनी हमारे यहां सड़कें नहीं है, सड़कों की जरूरत है और सड़कों में गुणवत्ता भी अच्छी होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे इस सदन में मैं अभी देख रहा हूं तीन ऐसे पूर्व सार्वजनिक निर्माण मंत्री भी बैठे हैं, सबसे वरिष्ठतम माननीय गुलाबचन्दजी कटारिया बैठे हैं, उनके पास माननीय राजेन्द्रजी बैठे हैं, पीछे पूनिया साहब विराज रहे हैं, इन सब लोगों का भी मुझे आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलेगा।

माननीय वसुन्धराजी का पहला कार्यकाल था, जब माननीय राजेन्द्रजी राठौड़ सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे दो बार वे दिल्ली गये। दिल्ली इसलिए नहीं गये कि सड़कें मांगनी हैं। दिल्ली इसलिए गये कि हमारे राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ प्रदेश घोषित किया गया, बाकायदा इनाम दिया गया और राजस्थान प्रथम आया। अगर हम दोनों कार्यकाल का विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि 2003 से 2008 तक 9127 गांवों को उस समय जोड़ा गया जबकि जो पिछला 5 साल का कार्यकाल था उसमें मात्र 1638 गांवों को जोड़ा गया। यह फर्क हमारी रूरल कनैक्टिविटी के अन्दर आया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब हम रूरल कनैक्टिविटी की बात करते हैं तो हमने 2004 में जब कार्यभार संभाला और कैबिनेट ने शपथ ली उस समय राजस्थान लगभग रूरल कनैक्टिविटी में 56 परसेंट पर था जिसको 5 साल में माननीय वसुन्धराजी के नेतृत्व में और

(श्री युनुस खान)

हमारे पूरे साथियों ने भरसक मेहनत करके 80 प्रतिशत तक पहुंचाया। लेकिन दुर्भाग्य रहा इस प्रदेश का कि काम करने के बाद में भी वापस मौका नहीं मिला। हमारे साथियों को मौका मिला और उन साथियों ने भी काम किया, ऐसा नहीं कहूंगा। लेकिन इस कार्यकाल में जो गांवों को जोड़ने की बात करते हैं आपको आश्चर्य होगा जो आंकड़े मैंने अभी बताए हैं उसके मुताबिक मात्र 3.5 परसेंट, यानि जिस 56 परसेंट को बढ़ाकर हमने 80 प्रतिशत किया, जो मैंने 9127 गांवों की चर्चा अभी की, हमने जिसको 80 प्रतिशत किया, लगभग 24 प्रतिशत 5 साल के कार्यकाल में रूरल कनैक्टिविटी को बढ़ाया उसकी एवज में इन्होंने मात्र 3.5 परसेंट गांवों की कनैक्टिविटी को बढ़ाया जो कि इस प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। जबकि इस प्रदेश में उसी दल की सरकार थी और दिल्ली में भी उसी दल की सरकार थी। यह एक संयोग था कि दिल्ली के अन्दर भी उस समय एक मौका भी मिला था कि हमारे प्रदेश से चुनकर गये दो सांसद दिल्ली में जाकर मंत्री बने। बहुत अच्छी बात थी प्रदेश के लिए और मंत्री भी भूतल परिवहन विभाग का कार्यभार दोनों मंत्रियों के पास रहा। एक राज्यमंत्री के रूप में, फिर उसके बाद कैबिनेट मंत्री के रूप में रहा। राजस्थान ने यह उम्मीद जगायी थी कि अबकी बार हमारा भला होगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वह लाभ भी राजस्थान को नहीं मिल पाया।

जैसे अभी फतेहपुर से आने वाले माननीय सदस्य लास्ट में चर्चा कर रहे थे कि आज राजस्थान में जो सड़कों की लम्बाई है वह 195880 किलोमीटर है। अभी जब दोनों माननीय मंत्रीगण की चर्चा कर रहा था तो मैं यह भी कहूंगा कि उनके कार्यकाल में जो स्वीकृतियां हुईं बहुत अच्छी बात थी। हम भी राज़ी हुए अख़बार पढ़कर कि बहुत ही अच्छी हैं। लगभग जितनी योजनाएं स्वीकृत हुईं उनमें से 33 योजनाएं थीं, मैं आंकड़ों के साथ पेपर लाया हूं, आप आश्चर्य करेंगे उनमें से 19 योजनाओं पर तो काम शुरू हो ही नहीं पाया और आज तक भी नहीं हुआ। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब उसमें मैं जाऊंगा तो हमारे लक्ष्मणगढ़ से आने वाले साथी फिर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि आप पुरानी सरकार को कह रहे हो इसलिए मैं उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। मैंने आंकड़ों के साथ बता दिया कि 33 परियोजनाएं इन्होंने उस समय स्वीकृत कीं।

उनमें 19 पर तो अभी कार्यवाही ही शुरू नहीं हुई तो यह प्रदेश के लिए ठीक नहीं था। लेकिन माननीय वसुंधराजी ने और हमारी पार्टी के नेताओं

(श्री युनुस खान)

ने जब पांच साल 2008 से 2013 के काल में गांव-गांव घूमकर देखा, माननीय वसुंधराजी ने 14 हजार किलोमीटर की यात्रा राजस्थान की सुराज संकल्प यात्रा के रूप में की और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने माननीय गुलाबजी कटारिया के नेतृत्व में एक डाकूमेंट निकाला और उस डाकूमेंट को सुराज संकल्प, 2013 नाम दिया। आज मुझे खुशी है, मेरे हाथ में वो डाकूमेंट भी है और मेरे हाथ में जो अभी 14 तारीख को माननीय वसुंधराजी ने जो अपना बजट रखा वो डाकूमेंट भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दोनों डाकूमेंट सदन में लेकर आया हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको और पूरे सदन को खुशी होगी कि जो डाकूमेंट इन्होंने सुराज संकल्प के रूप में तैयार किया था उसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग की जितनी बातें बताई गई थीं वो सारी की सारी बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस बजट में माननीय वसुंधराजी ने सारी की सारी अक्षरशः घोषणा की। इसको बोलते हैं सुराज संकल्प पत्र। जो उन्होंने संकल्प लिया, एक-एक लाइन को अगर आप मिलायेंगे, आप देखेंगे तो इसमें सारी चीजें उन्होंने सम्मिलित कर दीं चाहे वो स्टेट हाइवे की बात हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में गांवों को गौरव पथ के रूप में जोड़ने की बात हो, चाहे 20 हजार किलोमीटर सड़कों की बात उन्होंने कही। जब सफलता और असफलता की बात करते हैं तो पी.पी.पी. माडल की भी अभी चर्चा आई और यह आया कि इस तरीके का अराजकता का राजस्थान में माहौल बन जाएगा तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सिर्फ फर्क है गवर्नेंस का। सिर्फ फर्क है तो वो गवर्नेंस का है कि जब माननीय वसुंधराजी मुख्य मंत्री थीं तो उन्होंने एक कम्पनी बनाई रिडकोर। उसने जो राजस्थान में काम किये वो काम आज भी पूरे हिन्दुस्तान में सराहे जाते हैं। मैं राजेन्द्रजी राठौड़ साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि रिडकोर ने किशनगढ़ से लेकर हनुमानगढ़ तक 401 किलोमीटर 403 करोड़ रुपये में उस समय बनाया वो आज भी इतना शानदार है कि लोग उसकी सराहना करते हैं। एक तरफ वो सारे काम जो रिडकोर ने उस समय किये और दूसरी तरफ 2008 से 2013 तक जो काम किये उनकी चर्चा भी मैं करना चाहूंगा। पहले हमें भरतपुर सम्भाग में जाने का मौका मिला। सवाई माधोपुर से बाड़ौती से गंगापुर और वहां से मथुरा बोर्डर तक रिडकोर ने काम शुरू किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि वो काम आज भी अधूरा है, लोगों को असुविधाएं हो रही हैं और हमारे गंगापुरसिटी से आने वाले माननीय सदस्य, बयाना से आने वाले माननीय सदस्य, ये सब इन चीजों से वाकिफ हैं।

(श्री युनुस खान)

अभी आपने पहले मुझे बोलने के लिए खड़ा कर दिया लेकिन बाद में आपने कहा कि दो सदस्यों को और मौका देंगे माननीय विश्नोईजी को और माननीय बेनीवालजी को। आज के वक्ताओं में माननीय बेनीवालजी आखिरी वक्ता थे। उन्होंने जो अपना दर्द गाया वो दर्द इतना है कि वास्तव में आप और मैं भी जाएंगे, मैं तो अभी जाकर आया हूं, हम देखेंगे रावतसर से भादरा और भादरा से बोर्डर तक तो उस सड़क से 4-5 घंटे नहीं, 10 घंटे में भी बोर्डर तक नहीं पहुंचा जा सकता, यह हालत थी जो रिडकोर का काम उन्होंने दिया। इन्होंने दो प्रोजेक्ट हाथ में लिये और दोनों फेल हो गये। जिस तरीके से फेल हो गये, मैं आज आपको इस सदन में विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इनकी फेल्योर का गीत नहीं गायेंगे। हम गुड गवर्नेंस देने के लिए आये हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बात को कहा है इसलिए इस संकल्प के साथ आये हैं तो आज मैं हाउस में घोषणा करता हूं कि उन दोनों सड़कों को राज्य सरकार अतिशीघ्र ही शुरू करेगी और उनको हम जल्द से जल्द पूरा करने का काम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैंने दो डाकूमेंट आपको दिखाये तो पिछले पांच वर्षों के माननीय गहलोत साहब ने जितने बजट प्रस्ताव रखे उन सब को भी मैं लेकर आया हूं। उन्होंने बी.ओ.टी. आधार पर 1712 किलोमीटर लम्बाई की 21 सड़कों के निर्माण कार्य हाथ में लिये जाने की घोषणा की और बहुत मेजें थपथपाई गईं। उस दिन सौभाग्यवश मैं भी अध्यक्षीय दीर्घा में बैठा हुआ था। हमारे पुराने साथी जो आज बहुत सारे इस हाउस में नहीं रहे, वैसे तो हम इनको सुना ही रहे हैं लेकिन सुनने वाले लोग तो हाउस में पहुंचे ही नहीं। एक-दो पहुंचे हैं, उनकी आदत है कि हाउस में आते भी नहीं हैं। एक बार बजट पेश होता है तब आते हैं और एक बार गवर्नर का भाषण होता है तब आते हैं। आप सब मेरी बात को समझ रहे हैं। अब जो लोग थे उनमें से अगर सौभाग्यवश कुछ चुनकर आते तो उनको सुनाने में भी मजा आता। अब तो हमारे करीब-करीब एक-दो साथी को छोड़कर सब नये साथी हैं और अभी तो एक ही साथी बैठे हैं जो कि पिछले सदन में थे। इनको पता है और जब ये अपना वक्तव्य दे रहे थे तो ये खुद भी इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि मैंने बार-बार कहा कि इन ठेकेदारों पर अंकुश रखो, इन अधिकारियों पर अंकुश रखो लेकिन उस समय नहीं हुआ और उसका नतीजा वास्तव में यह तो कह नहीं सकते क्योंकि इनकी अपनी सीमाएं हैं लेकिन मैं तो कह सकता हूं कि

(श्री युनुस खान)

उसी का परिणाम था कि गहलोत साहब ने वन मैन आर्मी बनाकर जिस तरीके से अपना अविश्वास लोगों में जताया उसका फल राजस्थान की जनता ने उनको दिया। अच्छा लगता यदि आज वो भी सुनते। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो 21 घोषणाएं कीं 1712 किलोमीटर की, आपको आश्चर्य होगा कि उनमें से एक को भी फलीभूत नहीं कर पाये और अंत में उन 21 में से 6 जो हमारी राजकीय कम्पनी है आर.एस.आर.डी.सी., उसको दिये गये। उनके सारे के सारे प्रोजेक्ट फेल हो गये और वो उनको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज सदन में जब चर्चा हुई और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिन 20 हजार किलोमीटर सड़कों की घोषणाएं कीं उसके बारे में हमारे हां पक्ष के लोगों ने, हमारे साथियों ने उसकी सराहना की और कुछ लोगों के मन में शंका भी थी। इधर से भी माननीय सदस्यों ने जो अपनी बात रखी उसमें पी.पी.पी. माडल पर, जो बी.ओ.टी. में बनने वाली सड़कें हैं उन पर शंका जाहिर की। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दोनों सरकारों में फर्क है, दोनों मुख्य मंत्रीगण में एक फर्क है और वो फर्क यह है कि एक घोषणाओं के बादशाह थे, घोषणाएं करते थे और दूसरे पहले कार्यक्रम बनाकर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके उसके बाद में घोषणा करती है, उसके पहले घोषणा नहीं करती है। हमारी सदन की नेता माननीय वसुंधराजी को इस बात के लिए जाना जाता है कि वो वित्तीय प्रबन्धन में बहुत ही अनुशासित और स्ट्रिक्ट रहती हैं और कुशल भी हैं। उनकी कुशलता का नमूना उन्होंने कल खुद पेश किया कि जो हालत 2008 तक उन्होंने हमारे खजाने की रखी और जो हालात 2013 में आये उसके बारे में आप सबको पता है, इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 20 हजार किलोमीटर की सड़कों की घोषणा की है, माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश के बाद में, हमारी नेता के निर्देश के बाद में स्वयं पिछले छह महीने से जब से हमें यह जिम्मेदारी मिली है इस काम के लिए लगे हुए हैं। आपको सुनकर खुशी होगी कि मैं स्वयं चार बार और मेरे अधिकारी सात बार इस काम के लिए दिल्ली बार-बार गये। हमने प्लानिंग कमीशन के साथ में उनकी जितनी गाइड लाइन हैं उन पर सारी चर्चा करके, योजना बनाकर और जब हम एकदम मुतमइन हो गये कि अब इस योजना को हम कामयाब कर सकते हैं उसके बाद में हमने हमारी नेता के हाथ

(श्री युनुस खान)

में डाकूमेंट दिया और उसके बाद हमारी नेता ने इस हाउस में उस 20 हजार किलोमीटर की घोषणा की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे मित्र लोग चर्चा कर रहे हैं कि यह योजना फेल होगी। अब तक राजस्थान में अगर हम आंकड़े देखें और टोल की संख्या देखें तो अभी तक राजस्थान में राजस्थान सरकार या प्राइवेट सैक्टर में जितने भी आर.एस.आर.डी.सी. और उसके अलावा जो हैं, लगभग 5 हजार किलोमीटर सड़कें ही हैं जो टोल पर चल रही हैं नेशनल हाइवे को छोड़कर। अब यह जो 20 हजार किलोमीटर हम ला रहे हैं यह जरूरी नहीं है कि इन सारी की सारी सड़कों पर टोल लगेगा ही। उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं और उन योजनाओं के लिए आज जब सदन में बहस हो रही थी तो हमारे लोगों के मन में यह शंका आई कि यह किस तरीके से होगा तो उस शंका को दूर करने के लिए मैं आंकड़ों की ओर जाना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अगर हम वाहनों की संख्या देखें तो अब तक 1 करोड़ 10 लाख वाहन राजस्थान में रजिस्टर्ड हैं उसमें से लगभग 80 लाख वाहन दुपहिया हैं जिन पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता, मतलब टोल नहीं लगता क्योंकि दुपहिया वाहनों को एग्जम्प्ट किया हुआ है। अगर हम एक वाहन की उम्र 15 वर्ष मानें और उन आंकड़ों की तरफ अगर हम जाएंगे तो 15 वर्ष में जो वाहन आते हैं उनकी संख्या भी लगभग 87,40,565 आती है। यह संख्या जो आती है 15 सालों में, तो इस संख्या में भी टोलेबल व्हीकल हैं यानि आप यह देखेंगे, आटो-रिक्शा पर कोई टोल नहीं लिया जाता, टू-व्हीकल पर नहीं लिया जाता, टैम्पों पर नहीं लिया जाता, ट्रैक्टर पर जो किसान का वाहन है, उस पर नहीं लिया जाता, ट्रेलर है, उसकी ट्रोली है, उस पर नहीं लिया जाता...

श्री रमेश (सपोटरा): यह आपका कैलकुलेशन गलत है। आप अधिकारियों से पता कर लें। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनसंख्या के अनुपात में, जो कि 2011 की जनगणना में 6.84 करोड़ आई थी, लेकिन आज के आंकड़े लगभग 7.20 करोड़ है। उनमें जो पिछले 15 साल के व्हीकल जो टोलेबल हैं, उनकी संख्या लगभग 8 लाख आती है जिन पर टोल टैक्स लग सकता है तो यह एक प्रतिशत आता है यानि 99 प्रतिशत लोगों पर किसी भी तरीके का टोल

(श्री युनुस खान)

नहीं लगेगा। जो व्हीकल सड़क पर आयेगा, उसी पर टोल लगेगा और उसमें भी मैंने आपको कहा कि हम कुछ इस योजना में जो हमारी अब तक चर्चा हुई है, उसमें 20 प्रतिशत राज्य सरकार वाइबल गैप फण्ड के रूप में देगी, 20 प्रतिशत राशि भारत सरकार वीजीएफ के रूप में देगी, 40 प्रतिशत राशि यह आयेगी और उसके बाद में भी अगर वह रोड वाइबल नहीं है तो उसमें हम टोल में नहीं जायेंगे। क्योंकि जब वह रोड किसी भी कंसेशनियर के लिए वाइबल नहीं है तो वह कंसेशनियर नहीं आयेगा। कोई भी प्राइवेट बनाने वाला प्लेयर नहीं आयेगा। इसलिए उस सड़क को हमारे पास अभी भी बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में ले जायेंगे। हम उसको एनओटी में ले जायेंगे। एनओटी की बात जब आई और आज हमारे माननीय सदस्य ने एक चर्चा में बात कही कि नितिन गडकरीजी ने कहा है कि ये सारे फेल हो गये। उन्होंने वक्तव्य को आधे को पढ़ा और जो उनके हित में नहीं था, उसको छोड़ दिया तो मैं उसको पढ़कर सदन में सुनाऊंगा कि माननीय नितिन गडकरीजी ने क्या कहा और माननीय जेटलीजी ने इन विषय पर क्या कहा? तो यह 40 प्रतिशत पैसा वाइबल गैप फण्ड के रूप में देंगे, 60 प्रतिशत पैसा जो भी प्राइवेट प्लेयर आएगा, यानी जिसको कंसेशनियर बोलते हैं, वह आयेगा, वह लगायेगा, उस सड़क को बनायेगा तो उसके लिए हमने अब तक इस 20,000 किलोमीटर में से 27 पैकेज बनाकर काम शुरु कर दिया है अध्यक्ष महोदय, और उन 27 पैकेज में पहले 10 पैकेज हैं, लगभग 8,290 किलोमीटर की फिजिबल स्टडी के लिए हमने निविदाएं निकाल दी हैं और उसके लिए एक चर्चा यह भी आई आज सदन में कि उसमें फर्जीवाड़ा होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो फिजिबल करने वाली एजेंसी है, उसका बाकायदा स्क्रीनिंग करके, उसका फाइनेंशल स्टेटस देखकर, उसका टैक्नीकल स्टेटस देखकर, अन्तरराष्ट्रीय स्तर के लोगों को पूरे राष्ट्र में एक तरह से विज्ञापन देकर फिर लिया। उनमें से जो लोग क्वालिफाई हुए, उनको लिस्टेड किया और लिस्ट करने के बाद में भी अब जो हमारे यह 10 फर्स्ट पैकेज के फिजिबल स्टडी चल रही हैं, उसमें भी उन लोगों को दिया जो एल-1 थे। यह नहीं है कि हमने हर किसी को दे दिया। इसलिए अन्तरराष्ट्रीय स्तर के मानकों को मानते हुए भारत सरकार का हमारा जो योजना आयोग है, उनके मानकों को मानते हुए, उसके बाद फिजिबल स्टडी के लिए काम शुरु कर दिया तो जो 8,290 किलोमीटर है, उसमें पहले 10 पैकेज हैं, उनका काम शुरु हो गया है और लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय

(श्री युनुस खान)

सदस्य, मुख्य मंत्रीजी के बजट भाषण में से पढ़ रहे थे कि 2017 तक यह काम शुरु कर दिये जायेंगे। मैं आपको बताऊं, यह जो 20,000 किलोमीटर सड़कें हैं, जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था, फर्स्ट फेज में हमारी 8290 किलोमीटर सड़कें हैं, इनके अलावा भी जो बची हुई सड़कें हैं, उनका आखिरी पड़ाव जो है, 2017 में हम कार्यादेश दे देंगे तो धीरे-धीरे डिलीवरी इस साल के अंत तक और अगले साल के शुरु तक काम शुरु हो जायेंगे। इस साल हम वर्कआर्डर दे देंगे इस फर्स्ट पैकेज के और उसके बाद में अगले साल वर्कआर्डर हो जायेंगे, अगले साल से काम शुरु हो जायेंगे और अब के दो साल बाद में राजस्थान में हमें 5,000, फिर 8,000, फिर 10,000, फिर 20,000 किलोमीटर तक सड़कें मिल जायेंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, उस बात को भी मैं पूरा करना चाहूंगा कि आप सबको ध्यान है कि पीएमजीएसवाई और आज जो हम इतनी सड़कें देख रहे हैं, जो चौड़ी सड़कें हैं, 6 लेन, 8 लेन, 4 लेन, इनका जन्मदाता इस हिन्दुस्तान में कौन था? इनके जन्मदाता के बारे में आप सबको पता है और आपने भी उनके साथ मंत्री के रूप में काम किया है अध्यक्ष महोदय, उनकी चर्चा मैं यहां जरूर करना चाहूंगा। परम श्रद्धेय हमारे अटल बिहारी वाजपेयीजी इस बात को लेकर आये और चूंकि माननीय सदस्य ने आज यह बात उठाई तो मैं उसको पढ़ना चाहूंगा क्योंकि माननीय वाजपेयीजी के बारे में तो आगे चर्चा करूंगा। उन्होंने कहा कि ''Topping forward the earlier Atal Bihari Vajpayee led National Democratic Alliances Govt. focused on roads. Jaitely made a healthy allocation of Rs. 37,880/- crores to the Ministry of Road, Transport and Highway against Rs. 33,050/- crores allocated in the previous …..'' यानी उन्होंने यह कहा है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी की जो एनडीए गवर्नमेंट थी, उसमें इस सैक्टर में 37,880 करोड़ रुपये दिये गये, जबकि इस गवर्नमेंट ने, जो अभी यूपीए गवर्नमेंट गई है, इसने अपने कार्यकाल में मात्र 33,050 करोड़ रुपये दिये। आगे वह कहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। अब यह कम्पेरिजन देख सकते हैं कि एक तरफ एनडीए का सात साल का कार्यकाल था और एक तरफ यूपीए का 10 साल का कार्यकाल था। उसमें भी ये रोड सैक्टर में वहां तक नहीं पहुंच पाये और...

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): मंत्री महोदय, इन्होंने तो उनके फोटो हटा दिये थे। उन अटल बिहारीजी वाजपेयी की फोटो वापस लगाई जाये।

श्री अध्यक्ष: आप यील्ड कर रहे हैं? आप यील्ड कर रहे हैं क्या?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मुझे बोलने दें, फिर बता देना। (व्यवधान) अब आज जो चर्चा आई माननीय अध्यक्ष महोदय, वह ई पी सी की आई...

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): उनका फोटो आपने हटाया है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वह तो जिन्होंने हटाया है, उनके हट जायेंगे, सब हट गये, चिंता मत करो आप। (व्यवधान) उन्होंने जो बात कही, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नितिन गडकरीजी ने जो बात कही, उसको भी मैं कोट करना चाहूंगा कि 21 रोड प्रोजेक्ट जो 26,000 करोड़ के थे, वह फेल हो गये तो उन्होंने यह कहा है कि ये फेल इसलिए हुए कि इनके बारे में जो योजनाबद्ध तरीके से काम होना चाहिए था, जो नोर्म्स थे, उनको पूरा नहीं किया गया और उन सड़कों को किस तरीके से बनाया जायेगा, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, इसलिए उन्होंने ईपीसी माडल की बात कही और उस ईपीसी माडल में भी अभी मैंने आपके सामने चर्चा, Engineering, Procurement and Construction माडल है, उसको राजस्थान भी इस 20,000 किलोमीटर में लायेगा और उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तीन बार इस विषय में बैठकें कर लीं।

मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि एक बार दिल्ली में उन्होंने बैठक की यू.के. और जापान के लोगों के साथ में। जापान और यू.के. में बहुत कम दरों पर ब्याज पर लोन मिलता है। यहां जहां 13-14 पर्सेंट पर मिलता है, वहां लगभग 4 और 5 पर्सेंट पर लम्बे पीरियड के लिए, 50 साल तक के पीरियड के लिए ब्याज दरों पर लोन मिलता है। उसके लिए भी हमारी सरकार बैठकें कर रही है और अभी आपको ध्यान होगा, इसी 10 तारीख को हाउस के शुरु होने से पहले, फ्रांस का 40 लोगों का एक डेलीगेशन भी यहां आया। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बैठक की तो उसमें रोड सैक्टर को भी लिया गया। ईपीसी माडल पर हम भी काम करने का विचार कर रहे हैं जिसमें 50 प्रतिशत पैसा पहले दे दिया जायेगा और बाकी 50 प्रतिशत पैसा इक्विल इन्स्टालमेंट में जो भी रोड बनायेगा, उसको दे दिया जायेगा। उसमें जनता पर किसी भी तरीके का भार नहीं आयेगा। इसलिए यह शंका रखना कि यह जो सड़कें बनेंगी, सब पर टोल लग जायेंगे, राजस्थान का माहौल खराब हो जायेगा, यह भी गलत है क्योंकि जहां टोलेबल होगी, वहीं टोल लगेगा। जहां टोलेबल नहीं होगी, वहां पर थोड़ा सा टोल लगायेंगे। एनओटी बुलायेंगे। जहां वाइबल गैप

(श्री युनुस खान)

फण्ड देने के बाद में भी नहीं होगी, वहां शैडो टोल लगायेंगे और इनके बाद में भी नहीं होगी तो उसको ई पी सी पर ले जायेंगे। उसके बाद में भी नहीं होगी तो यह माननीया वसुन्धराजी की सरकार है, अपने खुद के पैसों से इस सड़क का निर्माण करेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी रोजे में हैं। अगर अनुमति हो तो शायद रोजे का समय हो रहा है खोलने का।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है अध्यक्ष महोदय। खोल लिया।

बस बात को मैं शोर्ट में ही पूरी कर दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे साथियों की शंका थी आप पर, जनता पर कोई भार नहीं है। क्योंकि अपने को जब लोग कहते हैं कि टोल लग गया, टोल लग गया। एक परसेंट लोगों के पास व्हीकल है बाकी 99 परसेंट लोगों के पास तो टोलेबल व्हीकल ही नहीं है। उनके घर जाकर के तो कोई टोल वसूल करने वाला ही नहीं है। इसलिए इस बात को भूल जाए। राजस्थान एक माडल स्टेट बने, राजस्थान को माडल स्टेट बनाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर की जो महत्वपूर्ण कड़ी है उसको पूरा करने के लिए हम सबको साथ चलकर के काम करना होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी राजस्थान के अन्दर सुराज संकल्प यात्रा में लगभग पूरे राजस्थान का दौरा किया और राजस्थान की सड़कों की स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच वर्षों के खर्चे पर अगर हम जाएंगे और जो खर्चा राजस्थान में हुआ। आपको भी पता है 900 करोड़ रुपये से खर्चा शुरू हुआ और 2600 करोड़ तक पहुंचा। पहले वर्ष 2009-10 में सरकार ने खर्चा किया सड़कों पर वह 900 करोड़ का किया और अभी उनका आखिरी वर्ष जो गया 2013-14 का उसमें 2600 करोड़ के लगभग खर्च किया। अब 1 लाख 95 हजार किलोमीटर सड़कें, उनका 2600 करोड़ में रख-रखाव, नई सड़कें, मिसिंग लिंक सड़कों का स्ट्रेंथ नहीं, बाइंड नहीं, यह सम्भव नहीं। अगर राजस्थान को आगे ले जाना है तो हमें पीपीपी माडल पर जाना पड़ेगा और पीपीपी माडल पर ही दूसरे प्रदेशों ने काम किया है। चाहे हमारा पड़ौसी राज्य मध्य प्रदेश हो, चाहे पड़ौसी राज्य गुजरात हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुराज संकल्प यात्रा में आप भी खूब चले और आप जब भी गाड़ी में बैठ जाते

(श्री युनुस खान)

थे तो पीछे से आवाज आती, एक गाना चलता था आओ साथ चलें, आओ साथ चलें। इसलिए सदन से आह्वान करुंगा कि आओ साथ चलें, हम सब मिलकर के राजस्थान को माननीय वसुंधराजी का माडल स्टेट बनाने का काम करें। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इन्होंने क्या किया? एक भी सड़क बता दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सबको पता है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी की दो चीजें बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रधान मंत्री सड़क योजना और फोर-लेन, सिक्स लेन हाइवेज! दूसरा आपको ध्यान होगा एक काम किया कि शहीदों को और उनके परिवार को सम्मान देने के लिए पहली बार हिन्दुस्तान के अन्दर शहीदों के शव उनके घर तक आने लगे। यह काम अगर किसी ने किया तो वह अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किया और उसी तर्ज पर जब सार्वजनिक निर्माण मंत्री के रूप में जब काम सम्भाला तो मैंने कहा कि इस विभाग की शुरूआत कहां से करूं, तो मेरे को ध्यान आया। आप अगर इजाजत दें तो मैं उसकी बात भी बता दूं कि वह सड़क किन कारणों से बनाई। पहला कारण तो यह था माननीय अध्यक्ष महोदय, कि वाजपेयीजी का शहीदों के लिए जो एक जज्बा था उसको याद करते हुए मैंने भी मेरे जीवन की पहली सड़क की स्वीकृति दी थी शहीद जीवनराम मूर्ति से लेकर उसके ढाणी तक 74 लाख की। मुझे खुशी है कि वह सड़क बन चुकी है। उसके बाद में यह जो कारवां शुरू हुआ और जो स्वीकृतियां जारी हुईं, वह सबको पता हैं। मैं दिल्ली भी गया, दिल्ली से भी हमारा हक था, वह लेकर के आया। उसके बाद में उसकी एनआईटी भी निकाली। उनकी स्वीकृतियां भी जारी कीं और इस गवर्नमेंट के आने के बाद में स्टेट हाइवे प्लान में 96 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां भी हमने जारी की हैं और काम भी उसके शुरू किए हैं। एमडीआर के 87 करोड़ के काम हमने शुरू किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टीएफसी के 20 करोड़ के काम शुरू किए हैं। आर आई डी एफ के, नाबार्ड के 60 करोड़ के किए हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय, पीएमजीएसवाई में मैं चार बार दिल्ली गया और माननीय मंत्रीजी को हमने कहा कि हमारे जितने प्रपोजल आये। उन्होंने कहा कि आपकी यह-यह खामियां हैं, उनको हमने चार-पांच बार में जाकर के दूर किया। आपको सुनकर के खुशी होगी कि वो भी हम 1187 करोड़ की स्वीकृतियां लेकर के आये और सब के सब लगभग 80 परसेंट गांवों को जोड़ने के लिए उसकी एन आई टी जारी कर दी। वर्ल्ड बैंक से भी 593 करोड़ का आते ही हमने एग्रीमेंट किया, उनकी भी आज एन आई टी हो

(श्री युनुस खान)

गई। लगभग 60 से 70 परसेंट वर्क आर्डर हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क का एक प्रोसीजर होता है। टैण्डर निकलने का प्रोसीजर होता है, उसको पूरा करके हमने काम शुरू किया है। तो राजस्थान में एक यह बेहतरीन शुरूआत हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जितनी चर्चाएं हुई, उसमें बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपनी सड़कें बनाने की बात कही। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपनी बात को रखा, मिसिंग लिंक की बात को रखा। मैं उनको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अबकी बार जो हमारा बजट का प्रोविजन हुआ है। उसकी राशि भी लगभग 5 हजार करोड़ रुपये के आसपास हमें अलाट हुई, वह आई है। उसमें अभी लायबिलिटी थी। क्योंकि ये लोग बार-बार चर्चा करते हैं कि हमारी सड़कें कैंसिल कर दीं, राजनीतिक द्वेष से कर दीं। उसके लिए भी माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से सारे सदन को अवगत कराना चाहता हूं। जब आखिरी बजट माननीय गहलोत साहब ने 2013 -14 का रखा। उसमें बजटीय प्रावधान 2242 करोड़ का रखा और चूंकि चुनावी वर्ष था। गांवों में जब माननीय वसुंधराजी ने सुराज संकल्प यात्रा निकाली। उसकी नकल करने के लिए निकल गए और उन्होंने नकल में एक संदेश यात्रा निकाली। उस संदेश यात्रा में उनके पीछे-पीछे घूमने लग गए और वसुंधराजी तो टूटी हुई सड़कों को देखती थीं। उसके अलावा तो कोई उनके पास पावर था नहीं। इनके पास पावर था और यह भूल गए कि हमने बजट की सीमा 2242 करोड़ रुपये रखी और इन्होंने 4 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृतियां संदेश यात्रा के दौरान जिसने जो सड़क मांगी, उसको दे दी और वोटों की फसल काटने के लिए इस तरीके का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहां 2242 करोड़ और कहां 4 हजार करोड़? सरकार का इतना प्रोविजन नहीं है उससे ज्यादा तो उन्होंने एक्सट्रा घोषणाएं कर दीं।

जब परिवर्तन हुआ तो हमारी सरकार ने एक कैबिनेट सब-कमेटी बनाई। उसने बहुत परीक्षण किया और वरिष्ठ नेतृत्व जिसमें दो पूर्व मंत्री जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से जुडे हुए थे, वो मैम्बर थे। माननीय गुलाबजी और राठौड़ साहब, उन्होंने कहा कि कहीं राजस्थान की जनता का अहित न हो जाए। यह संदेश नहीं चला जाए कि यह सरकार आई और आते ही कैंसिल कर दिया। बार-बार परीक्षण हुआ और जब तक बजट नहीं हो सकता, आप भी जानते हैं घोषणाओं से सड़क नहीं बनती है। इसलिए उनमें से भी जिनके वर्क आर्डर हो गए और काम शुरू हो गए, उनको हमने नहीं रोका। जिनके वर्क

(श्री युनुस खान)

आर्डर नहीं हुए उन कामों को जरूर निरस्त करने का काम किया है। जैसे-जैसे बजट का प्रोविजन होगा उसी अनुसार उनको माननीय सदस्यों से चर्चा करके ले लिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लास्ट में मुख्य मंत्री प्राथमिकता सड़कें, जिसमें 150 करोड़ रुपये का प्रोविजन उन्होंने किया और सुनकर के आपको भी आश्चर्य होगा, सदन को भी होगा, हमारे साथियों को भी होगा। उसमें भी उन्होंने 537 करोड़ की स्वीकृतियां जारी कर दीं। अब अध्यक्ष महोदय, 150 करोड़ रुपये और कहां पर 537 करोड़ रुपये, उसमें भी यही हाल होना था। फिर भी उसमें जिनके वर्क आर्डर हो गए, काम शुरू हो गए उनको नहीं रोका गया और उनको करने दिया गया। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि यह पिछली सरकार की गलती है। इनको तो मौका नहीं मिलेगा, इसलिए इस पांच साल में आपकी ऐसी सड़कें जो जरूरी हैं, आपके साथ बैठकर चर्चा करके अगले बजट वर्षों में, इस बजट वर्ष जैसे-जैसे प्रावधान होगा, आपके कहे के अनुसार, माननीय सदस्यों के कहे के अनुसार उन सड़कों का भी निर्माण करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इधर ही हाथ कर रहे हैं मंत्रीजी, इधर नहीं कर रहे हैं चर्चा के लिए।

श्री अध्यक्ष: इधर संख्या थोड़ी कम है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय लक्ष्मणगढ़ से आने वाले सदस्य हैं इनकी मुराद तो पूरी कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बीच में जब टोक दिया तो मैं एक बार इधर भी मुंह कर लेता हूं। (व्यवधान) मैं इनकी तरफ भी मुंह कर लेता हूं। मैंने अभी जो डाकूमेंट रखा और 8 हजार 290 किलोमीटर की सड़कें रखीं और 20 हजार की जिसकी चर्चा कर रहे हैं, इनका विधान सभा क्षेत्र भी उसमें शामिल है और इनका जो गृह जिला सीकर है। वहां से वह सड़क शुरू होगी और गनेड़ी आएगी। गनेडी के बाद में रायदूला जाएगी, रायदूला के बाद में वह लाडनूं होते हुए जो इनके आगे बैठते हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष उनको जोड़ने के लिए हमने काम किया है। उस पैकेज को भी हमने लिया है। इसलिए इनको भी हम जोड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस पैकेज में खाली इतना ही नहीं, हम पीछे से यह चाहे रामदेवरा जाना चाहें, चाहे दतिमाता

(श्री युनुस खान)

के मंदिर जाना चाहें, या करणी माता के मंदिर जाना चाहें तो यह नोखा रोड से जा सकते हैं। अगर इनको दतिमाता मंदिर जाना है, वीर तेजाजी में इनकी बहुत आस्था है, उसमें जाना है तो नागौर से लेकर के तरणाऊ डीडवाना होते हुए इनके विधान सभा क्षेत्र जिस बोची की इन्होंने चर्चा की है कि मेरी बोची की बहुत हालत खराब है। उस बोची के अन्दर उस सड़क को हम बनायेंगे और आगे ले जाकर के सालासर मंदिर तक छोड़ेंगे इसलिए इनकी तरफ भी बहुत ध्यान दिया है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): अब तो धन्यवाद दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारा और मंत्रीजी के बीच का मामला है आप बीच में काहे को हल्ला कर रहे हो?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक चर्चा आई कि ये सरकार अपना समय नष्ट कर रही है। पहले हम भरतपुर गये। हम अभी बीकानेर जाकर के आये सम्भाग में। भरतपुर जब सरकार के चीफ सेक्रेटरी से लेकर के सारे आफिसर्स, मुख्य मंत्री से लेकर के सारे मंत्री पंचायतों में घूमे तो वास्तव में वहां की जो समस्याएं देखीं, लोगों के जो हालात देखे और सभी विभागों ने अपनी-अपनी समस्याओं को नोट किया उनके समाधान के लिए योजना बनी। अब मैं तो वो कैबिनेट नोट भी आज साथ लेकर आया हूं कि हमने कितनी स्वीकृतियां जारी कीं, चूंकि समय कम है इसलिए मैं ज्यादा लम्बा नहीं जाना चाहता जितनी घोषणाएं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वहां कीं उन सारी घोषणाओं को हमने पूरा किया। दो इश्यु जो रमेश जी थोड़ा बार-बार उठने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। दो इश्यु थे एक बाड़ी में बहुत पहले चम्बल नदी के ऊपर सोने का गुर्जा पर एक पुल का निर्माण हुआ था और वो पुल आधा लटका हुआ पड़ा है। वहां जब मैंने जाकर के मौका देखा और जिस गांव में हम गये, अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुख होता है, 67 साल के बाद में, मैं इन पर और मेरे पर नहीं कर रहा, क्योंकि 67 साल में जिस तरीके से ये लोकतंत्र में हुआ, जो होना चाहिए था, वो नहीं हुआ और वहां जाकर के देखा सोना के गुर्जा से जुडे हुए पन्द्रह गांव में न बिजली है, न सड़क है और गांव या दो गांव में स्कूल है, ऐसे हालात गांवों के आज भी हैं और सोने का गुर्जा उससे चम्बल को क्रोस करके मध्य प्रदेश में जाने के लिए काम में आता है तो माननीय अध्यक्ष

(श्री युनुस खान)

महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और हमारी कैबिनेट ने उस सोने के गुर्जा को बनाने की घोषणा की। आज इन्होंने कहा कि बजट में प्रोविजन नहीं किया। चूंकि उसमें आप सबको पता है कि वहां पर अभयारण्य है इसलिए उसकी परमीशन सुप्रीम कोर्ट से लेनी होती है तो परमीशन के लिए यहां से राज्य सरकार की जो बाडी बनी हुई है, बोर्ड बना हुआ है, उसने वहां भेज दिया और हमने एक नोडल आफिसर लगा दिया है, जब भी वहां की स्वीकृति आ जाएगी क्योंकि उस स्वीकृति में अमूमन ये माना जाता है कि आठ-नौ महीने लगते हैं अगर पहले आ गई तो हम उसकी डीपीआर वगैरह सारी तैयार पेरेलल ही कर रहे हैं, पहले हम कोई घोषणा कर देंगे। मतलब प्रोविजन करने की कोशिश करेंगे इस बजट में कि इस साल दे दें, नहीं तो अगले साल तो उसमें देना ही देना है क्योंकि उस सोने के गुर्जा को बनाना है।

दूसरा मंडरायल और सबलगढ़ जो सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही। अध्यक्ष महोदय, एक बात कहते हुए मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जब हम सपोटरा गये तो मेरे हिसाब से आप इंजीनियर भी रहे हैं, इनकी पिछली बार सरकार थी तो सरकार में भी इनका हिस्सा था। मैं किसी के व्यक्तिगत मामले में ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। ठेकेदार होना कोई बुरी बात नहीं है, ठेकेदार होना अच्छी बात है क्योंकि हमारा काम सारा ठेकेदारों के थ्रू होता है इसलिए ठेकेदार होना बुरी बात नहीं है। लेकिन ये इंजीनियर रहे, पिछले पांच साल एमएलए रहे, सरकार में हिस्सा रहा, अगर मेरे को पूछा जाए ईमानदारी से कि दो सौ विधान सभा क्षेत्रों में सबसे खराब सड़कें कहां हैं तो मैं यह बिलकुल दावे से कह सकता हूं कि सपोटरा की सड़कें सबसे ज्यादा खराब हैं। मुझे कहते हुए कतई हिचक नहीं हो रही है तो सपोटरा की जब हमने हालत देखी और वहां जो गरीब लोग हैं उनकी रिश्तेदारियां सारी मध्य प्रदेश में हैं। इसलिए सबलगढ़ मंडरायल की जो बात आज माननीय सदस्य कर रहे थे उनको मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान की मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धराजी और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय शिवराज सिंहजी चौहान दोनों की बैठक हो गई। हम दोनों मंत्रियों की हो गई और हमारे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष के साथ मीटिंग हुई अब तो केन्द्र में वो मंत्री बन गये तो सबलगढ़ का और मंडरायल का भी हमारी ज्यों ही एनओसी आई सुप्रीम कोर्ट से और बोर्ड से त्यों ही दोनों सरकारें मिल करके इसको आधा-आधा बनायेंगे। आधा वो बनायेंगे

(श्री युनुस खान)

आधा हम बनायेंगे। जब तक, मैं आज यह घोषणा करता हूं कि जो उसकी अप्रोच रोड है उसका निर्माण हम करेंगे क्योंकि वहां बहुत सारे ऐसे लोग वंचित हैं उनके लिए वहां तक की अप्रोच रोड को सुदृढ़ीकरण का काम हम करेंगे। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): आप तो ब्रिज का बताओ, मंत्रीजी, ब्रिज कब बनेगा? आपने भरतपुर सम्भाग में घोषणा की है उसकी बताओ आप तो सदन में। सदन की नेता ने भी घोषणा की है और आप भी बतायें। आप तो ब्रिज की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार ब्रिज बनाने जा रही है और आप असत्य बोल कर गुमराह कर रहे हो यहां सदन को। असत्य बात कह रहे हैं आप।

श्री अध्यक्ष: सपोटरा के माननीय विधायक, विराजिये। मंत्रीजी को भाषण देने दीजिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से आर्डर मिलने के बाद में उसमें हण्ड्रेड परसेंट कार्यवाही शुरू हो जाएगी इसलिए कहीं भी शंका करने की कोई जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सड़कें बनती हैं, टूटती भी हैं फिर नयी बनती हैं और इन्हीं सड़कों पर दुर्घटनाएं होती हैं। आप सबको पता है अध्यक्ष महोदय, जब कोई हत्या हो जाती है तो पूरा शहर बंद हो जाता है, महीनों तक धरने-प्रदर्शन चलते रहते हैं लेकिन आप पिछले दस साल के देख लें, चाहे पांच साल के देख लें राजस्थान में लगभग पच्चीस हजार दुर्घटनाएं इन सड़कों पर होती है और उन पच्चीस हजार दुर्घटनाओं में लगभग साढ़े नौ हजार औसत आ रहा है। साढ़े नौ हजार लोग अगर हम देखें कि एक साल में मर जाते हैं और बाकी जो लोग हैं वो या तो स्थाई रूप से अपंग हो जाते हैं, या फिर कहीं उनकी बाद में अस्पताल में, या साल छह महीने बाद में मौत हो जाती है, उनकी संख्या नहीं है। ये लोग मर रहे हैं इसके लिए भी इन सड़कों पर सड़क सुरक्षा हो और इस तरीके की बार-बार घटनाएं नहीं हों तो उसके लिए भी हमने पुलिस के सहयोग से जो दुर्घटनाएं अब तक हुई हैं पिछले दस साल का रिकार्ड निकालकर के पांच सौ पाइंट चिह्नित किये हैं और पांच सौ पाइंट्स पर हम दुरुस्तीकरण करेंगे कि आगे दुर्घटनाएं नहीं हों, बिलकुल कम हों और उन मरने वाले के परिवारों को इस तरह से वंचित नहीं होना पड़े अपने मुखिया से और अपने परिवार के कोई नौजवान से। उसके लिए विश्व बैंक के सहयोग से सौ

(श्री युनुस खान)

करोड़ रुपये की योजना इस वर्ष हम लागू करेंगे। 9177 जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं अध्यक्ष महोदय, आपको भी पता है कि ये अभियान जब भी चलते हैं, शहरों में चलते हैं, गांवों में नहीं चलते इसलिए हमने फैसला किया है और माननीय पंचायत राज मंत्री महोदय बैठे हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि उनके साथ भी हम बैठक करेंगे वो जब डेट देंगे उस एक डेट को हम पूरे राजस्थान में यह अभियान चलायेंगे और जब भी उनका कोई इस तरीके का कार्यक्रम होगा उसमें हम क्लब करेंगे उसमें पूरा लिटरेचर, पूरा सामान सब चीजें एक्सीडेंट नहीं हो उसके रोकथाम के लिए जितना लिटरेचर है उसको लेकर के 9177 ग्राम पंचायतों तक हम जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब सवाल आता है कि जो खराब सड़कें हैं उनका क्या होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि बीस हजार किलोमीटर सड़कें तो हमारे स्टेट हाइवेज जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, उनमें से लेंगे लेकिन उसके बाद भी जिलों में बहुत खस्ता हाल हैं। अगर जिलों की हम देखें तो बहुत सारी सड़कें आज राजस्थान में लगभग बारह-तेरह हजार किलोमीटर तो ऐसी हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलकुल सड़क नाम है बाकी आप सड़क के नाम से ढूंढोगे तो वहां कुछ नहीं मिलेगा। अब उन सड़कों का हम पैच वर्क करायें तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मुख्य मंत्रीजी ने फैसला किया है कि पैच वर्क पर जो पैसा खर्च होता है और पैच लगाने के बाद में आज तीन माननीय सदस्यों ने इस हाउस में बोला है कि पैच लगा कर के गये, एक नौजवान माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि मैं जब दुबारा गया तो मुझे वो पैच मिला नहीं। पैच की यही हालत है। कई जगह पैचवर्क होता है, इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह फैसला किया कि राजस्थान की बीस हजार किलोमीटर को मैं अच्छा बना दूं तो राजस्थान माडल स्टेट बनने वाला नहीं है इसलिए एक नयी चीज ओपीआरसी आउटपुट परफोरमेंस बेस कांट्रैक्ट की बात उन्होंने कही कि हम ओपीआरसी लागू करेंगे जो राजस्थान की एक लाख पांच हजार किलोमीटर सड़कों पर होगा, उस पर कोई टोल नहीं लगेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका पुनर्निर्माण, उनकी स्ट्रेन्थ, उनकी मेंटीनेंस, उनकी कारपेटिंग राज्य सरकार अपने संसाधनों से करेगी। हर वर्ष इसको डिवीजनवाइज, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी डिवीजनवाइज घोषणा की है, लेकिन एक हमारा

(श्री युनुस खान)

ओब्लिक भी है कि एक जिले को एक यूनिट मान करके हम काम करेंगे। आज कुछ लोगों ने धन्यवाद भी दिया कि हमारे कोटा सम्भाग के चार जिलों में हमने चार हजार करोड़ के एनआईटी जारी किये हैं तो वो ओपीआरसी में राज्य सरकार ने जारी किये हैं। उसी में धौलपुर और अलवर को भी हमने लिया है, दो जिले लिये हैं, एक पूरा सम्भाग लिया है। हमने इसमें विशेषज्ञ लोगों के पास, मतलब जो लोग आएंगे उनकी क्वालिफिकेशन के लिए काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो सड़क बनेंगी तो पहली प्रायोरिटी हमारी इसमें यह रहेगी कि जो टूटी हुई सड़कें हैं उनको हम पहले फेज में लेंगे पूरे राजस्थान भर में। उसके बाद में हर साल सड़कों की संख्या बढ़ती चली जाएगी और जो आठ साल की बात कही, पहले वर्ष जो सड़क बनेगी उस कंस्ट्रक्टर की यह जिम्मेदारी होगी आठ साल तक उसको मेंटेन करें, उसकी स्थिति वो की वो रखे, अच्छी रखे। दूसरे साल, फिर तीसरे साल, फिर चौथे साल, इस तरीके से आठ साल तक पूरे राजस्थान का प्रायोरिटी के बेस पर हम काम करेंगे, तो यह 1 लाख 5 हजार किलोमीटर सड़कें ओपीआरसी में बनाई जाएगी। इसमें कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। विशेषज्ञ और सक्षम लोगों को दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमने सारे लोगों से चर्चा करके, सारे प्रदेशों और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी जो विशेषज्ञ हैं, उनकी राय से डाक्यूमेंट तैयार किया है। यह योजना भी इसी साल से, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि बनाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समय ज्यादा नहीं लूं यह देखते हुए मैं आपसे कहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ने एक घोषणा गांव गौरव पथ की करी। आपको ध्यान होगा और हमारे पुराने जो साथी है उन सबको ध्यान है, माननीय सदस्यों को ध्यान है कि जब माननीय मुख्य मंत्रीजी पिछली बार थीं तो उन्होंने एक शहर में गौरव पथ बनाने की बात कही। हर विधायक को कहा कि आप 70 लाख रुपये तक की राशि का एक मार्ग चिह्नित कर दें उसको हम आइडल मार्ग बनाएंगे। उसको गौरव पथ नाम दिया था। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल में जब मैंने शहरों को यह प्राथमिकता दी तो मेरे गांव में बसने वाला गरीब, किसान, नौजवान, हमारी माताएं और बहनें गांव में रहती हैं वह कीचड़ में चलती हैं। माननीय गुलाबजी ने इस बात को सुराज संकल्प यात्रा के दौरान बहुत महसूस किया। तो जब यह डाक्यूमेंट बना रहे थे उस

(श्री युनुस खान)

डाक्यूमेंट में भी आपने इस बात को कहा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 1800 करोड़ रुपये उन 9177 गांवों के लिए भी घोषित किए हैं, मैं सोचता हूं कि यह अपने आपमें एक बहुत बड़ी बात है। गांवों की तरफ ध्यान देना, गांव में आधे किलोमीटर से लेकर दो किलोमीटर तक सड़क का बनाना कोई छोटी बात नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ लोगों को शंका है कि यह क्या हो रहा है? कुछ योजनाएं तो हमारी ओपीआरसी में आ जाएंगी, कुछ गांवों में से हमारी 20-30 हजार किलोमीटर सड़कें निकलेंगी वह आ जाएंगी, इसके बावजूद भी जो गांव बिल्कुल ही इनसे वंचित रह गए उन गांवों में हम कम से कम सीसी रोड बनाकर, नाला बनाकर, स्लोब बनाकर काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इतना ही काम हम सब कर रहे हैं तो एक चीज की और जरूरत पड़ती है कि राजस्थान में एक इस तरीके का कानून आए जो इन सबको मानिटर करे, इनको फैसिलेटेड करे, सड़कों के रखरखाव में जो चीजें छूट गई थीं उनको भी ले। सुराज संकल्प यात्रा की तर्ज पर राजस्थान स्टेट हाइवे अथोरिटी का भी काम करने का कहा, मैं आपसे कहना चाहूंगा उसकी भी हमारी पूरी-पूरी तैयारी है। जब इसी हाउस में बिजनस आएगा, हमारा प्रयास है कि उस बिल को इसी हाउस में लेकर आएंगे। उसी के तहत हम इन सारी योजनाओं को गवर्न करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, लैण्ड एक्वीजीशन में बहुत समय लगता है। बैंकों से लोन लाने में बहुत समय लगता है उसके लिए सारे प्रोविजन करके हम आ रहे हैं। फिजिबल स्टडी के बाद में लोन कन्सेंसनल को कैसे मिलेगा उसको पूरा फैसिलेट करके सरकार आएगी। कानून में उसको क्या अधिकार रहेंगे, पूरे अधिकारों के साथ आएगी, इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शंका करने की जरूरत नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं यह बात कर रहा हूं तो मैं एक चीज और कहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी ने जो बातें कही हैं चाहे वह ओपीआरसी की हो, चाहे वह स्टेट हाइवे की हो, चाहे वह पीपीपी माडल पर 20 हजार किलोमीटर की हो। मेरा नहीं है, मैं तो लिखा हुआ ही बोल हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोटेशन मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी का 14 तारीख का बजट था वह इस ओर एक कदम है ‘‘The journey of a thousand miles begins with one step.” तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वह स्टेप उठा लिया, हजारों मील के लिए कभी न कभी हमें

(श्री युनुस खान)

कदम उठाना पड़ेगा, हजारों मील की यात्रा तय करने के लिए। राजस्थान को माडल स्टेट बनाने के लिए मुख्य मंत्रीजी ने 14 तारीख को वह स्टेप उठा लिया। अब हर स्टेप आगे बढ़ता जाएगा तो एक दिन वह आएगा जब हम इस 20 हजार किलोमीटर की यात्रा को भी अचीव कर लेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक चर्चा डाक बंगलों की आई। डाक बंगलों की वास्तव में स्थिति खराब है मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं। राजस्थान के डाक बंगले बहुत अच्छे भी हैं। आप जयपुर का डाक बंगला देखेंगे तो बहुत अच्छी जगह है। और भी बहुत सारे, राजस्थान में 10-12 डाक बंगले हैं जो बहुत अच्छे हैं। मैं आज माननीय सदस्यों को कहना चाह रहा हूं कि उनमें कहीं कर्मचारी नहीं है, सफाई वाला नहीं है, खाना बनाने वाला नहीं है, उसके लिए भी हमने मुख्य मंत्रीजी के निर्देशन पर एक विस्तृत योजना बनाई है। आज इस हाउस में मैं उसकी घोषणा करना चाहता हूं कि पीपीपी माडल पर बुरा लग रहा होगा लेकिन उसको लाने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्योंकि हमने स्टडी किया, अगर जयपुर में भी हम लाए तो आज हमारी लोकेशन ऐसी जगह है कि उसको बनाने के बाद में, हम वहां नहीं देंगे, उसको अलग से डवलप करेंगे, उसके बदले में हमारे पास बहुत सारी जमीने पड़ी हैं ऐसी। दोनों का नेगोशियेशन करके इस तरीके की नीति हम बनाएंगे कि इन सारे डाक बंगलों को भी अगले पांच साल के अन्दर इस तरीके का कर देंगे जिस तरीके के कर्नाटक और केरल के अन्दर पीपीपी माडल में बने हुए हैं। उसी को आधार को मानते हुए इन सारे डाक बंगलों को कर देंगे। फिर सदस्य के साथ सिफारिश यह आएगी कि मुझे आज माउण्ट आबू जाना है, मुझे आज जयपुर जाना है तो मैं आपके डाक बंगले में रूकूं, इस तरह की सिफारिशें आएंगी, यह विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात को ज्यादा लम्बा नहीं करते हुए, बहुत सारे नवाचार भी हम लोगों ने किए हैं। आपको ध्यान होगा, अखबारों के जरिए भी। अब समय कम है, आप भी मेरी तरफ देख रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कुछ नवाचार हमने प्लास्टिक की रोड बनाने का, कंकरीट रोड बनाने का, कुछ फ्लाई एश है उनकी सड़कें बनाने का, लगभग इस तरीके की 80 सड़कों का भी एक एक्सपेरिमेंट हमारे यहां राजस्थान में चल रहा है कि फ्लाइ एश से कैसे सड़क बने, प्लास्टिक की कैसे सड़क बने और बहुत सारे इस तरीके के 5-6 नवाचार हम राजस्थान में कर रहे हैं। माननीय

(श्री युनुस खान)

पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी थे, उन्होंने जो सपना देखा और बात सोची आज राजस्थान उसी पर चल रहा है। (व्यवधान) काका मेरे को कह रहे हैं पहले घोषणा कर दो, यह भाषण रहने दो। मैं उसी पर आ रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने में एक पेपर मेरे हाथ लग गया।

माननीय प्रधान मंत्रीजी ने योजना 25 दिसम्बर, 2000 को अपने जन्मदिन पर शुरू की। माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी के जन्मदिन पर यह योजना शुरू हुई। उस समय राजस्थान में जो काम हुआ वह भी कम नहीं था। लगभग 918 गांव 9460 किलोमीटर जुड़े थे। माननीय राजेन्द्रजी जब पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, वसुंधराजी मुख्य मंत्री थीं, वाजपेयीजी की यह योजना थी पीएमजीएसवाई। अध्यक्ष महोदय, उसमें जो काम हुआ वह अकेला 35050 किलोमीटर का काम हुआ। लैंथ 32206 किलोमीटर ही थी। अगर हम कांग्रेस के दोनों शासन की कहें साहब यह भारत सरकार का पैसा आता है, कुछ लोग कहते हैं। अगर हम दोनों सरकार का जोड़ भी लगायें और मैं इसको लम्बाईवार भी कहूं तो मात्र 18 हजार किलोमीटर इन्होंने दोनों कार्यकाल में। वाजपेयीजी का 2000-2003 से जो यह योजना थी उसमें और 2008 से 2013 का दोनों कार्यकाल भी जोड़ लें तो इनकी लगभग 18 हजार किलोमीटर बनती है जो कि हमारे पांच साल के कार्यकाल से आधी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के तहत कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि हम राष्ट्रीय राजमार्ग बनाएंगे, ओपीआरसी लेकर आएंगे, गौरव पथ बनाएंगे। हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि और क्या आपने काम किया, 60 दिन की भी चर्चा होती है। बहुत सारे वर्क आर्डर हैं लेकिन एक बड़ा काम भी हमने किया। हमारे जो एमडीआर थे, मैटल डिस्ट्रिक रोड थी, 687 किलोमीटर को हमने राजमार्ग में बदलने का काम किया। 219 किलोमीटर ओडीआर थी उसका भी हमने स्टेट हाइवे में बदलने का काम किया।

बातें बहुत सारी हैं, इस विषय में बहुत सारा बोलना है, लेकिन मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि समय को देखते हुए, सबकी कल छुट्टी है उसको देखते हुए अब मैं उन चीजों पर आना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा अगले साल तक इस फाइनेंशियल ईयर में हम लगभग 3 हजार किलोमीटर, 950 करोड़ रुपये के साथ 31 मार्च तक इन गांवों का काम कम्प्लीट कर देंगे। 950 करोड़ रुपये में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं घोषणा करता हूं। लोग कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए और वह वास्तव में अच्छे दिन आ गए।

(श्री युनुस खान)

(20.00 बजे)

केन्द्र में सबको पता है कि आज इस हिन्दुस्तान के तख्त पर एक ऐसा नेतृत्व है जिनका लोहा गुजरात को देखते हुए पूरे हिन्दुस्तान ने ही नहीं, पूरे विश्व ने माना और हिन्दुस्तान की जनता ने उन पर विश्वास किया। माननीय नरेन्द्रजी मोदी साहब की पहली बार पूरी मैजोरिटी के साथ में भारतीय जनता पार्टी केन्द्र के शासन में आयी और उनके नेतृत्व में, उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, उन्होंने चुनावों के दौरान जो बातें कही हैं उनको पूरा करने के लिए केन्द्र में एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री इस विभाग का बनाया है जो दोनों विभाग संयोग आज उन्हीं के पास है। एक भू-तल परिवहन मंत्रालय और दूसरा पंचायती राज। पंचायती राज मंत्रालय मतलब, साथ-साथ में यह भी देखता है कि यहां पर पी.एम.जी.एस.वाई. की जो सड़कें हैं, वे बनें। तो यह दोनों विभाग माननीय नितिन गड़करीजी के पास हैं। माननीय वसुन्धरा जी के नेतृत्व में चार तारीख को राजस्थान के सारे आफिसर्स, मैं स्वयं और मुख्य मंत्रीजी ने, माननीय नितिन गड़करीजी के साथ बात की और जब राजस्थान के बारे में हमने चर्चा की तो कहा कि जो हमारे हाई-वेज की हालत है, हाई-वेज में 33 में से 19 की चर्चा की कि काम शुरू नहीं हुआ।

दूसरा, हमारे एन.एच-8 की बात है तो उन्होंने हमको विश्वास दिलाया कि मेरा सैक्रेटरी, मेरी पूरी एन.एच.आई. टीम मतलब, जो सैक्रेटरी-ट्रांसपोर्ट हैं वे और पूरी टीम, उनके साथ में आपके चीफ सैक्रेटरी, आपके प्रिंसीपल सैक्रेटरी और आपकी पूरी टीम मतलब, गुड़गावां से लेकर आखिरी छोर तक जाएगी और पूरी रिपोर्ट लाएगी। उन्होंने वसुन्धराजी को कहा कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं स्वयं इस प्रोजेक्ट को देखूंगा। क्योंकि, मैं सुन-सुनकर इतना हैरान हो गया हूं कि दो राजधानियों के बीच में जो बनी हुई सड़क है उसकी यह हालत है। इसलिए अब मैं निर्णय लेता हूं कि यह अगले 12 महीने के अन्दर-अन्दर और मैं तो आपको यह कह रहा हूं बिना देखे कि अगले मार्च तक मैं इसको पूरा करवा दूंगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि एन.एच.-8 भी होगा।

उसी कड़ी में जब हमने उनसे चर्चा की कि आपके पास में यह विभाग है। हमें दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह नई घोषणा है और हमारे लोग कह रहे हैं कि हमें क्या मिलेगा? तो उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आपके यहां पर क्या है माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ी सी चर्चा में यह करना

(श्री युनुस खान)

चाहूंगा कि जो पी.एम.जी.एस.वाई. है, उसमें 2001 की जनगणना को आधार माना गया है। उस समय लगभग 39756 गांव थे, उनमें से लगभग 2100 के करीब उन गांवों में से आज की तारीख में रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 31 दिसम्बर, 2013 तक हमारे राजस्थान में लगभग राजस्व गांव 44 हजार हो गये। यानि, जो संख्या 39756 थी वह बढ़कर लगभग 44 हजार के करीब हो गयी। जो राजस्व गांव बढ़े हैं उनमें कुछ तो जुड़े हुए हैं और कुछ 2001 की जनसंख्या के भी रहे हुए हैं। लगभग मैं यह कह सकता हूं कि साढ़े पांच हजार गांव ऐसे हैं जो कि रह गये, कनैक्ट नहीं हो पाये। उनके लिए इस वर्ष मैं यह आज घोषणा कर रहा हूं, माननीय मंत्रीजी से बात होने के बाद में कि 2056 गांवों की, लगभग 1600 करोड़ रुपए से इसी साल हम स्वीकृतियां जारी कर देंगे जो इन माननीय सदस्यों के विधान सभा क्षेत्र में आएगा। हम हैबिटेशन ले रहे हैं। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व का जिक्र नहीं है, हैबिटेशन का है तो कुछ लोगों के सुझाव आये थे, जिसमें चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य अभी चले गये। उन्होंने भी सुझाव दिए थे बहुत सारे तो हैबिटेशन को लेकर वह लगभग सारे आकड़े, चाहे वह राजस्व गांव के हों, बाली से आने वाले माननीय सदस्य, चाहे वह 2001 की जनसंख्या के हों या फिर 2003 में माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सर्वे हुआ था पी.एच.ई.डी. का उसको भी आधार, केन्द्र सरकार ने मान्यता दे रखी है। कल-परसों हमारे जो इस सदन में बोलने की स्टार रही थीं, उन्होंने चर्चा की थी 2001 के सर्वे की, तो वह 2003 का सर्वे था उसको मानते हुए लगभग मैं आपको यह विश्वास दिला रहा हूं कि इन पांच सालों में राजस्थान का एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जो किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं होगा। इसलिए यह साढ़े पांच हजार गांवों को भी जोड़ेंगे। नई ढाणियां, हैबिटेशन है, उनको भी जोड़ेंगे लेकिन उसमें लगभग 2056 गांव इसी वर्ष जोड़ने का काम हम शुरू कर देंगे। यह मैं आज माननीय अध्यक्ष महोदय, 1600 करोड़ की लागत से घोषणा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी घोषणा करता हूं कि आज इतना सारा सड़क तंत्र बन जाएगा और उसमें यह एक मेन जो बात है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने भी कोशिश की थी कि यह जो माइनिंग रोड्स हैं उनकी वजह से सड़कें बहुत ज्यादा टूटती हैं। इसकी भी हमने अलग से योजना बनाई है। आप भी पहले और अभी भी इस सरकार में खान मंत्री रहे हैं। आपको भी पता है कि किस तरीके से मार्बल के, सीमेंट के, कोटा स्टोन के

(श्री युनुस खान)

ओवर-लोडेड ट्रक चलते हैं तो उनसे सड़कें टूटती हैं। उसकी भी हम पूरी योजना बना रहे हैं तो माइनिंग के लिए भी अलग सड़कें बनाने की माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश के बाद में आज मैं घोषणा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक शंका आई थी कि क्वालिटी कंट्रोल की बात कही गई थी, हमने इसमें भी काम शुरू किया है। इन सबके बावजूद भी, हमारे अधिकारी उसको चैक नहीं करें, उसके लिए हम थर्ड पार्टी जांच मतलब, तीसरी पार्टी जांच करेगी इन सड़कों की, यह आज इस हाउस में घोषणा करता हूं। जिससे जो हमारा माडल स्टेट का नारा है। जो हमारे डिपार्टमेंट का नारा है 'क्वालिटी और पंक्चुअलिटी' का, वह भी पूरा हो सके। इसलिए थर्ड पार्टी इसकी जांच करेगी, उसकी भी मैं आज इस सदन में घोषणा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जब हम लोग यात्रा पर थे बीकानेर में तो इंदिरा गांधी नहर के आस-पास लगभग घूमे। आज हमारे करणपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी बात कही। इन्होंने भी खूब घुमाया वहां पर। तो पता चला कि जल संसाधन मंत्रालय और सिंचाई मंत्रालय ने जो सड़कें बनाई थीं वह इंदिरा गांधी नहर के आस-पास 476 किलोमीटर सड़कें हैं। वे बिलकुल टूटी हुई हैं। माननीय सदस्य गुरजण्ट सिंहजी भी इस समस्या से जूझ रहे हैं और भी सारे साथी जूझ रहे हैं तो उस 476 किलोमीटर को भी सार्वजनिक निर्माण विभाग कम्प्लीटली अपने खर्चे पर बनाएगा, यह घोषणा आज मैं करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सोने की गुर्जा की चर्चा इससे पहले कर दी। मंडरायल सफलगढ़ की चर्चा मैंने इससे पहले कर दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक समस्या और आयी थी जब हम इस क्षेत्र में घूमे। लगभग जो बी.आर.ओ. है, बोर्डर रोड आर्गेनाइजेशन है, जिसकी ग्रेफ की जो सड़कें हैं, वे लगभग 4051 किलोमीटर हमारे सीमावर्ती जिले में है।

एक बात मैं और मेंशन करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान एक और दुविधा से जूझ रहा है क्योंकि बाकी स्टेट्स को तो ट्रैफिक मिल जाता है पी.पी.पी. में, हमारे यहां पर एक प्राब्लम और है कि हमारा बोर्डर जो पाकिस्तान का है वह लगभग 1100 किलोमीटर का है और उसमें 4051 किलोमीटर उस समय ग्रेफ ने बना दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए हर्ष भी है कि जब 4 तारीख की चर्चा में माननीय वसुन्धराजी ने उनको अवगत कराया कि मैं स्वयं इन चार जिलों में घूमी हूं और मैंने देखा

(श्री युनुस खान)

कि ग्रेफ की जो सड़कें हैं वे जीर्ण-शीर्ण हालत में है, क्षतिग्रस्त हैं, चलने लायक नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी आप इसकी लिस्ट बनाकर ले आइये। अपन दोनों चलेंगे माननीय रक्षा मंत्रीजी के पास में और 4051 किलोमीटर के लिए मैं अलग से आपके राजस्थान को पैकेज दिलवाऊंगा यह भी उन्होंने हमको आश्वस्त किया है। हम उसकी पूरी सूची बना रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो यह ग्रेफ की जो सड़कें हैं उनको भी माननीय मुख्य मंत्रीजी और हम लेकर जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जब नए अच्छे दिन आने की बात कही, हजारों गांवों को जोड़ने की बात कही। एन.एच. के जो काम रुके हुए थे उनको लेकर एन.एच.आई. के पास हम गये। एन.एच. की समस्याओं को जब माननीय मंत्रीजी के पास, इससे पहले भी मैं मिला था, एक जुलाई को ही उन्होंने इसके लिए जब मैं पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग में गया तो जो महत्वपूर्ण सड़कें थीं, नागौर जिले में जो जोधपुर से आती है। जो जोधपुर का पोर्शन है, उस पोर्शन में चार लेन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर में बहुत बड़ी समस्या से नागौर के लोग जूझते हैं और बाइपास नहीं है, जोधपुर और नागौर का जो हमारा एन.एच. है, उस पर बहुत सारे लोग आते-जाते हैं। उस पर साढ़े चार सौ करोड़ की स्वीकृतियां माननीय अध्यक्ष महोदय, हम ले आये हैं जिसमें नागौर का बाइपास भी है और इसका भी काम हम शीघ्र शुरू कर देंगे। (व्यवधान) दो मिनट और।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रामगंजमण्डी से आने वाली माननीय सदस्या ने भी आज कहा 32 किलोमीटर की फोर लेन के लिए, कोटा से दरा तक फर्स्ट फेज की, 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी हम ले आये हैं। रामगंजमण्डी से आने वाली माननीय सदस्या, एक घोषणा मैं आज और करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कार्य काल में बहुत धरने प्रदर्शन हुए थे जब कांग्रेस का राज था और वे एम.एल.ए. थीं। जब परिवर्तन हो गया तो इनके एक आर.यू.बी. भी है, रामगंजमण्डी में। उसके लिए भी छह करोड़ रुपए की आवश्यकता है तो इस बजट के पास होते ही छह करोड़ रुपए हम रामगंजमण्डी के लिए भी जारी कर देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ और गंगानगर के बीच में जो 76 किलोमीटर का एन.एच है, उसकी स्वीकृति भी हम ले आये। मैं सूरतगढ़-गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि वह काम भी हम कर देंगे।

(श्री युनुस खान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब कुछ ऐसी चीजें हैं, छोटे-छोटे अनाउंसमेंट हैं, पुराना ढर्रा चला आ रहा है कि गांव में पटवारी कहां, ग्राम सेवक कहां, स्कूल कहां, बिल्डिंग बनेगी तो ऐसे लगेगा नीचे होगा जमीन से, छोटे-छोटे कमरे होंगे और होगा, कोई एलीवेशन नहीं होगा। अब जमाना बदल गया है, इसलिये हमने भी अब फैसला किया है कि अब जो सरकारी भवन बनेंगे, अभी तक तो जो सैंक्शन हो गये, वह तो हो गये, नये जो सरकारी भवन बनेंगे, वह एक नई नीति लाकर, नये नोर्म्स के अन्दर सरकारी भवनों का अच्छा एलीवेशन हो, अच्छा कंस्ट्रक्शन हो, जिससे पी.डब्ल्यू.डी. बार-बार बदनाम नहीं हो और माननीय सदस्यों की शिकायतें नहीं आयें। इसकी भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण धाम है बैणेश्वर और हमारे ट्राइबल एरिया के लोगों की उसमें बहुत बड़ी आस्था है। वहां पर बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, इसलिये डूंगरपुर जिले के बैणेश्वर धाम में सावला से बैणेश्वर पांच किलोमीटर सड़क को सात मीटर चौड़ा करने की आज मैं घोषणा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे हमारे सदस्य हैं। यहां हर जाति, धर्म के लोग हैं। माननीय वसुन्धराजी का और हमारी सरकार का यही मत है कि सब धर्म, सब जाति, सब 36 कौम हमारी हैं, इसलिये हमारे जो लोक देवी-देवता हैं, उनकी आस्थाओं का भी ध्यान रखें। यह राजस्थान है, इसमें लोक देवी-देवता है। इसलिये बेणेश्वर धाम के बाद में हमारा मुकाम का धाम है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां रोड तो नोखा से मुकाम तक है, लेकिन जब मेला होता है, उसमें लगभग 30 लाख यात्री आते हैं। वहां जाम लग जाता है और बहुत परेशानी होती है। इस दौरे के दौरान भी यह महसूस किया। आज हमारे नेता प्रतिपक्ष नहीं है, यह उनका क्षेत्र है और मुझे याद है वसुन्धराजी जब सुराज संकल्प से पहले मेले में गयी थीं तो पार्टी की अध्यक्ष ही थीं और अध्यक्ष होने के नाते ही उसमें गयीं। उसमें नेता प्रतिपक्ष भी जिला प्रमुख के नाते थे और उन्होंने उस समय उनको कहा कि आप जब मुख्य मंत्री थीं, आपने घोषणा की थी कि हम यह रोड बनायेंगे। वह रोड तो हम बनायेंगे। उन्होंने उलाहना दिया तो मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि मैंने तो यह बात लास्ट में दिसम्बर, 2008 में कही थी। उसके बाद में तो सत्ता परिवर्तन हो गया। पांच साल आपने क्या किया? नेता प्रतिपक्ष तो अपनी सरकार से करवा नहीं पाये। चूंकि यह उनका क्षेत्र है और उनके क्षेत्र में यह मुकाम पड़ता

(श्री युनुस खान)

है। बहुत सारे लोगों की आस्था है, इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी 18 किलोमीटर की जो डामर की सड़क है, उसको भी हम सात मीटर चौड़ा करने का काम करेंगे और आज मुख्य मंत्रीजी की तरफ से घोषणा है यह। उन्होंने वहां कहा था कि यह बनानी है, इसलिये इसकी घोषणा आज मैं हाउस में करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा बहुत सारी घोषणाएं तो हमने इसमें कर दीं। यह काका बहुत नाराज हो रहे हैं, लेकिन अभी सवाई माधोपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने अपनी बात कही हमीर सर्किल से भैंरू दरवाजा तक टूरिस्ट के लिये मेन सड़क काम में आती है, वह भी लगभग साढ़े 10 करोड़ रुपये से बनेगी और ढाई किलोमीटर के करीब है। उसको भी बनाने की मैं घोषणा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बेतेर से मलारना स्टेट तक 13 किलोमीटर की सड़क, जो सात मीटर चौड़ी होगी और करीब 39 करोड़ रुपये की होगी, उसको भी बनाने की हम घोषणा करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले में, मैं अभी यात्रा पर गया था, पहला ही दिन था, पहली ही पंचायत थी, उन्होंने मांग की। एक छोटा-सा वहां पर लिखमेवाला हैड है आरबी 1.5 किलोमीटर, 82 आरबी. है लिखमेवाला से, 82 आरबी तक की डेढ़ किलोमीटर की सड़क, जो लगभग 50 लाख रुपये में बनेगी, तो वह यात्रा का एक तोहफा उनको भी हम देना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले में जब मुख्य मंत्रीजी गयी थीं तो राजियासर से मोकलसर तक सात किलोमीटर की मिसिंग लिंक थी, 220 लाख रुपये से बनाने की भी घोषणा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले में 2 केके से एक पीपी ढाई किलोमीटर की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी। उसको भी बनाने की विधिवत, मतलब इस हाउस में उन्होंने कहा था कि यह लिख लेना, मैं लिखकर लाया था और आज इसको बनाने की मैं घोषणा करता हूं।

चूंकि हम धीरे-धीरे सारे धार्मिक स्थलों और सब जातियों की बात करते हैं। झालावाड़ में मीठेवाला शाह की एक दरगाह है, उस पर भी सड़क की जरूरत है। माननीय मुख्य मंत्रीजी भी कई बार जाती रहती हैं। वहां धार्मिक सद्भाव भी है, वहां के हिन्दू-मुसलमान सब मानते हैं। उसमें भी लगभग तीन किलोमीटर की सड़क है, माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश के बाद में आज हाउस में मैं विभाग की ओर से अध्यक्ष महोदय, घोषणा करता हूं।

(श्री युनुस खान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि हमारे बहुत सारे भाइयों का रामदेवरा में भी विश्वास है। उसके लिये भी हमारे पोकरण से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही। उन्होंने कहा है कि इसको छह फीट ही बना दो और सी.सी. ही बना दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि उस सड़क के ऊपर लोग नंगे पांव चलते हैं। सी.सी. रोड पर नंगे पांव चलेंगे तो दिक्कत रहेगी। इसलिये पूर्व घोषणा के अनुसार उस काम को पूरा करने, रामदेवरा मंदिर के पैदल तीर्थ यात्रियों के लिए जितना पैसा खर्च होगा, उसका एस्टीमेट बनकर आ रहा है, उसकी भी घोषणा मैं आज करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, करौली में कैला देवी मंदिर में हमारे पैदल तीर्थ यात्री जाते हैं, उसके लिये जितना भी खर्चा लगेगा, क्योंकि एस्टीमेट हमारे पास में नहीं है, अभी हम घोषणा ही कर रहे हैं, उसकी भी घोषणा मैं करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही, तो मैं आपको कह दूं कि जो 20 हजार किलोमीटर लिया है, इसमें सब चीजों का ध्यान रखा है। जहां-जहां से यह हाइवे निकलेंगे, जहां-जहां पर धार्मिक स्थान होंगे, जहां-जहां पर हैरिटेज प्रोपर्टी होगी, जहां-जहां फोर्स होंगे, हमारे इको-एनवायर्नमेंट के लिये जो जगह ट्यूरिज्म की दृष्टि से होगी, ट्यूरिज्म का ध्यान रखेंगे, फोर्स का ध्यान रखेंगे, हैरिटेज प्रोपर्टीज का ध्यान रखेंगे, रिलीजियेस प्लेसेज का ध्यान रखेंगे। सबको बना देंगे। इसलिये मैं आपको कह रहा हूं, उनको आपको अलग से कहने की जरूरत नहीं, उनको सबको हमने एक नक्शे पर ले लिया है। उनकी सबकी योजना बना ली है और फेजवाइज इन सबको बना देंगे।

अब चूंकि बहुत सारा समय हो गया, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो गंगानगर में...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मंत्रीजी, जोधपुर, सबसे पिछड़ा हुआ है सड़कों के मामले में। मुख्य मंत्री रहने के बावजूद भी सबसे पिछड़े हुए हैं। आप जोधपुर की तरफ भी देखना।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस बात से विदित हैं, सदन इस बात से विदित है कि जोधपुर तो आपको पता है दस साल तक उसकी दसों अंगुलियां घी में रही हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): फिर भी घी नहीं मिला हमको बिलकुल ही। अंगुलियां ही रहीं, घी बिलकुल नहीं मिला। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): लोगों को जाना है, सैटरडे है।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): मंत्रीजी जैसलमेर।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ..(व्यवधान) एक मिनट। एक-एक सड़क की चर्चा मैं करूंगा लम्बा हो जायेगा। हमने ग्रेफ को ले लिया, 4051 किलोमीटर है, जिसमें जैसलमेर ही ज्यादा है। सबसे ज्यादा ही जैसलमेर है। उन सड़कों के लिये हमने ले लिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक सैकण्ड, एक सैकण्ड, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड माननीय मंत्री महोदय ...(व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): लास्ट घोषणा है, फिर बोल देना आप।

श्री अध्यक्ष: बोलिये-बोलिये, मैं अनुमति दे रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से, मैंने चर्चा में जब भाग लिया था तो निवेदन किया था कि हमारी सरकार ने लक्ष्मणगढ़ से सीकर तक जो फोर लेन बनाया था, उसकी स्वीकृति के बावजूद सात महीने से काम चालू नहीं हो रहा है, उसके लिये फरमा दें कि कब चालू करेंगे?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस यात्रा के दौरान मैं, गंगानगर जिले और अनूपगढ़ रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन है। उस पर 5 आर.यू.बी; जो डी.ए.डी.पी. में बनने थे और वह काम नहीं हुआ, पिछली सरकार ने घोषणा की थी, चूंकि वहां गये तो यह मांग आई थी। आज उन पांचों आर.यू.बी. का लगभग जितना पैसा लगेगा, उसको बनाने की मैं घोषणा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन समय कम है। मेरे पास कटमोशन के जरिये जो बातें आई हैं, जो माननीय सदस्य ने लिखकर दिया है, उनको देखते हुए इन सब कामों को पूरा किया जायेगा। मैं सदन को, आपको और राजस्थान की जनता को इतना विश्वास दिला सकता हूं कि आपका कैबिनेट में ले लिया। नदबई का बाइपास, माननीय अध्यक्ष महोदय, कैबिनेट ने ही अप्रूव कर दिया, वह तो बनना ही है और उसकी तो घोषणा मुख्य मंत्रीजी स्वयं कर चुकी हैं, इसलिये यह चाह रही थीं कि इस हाउस में हो। राजसमंद से आने वाली माननीय सदस्या, हमेशा

(श्री युनुस खान)

चिन्ता करती हैं उन सड़कों की, जो ओवरलोड से टूट जाती हैं, उसके लिये हमने अलग माइनिंग रोड की घोषणा कर ही दी। माननीय अध्यक्ष महोदय वह बनायेंगे। अब सदस्य यह चाहें कि मेरी एक एक सड़क की यहां घोषणा हो और अंत में चूंकि माननीय हमारे राठौड़ साहब जो हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उनकी भी इच्छा थी कि एक घोषणा आज यहीं हो जाए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट सड़कों से ज्यादा राठौड़ साहब पर हुआ है, राठौड़ साहब पर ज्यादा चर्चा चली है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये, बैठिये। अब यह अंकित नहीं होगा फिर।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पालसर से कालूसर कनैक्टिविटी की है, जो हमारे पूर्व मंत्रीजी का जन्म स्थान रहा है तो उसको भी जोड़ने की लास्ट में मैं घोषणा करता हूं। (व्यवधान)

वो डेढ़ किलोमीटर ही है ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा आपको देंगे।

अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब बातें आ गयीं। लास्ट में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज की सार्थक चर्चा में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की सार्थक चर्चा में जितने सुझाव आये हैं, जो बात आयीं, और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार, अभी तो आपने 210 दिन की चर्चा की थी, यह तो 1825 दिन की सरकार बनी थी। सर, बनी है तो अब 1825 दिन में, अगर हम इसी साल सारी घोषणाएं सारे काम कर देंगे तो फिर अगले चार साल क्या करेंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये, कृपया विराजिये। वो आप बाद में पूछ लेना। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसलिए फेज वाइज सारे काम करेंगे, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इनके सारे जो सुझाव आये, काका हमारे वरिष्ठतम साथी, सदस्य हैं, उनके निर्देशन में, इनकी छत्रछाया में बैठ कर काम करता हूं। इन्होंने जो इकट्ठे किये हैं उनको एक-एक को हम पढ़ेंगे और एकदम प्राथमिकता के आधार पर होगी और जो यह माननीय, इधर से हाथ कर रहा हूं, माननीय सदस्य अपनी सड़कों को

(श्री युनुस खान)

प्राथमिकता पर देंगे तो उन सड़कों को हम प्राथमिकता के आधार पर जैसे-जैसे बजट में व्यवस्था होगी वैसे-वैसे बना देंगे। यह मैं आपसे निवेदन करता हूं।

अब मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मैंने आज सुबह जो मांग संख्या 19 और मांग संख्या 21 सदन के सामने रखी थी, उसको पास करने की घोषणा करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, पूरे सदन ने शांति से सुना और अन-इंट्रप्ट सुना उसके लिए मैं हाथ जोड़कर सब मेरे साथियों का, सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी को कुछ नहीं मिला, केवल लालीपोप मिली है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये, बैठिये।

मांग संख्या 19 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,09,25,93,000/- (अठारह अरब नौ करोड़ पच्चीस लाख तिरानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल।

मांग संख्या 21 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 50,02,64,31,000/- (पचास अरब दो करोड़ चौंसठ लाख इकत्तीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 21 जुलाई, 2014 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.24 बजे सोमवार, दिनांक 21 जुलाई, 2014 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

मांग संख्या-19 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-19 मुख्य शीर्षक लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

1. सिवाना उपखण्ड मुख्यालय पर स्वीकृत उपकोष कार्यालय हेतु भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सिणधरी उपखण्ड मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी का कार्यालय भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. सिवाना मुख्यालय पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सिणधरी में सार्वजनिक निर्माण विभाग का अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

5. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के बहरोड़ में अधिकारी व कर्मचारी भवन का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में बहरोड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र बहरोड में बहरोड़ न्यायालय परिसर में अपूर्ण निर्माण कार्य पूरा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्राम माढशा में उप तहसील भवन का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
9. विधान सभा क्षेत्र बहरोड में विश्राम गृह बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

10. ग्राम ढोला, जिला पाली स्थित डाक बंगला व्यवस्थित रूप से चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

11. विधान सभा क्षेत्र भीम में सरकारी भवनों एवं स्कूलों के कक्षा कक्ष एवं क्षतिग्रस्त चारदीवारी ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

12. प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग में ठेकेदारों से रायल्टी हेतु एस.टी.पी. लेने में पर्यावरण क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट लेने हेतु आने वाली कठिनाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. प्रदेश में सार्वनिक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता पद से निम्न स्तर के पदों यथा मिस्त्री, सुपरवाइजर, फोरमेन, मेट एवं गेंगमैनों के पदों पर भर्ती नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

14. प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में स्थित सरकारी डाक बंगलों/गेंग हटों का जीर्णोद्धार एवं शीघ्र मरम्मत कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ओटाराम (सिरोही) :

16. विधान सभा क्षेत्र सिरोही में जर्जर सरकारी भवनों के कार्यालयों को नवीन भवन में स्थानान्तरित करने एवं विधि महाविद्यालय के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

17. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के ग्राम सीमलवाड़ा में डाक बंगला निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) :

18. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के भीण्डर में स्थित पी.डब्ल्यू.डी. रेस्ट हाउस की मरम्मत व नवीन कमरों का निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

19. शाहपुरा (जयपुर) कस्बे के डाक बंगला में उच्च श्रेणी की सुविधाएं प्रदान करने व नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

20. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सुमेरपुर में डाक बंगला बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. पाली के सर्किट हाउस में 10 नये कमरों का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. राजस्थान हाउस, नई दिल्ली में मल्टी स्टोरी भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस परिसर में कर्मचारियों के आवासों का पुनर्निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई) :

24. विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के कस्बा नदबई में डाक बंगला निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

25. विधान सभा क्षेत्र लूणी में समस्त पटवार घरों व ग्राम सेवकों के मुख्यालय पर भवनों के निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. उपखण्ड मुख्यालय लूणी में तहसील भवन व पटवार भवन का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र लूणी के प्रमुख ग्रामों दुन्दाड़ा, लूणी, गुडा विश्नोईया, केरू, बेरू, सलोडी, धबा, सुवदण्ड, पीपरली, रोहियाकला, खेजड़ीकला, झालामणपाल, बोरानाडा, शालावास, इत्यादि ग्रामों में पुस्तकालय भवनों का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र लूणी के समस्त उच्च माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय व खेल मैदान का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र लूणी के मुख्यालय लूणी में डाक बंगला (विश्रामगृह) का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

30. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में सरकारी भवनों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में नकारा भवनों को ध्वस्त कर नये भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर (खण्डेला) :

32. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में रींगस एस.एच.सी. हास्पिटल के भवन की मरम्मत कराने एवं चारदीवारी को ऊंचा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के खण्डेला सी.एच.सी. हास्पिटल के भवन को सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में रींगस (सीकर) कस्बे में स्थित डाक बंगला को उच्च श्रेणी का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) :

35. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री प्रयोग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

36. जोधपुर मेडीकल कालेज से संलग्न तीनों मुख्य अस्पतालों एवं एम्स अस्पताल में आने वाले रोगी एवं परिजनों के ठहराव हेतु विश्रामगृहों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के सेटेलाइट अस्पताल प्रताप नगर के भवन को रखरखाव हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़) :

38. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के राजकीय बालिका सीनियर सैकेण्डरी स्कूल की जर्जर इमारत का पुनर्निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में जैयतसर मण्डी में बालिका विद्यालय के कमरों की छत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा असुरक्षित घोषित करने के उपरान्त भी छत का नवीनीकरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की सीगरासद पंचायत के डीडवाना गांव के विद्यालय भवन का नवीनीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

41. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में रानी तहसील भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के रानी में उपखण्ड कार्यालय भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के रानी में सामुदायिक केन्द्र का भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के डाक बंगले में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में खिवाडा उप तहसील भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

46. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के निर्माणाधीन ग्रामीण हाट बाजार को पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्थापित राजकीय महाविद्यालय के अधूरे भवन को पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के राजकीय चिकित्सालय के भवन का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के मोडक गांव में जीर्ण-शीर्ण सरकारी भवनों का पुन: निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

50. जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर के जीर्ण-शीर्ण भवन को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. किशनगढ़-ब्यावर सिक्सलेन राजमार्ग परियोजना पर नवनिर्मित टोलबूथ गेगल पर टोल टेक्स वसूलने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश (सपोटरा) :

52. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में कैलादेवी में विश्राम गृह निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के मण्डरायल उपखण्ड पर विश्राम गृह निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के मण्डरायल सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय भवन का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के उपखण्ड सपोटरा पर विश्राम गृह निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) :

56. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास की तहसील किशनगढ़ बास व कोटकासिम में विश्राम गृह निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में तहसील मुख्यालय कोटकासिम में प्रशासनिक अधिकारियों के सरकारी आवासों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दर्शन सिंह (करौली) :

58. विधान सभा क्षेत्र करौली की तहसील मुख्यालय मासलपुर के सार्वजनिक निर्माण विभाग का सहायक अभियन्ता कार्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

59. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील नादौती में सार्वजनिक निर्माण विभाग का सहायक अभियन्ता कार्यालय बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम व नादौती के उपखण्ड कार्यालय में विश्राम गृह बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

61. अजमेर स्थित राजकीय महाविद्यालय भवन के रख-रखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में स्थित अनुसूचित जति व अनुसूचित जनजाति के छात्रावास भवन के रख-रखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में स्थित पशु चिकित्सा केन्द्रों के भवन के आवश्यक रख-रखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के रख-रखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में स्थित पुलिस थानों के भवनों के रख-रखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

66. उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के निवास हेतु भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. तहसील लक्ष्मणगढ़ सीकर के अधूरे भवन को पूर्ण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

68. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द की रेलमगरा पंचायत समिति में ग्राम कुंवारिया में पंचायत भवन की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के रेलमगरा में डाक बंगले का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. राजकीय महाविद्यालय राजसमन्द में कमरों एवं हाल का निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द की रेलमगरा पंचायत समिति के ग्राम काबरा, जूणदा, पनौतिया, कोटड़ी, गिलूण्ड एवं जवासिया में नये पंचायत भवन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में वर्ष 2011 में बने आंगनबाड़ी भवन के मात्र 3 वर्ष में ही खण्डहर होने की जांच किसी एजेन्सी से करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर) :

73. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के लोक निर्माण विभाग के खण्ड सराड़ा में अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उपखण्ड क्षेत्र सराड़ा में डाक बंगला निर्माण नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र (डग) :

75. विधान सभा क्षेत्र डग के राजकीय माध्यमिक विद्यालय-भोगरा के जर्जर भवन का पुन: निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र डग के चौमहला-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास का पुन: निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) :

77. विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में स्वीकृत विभिन्न राजकीय भवनों का निर्माण पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण) :

79. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के मालाखेड़ा में तहसीलदार एवं कर्मचारियों के निवास हेतु भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के मालाखेड़ा में तहसील भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बालू राम चौधरी (सहाड़ा) :

81. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के अपूर्ण सरकारी भवनों का निर्माण पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता (नगर) :

82. विधान सभा क्षेत्र नगर में मेवात विकास बोर्ड द्वारा गुलपाड़ा व चोरगढ़ी में बनाये गये छात्रावासों की देख-रेख के अभाव में जीर्णशीर्ण एवं अतिक्रमण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र नगर के डीग व नगर में डाक बंगले में चल रहे सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय के लिये अलग कार्यालय बनवाकर डाक बंगला की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र नगर में लोक निर्माण के अन्तर्गत आने वाले भवनों पर अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र नगर के नगर कस्बे में स्थित डाक बंगले में दो नये कमरे बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लादूराम (गुढामालानी) :

86. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी के ग्राम बारासण में चेतन प्राग मठ का भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी के धोरीमना में आलम गौशाला में भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय हेतु भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी के धौरीमना में अजाणियों की ढाणी के हरिदासजी का आश्रम में भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी के ग्राम छोटू में पुरखाराम मंदिर भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर) :

91. विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर के ग्राम मकसूदनपुरा में राजकीय माध्यमिक विद्यालय के जीर्णशीर्ण भवन की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़) :

92. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ के डाक बंगले का सौन्दर्यकरण व चारदीवारी निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में बावड़ी उपखण्ड व पंचायत समिति स्तर पर डाक बंगला बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

94. विधान सभा क्षेत्र बायतू के उपखण्ड कार्यालय बायतू में कार्यालय भवन को पूरा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र बायतू के उपखण्ड मुख्यालय बायतू में सार्वजनिक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

96. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में खेलना राजकीय माध्यमिक विद्यालय

के जर्जर भवन की मरम्मत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में चिमनपुरा कालेज के भवन की मरम्मत न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के तहसील भवन, हास्पिटल भवन एवं डाक्टर आवास भवन के घटिया निर्माण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

99. विभाग के डाक बंगला विराटनगर में आवश्यक सुविधा फर्नीचर, लान, पेड़-पौधे आदि उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में बीलवाड़ी राजकीय सीनियर विद्यालय के भवन का रख-रखाव न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) :

101. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में चल रहे भवन रहित पी.एच.सी., सी.एच.सी. व उपस्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में चल रहे समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में सहायक अभियन्ता कार्यालय, बबाई का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) :

104. कोटपूतली एल.बी.एस. कालेज में 5 कमरों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में पानादेवी कन्या महाविद्यालय में 5 कमरों का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. कोटपूतली सार्वजनिक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में अतिरिक्त तीन कमरों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की पंचायत समिति रामसिंहपुरा के ग्राम खेड़कीवीमान में सामुदायिक भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की कांसली ग्राम पंचायत में आबंटित

भूमि में खेल मैदान (स्टेडियम) के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम) :

109. बीकानेर के पी.बी.एम. अस्पताल के भवन का नवीनीकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कुंजीलाल (बामनवास) :

110. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में नवीन कार्यालय का नवीन भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम वाटोदा में नवीन थाने के भवन का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम भावरा में उप तहसील के भवन निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) :

113. विधान सभा क्षेत्र कपासन के उपखण्ड मुख्यालय राशमी, भूपालसागर एवं मदेसर में सहायक अभियन्ता कार्यालय निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र कपासन के उपखण्ड मुख्यालय कपासन के सहायक अभियन्ता कार्यालय के पुराने भवन के स्थान पर नया भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. विधान सभा क्षेत्र कपासन में सार्वजनिक निर्माण विभाग के भवनों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र कपासन में उपखण्ड मुख्यालय राशमी, भूपालसागर, भदेसर में नवीन डाक बंगले बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. डाक बंगला कपासन में अतिरिक्त कमरों का निर्माण व रख-रखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

118. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में सहायक अभियन्ता कार्यालय डूंगला व बड़ी सादड़ी में खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के डूंगला में तहसील भवन का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के डूंगला में डाक बंगला निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं) :

121. विधान सभा क्षेत्र बेगूं में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय बेगूं, सहायक अभियन्ता कार्यालय रावतभाटा एवं गंगरार सहायक अभियन्ता कार्यालय भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. उपखण्ड मुख्यालय बेगूं व रावतभाटा एवं गंगरार डाक बंगले के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) :

123. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के ग्राम रूपनगढ़ के उपखण्ड पर उपखण्ड भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में प्रस्तावित महाविद्यालय का भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में स्थित हाडी रानी महिला बटालियन में आवास निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में रूपनगढ़ उपखण्ड पर डाक बंगला निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

127. वीरकाली बाई कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर के कक्षा कक्ष प्रशासनिक भवन, लाईब्रेरी तथा छात्रा यूनियन भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. देवेन्द्र बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय डूंगरपुर के हाल, कक्षा कक्ष तथा प्रशासनिक भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. एस.बी.पी. राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर में प्रशासनिक भवन एवं कक्षा कक्ष निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. राजकीय विजय माध्यमिक विद्यालय डूंगरपुर में पांच कक्षा कक्ष के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. श्री हरिदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय डूंगरपुर में सर्जिकल वार्ड, मेडिकल वार्ड, आर्थोपेडिक वार्ड, शिशु वार्ड, जनाना वार्ड, डाक्टर्स क्वाटर एवं नर्सिंग क्वार्टर निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-2

मांग संख्या-21 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-21 मुख्य शीर्षक सड़कें एवं पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

1. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सिवाना से समदड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालय की गौरव पथ योजना को डबल रोड से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में छिपाली से खण्डप सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. स्टेट हाइवे-38 सिरोही जालौर सिवाना बालोतरा किमी/110/0 से 118/0, 123/0 किमी से 136/0, 138/0 किमी से 140/0 किमी एवं 155/0 किमी से 158/0 तक पुलिया एवं डबल सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर) :

4. विधान सभा क्षेत्र करणपुर में केसरीसिंहपुर से मिर्जावाला तक 72 फीट चौड़ी सड़क का सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र करणपुर में चूनावठ से चानणाधाम 8एनएनए तथा गुलाबे वाला 52जीजी से 54एफ मुकन की सड़क चौड़ी करने एवं सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. श्री गंगानगर-करणपुर जिला मुख्य सड़क को ग्रेफ से निकालकर पी.पी.पी. या अन्य योजना में श्रीगंगागनर से करणपुर वाया जैड माईनर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र करणपुर के गांवों को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. विधान सभा क्षेत्र करणपुर में पदमपुर से जैतसर वाया बुढा जोहड़ तीर्थ स्थल तक पहुंचने वाली सड़क को ग्रेफ से निकालकर पी.पी.पी. या अन्य योजना में बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा) :

9. विधान सभा क्षेत्र भादरा में भादरा-साहवा सड़क की शीघ्र मरम्मत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

10. विधान सभा क्षेत्र भादरा में भादरा रेलवे अण्डरब्रिज एवं रेलवे ओवरब्रिज स्वीकृत कर निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र भादरा में भादरा से बालसमन्द (हरियाणा सीमा) तक क्षतिग्रस्त सड़क का पुनर्निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र भादरा में मुनसरी-ढीलकी सम्पर्क सड़क का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र भादरा में भादरा-नोहर, भादरा-साहवा तथा भादरा-राजगढ़ रोड को जोड़ने हेतु बाइपास स्वीकृत कर निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

14. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में नारनौल रोड से रैवाराज होते हुए हरियाणा बादरे, ग्राम नीमोर बसई, खोहर एवं शिवदानसिंहपुरा में सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में 1000 से ऊपर आबादी वाले ग्राम बिजोरावास, गोलावास, कीर्तिनसिंहपुरा, रघुनाथपुरा, विजयसिंह नगर, कूड रोड से मिलवपुर, खालखेडा, सोरवा, नागल खोडीया होते हुए नीमोर तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में बहरोड़ से हमीदपुर खोहरी वाया उनटोली से हरियाणा बार्डर तक सड़क की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में अलवर रोड से ढीस व अजमेरीपूर की सड़कों का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में कुंड रोड से अडींद महतावास, नंगली बलीहार होते हुए हरियाणा बार्डर व नानगवास गिगलाना रायसराना-हरियाणा बार्डर व पोसला बीधानाजाट हरियाणा बार्डर तक की सड़कों का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

19. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की राष्ट्रीय राजमार्ग से जुडने वाली, स्टेट की सड़कों का सम्पर्क सरल व सुनिश्चित ''मीडियन'' रखवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

20. विधान सभा क्षेत्र भीम की सभी सड़कें एवं क्षतिग्रस्त पुलिया के नवीनीकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

21. राष्ट्रीय राजमार्ग-112 बर से बिलाड़ा सड़क का फोरलेन निर्माण हेतु सरकार द्वारा 500 करोड़ की घोषणा करने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में सरकार द्वारा बजट घोषणा के उपरान्त भी बिलाड़ा नगरपालिका में रेलवे लाइन पर RUB (Road Under Bridge) का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में मिसिंग लिंक/धार्मिक स्थलों की सड़कों के निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में पीपाड़शहर नगरपालिका के पास गुजरने वाली जोजरी नदी पर पुल निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की सड़कों के किनारे पर पटरी पर अंग्रेजी बबूलों की झाड़ी के उगने से सड़कों पर दुर्घटनाएं घटित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

26. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में किशनगढ़ मार्बल एरिया स्थित हरमाड़ा रोड चौराहा से मडांवरिया स्थित कन्टेनर यार्ड तक की 6 कि.मी. सड़क का सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में किशनगढ़ से मालपुरा तक 70 कि.मी. मार्ग पर मेगा हाइवे के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में किशनगढ़ स्थित रेलवे ओवरब्रिज से मकराना रोड चौराहा तक सड़क पर सुदृढ़ीकरण एवं पेवरीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में किशनगढ़ (अप) स्थित फरासिया फाटक से वैष्णव देवी मंदिर तक मुख्य सड़क को चौड़ी करने एवं डामरीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ के पाटनचौराहा से तिलोनिया तक 7 कि.मी. की ग्रामीण सड़क का डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओटाराम (सिरोही) :

31. विधान सभा क्षेत्र सिरोही में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

32. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में चिरवली से आनन्दपुरी तक पुलिया मय सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में सड़कों की मरम्मत करने एवं नई सड़कों के निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में किरकी चौकी से (वाया सलूम्बर, डूंगरपुर) गुजरात सीमा सरथुना तक फोर लेन सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर) :

35. विधान सभा क्षेत्र बल्लभनगर में नगरपालिका भीण्डर के बाइपास निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

36. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) की मेजर ग्राम सड़कें व दो राज्य मार्गों की सड़कों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) की अपूर्ण व मिसिंग लिंक सड़कों को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों के निर्माण में सड़क सुरक्षा नियमों की पालना नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) की प्रस्तावित व लम्बित सड़कों के निर्माण पर रोक लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभगनर) :

40. विधान सभा क्षेत्र बल्लभगनर की प्रस्तावित एवं लम्बित सड़कों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

41. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में एनएच-65 के पाली बाइपास से पाली रूपावास-भांवरी-आहोर सड़क क्रासिंग पर पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई) :

42. विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के ग्राम खांगरी पर स्थित पथैना कैनाल की पुलिया की चौड़ाई बढ़ाये जाने एवं मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के गांव सैहपुरा से बरिधा तक के मार्ग पर डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के गांव हवीवपुर से धांधोली तक के मार्ग पर डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के गांव रौनीजा से भदीरा तक के मार्ग पर डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के गांव महरमपुर से रायसीस वाया किशनपुरा मार्ग पर डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा) :

47. विधान सभा क्षेत्र देवली में टोंक से बनेठा के मध्य क्षतिग्रस्त सड़क के नवीनीकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

48. विधान सभा क्षेत्र लूणी के बोरानाडा चौराहा से ग्राम झंवर की सड़क को एम डी आर (मेजर डिस्ट्रीक रोड) घोषित कर चौड़ाई बढाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र लूणी के ग्राम सालावास तहसील लूणी से ग्राम दुन्हाडा भाइ कला से फीच तक की सड़क को चौड़ा करने एवं नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र लूणी की सभी मिसिंग लिंक रोडो को मुख्य सड़क से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र लूणी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 114 से ग्राम केरू की सड़क को एमडीआर (मेजर डिस्ट्रीक रोड) घोषित करने एवं केरू की आबादी क्षेत्र में सड़क को चौड़ा करके नई सी.सी. रोड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र लूणी की सभी स्टेट हाइवे एच.डब्ल्यू. क्रम संख्या 61, 68, 58 इत्यादि की चौड़ाई बढ़ाकर नवीन रोड़ बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर (खण्डेला) :

53. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में शाहपुरा से चौमूं पिरोहितान की सड़क को जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में लापुवा से डोटड़ी कायलान वाया तिपिपलया सड़क की चौड़ाई 3.75 मीटर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में उदयपुर वाटी रोड से केरपुरा सड़क को 3.75 मीटर चौड़ी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में सुतलिया से कासल्डा को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) :

57. राज्य में सड़क मार्गों पर टोल टैक्स के रूप में हो रही वसूली से आम जनता पर पड़ रहे आर्थिक भार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में सड़कों के निर्माण व मरम्मत के लिए वर्ष 2014-15 में पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

59. विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

60. राज्य में 100 से अधिक आबादी वाले समस्त गांवों को सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में वर्ष 2013 में स्वीकृत सड़कों में से कुछ सड़कों की स्वीकृति वापस लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

62. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में गुरों का तालाब क्षेत्र से भीतर की ओर कायलाना चौराहा तक की सड़क के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
63. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में बडली मंदिर से बी.आर.ओ. बाइपास सड़क का सुदृढ़ीकरण, ड्रेनेज एवं चौड़ाई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
64. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में सोजती गेट चौराहे पर फ्लाई ओवर निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
65. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में राजस्थान उच्च न्यायालय से पावटा सर्किल होते हुए मण्डोर रोड से बी रोड तक फ्लाई ओवर निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये1
66. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में शनिश्चरजी का थान से महात्मा गांधी अस्पताल के आगे सर प्रताप स्कूल के पास तक वाया जालोरी गेट पर गांधी स्कूल की ओर टी एक्सटेंशन देते हुए फ्लाई ओवर निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) :

67. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में नागलसिया से गाहुबास तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
68. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में नीमराना से सिलारपुर-नाथेडी सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
69. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में वर्ष 2003-2008 तक निर्मित सड़कों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
70. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में शाहजहापुर से बर्डोद सड़कों की चौड़ाई बढ़ाकर नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
71. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में मोलावास से मिर्जापुर सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

72. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में सम्पर्क सड़कों का निर्माण एवं पूर्व में बनी सड़कों के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में 100 की आबादी वाले गांवों को सम्पर्क सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. मारवाड़ जंक्शन रेलवे कोरीडर पर ओवर ब्रिज बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में कन्टालिया से मारवाड़ जंक्शन ग्रामीण गौरव पथ निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंकशन में स्टेट हाइवे 61 व 62 के स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराने एवं राणी उपखण्ड कार्यालय को मेजर डिस्ट्रीक रोड से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़) :

77. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की कीकर वाली जोहड़ी से 239 आर.डी. होते हुए मधेवासी ढाणी तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की सीगरासर पंचायत में डीडवाना से खारिया होते हुए अर्जुनसर पल्लू रोड को जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के ठेठार ग्राम से सरदारपुरा खर्था गांवों को जोड़ने वाली सड़क पर घग्घर डिप्रेशनों पर पुल के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के राजीयासर स्टेशन ग्राम पंचायत में चक अमरपुरा में फुलेजी माईनर पर पुली निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की गोविन्दसर पंचायत के ग्राम सूरजनसर से 2 जीडीएम, 4 जीडीएम एवं 6 जीडीएम (पातलीया ढहर) को जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

82. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्थित ताकली नदी, आहू नदी व अभझार नदी के बीच पड़ने वाले गांवों में नवीन पुलिया निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में कुदायला अमरपुरा की स्वीकृत सड़क का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. कोटा से झालावाड़ तक राष्ट्रीय राज्य मार्ग की 7 किलोमीटर सड़क की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में मोडक व नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत निर्माणाधीन ओवरब्रिज का अधूरा कार्य पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में निर्माणाधीन पुलियाओं का निर्माण अतिशीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) :

87. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में साकड़ से खारा की सड़क का नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में भीनमाल से खाराकी तक की नवीन सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में शिवगढ़ से पावली तक की सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में मनोहरजी के वास से गजीपुरा सड़क का नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में रानीवाड़ा से चारवाड़ा की क्षतिग्रस्त सड़क के नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

92. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की चाणोद ग्राम से सुमेरपुर तक वाया बड़गांवड़ा, बाबागांव, कोसेलाव, तखतगढ़ मेघा रोड स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के ग्राम भांगेसर से खामल (तहसील सोजत) को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी) :

94. विधान सभा क्षेत्र बूंदी के गुमानपुरा पंचायत के अल्कोदिया ग्राम में क्षतिग्रस्त पुल का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र बूंदी के ग्राम पंचायत डाबी में अहिंसा सर्कल से चमन चौराहे तक 12 इंच मोटी सी.सी. सड़क का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र बूंदी में नमाना से गरडदा तक नई सडक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र बूंदी के लाखेरी से बिजोलिया से बीच मेघा हाइवे बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र बूंदी के हनूतिया और जैयथल के बीच कूरेल नदी पर पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश (सपोटरा) :

99. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में कैलादेवी से सपोटरा तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में मण्डरायल-करणपुर सड़क के दर्रा पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के ग्राम पंचायत शहिर, तहसील सपोटरा को मुख्य सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में कुडगांव-सपोटरा व नारौली डांग सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में बथुआ खोह सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

104. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में किशनगढ़ बास से गढ़ी बोलनी हरियाणा की सीमा तक बनी सड़क में ग्राम नया गांव से ग्राम पहाड़वास तक 4 कि.मी. सड़क को चौड़ा करने व ग्राम बिलाहेड़ी, कोटकासिम व बीबीरानी में पानी निकासी हेतु सड़क के दोनों ओर नाका निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में सावन वाटिका चौराहे से तोप चौराहा व तोप चौराह से बम्बोरा बाइपास तक सड़क का निर्माण कार्य व दोनों और पानी निकासी हेतु नाला निर्माण एवं किशनगढ़ बास व खैरथल में बाइपास सड़क का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में खैरथल से बल्लभ ग्राम होते हुये विजय मंदिर अलवर तक सड़क की चौड़ाई 7 मी. तक कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

107. अलवर जिले में अलीपुर सांचोर, खानपुर डागरान, नीमलाका, पुर, कलगांव, हिगवाहेड़ा, असलीमपुर व तिजारा तक सड़क को एम.डी.आर. घोषित कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में बीबीरानी से हरसौली होते हुये खैरथल तक सड़क की चौड़ाई 7 मी. तक करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दर्शन सिंह (करौली) :

109. विधान सभा क्षेत्र करौली के ग्राम आरेणी गुर्जर से मदनपुर तक नवीन सड़क निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र करौली के ग्राम मदनपुर से ऊंचा गांव (बाबूपुरा) तक नवीन सड़क निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. करौली शहर के बाहर गंगापुर सिटी से धौलपुर पर मेघा हाइवे पर गदका की चौकी से मासलपुर चुंगी तक बाइपास निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र करौली के ग्राम खानाके से निमरीपुरा तक सड़क निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र करौली के ग्राम बिचपुरी से महाराजपुरा के बीच पुल निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोड़ाभीम) :

114. विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम के ग्राम ल्हावद से केमरी तक नवीन सड़क निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये

115. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में तालचिड़ा की घाटी को चौड़ा कर नीचा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्राम लपावली में गम्भीर नदी पर पुल निर्माण कर सड़क निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील नादौती से जिला हैड क्वार्टर तक सीधी सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

118. अजमेर शहर के प्रमुख मंदिर साईबाबा की रोड़ निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में स्थित रेलवे क्रासिंग संख्या 1बी,

50बी, 46बी, 48बी पर आर.ओ.बी. निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. अजमेर शहर के चारों ओर मास्टर प्लान के अनुरूप एक रिंग रोड व एक एलिवेटेड रोड स्टेशन मार्ग पर बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) :

121. अजमेर शहर में स्थित तेजाजी की देवली से कल्याणपुरा तक की सड़क को मास्टर प्लान के अनुसार चौड़ा कर निर्माण कराये जाने एवं अजमेर से पुष्कर के बीच सुरंग निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

122. अजमेर शहर से गुजरने वाले नेशनल हाइवे संख्या 8 पर स्थित पर्वतपुरा चौराहे से माजुपुरा चौराहे तक के मार्ग को चौड़ा कर चार लेन में परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

123. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में सड़कों के नवीनीकरण एवं नवीन सड़कों को तय समय सीमा में नहीं बनाने पर पेनल्टी एवं ठेकेदार के विरुद्ध की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में बनी नवीन सड़कों को गारण्टी अवधि में ठीक कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) की क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में धाणा से रामसिंहपुरा, रामसिंहपुरा से जालू एवं बठोठ से लोक स्मारक तक की स्वीकृत सड़क को निरस्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

127. जिला सीकर में वर्ष 2013-14 में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के बावजूद भी नवीन सड़कें नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

128. विधान सभा क्षेत्र पिलानी की सड़कों का पुन: निर्माण व मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के ग्राम नेहरा की ढाणी, (पीपली पंचायत) से पूर्ण भगत का मंदिर जीणी से काजड़ा पंचायत समिति सूरजगढ़, विशनपुरा से हमीनपुर एवं हमीनपुर से डूलानिया में सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के BOT द्वारा निर्मित सड़कों पर अत्यधिक टोल वसूली को बंद करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के ग्राम महूला से रबूडी (जिला चूरू) एवं मंडेला से बाघपुरा सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के ग्राम फरट से बिजोली (पंचायत समिति सूरजगढ़), लाना गोठडा से चिड़ावा एवं लाना से अलीपुर सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा):

133. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में धौलपुर-राजाखेड़ा रोड से लालपुर की सड़क का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा के खेरली जसुपुरा रोड का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा की सड़कों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़) :

136. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के ग्राम कोटड़ाराणगा से खुटा ममपूल, गामड़ा रोड खेरीया घाटी से खजुरा बिजोरी, पेरमीदेन बावली का पाग से कलघाटी घतेनाका बस्सी एवं पाटन से बड़ी सखा सड़कों का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. विधान सभा कुशलगढ़ के ग्राम सज्जनगढ़ से ताम्बंसरा, कलीजरा से कुशलगढ़ वाया तांम्बेसरा, जिवाखुरा से नेशनल हाइवे बडवेल मट्टुडी गोडावरी तथा सज्जनगढ़ से ईराला सड़कों का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के ग्राम कुशलगढ़ से गांमदा वाया कोटड़ा

मायन घाटी से कुशलगढ़ वाया टिमेडा, कुशलगढ़ से बाजना वाया पाटन छोटी सखा, कुशलगढ़ से कलीजरा वसुनि काकनवनी उकाला तथा खेटा बारी से उकाला सड़कों का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के ग्राम भीलकुआ से डुगरा छोटा, गुजरात सीमा हुटीकंकासीला जालीमपुरा से कुशलगढ़ वाला डुगरा बोरकुण्डा, कसारवाड़ी रानी हीमतगढ़ी कसाखाड़ी से नालपाड़ा, कुशलगढ़ से बडलीपाड़ा सुरज कुण्ड, सबलपुरा, काकनिया, करमदीया आदि सड़कों का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में टिमेड़ा रोड़ बाकड़ी नदी पर बालदीया से झामरी, कुशलगढ़ से अखेपुर एवं ठीडोलीला सड़क पर पुल निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

141. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द की रेलमगरा पंचायत समिति के ग्राम चौकड़ी से पीपली अहिरान तक पुल निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के ग्राम पसून्द से तासोल तक नयी सड़क का निर्माण स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

143. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के रेलमगरा पंचायत समिति के ग्राम गांगास से ग्राम गिलुण्ड पर पुल निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के रेलमगरा पंचायत समिति के ग्राम जिनावास से जीवाखेड़ा तक पुल निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

145. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द की रेलमगरा पंचायत समिति के ग्राम कुराज में पुलिया निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिये।

श्री अमृत लाल (सलूम्बर) :

146. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सलूम्बर काबरा पैट्रोल पम्प के पास पुल का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सलूम्बर-बासवाड़ा रोड की पुलिया को चौड़ी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उपखण्ड सराडा में पादरडा से मड्डी (ग्राम पंचायत श्यामपुरा) नदी पर पुल एवं सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उपखण्ड सराडा में गोमती नदी पर मुलेवजी बावसी के पास पुलिया एवं सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के कराकली से रेबारी ढाणी नदी पर रपट व गुडेल नदी पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला) :

151. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला के ग्राम लाखनसर से कृष्णनगर तक डामर सड़क का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

152. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में RD 482 से 4 GM, 3 KM तक डामर सड़क का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में कानासर से JMD होते हुए धोलेरा फाटा तक सड़क का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में कावनी से जयमलसर तक 5 KM डामर सड़क का निर्माण कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू) :

155. विधान सभा क्षेत्र चाकसू की कोटखावदा से चाकसू व चाकसू से फागी तक की रोड की चौड़ाई बढ़ाने, डामरीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. विधान सभा क्षेत्र चाकसू के डाबिच से टूटोली तक नवीन सड़क के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. विधान सभा क्षेत्र चाकसू की सभी ग्रेवल सड़कों का डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. विधान सभा क्षेत्र चाकसू में बनी सभी क्षतिग्रस्त डामर सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

159. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में 250 से 499 तक जनसंख्या वाली ढाणियों को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल करवाकर स्वीकृति जारी करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

160. जोधपुर से देचू वाया तिवरी-चेराई-चामू सड़क को दो-लेन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में धार्मिक स्थल को डामर सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में ग्राम देवातू से गोगादेवजी का मंदिर सेखाला सड़क कार्य के लिए अतिरिक्त राशि की स्वीकृति जारी करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण एवं गारण्टी अवधि की सड़कों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र (डग) :

164. विधान सभा क्षेत्र डग के ग्राम कुमाटिया चायड़ा से सरवर तक हाई लेवल पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. विधान सभा क्षेत्र डग के ग्राम झिकड़ियां, चोरखेड़ी से होते हुए गरनावद तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. विधान सभा क्षेत्र डग के ग्राम टोकड़ा से एम.पी. सीमा तक ब्रिज निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. विधान सभा क्षेत्र डग में भवानी मण्डी बाण्डया बाग रोड से दो पुलिया के साथ सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) :

168. प्रदेश में टोल-रोडो पर आमजन को होने वाली असुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

169. हरियाणा सीमा से फतेहपुर जिला सीकर वाया झुंझुनूं पर बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. झुंझुनूं शहर में स्टेट हाइवे नम्बर-8 झुंझुनूं-जयपुर सड़क पर ROB निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण) :

171. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के ग्राम मोहब्बदपुर से ग्राम पकखड़ी वाया ग्राम साहोदी तक सड़कें निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

172. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण से भन्डोडी सम्पर्क सड़क की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

173. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के बीहा प्रतघाट रूपारेल नदी पर इन्दरगढ़ में सालपुर रोड पर पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

174. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के नटनी का बारह स्टेट हाइवे 44 पर पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगसीराम (रेवदर) :

175. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में राजस्व ग्राम को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

176. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में रेवदर मण्डार बाइपास बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

177. आबूरोड़, रेवदर सम्पर्क सड़क से गिखर पाठनारायण मंदिर के बीच पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबू राम चौधरी (सहाड़ा) :

178. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में फोरलेन का मुआवजा किसानों को दिलाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

179. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में नयी बनने वाली सड़कों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

180. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की अपूर्ण सड़कों को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

181. बाड़मेर शहर में चौहटन मार्ग पर रैन बसेरा के पास रेलवे फाटक पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

182. बाड़मेर-सिणधरी-जालौर स्टेट हाइवे की चौड़ाई बढ़ाने एवं इसके सुदृढ़ीकरण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

183. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर की सम्पर्क सड़कों के डामरीकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

184. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में पिण्डियों का तला से बालेरा तक डामर सड़क निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

185. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में सम्पर्क सड़क रोहिली भाडखा के डामरीकरण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) :

186. NH 12 पर दरा अभयारण्य में वन विभाग की आपत्ति को दूर करने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता (नगर) :

187. विधान सभा क्षेत्र नगर में पसोपा में पहाड़ स्थित मंदिर की अधूरी पड़ी सड़क को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

188. विधान सभा क्षेत्र नगर में खेड़ली-नगर-सीकरी-पहाड़ी से बीमा एवं राजस्थान बोर्डर तक मेगा हाइवे की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

189. भरतपुर में 84 कोस परिक्रमा मार्ग में डामर रोड बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

190. विधान सभा क्षेत्र नगर के सेऊ स्थित गोशाला के लिए सेऊ से जरखोड मंदिर तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

191. विधान सभा क्षेत्र नगर में कैथवाड़ा से डीग मार्ग का पुन: निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) :

192. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में सड़कें विहिन गांवों को सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

193. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में रामगढ़ बांध से रायसर सड़क की मरम्मत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

194. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में टूटी सड़कों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

195. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में गोडाणा से टोडेश्वर महादेव मंदिर तक रोड बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

196. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में बूज से चावण्डिया तक सड़क की मरम्मत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश (महुवा) :

197. विधान सभा क्षेत्र महुवा में टुडीयाना से बेरखेड़ा तक सड़क निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

198. विधान सभा क्षेत्र महुवा में पाली से भोपर तक नदी के बीच में पुल बनाकर सड़क बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

199. विधान सभा क्षेत्र महुवा RTDC मिड-वे से भरतपुर रोड बाइपास तक सीसी रोड बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

200. विधान सभा क्षेत्र महुवा में एन एच-11 पर हिण्डौन रोड पर बाय लेन बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

201. बाण गंगा नदी पर स्थित रसीदपुर पर पुल निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री लादूराम (गुढामालानी) :

202. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी में धनाऊ रोड से सियागों का बास कोजा तक सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

203. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी के ग्राम कौशलू से खिवालिया नाड़ा व सारणों की ढाणी में कच्चे रास्ते का डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

204. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी के ग्राम कोजा से रामवास एवं डारों की बेरी तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

205. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी के ग्राम गुढामालानी से सिंधासवा चौहान सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

206. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी के ग्राम रतनपुरा से मोलागरजी महाराज का धान तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर) :

207. विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर के ग्राम मलारना डूंगर से मलारना स्टेशन तक BOT सड़क बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

208. विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में हम्मीर सर्किल से भैरू दरवाजे तक डिवाइडर सहित सड़क निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) :

209. फायसागर रोड अजमेर से हाथीखेड़ा गांव तक सडक निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

210. फायसागर रोड अजमेर से बोराज-काजीपुरा सड़क का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

211. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर में वर्ष 2012-13 में स्वीकृत मिसिंग लिंक सड़कों के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने तथा इसको रिपोर्ट में पूर्ण दिखाने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

212. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर के अजमेर चौरसियावास रोड का पुन: निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

213. राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पर बनी सड़कों को खराब होने से बचाने के लिए इन पर चलने वाले ओवरलोड वाहनों की रोकथाम हेतु नियम बनाकर प्रभावी कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

214. सार्वजनिक निर्माण विभाग के जयपुर स्थित मुख्यालय में प्रान्तीय संघर्ष समिति को नियम विरुद्ध आबंटित कमरा संख्या डी-108 को अब तक खाली नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़) :

215. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ कजनऊ कला से कजनऊ खुर्द तक सड़कें बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

216. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्राम तोडियाना को रातड़ी से जोड़ने के लिए सम्पर्क सड़क का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

217. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ रामड़ावास खुर्द से आसापुर व नाड़ा खुर्द तक सम्पर्क सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

218. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्राम पंचायत कजनऊ कला में गांव के अन्दर पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

219. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में जाजिवाल गहलोता में पक्का बड़ा नाला एवं पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

220. विधान सभा क्षेत्र बायतू में पचपदरा से कानोड वाया पाटोदी डबल लेन सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

221. भारखा-बाटाडू-कानोड-सवाऊ पदम सिंह हीरा की ढाणी खोखसर-चाबा होते हुए जोधपुर के लिए डबल सड़क मार्ग की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

222. बायतू से फलसून सड़क को डबल-रोड में परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

223. प्रदेश में गारन्टी पीरियड की सड़कों की मरम्मत समय पर न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

224. विराटनगर के ऐतिहासिक गणेश मंदिर एवं उपखण्ड कार्यालय से जैन नसिया को सड़क से न जोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

225. एन.एच.-8 से MDR सड़क गढटकनेत नीमकाथाना स्टेट हाइवे रोड तक निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

226. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के आंतेला गांव में टूटे पुल के नव निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

227. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में एनएच-8 चौकी से करागा वाया राजचेता सड़क की मरम्मत न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

228. विधान सभा क्षेत्र निवाई के पुहाड़ा से जयकिनपुरा तक पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

229. विधान सभा क्षेत्र निवाई के ग्राम बगडवा इब्राहीया बाड से दिसालु सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

230. विधान सभा क्षेत्र निवाई में सिरस नल सड़क निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

231. विधान सभा क्षेत्र निवाई के बड़ा गांव (निवाई) देवडूंगरी लोरवाडा से अजमपुरा (पीपलू) तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) :

232. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में गुता से माची मीरापुर वाले रोड पर गहरे नाले पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

233. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में रामपुर मेन रोड से नाथुसर लोज तक रोड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

234. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में आड़ीगैली से कोठिया होता हुआ पंचायत गढी तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

235. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में बलवा काबास से मंगलवा होता हुआ काली पहाड़ी तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

236. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में मेन बावरिया रोड से बाडाली होता हुआ पंचायत भग्गू का बास तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) :

237. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में शिमला से महेन्द्र बागवान की ढाणी तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

238. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में आईवाला से मीणा का बास तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

239. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में बस स्टैण्ड बबाई से बाइपास स्वामीवाला तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

240. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में ढाणी हठवाली से सेफरागुवार तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

241. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में खरकड़ा से बसन्त विहार तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) :

242. राष्ट्रीय राज मार्ग सं. 79 व 113 की सड़कों के निर्माण के साथ निम्बाहेड़ा कस्बे से बाइपास देने पर नगरीय क्षेत्र की मुख्य सड़कों को एन.एच. 79 एवं 76 से लिंक करने हेतु सम्पर्क सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

243. चित्तौड़गढ़-निम्बाहेड़ा नीमच राष्ट्रीय राजमार्ग 79 पर निर्माणाधीन फोरलेन सडक पर ग्रा.प. रानीखेड़ा की ओर जाने वाले रास्ते पर अण्डर ब्रिज निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

244. चित्तौड़गढ़-निम्बाहेड़ा नीमच राष्ट्रीय राजमार्ग 79 को चित्तौड़गढ़-उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 76 से जोड़ने हेतु निम्बाहेड़ा-नंगलवाड (40 कि.मी.) की सड़क को फोरलेन सड़क करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

245. रेलवे स्टेशन निम्बाहेड़ा के समीप समपार रेलवे फाटक नं. 103 पर ओवर ब्रिज निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

246. पंचायत समिति छोटी सादड़ी से प्रतापगढ़ की सड़क मुवई से देवासमाता तक 5 कि.मी. सड़क के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) :

247. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में चौटिया से बनेटी होते हुए बसाट देवता होते हुए हरियाणा सीमा तक सड़क का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

248. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में एनएच 8 से रघुनाथपुरा से भैसलाना होते हुए सुजात नगर फार्म सडक का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

249. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में ग्राम गोरधनपुरा से कूजोता होते हुए पवाना अहिर पहाड़ी वाले मंदिर तक सड़क का पुन: निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

250. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली नाहरेड़ा से पावटा तक सड़क नवीनीकरण व नाहरेड़ा का बाइपास निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा) :

251. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में एनएच 8 से ऋषभदेव के अन्दर जाने वाली सड़क पर स्वीकृत पुल नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

252. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में लशढ़ी से पालीया जाने वाली नदी (तालाब) पर पुलिया नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

253. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में बावलवाड़ा पाडलियां से सागवाड़ा सड़क पर पुल नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

254. विधान सभा क्षेत्र खैरवाडा में एन.एच. 8 भाठवा ऋषभदेव मच्छारों की

ओबरी रोड पर नदी पुल नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

255. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में पडयावाड़ा ग्राम पंचायत में कल्याणपुर नदी पर बगड़ा कला पुलिया नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम) :

256. बीकानेर पश्चिम के सर्वोदय बस्ती करमीसर ग्राम एवं बंगला नगर में सड़कें बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

257. बीकानेर पश्चिम में Patch Work करवाने और सड़कों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

258. बीकानेर पश्चिम के शहरी इलाके की सड़कों का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कुंजीलाल (बामनवास) :

259. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम बासकी पुलिया से पीपलवाड़ा हिन्दूपुरा तक क्षतिग्रस्त सड़क का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

260. विधान सभा क्षेत्र बामनवास की ग्राम खिरणी से बोली तक क्षतिग्रस्त सड़क का नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) :

261. विधान सभा क्षेत्र कपासन में कपासन से सूरजपुरा वाया धमाना सड़क की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

262. विधान सभा क्षेत्र कपासन में राशमी से नेवरिया सड़क वाया मरमी माताजी की चौड़ाई 7 मीटर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

263. विधान सभा कपासन में कारोई से कपासन वाया राशमी सड़क की चौड़ाई 7 मीटर कर पुन: बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

264. विधान सभा क्षेत्र कपासन में बनास नदी पर सांखली के पास निर्मित पुल की चौड़ाई बढ़ाकर 2 मीटर ऊंचा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

265. विधान सभा क्षेत्र कपासन में शनि महाराज के पास की पुलिया की चौड़ाई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर) :

266. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में बछान्दी, खेमरा रोड से खुशहाला का नंगला तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

267. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में रारह रोड पर लेन ROB में हुई अनियमितताओं की जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

268. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के राजस्व ग्राम नंगला माना, ग्राम पंचायत बिलोटी में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।

269. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में एम एस जे कालेज भरतपुर से उत्तर प्रदेश बार्डर चिकसाना तक स्टेट हाइवे की टूटी सड़कों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

270. भरतपुर शहर की टूटी हुई सड़कों का मरम्मत कार्य नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (गढ़ी) :

271. विधान सभा क्षेत्र गढी में ग्राम नाटावाडा से मादलदा सड़क की डामरीकरण एवं पुलिया नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

272. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी की ग्राम टिमुरूवा से बोड़ी गाम सड़क का डामरीकरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

273. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में ग्राम पंचायत देवलिया में पुलिया निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

274. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में ग्राम पंचायत मादलदा से परतापुर का डामरीकरण उखड़ जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

275. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में तलवाड़ा से चिडियावास का डामरीकरण टूट जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

276. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में बेहेड़ा से बड़ी सादड़ी तक मिसिंग लिंक रोड की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

277. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में राणावतों का खेड़ा से सरथला तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

278. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में अमीरामा से नडवत तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

279. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में पालेड से पदमपुरा तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

280. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में पिराना से नोगावा होते हुये करौली तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं) :

281. विधान सभा क्षेत्र बेगूं में काइन्दा मोड़ से बेगूं सड़क की चौड़ाई 9 मीटर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

282. विधान सभा क्षेत्र बेगूं में जावड़ा निमड़ी क्षेत्र में नदी पर पांच पुलियाओं का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

283. विधान सभा क्षेत्र बेगूं में गंगरार से बसती तक सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

284. विधान सभा क्षेत्र बेगूं में सुनार की बाबड़ी से जोगणीला माताजी की सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

285. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में माडा से पाटड़ी होता हुआ मदाफरा भण्डारिया घाटा तक मय पुलियों के सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

286. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में रतनपुर-डमुनी-माखरेडा गेड होता हआ पालीसोडा तक सड़क मय पुलिया के चौड़ा व सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

287. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में उदयपुर सीमा पाल पादर से सेरावाड़ा तक सड़क चौड़ी व सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

288. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में ओटा छोटा से करौली को जोड़ने हेतु हाइट में पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

289. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में बारोठी एन.एच. 8 से नवलश्याम, ओडा छोटा होता हुआ हथोड़ पादरड़ी तक सड़क एवं पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कुंजीलाल (बामनवास) :

290. विधान सभा क्षेत्र बामनवास की ग्राम मिथुनपुरा से पीपल्दा तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

291. विधान सभा क्षेत्र बामनवास की तहसील बौंली से जस्टाना तक क्षतिग्रस्त सड़क का नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

292. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम पिपलाई मोड़ से बामनवास तक क्षतिग्रस्त सड़क को 7 मीटर चौड़ी कर नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-3

अनुदान की मांग संख्या 19 लोक निर्माण कार्य मांग संख्या 21 सड़कें एवं पुल पर श्री घनश्याम (टोडाभीम) का वक्तव्य जो पढ़ा हुआ माना गया

श्री घनश्याम (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको तहेदिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे आज सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांग संख्या 19 एवं 21 पर बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, टोडाभीम माडा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जहां की आबादी छितरी बसी हुई है। गांवों में न तो सड़क की सुविधा है और न ही पानी की व्यवस्था। जिसके अभाव में मेरे क्षेत्र की ग्रामीण जनता धीरे-धीरे शहरों की ओर पलायन करती जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के ग्रामों को शहरी सड़कों से जोड़ना नितांत आवश्यक है ताकि गरीब किसान अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा व अपनी फसल को मंडियों में बेचकर उचित मूल्य प्राप्त कर सके। इसी क्रम में माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान मेरे क्षेत्र की निम्नांकित सड़कों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

प्रथम तो टोडाभीम के गांव ल्हावद से केमरी तक की सड़क का नवीनीकरण, तालचिड़ा की घाटी का चौड़ाईकरण, जिससे आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। ग्राम लपावली में गम्भीर नदी पर पुल निर्माण ताकि एक ग्राम को दूसरे ग्रामों से लिंक किया जा सके। इसके अतिरिक्त टोडाभीम की तहसील नादौती से जिला हैड क्वाटर तक सीधी सड़क का निर्माण कार्य ताकि आम आदमी सीधे जिला हैड क्वाटर से जुड सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की तहसील नादौती में सार्वजनिक निर्माण विभाग का सहायक अभियंता कार्यालय तथा टोडाभीम व नादौती के उप खण्ड कार्यालय में विश्राम गृह का निर्माण करवाया जाये। दूर दराज से मेरे विधान सभा क्षेत्र के नजदीक धार्मिक स्थल श्री महावीरजी में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में अधिकारी/जन-प्रतिनिधि दर्शानार्थ पधारते हैं।

मेरा विधान सभा क्षेत्र अनेकों तीर्थ स्थलों के मध्य में पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि यदि मेहन्दीपुर बालाजी एवं श्री महावीरजी तीर्थ स्थल को मेगा हाइवे से जोड़ दिया जाये तो हजारों तीर्थ यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा तथा श्री महावीरजी से नादौती एवं

सिकन्दरा से गंगापुर सिटी तक मेगा हाइवे लिंक कर दिया जाये तो इस क्षेत्र की जनता ही नहीं लाखों की संख्या में प्रति वर्ष आने वाली यात्रियों को लाभ मिलेगा।

धार्मिक तीर्थ स्थल जगदीश धाम केमरी से नांगल शेरपुरतथा गुढाचन्द्रजी से हिण्डौन तक की स्टेट हाइवे निर्माण करवा दिया जाता है तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के आसपास पड़ने वाले तीर्थ स्थल जैसे कैला देवी, मदनमोहनजी, मेंहदीपुर बालाजी, श्री महावीरजी, जगदीश धाम आदि, जहां प्रति वर्ष लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री दूरदराज से दर्शनार्थ आते हैं। लहखर से कुजेला, रलावता से भहस्वा, सोप से पिलोदा, मेडा से तेस, बड़ागांव से ल्हावर सड़क निर्माण, कैमरी बस स्टैंड से जगदीश धाम कैमरी सड़क का चौड़ाईकरण व नये पुल का निर्माण, भीलापाड़ा से मोहनपुरा, कैमा से कुजेला, बरदाला से ल्हवार कुन्ड, बारदाला से अलुदा सड़क निर्माण कराना, श्री महावीरजी नाडाल शेरपुर के बीच आने वाली नदी पर (चौड़ाव) पुल निर्माण कराना।

अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।